हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

ई-कॉमर्स के तेजी से कसते शिकंजे पर वाजिब चिंता

ऑनलाइन खरीद-बिक्री यानी ई-कामर्स ने पिछले सालों में कारोबार के तौर-तरीकों में काफी बदलाव ला दिया है। यह भी कहा जाने लगा है कि इंटरनेट की घर-घर पहुंच रखने वाले भारत में अब ऑनलाइन शॉपिंग विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत बन गई है। एक तथ्य यह भी है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के इस फैलते कारोबार ने खुदरा कारोबार के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भारत में तेजी से बढ़ रहे ई-कॉमर्स को लेकर केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की इस चिंता को भी इसी संदर्भ में देखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन कारोबार छोटे विक्रेताओं के ऊंचे मार्जिन व ऊंची कीमतों वाले उत्पादों को खा रहा है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिनसे छोटे दुकानदारों की रोजी-रोटी चलती है।

देश में ऑनलाइन खरीद-बिक्री का दौर शुरू होने के साथ ही छोटे विक्रेताओं ने अपने ऊपर आए संकट की बात कहनी शुरू कर दी थी। एक हद तक उनके कारोबार पर इसका असर भी हुआ। अब केन्द्रीय मंत्री ने उनकी बात पर मुहर लगाने का ही काम किया है। मंत्री ने ई-कॉमर्स से जुड़ी एक रिपोर्ट को जारी करने के मौके पर यह भी कहा कि वर्ष 2019 में ई-कॉमर्स की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी महज 4.7 प्रतिशत थी जो इस साल 10.7 प्रतिशत हो जाएगी। सब जानते हैं कि ई-कॉमर्स कंपनियां उत्पादों की खरीद-परोक्ष जिन कीमतों पर करती हैं उन पर छोटे व्यवसायियों के लिए स्पर्धा करना और बाजार में टिके रहना मुश्किल हो जाता है। ये कंपनियां एक बार ऐसा करने के बाद कब कीमतें बढ़ा दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में कोई न कोई नियामक व्यवस्था तो लागू करने की आवश्यकता सदैव ही रहने वाली है। यह संतोष का विषय है कि अब भी आम भारतीय सब्जियां व छोटे-मोटे घरेलू सामान अपने आसपास के फुटकर विक्रेताओं से ही खरीदता है। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियां धीरे-धीरे इन पर भी कारोबारी शिकंजा कसती जा रही हैं। इस कारोबार का बड़ा मुनाफा कुछ नामी-गिरामी कंपनियों के पास ही पहुंच रहा है। यह तर्क दिया जा रहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। लेकिन यह चिंता भी किसी से छिपी नहीं है कि लाखों गिग श्रमिक रोजगार से संबंधित बिना किसी कानूनी सुरक्षा के काम कर रहे हैं।

केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा है कि वे नहीं चाहते कि ई-कॉमर्स कंपनियां खत्म हो जाएं लेकिन उनकी भूमिका को व्यवस्थित करने की जरूरत है। जाहिर है यह भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे खुदरा विक्रेताओं को कारोबारी नुकसान नहीं झेलना पड़े।

कृषि : कृषक परिवार जिन वस्तुओं का निर्माण करें, उनकी बिक्री की व्यवस्था हाट बाजारों में की जा सकती है

ग्रामीण उद्योगों को बनाएं किसानों की ताकत

प्रो. सी.एस. बरला
कृषि अर्थशास्त्री, विश्व बैंक और योजना आयोग से संबद्ध रह चुके हैं
@patrika.com

कृषकों की आय बढ़ाने के लिए कम पानी में पैदा होने वाली फसलों पर अधिक से अधिक ध्यान देना जरूरी है। साथ ही ग्रामीण उद्योगों का विकास करके भी कृषकों की आय को बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं।

भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि और किसानों की उपेक्षा करके भारत विकसित देश नहीं बन सकता। यही वजह है कि केंद्र सरकार कृषि के विकास और किसानों की आमदनी को बढ़ाने के प्रयास कर रही है। इसके बावजूद इस दिशा में अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है।

हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सदियों से भारत में कृषि एक एकीकृत सेक्टर के रूप में रही है। हमारे यहां खेतों का आकार छोटा होने पर भी कृषक आमतौर पर सुखी था। सिंचाई की व्यवस्था अपर्याप्त होने पर भी किसान एक फसल उगाते हुए, खाली समय में पशु पालन करता था। उसके पास प्रायः गाय, कुछ भेड़-बकरियां या दूसरे पशु हुआ करते थे, जिनसे उसे अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती थी। कुछ किसान बढ़ई, मोची, लुहार का काम भी करते थे, तो कुछ रस्सी बनाने का कार्य करते थे। इन गतिविधियों से अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती थी। इस स्थिति में धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। शहरों के विकास के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति समीपवर्ती कस्बों से होने लगीं। इनमें बढ़ई का सामान, जूते-चप्पल, साबुन, रस्सी, खाद्य सामग्री, दालें तथा अन्य खुदरा वस्तुएं शामिल थीं। इस कारण हमारे गांव के छोटे किसान अतिरिक्त आय से वंचित होने लगे। उनके रोजगार तथा आय के स्तर में कमी हो गई, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां केवल एक ही फसल उगाई जा रही थी। साथ ही गांव की स्वायत्तता भी समाप्त होती गई। वस्तुतः अनेक पीढ़ियों से भारत का किसान अनेक गतिविधियों का संचालन एक साथ करता रहा है। परिवार के लिए भरण पोषण के लिए अन्न के उत्पादन, बच्चों के लिए दूध की आपूर्ति, गायों के रख-रखाव, खेत में ही सब्जी व दालों का उत्पादन करने से किसान को आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त थी। गांव तथा समीपवर्ती कस्बे के हाट से उसकी अन्य प्रकार की जरूरतें पूरी हो जाती थीं।

गांव में ही कुछ परिवार जूते, लकड़ी की वस्तुएं आदि का निर्माण करते थे। इन वस्तुओं को सुविधापूर्वक हाट में बेचा जा सकता था। यह सही है कि परिवहन की अपर्याप्त सुविधा के कारण विभिन्न गांवों में वस्तुओं का पारस्परिक व्यापार संभव नहीं था। इसके बावजूद स्वतंत्रता से पूर्व हमारे गांव अपनी आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। इस अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह थी कि यह संतुलित थी और बाजार के उतार-चढ़ाव से मुक्त थी। उत्पादन का स्तर छोटा तथा बाजार की कुल मांग के अनुरूप बना रहता था। जैसे-जैसे भारत के शहरों में फैक्ट्री आधारित उत्पादन बढ़ने लगा, भारत की ग्रामीण तथा शहरी अर्थव्यवस्थाओं में मांग तथा आपूर्ति के बीच संतुलन बिगड़ना प्रारम्भ हो गया। वस्तुतः फैक्ट्री आधारित उत्पादन में जहां एक ओर बड़े स्तर पर पूंजी की जरूरत होती है, वहीं उत्पादन क्षमता का भी एक न्यूनतम स्तर निर्धारित होता है। इससे कम स्तर पर उत्पादक इकाई अस्तित्व में नहीं रह पाती। इसी कारण विभिन्न उत्पादक इकाइयों के लाभ के स्तर भी घटते-बढ़ते रहते हैं। साथ ही इनके शेयर मूल्य भी घटते-बढ़ते हैं। यही कारण है कि आज का दौर उतार-चढ़ाव का दौर है। इस विसंगति का भारत की परम्परागत अर्थव्यवस्था में कोई स्थान नहीं था। यह स्पष्ट कर देना उपयोगी होगा कि उस दौर में हमारी जीडीपी की वृद्धि दर कम रही, लेकिन संतुलित तथा विश्वसनीय थी। आज का दौर अन्तरराष्ट्रीय विषमताओं तथा विसंगतियों का दौर है। जहां एक जोत का का आकार अत्यंत छोटा होने के कारण, लाभप्रदता का स्तर कम है, वहीं सहायक गतिविधियां समाप्त होने के कारण कृषि उतार-चढ़ावों का शिकार हो रही है, विशेष रूप से जहां पर एक ही फसल उगाई जा रही है। यह राहत की बात है कि हाल के दशकों में भारत सरकार कृषि की त्वरित प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति गंभीर है। वर्ष 2025 तक कृषकों की आय को दोगुना करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिए गए हैं। फिर भी हमें यह स्मरण रखना होगा कि कृषि से प्राप्त आय में वृद्धि काफी हद तक पानी की निर्भर करेगी। इसलिए कम पानी का उपयोग करने वाली फसलों पर अधिक से अधिक ध्यान देना भी जरूरी है। इस बात पर भी विचार करना होगा कि कम लागत में हम ग्रामीण उद्योगों का विकास करके भी कृषकों की आय को बढ़ा सकते हैं।

ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त समय में साबुन निर्माण, बिजली-नल मरम्मत, बढ़ईगिरी, जूता निर्माण जैसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देकर हम कृषक परिवारों की आय में वृद्धि के प्रयास कर सकते हैं। आज भी देश के अनेक भागों में साप्ताहिक हाट की परंपरा चल रही है। कृषक परिवारों द्वारा निर्मित वस्तुओं को इन साप्ताहिक बाजारों में बेचने की व्यवस्था की जा सकती है। राजस्थान में 2004 में मिशन ऑन लाइवलीहुड की स्थापना की गई थी जिसके अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को कुटीर उद्योगों से सम्बद्ध प्रशिक्षण दिया गया था। यह तरीका उपयुक्त रहेगा। थोड़ा सा प्रशिक्षण हमारे ग्रामीण युवाओं को अतिरिक्त आय दिला सकता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर गंभीरता से प्रयास होने चाहिए।

फैक्ट फ्रंट

वाइल्ड टर्की

अधिकांश उत्तरी अमरीकी बच्चे टर्की की पहचान बचपन से ही सीख लेते हैं, थैंक्सगिविंग कार्ड बनाने के लिए ट्रेस पेपर की मदद से उनके हाथों की आउटलाइन तैयार कर। ये बड़े, शानदार पक्षी साल के बाकी दिनों में भी एक आम दृश्य बन जाते हैं, जब इनके झुंड जंगल व आसपास के मैदानों में छोटे डायनासोर की तरह घूमते हैं। प्रणय निवेदन करने वाले नर पक्षी पंखों की गेंदों में खुद को फुला लेते हैं और तेज आवाज करते हैं। खाने की मेज पर इनकी मांग ने इनके अस्तित्व के लिए संकट पैदा किया, पर अब स्थिति बेहतर है।

यूएस : राष्ट्रपति जॉनसन को शामिल होने से कर दिया गया था मना

बहुत शानदार नहीं रही बाइडन की विदाई, पर बहुत बुरी हो सकती थी

कैरेन टुमल्टी
राजनीतिक मामलों की स्तम्भकार
द वाशिंगटन पोस्ट से विशेष अनुबंध के तहत

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रपति बाइडन का उनकी पार्टी ने जिस स्नेह से स्वागत किया, वह आंशिक रूप से उस राहत के रूप में मापा जा सकता है जो बाइडन के प्रेसिडेंशियल रेस में फिर से शामिल न होने से पार्टी को मिली है। पार्टी का नेशनल कन्वेंशन अमरीका के शिकागो में हो रहा हैं जहां बाइडन ने सोमवार को विदाई भाषण दिया। बाइडन का जो स्वागत हुआ, वह डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में किसी भी पिछले राष्ट्रपति को मिले आदर-सम्मान से कहीं अलग था क्योंकि उन्होंने फिर से चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। इसके पहले अगस्त 1968 में, राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने वसंत ऋतु में घोषणा की थी कि वह दूसरा कार्यकाल नहीं चाहेंगे। उनका भाषण भी उस वर्ष के कन्वेंशन में बाइडन की तरह ही नियत था। संयोग से वह कन्वेंशन भी शिकागो में ही हुआ था। उस सप्ताह राष्ट्रपति जॉनसन का 60वां जन्मदिन भी था। पांच फुट लम्बा केक बनवाया गया था और हिल्टन होटल के भव्य इंपीरियल सुइट में उनका इंतजार हो रहा था। पर जब जॉनसन अपने सम्बोधन की विषयवस्तु को परिष्कृत कर रहे थे, तब भी शहर की सड़कों और पार्कों में पुलिस एवं वियतनाम युद्ध के विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों का माहौल था। इस बीच राष्ट्रपति के पास अमरीकी प्रतिनिधि सभा के लिए लुइसियाना के सदस्य हेल बोग्स का फोन आया और उन्होंने उन्हें आने से मना कर दिया। हालात बहुत ही नाजुक थे। बोग्स ने उनसे यह भी कहा कि अगर वे आते हैं तो हॉल के भीतर पार्टी के डेलीगेट्स उनका अपमान भी कर सकते हैं। ऐसे में प्रथम महिला, लेडी बर्ड जॉनसन ने अपने टेक्सास हिल कंट्री फार्म में अपने पति के जन्मदिन पर उदास माहौल में छोटे से रात्रिभोज का इंतजाम किया था।

प्रसिद्ध इतिहासकार डोरिस कियर्न्स गुडविन उस समय वाइट हाउस में सहयोगी थीं और शिकागो में मौजूद थीं। उन्होंने अपनी हालिया किताब में उस दौरान हुई घटनाओं को उकेरा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति का फोन आया तो वह हैरत में पड़ गई। उन्होंने बहाना बनाया कि वह उस टॉर्च को तलाश रहे थे जो उन्होंने (गुडविन ने) उनसे उधार ली थी। जब उन्होंने (गुडविन ने) उनसे पूछा कि वह क्या कर रहे हैं तो राष्ट्रपति जॉनसन ने प्रतिवाद किया: 'आपको क्या लगता है कि मैं कैसा हूं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी खुद को कमतर महसूस नहीं किया है। मैं अपने जन्मदिन पर अपने लोगों, अपनी पार्टी डेलीगेट्स के समक्ष शिकागो नहीं जा सकता।'

यह राजनीतिक घटनाओं या भाग्य का सबसे ज्यादा नाटकीय मोड़ था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। इस घटना के सिर्फ चार साल पहले, जब जॉनसन ने रिपब्लिकन पार्टी के बैरी गोल्डवाटर के मुकाबले भारी जीत हासिल की थी तब उनकी पार्टी ने आतिशबाजी करके अटलांटिक सिटी के आसमान को रोशनी से पाट दिया था। पर युद्ध में बड़ी हानि और उसी साल मार्टिन लूथर किंग जूनियर और और सीनेटर रॉबर्ट एफ. कैनेडी (डेमोक्रेट-न्यूयॉर्क) की हत्याएं हुईं और अमरीका अपना गुस्सा और क्षोभ अपने राष्ट्रपति पर निकाल रहा था। उसके बाद के दशकों में जॉनसन के राष्ट्रपति वाले कार्यकाल को नरम दृष्टि से देखा गया। अलबत्ता, वियतनाम एक त्रासदी थी जो उनके दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर दागदार धब्बा लिए है। पर इतिहासकार उनकी वास्तविक घरेलू उपलब्धियों की तारीफ ही करते आए हैं।

राष्ट्रपति जॉनसन ने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन की समाप्ति पर कांग्रेस और लाखों अमरीकियों को संबोधित करते हुए कहा था-'अब से अगले सौ साल के बाद भी, मुझे उम्मीद है, यह कहा जा सकता है कि हमने मिलजुल कर काम करते हुए देश को और अधिक न्यायपूर्ण और देश के सभी लोगों के लिए और अधिक न्यायसंगत वातावरण देने में मदद की, और इसके साथ ही हमारी समस्त भावी पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता का आशीर्वाद सुनिश्चित किया।' उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसी ही उम्मीद है।' यह भी जोड़ा- 'पर मेरा मानना है कि कम से कम यह तो कहा ही जाएगा कि हमने कोशिश तो की।'

ओशनएक्स : चीनी कंपनी ने तैयार किया सबसे बड़ा एकल क्षमता वाला फ्लोटिंग विंड पावर प्लेटफॉर्म

यह है दुनिया का सबसे बड़ा एकल क्षमता वाला फ्लोटिंग विंड पावर प्लेटफॉर्म ओशनएक्स। यह 13 अगस्त को चीन के गुआंगझोउ से ग्वांगडोंग में यांगजियांग मिंगयांग क्विंगझोउ-4 ऑफशोर विंड फार्म के लिए यात्रा पर निकला था। 191 नॉटिकल मील और 50 घंटे से अधिक की टोइंग के बाद, प्लेटफॉर्म का आगमन हरित ऊर्जा में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जो ऑफशोर विंड पावर तकनीक के लिए मानक स्थापित करने के लिए तैयार है। मिंगयांग ग्रुप द्वारा विकसित यह फ्लोटिंग विंड टरबाइन प्लेटफॉर्म 'वी' आकार में व्यवस्थित है और इसमें दो 8.3 मेगावाट की ऑफशोर विंड टर्बाइन हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रसंगवश

खनन माफिया के आगे जिम्मेदार नतमस्तक क्यों

प्रदेश में बढ़ते अपराधों का एक बड़ा कारण अवैध खनन से पनपे संगठित गिरोह भी हैं

जिनके पास अवैध खनन रोकने का जिम्मा है, यदि वे ही सरकार को चूना लगाए तो इसे क्या कहेंगे? हाल ही में ऐसा मामला डीग में सामने आया है। वहां खनन माफिया ने अवैध खनन कर करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व का चूना लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि विभाग पेनल्टी लगाने के बाद भी अब तक वसूली नहीं कर सका है। इतना ही नहीं, करीब नौ महीने पहले जिन दो गांवों में ड्रोन सर्वे कर अवैध खनन का आकलन किया गया, उस रिपोर्ट को ही जिम्मेदार अधिकारी दबाकर बैठे गए। ऐसे में खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। यहां जिन लीजों पर करीब 40 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी, वहां स्वीकृत रवन्ना से भी अधिक अवैध खनन हो चुका है। पेनल्टी वाली लीजों पर आज भी अवैध खनन जारी है।

दरअसल, प्रदेश के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। पेनल्टी हो या कार्रवाई का दूसरा कोई जरिया, सभी मामलों में बचाव का रास्ता खुद विभाग ही माफिया को दिखाता है। खनन इलाकों में माफिया पुरानी लीज का हवाला देकर संबंधित अधिकारियों को भ्रमित भी करते रहे हैं। कई जगह इनके आगे जिम्मेदार नतमस्तक भी नजर आते हैं। पुलिस थानों, तहसील और उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में से कोई भी अधिकारी शिकायत मिलने के बावजूद मौके पर जाने से कतराते हैं। खनन माफिया के हौसले बुलंद हो चुके हैं। पिछले साल बीकानेर में खनिज विभाग की विजिलेंस टीम से माफिया जिप्सम से भरे ट्रक जबरन छुड़ाकर ले गए थे। हालत यह हैं कि माफिया सरहद के आसपास के संवेदनशील इलाकों में भी धरती को छलनी करने से नहीं चूक रहे।

अवैध खनन से राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर भी है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों का एक बड़ा कारण अवैध खनन से पनपे संगठित गिरोह भी हैं। समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगा तो हमारी खनिज सम्पदा की तिजोरी खाली हो जाएगी और राजस्थान अपराधियों का गढ़ बन जाएगा। माफिया के खिलाफ ऐसा सख्त रुख अपनाना चाहिए कि फिर कोई अवैध खनन का दुस्साहस नहीं कर सके। बेहतर तो यह है कि पेनल्टी के स्थान पर सीधे लीज निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। जिम्मेदारों की मिलीभगत सामने आने पर कार्रवाई की नजीर पेश करने की भी दरकार है। **- आशीष जोशी**

ashish.joshi@epatrika.com

आपकी बात

आरक्षण सीमा नहीं बढ़ाई जाए

आरक्षण की पचास प्रतिशत सीमा को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। आरक्षण प्रतिशत को बढ़ाना अनारक्षित वर्ग के साथ अन्याय होगा। इससे असंतोष बढ़ेगा।
-ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उदयपुरा, मप्र

आज का सवाल

ई-कॉमर्स का देश के खुदरा व्यापारियों पर क्या असर हो रहा है?

ईमेल करें
edit@epatrika.com

विदेश नीति रूस-यूक्रेन युद्ध की विभीषिका के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कीव यात्रा के मायने

अमरीका और रूस के बीच कूटनीतिक संतुलन की कोशिश

डॉ. एन.के. सोमानी
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com

मोदी के कीव दौरे को रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति मिशन की तरह प्रचारित किया जा रहा है। इसकी अहम वजह यह है कि भारत ने अभी तक रूस-यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। यह अलग बात है कि दुनिया इसे रूस समर्थक तटस्थता के रूप में देख रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब रूस-यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर है। यूक्रेनी सेना रूस के सुदजा शहर पर कब्जा कर चुकी है। यहां रूस का प्राकृतिक गैस का बड़ा प्लांट है। दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है, जब रूस की जमीन पर किसी दूसरे देश की सेना ने कब्जा किया है। युद्ध में यह पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका है। रूस भीषण जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दुनिया के किसी भी राजनेता के लिए कीव यात्रा का शायद इससे ज्यादा खराब समय दूसरा नहीं हो सकता है। सवाल यह है कि मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे के लिए यही समय क्यों चुना है।

कहा जा रहा है कि जुलाई में मोदी जब मास्को दौरे पर गए थे तो उससे पहले इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। तभी जेलेंस्की ने मोदी को आमंत्रित किया था। तो क्या मोदी केवल जेलेंस्की के आमंत्रण पर ही कीव जा रहे हैं! कहानी का एक पक्ष और भी है।

दरअसल, मोदी जिस दिन मास्को की यात्रा पर गए थे, ठीक उसी दिन रूस ने कीव में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल से हमला किया था। इस हमले में कई लोगों के मरने की खबर आई थी। जेलेंस्की ने मोदी की मास्को यात्रा की यह कहकर आलोचना की कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने मास्को में दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधी को गले लगाया है। दूसरी ओर मोदी के रूस दौरे से अमरीका की भी भृकुटि चढ़ी हुई है। मास्को यात्रा के बाद अमरीका ने भारत को चेतावनी दी कि उसे अमरीका के साथ रिश्ते को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दोनों महाशक्तियों के साथ भारत के रणनीतिक हित जुड़े हैं। वह न तो वाशिंगटन को नाराज करना चाहता है और न ही मास्को को। भारत दोनों देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन साध कर चलना चाहता है। इस तरह देखें तो संभव है कि मोदी अमरीका को खुश करने के लिए जेलेंस्की को गले लगाने कीव जा रहे हैं।

मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं, जो युद्ध के शुरू से ही रूस और यूक्रेन को शांति का महत्त्व समझाते रहे हैं। वे कई बार पुतिन को युद्ध के दुष्परिणामों पर नसीहत दे चुके हैं। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी अमरीका द्वारा नियंत्रित जेलेंस्की को उसकी रजामंदी के बिना युद्ध विराम के लिए राजी कर सकेंगे। क्या मोदी के पास ऐसा कोई सर्वमान्य फार्मूला है जिसके जरिए मोदी पुतिन या जेलेंस्की को उनके जाने-पहचाने रुख से पीछे हटने के लिए राजी कर सकें। दोनों नेता जिस तरह मोर्चे पर डटे हैं, यह सब बहुत सरल नहीं रहने वाला है।

सच तो यह है कि दोनों नेताओं के अपने-अपने हित हैं। पुतिन की मुख्य चिंता नाटो के पूर्व की ओर निरंतर विस्तार से जुड़ी हुई है। नाटो रूस की सीमाओं पर आक्रामक हथियारों की तैनाती कर रहा है। पुतिन यूक्रेन का विसैन्यीकरण करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में यूक्रेन की शांतिकालीन सेना में सैनिकों की संख्या 85,000 से अधिक न हो। इसके अलावा पुतिन यूक्रेन को नाजीवाद से मुक्त करना चाहते हैं। वह जेलेंस्की को नव-नाजियों के प्रवर्तक के रूप में देखते हैं। दूसरी ओर जेलेंस्की के अपने हित हैं। हालांकि, पुतिन कई अवसरों पर युद्ध को स्थगित करने और बातचीत करने के संकेत दे चुके हैं, पर जेलेंस्की ने पुतिन की शर्तों पर शांति वार्ता में शामिल होने से इंकार कर दिया है। सच तो यह है कि जेलेंस्की ने युद्ध में खोए हुए क्षेत्रों को वापस लेने की कसम खाई है, जिसमें 2014 में कब्जाए गए क्रीमिया और पूर्वी डोनबास के कब्जे वाले हिस्से शामिल हैं।

मोदी अपनी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं। अमरीका में अगले कुछ माह में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। मोदी जेलेंस्की को यह समझा सकते हैं कि वाशिंगटन में सत्ता परिवर्तन उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। वैश्विक घटनाक्रम भी यूक्रेन के लिए समर्थन के मौजूदा स्तरों में बदलाव का संकेत दे रहा है। यूरोप के बहुत से देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन के बाद बनी नई सरकारों ने यूक्रेन को फंडिंग की समीक्षा की बात कही है। ऐसे में यूक्रेन के सामने बातचीत के अलावा कोई राह शेष नहीं रह जाती है।

तमाम परिस्थितियों के आलोक में अगर प्रधानमंत्री मोदी अमरीका और यूरोप की भागीदारी के बिना रूस और यूक्रेन को संघर्ष विराम के लिए राजी कर लेते हैं, तो यह न केवल भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता होगी बल्कि वैश्विक राजनेता के रूप में उनकी छवि और अधिक मजबूत होगी। लेकिन यात्रा का सारा दारोमदार इस सवाल पर निर्भर करता है कि परस्पर विपरीत मोर्चों पर डटे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को वह संघर्ष विराम के लिए किस हद तक राजी कर पाते हैं।

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

इसे स्कैन करें

पत्रिकायन का सवाल था, 'क्या आरक्षण की पचास प्रतिशत की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए?' प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।
https://shorturl.at/ImpGI

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 160

निवेश सुधार की मिली जुली तस्वीर

मांग के चार प्रमुख कारकों- निजी खपत, निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात - में सरकारी व्यय, खासतौर पर पूंजीगत व्यय के माध्यम से होने वाले व्यय ने पिछले कुछ वर्षों में देश की आर्थिक वृद्धि में मुख्य योगदान किया है। उदाहरण के लिए इस वर्ष केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय आवंटन सकल घरेलू उत्पाद के 3.4 फीसदी के बराबर है। किंतु आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए लंबे अरसे तक सरकारी व्यय पर निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि केंद्र और राज्य के खजानों की भी सीमाएं हैं। सीमित राजकोषीय क्षमताओं के बीच आर्थिक वृद्धि को मध्यम से दीर्घ अवधि तक बरकरार रखने के लिए निजी निवेश का रफ्तार पकड़ना जरूरी है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया आंकड़े दिखाते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता का इस्तेमाल बढ़ रहा है। वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में क्षमता का इस्तेमाल एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह 2021-22 की तीसरी तिमाही से ही लगातार 75 फीसदी के आसपास बना हुआ है। क्षमता के उच्च इस्तेमाल से आम तौर पर कारोबारों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे नया निवेश भी आता है। लेकिन बिक्री के मुकाबले इन्वेंट्री यानी उत्पादों के स्टॉक का अनुपात महामारी से पहले की तुलना में काफी ऊंचा है। यह 2020-21 की पहली तिमाही में 113 फीसदी था और उस उच्चतम स्तर से घटकर 2023-24 की चौथी तिमाही में 65 फीसदी रह गया परंतु इसका लगातार ऊंचा स्तर बताता है कि उपभोक्ता मांग में अनिश्चितता और कमजोरी है। क्षमता के बढ़ते इस्तेमाल और इन्वेंट्री का लगातार ऊंचा स्तर शायद बताता है कि खपत में वृद्धि अनुमान से सुस्त है। यह देखकर शायद कंपनियां फौरन बड़ा निवेश करने के लिए तैयार नहीं होंगी। इस समाचार पत्र में बुधवार को प्रकाशित समाचार का उदाहरण लें तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी अपने उत्पादन में कतरब्योंत कर रही है ताकि डीलरों के पास पड़ा कारों का स्टॉक कम हो सके।

इसके अलावा रिजर्व बैंक के नए मासिक बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र के पास अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं मसलन ब्राजील और यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक रिक्त क्षमता है यानी अधिक क्षमता इस्तेमाल के बगैर पड़ी है। रिक्त क्षमता वह है, जिसका इस्तेमाल मांग बढ़ने पर करने से अतिरिक्त उत्पादन किया जा सकता है। देश के विनिर्माण क्षेत्र के पास सेवा क्षेत्र के मुकाबले अधिक रिक्त क्षमता है। इसका अर्थ है कि मांग सुधरने पर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। सकारात्मक पहलू देखें तो कंपनियों और बैंकों की बैलेंस शीट अच्छी स्थिति में हैं और इनसे निजी निवेश में सुधार को मदद मिलनी चाहिए। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारतीय कंपनियां क्षमता विस्तार के साथ अगले एक-दो साल में 45 से 50 अरब डॉलर सालाना निवेश कर सकती हैं। यह व्यय विभागों को एक साथ लाने, नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के प्रयासों के कारण होगा। मूडीज का अनुमान यह भी है कि भारत में जिन कंपनियों को वह रेटिंग देती है, उनका कुल मुनाफा अगले दो वर्ष में सालाना 5 फीसदी दर से बढ़ेगा। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली व्यापक वृद्धि से इसमें मदद मिलेगी।

बैंक ऋण से संबंधित आंकड़े यह भी बताते हैं कि निवेश के मोर्चे पर गतिविधियां सुधरी हैं। मगर यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि व्यापक निजी निवेश में सुधार हो रहा है। क्षमता का इस्तेमाल बढ़ा है लेकिन उद्योग के पास इन्वेंट्री भी बहुत अधिक है। ऐसे में काफी कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि निजी खपत मांग आने वाली तिमाहियों में किस तरह बढ़ती है। मॉनसून अच्छा होने और ग्रामीण मांग पटरी पर आने से मदद मिल सकती है परंतु निवेश को वैश्विक कारण भी प्रभावित करेंगे। बढ़े हुए भूराजनीतिक तनाव, व्यापार में उथलपुथल और विकसित देशों में मांग में कमी की संभावना निर्यात मांग और निवेश में रोड़ा अटकाएगी। चीन में काफी अतिरिक्त क्षमता भी भारत में निवेश पर खास तौर पर निर्यात करने वाले क्षेत्रों में निवेश पर असर डालेगी।

अजय मोहंती

नौकरियां और विकास: अच्छी और बुरी खबरें

दशकों तक उच्च विकास हासिल करने की क्षमता के लिए आवश्यक है कि हम श्रम के आधिक्य वाले उद्योगों में लाखों की संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार सृजित करें। बता रहे हैं नौशाद फोर्ब्स

हमारी आकांक्षा 2047 तक विकसित देश बनने की है। किसी विकसित या उच्च आय वाले देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी करीब 14,000 डॉलर होता है यानी 2,700 डॉलर के हमारे वर्तमान प्रति व्यक्ति जीडीपी के पांच गुने से भी अधिक। उस स्तर तक पहुंचने के लिए हमें अगली चौथाई सदी तक वृद्धि दर को मौजूदा दर से दो फीसदी अधिक यानी करीब 8.5 फीसदी पर रखना होगा।

वृद्धि और रोजगार आपस में जुड़े होते हैं। जैसे-जैसे देशों का विकास होता है वैसे-वैसे वृद्धि सबसे नाटकीय कारक के रूप में लोग कृषि जैसे कम उत्पादकता वाले काम से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र जैसे अधिक उत्पादकता वाले पेशों में जाने लगते हैं। जब किसी किसान का बेटा चेन्नई में जोहो, पुणे में जोमैटो या बेंगलूरु में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने जाता है तो परिवार की आय में हुआ इजाफा सीधे जीडीपी में नजर आता है। आय में इस वृद्धि से अर्थव्यवस्था में इजाफा होने लगता है क्योंकि परिवार छुट्टियों से लेकर प्रोसेस्ड फूड तक सभी की खपत करने लगता है।

बीते 30 सालों से हमारे जीडीपी में वृद्धि खपत के बल पर हुई है। इसी तरह जब हम शहरों से गांवों की ओर उलटा पलायन देखते हैं तो आर्थिक वृद्धि पर असर होता है। पिछले चार साल में कृषि और अनौपचारिक ग्रामीण स्वरोजगार सेवाओं में दो करोड़ रोजगार शामिल हुए हैं। हमें देखना होगा कि दशकों तक कम उत्पादकता वाले ग्रामीण रोजगारों से उच्च उत्पादकता वाले शहरी रोजगारों तक पलायन हुई। हाल के दिनों का उलटा रुझान विकास की नाकामी को दिखाता है।

जुलाई में आई आर्थिक समीक्षा बताती है कि 56.5 करोड़ के हमारे कुल श्रम बल में 46 फीसदी कृषि में, 11 फीसदी विनिर्माण में, 13 फीसदी निर्माण कार्यों में और 29 फीसदी सेवा क्षेत्र यानी व्यापार, होटल तथा परिवहन आदि में है।

कृषि 46 फीसदी रोजगार देता है किंतु जीडीपी में उसका योगदान केवल 18 फीसदी है। कृषि में इतने लोगों की आवश्यकता नहीं है। रूमानियत से परे देखें तो अधिकतर किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। तकनीक के मामूली इस्तेमाल के साथ हम इतना ही अनाज एक चौथाई किसानों के बल पर भी उगा सकते हैं।

समीक्षा में कृषि क्षेत्र से बाहर सालाना 80 लाख रोजगार तैयार करने की बात कही गई है। इसके लिए तार्किक अनुमानों का सहारा लिया गया है। श्रम बल में पुरुषों की भागीदारी मौजूदा स्तर यानी 54 फीसदी पर ही बनी रहेगी। महिलाओं की भागीदारी मौजूदा 27 फीसदी से हर साल 1 फीसदी बढ़ती जाएगी। यह दर कम प्रतीत होती है लेकिन बीते 30 वर्ष दिखाते हैं कि शहरों में महिलाओं के लिए रोजगार तैयार करने में हमारा प्रदर्शन कमजोर रहा है। हर वर्ष कम से कम एक फीसदी लोगों को कृषि से विनिर्माण और सेवा में आना चाहिए। यह भी कम लगता है लेकिन बीते 23 सालों में इसका बड़ा प्रभाव हुआ है। हमें नहीं पता कि ग्रामीण इलाकों में कितने लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 70 फीसदी लोग गांवों में रहते थे। 2021 की जनगणना में बहुत देर हो चुकी है किंतु अनुमान है कि अब 60 फीसदी लोग ही गांवों में रहते होंगे। शेष 10 फीसदी वहां से निकलकर महानगरों नहीं बल्कि छोटे शहरों में रहने लगे होंगे।

यह अनुमान अच्छी खबर लाता है। श्रम बल में नए लोगों का शामिल होने और कृषि से दूर होना सीधे जीडीपी बढ़ाता है। समीक्षा यह भी दिखाती है कि रोजगार में सर्वाधिक वृद्धि निर्माण में तथा लॉजिस्टिक्स तथा कंपनियों के भीतर ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों में हुई है। निर्माण क्षेत्र में अधिकांश रोजगार ठेके पर होता है। ये बहुत स्तरीय काम नहीं हैं लेकिन उत्पादक हैं और कृषि की तुलना में अधिक आय प्रदान कराते हैं। विनिर्माण और सेवा के क्षेत्र में 80 लाख से अधिक नौकरियां अगले 23 साल में हर वर्ष जीडीपी में तीन चौथाई से एक प्रतिशत तक वृद्धि करेंगी। 2047 तक यह विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में जो फासला है, उसका आधा तो इससे ही दूर हो जाएगा।

यह तो हुई अच्छी खबर। बुरी खबर यह है कि एक साल में कृषि से बाहर 80 लाख रोजगार हम कभी तैयार नहीं कर पाए। समीक्षा बताती है कि कृषि प्रसंस्करण और केयर इकॉनमी यानी बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों आदि की देखभाल से संबंधित सेवाओं में संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में बहुत गुंजाइश है।

इस वर्ष के बजट में मौजूदा कंपनियों में रोजगार बढ़ाने के तीन तरीके अपनाने का प्रयास किया गया है: पहले माह का वेतन बतौर सब्सिडी देना, नए कर्मचारियों की भर्ती के बाद पहले दो साल उनकी भविष्य निधि की राशि देना और एक बड़ा इंटर्नशिप कार्यक्रम, जिसमें सरकार छात्रवृत्ति देगी। ये सभी उपयोगी हैं और पहले से ही नौकरियां दे रही कंपनियों के लिए मददगार होंगे। यह अलग सवाल है कि उनकी वजह से कंपनियां ज्यादा लोगों को नौकरियां देंगी या नहीं। मेरा सुझाव है कि श्रम आधारित उद्योगों पर ध्यान दिया जाए।

आर्थिक समीक्षा के मुताबिक विनिर्माण में कार्यरत छह करोड़ लोगों में से केवल 1.7 करोड़ कारखानों में काम करते हैं। शेष लोग छोटे उपक्रमों में काम करते हैं। परंतु यह धारणा भी सही है कि कारखानों में ही वह आधुनिक विनिर्माण रोजगार होता है, जिसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। ये रोजगार कहां हो सकते हैं?

लाखों में रोजगार तैयार करने की क्षमता तीन क्षेत्रों में है - वस्त्र, खाद्य और इलेक्ट्रॉनिक असेंबली। हमारा वस्त्र क्षेत्र लंबे समय से पिछड़ा हुआ है क्योंकि इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। अब इसमें जरूरी सुधारों की आवश्यकता है। जिस तरह हमने फॉक्सकॉन को भारत में बुला लिया है उसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी परिधान कंपनी ली ऐंड फंग को भी बुलाना चाहिए, जो चीन में करीब 10 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार देती है। बांग्लादेश में परिधान के एक बड़े कारखाने में 30,000 से 50,000 लोगों को नौकरी मिलती है मगर भारत में केवल 3,000 से 5,000। इसमें इजाफा कैसे किया जा सकता है? डिजाइन और तकनीक के जरिये? या कौशल की मदद से? मुक्त व्यापार समझौते के तहत बाजारों तक शुल्क मुक्त पहुंच भी ऐसा कर सकती है? या श्रम सुधार अथवा एक खास अवधि के लिए श्रमिकों को अधिक आसानी से काम पर रखना?

खाद्य प्रसंस्करण में हम अब भी अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बहुत पीछे हैं। दुनिया के 20 फीसदी फल और सब्जियां हमारे देश में उगते हैं लेकिन डेलॉयट के अनुसार हम अपने 4.5 फीसदी फलों और 2.7 फीसदी सब्जियों का ही प्रसंस्करण करते हैं। हम इन क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में सफलता नई है। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन श्रम के बहुत अधिक इस्तेमाल वाले कारखाने स्थापित कर रही हैं। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक असेंबली उन 14 पीएलआई क्षेत्रों में से इकलौता है, जहां श्रम का बहुत अधिक इस्तेमाल होता है। आईफोन के खोल बनाना, फोन असेंबल करना, कपड़े बुनना और संतरों का प्रसंस्करण करना ड्रोन और सेमीकंडक्टर बनाने जैसा आकर्षक काम बेशक नहीं हो मगर लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। रोजगार की कारगर रणनीति के लिए श्रम के अधिक इस्तेमाल वाले उद्योगों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(लेखक फोर्ब्स मार्शल के को-चेयरमैन और सीआईआई के पूर्व अध्यक्ष हैं)

पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की बढ़ती होड़

वित्त वर्ष 2025 के बजट से काफी पहले से ही रोजगार की समस्या का मसला अखबारों के पहले पन्ने पर छपता रहा है। लेकिन इस बजट से पता चला है कि देर से और खीझकर ही सही सरकार ने इस पर ध्यान दिया है। अर्थशास्त्री खुले तौर पर और निजी क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां गुपचुप बातचीत में यह मान रही हैं कि बजट में रोजगार से जुड़ी जिन तीन प्रोत्साहन योजनाओं और इंटर्नशिप योजना का जिक्र किया गया है उनसे कोई बड़ा बदलाव शायद ही दिखेगा। मगर इस साल के बजट में जिसे बड़े आइडिया के नाम पर रोजगार के लिए भारी भरकम प्रयास करने का दबाव निजी क्षेत्र पर बढ़ाया जा रहा है।

इस बीच बेरोजगारी और अच्छी नौकरियां कम होने के कारण निचले वर्ग में शामिल होने की होड़ बढ़ रही है और कभी संपन्न समझे जाने वाले समुदाय भी पिछड़े वर्ग का ठप्पा लगाने के लिए तैयार हैं ताकि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएं। ये दोनों रुझान 2016 की नोटबंदी के बाद तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं। विडंबना की बात यह है कि ये रोजगार सृजन की रफ्तार को और कमजोर कर सकते हैं।

अब निजी क्षेत्र पर विचार करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तर्ज पर ही यहां भी जातिगत आधार पर ठोस उपाय किए जाने की सुगबुगाहट 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों से ही सुनी जा रही है। राहुल गांधी ने भी हाल में इसका जिक्र किया था मगर वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। असल में यह विचार इतना खराब है कि किसी ने भी इसे या राहुल को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 30,000 रुपये तक मासिक कमाई वाले स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में भी तीन-चौथाई नौकरियां आरक्षित करने का कानून पारित नहीं कर दिया। 2019 में पारित यह कानून अधर में लटका है क्योंकि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक बता दिया।

इसके बावजूद हरियाणा ने कदम नहीं रोके। हरियाणा में जाट समुदाय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के शामिल किए जाने की मांग पर आंदोलन किया, जिसके बाद चुनावों में सत्तारूढ़ दल की सीटें काफी कम हो गईं। इसके बाद 2020 में हरियाणा ने भी इसी तरह का कानून पारित किया, जिसे राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई। जिस राज्य का सबसे प्रमुख शहर गुरुग्राम ही प्रवासी कामगारों के दम पर तैयार हुआ है, वहां संकेत एकदम स्पष्ट थे। लेकिन फरीदाबाद उद्योग संघ ने इसे कानूनी चुनौती दी, जिस पर नवंबर 2023 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णायक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कहा कि यह कानून संविधान द्वारा तय किए गए संघीय ढांचे का उल्लंघन करता है।

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

राजनेता जनता को खुश करने के लिए अक्सर अदालत के फैसलों जैसी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। दिसंबर 2023 में झारखंड विधानसभा ने ऐसा कानून पारित किया, जिसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों (चपरासी, ड्राइवर आदि) में स्थानीय लोगों के लिए शत-प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया। स्थानीय लोगों की परिभाषा में वे लोग आते थे, जिनके पास 1932 या उससे पहले जमीन होने के रिकॉर्ड हैं। मगर राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह कानून लागू नहीं हो सका।

अन्य राज्यों की नाकामी और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मुद्दे की जांच शुरू किए जाने के बावजूद कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने इस साल जुलाई में ऐसे कानून को मंजूरी देने का फैसला कर लिया, जिसमे बाकी सभी कानूनों को भी पछाड़ दिया। इसमें स्थानीय लोगों को प्रबंधन पदों पर 50 प्रतिशत और शेष पदों पर 70 फीसदी आरक्षण देने का प्रस्ताव था। इस बार बेंगलूरु के आईटी और आईटीईएस उद्योगों के विरोध के कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा।

संवैधानिक औचित्य को छोड़ दें तो भी नौकरियों के मौके बढ़ाने में निजी कंपनियों को शामिल करने के ये प्रयास आत्मघाती और बेतुके हैं। हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्य तो पहले से ही बड़े पैमाने पर विदेशी कंपनियां बुलाने में कामयाब रहे हैं। आंध्र प्रदेश भी ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है और झारखंड को उम्मीद है कि दुनिया भर की बड़ी खनिज कंपनियां उसके यहां ठिकाना बनाएंगी। ये सभी राज्य बड़ी कंपनियों को अपने यहां निवेश करने के लिए बुला रहे हैं और इसके 'व्यापार निवेशक सम्मेलनों' का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन इन कंपनियों को जो प्रतिभा चाहिए, उसके चयन पर पाबंदियां लगाई गईं तो कंपनियां राज्य में शायद ही आएंगी।

फिर भी यह समझना आसान है कि आखिर नेताओं के बीच नौकरी के नाम लोकलुभावन वादे करने की होड़ मची हुई है। पिछले दस सालों में प्रधानमंत्री द्वारा कई बार कहे जाने के बावजूद घरेलू निजी कंपनियां निवेश करने से कतरा रही हैं और अस्थिर नीतियों के कारण विदेशी निवेशक भी दूर भाग रहे हैं। इसीलिए अच्छी नौकरियां (जिनमें सुविधाएं होती हैं) बढ़ नहीं रही हैं, जिससे राज्यों में बड़ी संख्या में नाराज और युवा मतदाताओं की चुनौतियां बढ़ गई हैं।

नौकरियों में कमी आने की वजह से पटेल, जाट, मराठा जैसी कई प्रभावशाली जातियां उन नौकरियों के लिए होड़ कर रही हैं जो पहले से ही पिछड़ी जातियों और वर्गों के लिए आरक्षित हैं। ये समुदाय अंग्रेजों के शासनकाल और उसके बाद के लाइसेंस राज के दौरान तो फल-फूल रहे थे लेकिन आर्थिक उदारीकरण के शुरुआती मौकों का फायदा नहीं उठा पाए। अब धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण कारोबार के अवसर कम हो रहे हैं और ये समुदाय पिछड़ते जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले में अनुसूचित जातियों के भी उप वर्ग बनाने की अनुमति दी गई है, जिसके कारण ऐसी लड़ाई और बढ़ सकती हैं। हालांकि यह फैसला सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन इस वजह से कई अनुसूचित जाति समुदाय पिछड़े वर्ग का दर्जा दिए जाने की मांग कर सकते हैं।

इस तरह की होड़ को रोकने का सबसे आसान तरीका है भारत को कारोबारियों के लिए आकर्षक देश बनाया जाए, जहां वे निवेश कर पाएं और अपना विस्तार करें। यह काम वाकई मुश्किल है मगर केंद्र और राज्य सरकारें अब भी इस बात को समझ ही नहीं पा रही हैं।

आपका पक्ष

चयन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता

लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय और केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से, चयनित उम्मीदवारों को 19 विभिन्न सेवाओं में आवंटित किया जाता है। भारतीय विदेश सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा आदि में अधिकारी के रूप में काम करने वाले उम्मीदवारों के चयन के लिए एक ही परीक्षा, प्रक्रिया और मानदंड लागू किए जा रहे हैं। हालांकि उम्मीदवार को अपने आवेदन पत्र में सेवा प्राथमिकता का उल्लेख करना आवश्यक है, लेकिन सेवा आवंटित करते समय प्रक्रिया में उम्मीदवार की योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि आवंटन प्रक्रिया सामान्य परीक्षा में योग्यता एवं रैंक के आधार पर होती है। चयन के बाद, उम्मीदवारों को सरकार में विभिन्न प्रशासनिक पदों को संभालने वाले सामान्य अधिकारी बनने के लिए

संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों का 19 विभिन्न सेवाओं में आवंटन करता है

प्रशिक्षित किया जाता है। आवंटित पद और कार्य की प्रकृति न केवल उम्मीदवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि से, बल्कि उसकी योग्यता और रुचि से भी पूरी तरह भिन्न हो सकती है। यह व्यक्ति-नौकरी की अनुकूलता के बारे में गंभीर प्रश्न उठाती है। अतः सेवाओं को आवश्यक कौशल और योग्यता के आधार पर समूहीकृत करने की आवश्यकता है। चरण-1 परीक्षा सभी सेवाओं के लिए समान हो सकती है, जबकि चरण-2 परीक्षा को सेवाओं के विभिन्न समूहों के लिए अलग-अलग आयोजित किया जा सकता है। इससे प्रक्रिया की सामान्य प्रकृति कम हो जाएगी और यह अधिक विशिष्ट और केंद्रित हो जाएगी।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

अक्षय ऊर्जा पर्यावरण हितैषी

देश में 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के प्रति जागरूकता फैलाना भी है। वर्ष 2004 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब महिलाओं को चूल्हे के धुएं से बचाने के लिए मुफ्त रसोई गैस उज्ज्वला योजना के तहत वितरित की। देश में दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक करेंगे। इससे उम्मीद है कि दुनिया के यह सभी देश ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को देखते हुए अक्षय ऊर्जा पर अपने-अपने देश में कार्य करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे देश की मदद भी करेंगे। आज सारी दुनिया ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ते खतरे के लिए चिंतित है। अक्षय ऊर्जा का मतलब समझना जरूरी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत ऊर्जा, ज्वार-भाटा से प्राप्त उर्जा, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के कुछ उदाहरण हैं। हमारा देश प्रकृति से संपन्न देश है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें अक्षय ऊर्जा के प्रति गंभीरता से काम करें तो भारत अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बन सकता है। जर्मनी के लोग बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयासरत हैं। वहां के बहुत से होटल, विद्यालय, अस्पताल सोलर पैनल के जरिये बिजली प्राप्त कर सराहनीय काम कर रहे हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को फरीदाबाद स्थित जे सी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को 13 पीएचडी डिग्री और दो पदक एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए। विश्वविद्यालय के कुल 1,536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां दी गईं। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित थे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

भारत-मलेशिया संबंध

भारत-मलेशिया राजनयिक संबंध 1957 में स्थापित हुए थे। मलेशिया में लगभग 7.2 प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है, इसलिए वह भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मलक्का, जल डमरू मध्य और दक्षिणी चीन सागर जैसे समुद्री मार्गों से घिरा मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख स्तम्भ है और वह भारत की समुद्री सम्पर्क रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अनवर इब्राहिम की द्विपक्षीय वार्ता ने दोनों देशों के संबंधों के नए युग की नींव रख दी है। दोनों देशों के बीच श्रमिकों की भर्ती, आयुर्वेद और अन्य पारम्परिक चिकित्या प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, पर्यटन क्षेत्र, स्टार्ट अप पर सहयोग संबंधी अहम समझौते भी हुए हैं। भारत मलेशिया को 2 लाख टन सफेद चावल और आईटीईसी स्लॉट का आवंटन भी करेगा। इन समझौतों के साथ ही दोनों देशों में मलेशिया के पूर्व पीएम महाथिर मोहम्मद के कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों में जो तनाव पैदा हुआ था वह पूरी तरह से खत्म हो गया है। दोनों देशों के रिश्तों के दर्जे को बढ़ाकर समग्र रणनीतिक साझेदारी कर दिया गया है। मलेशिया पिछले कुछ वर्षों से कट्टरपंथी इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के कारण चर्चा में रहा है। जाकिर नाइक भारत में हेट स्पीच और मनी लॉड्रिंग मामले में अभियुक्त है। महाथिर मोहम्मद के दौर में मलेशिया कई मुद्दों पर भारत विरोधी बयानबाजी करता रहा है।

भारत-मलेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलना भी व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व रखता है। मलेशिया को इस क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है, खासकर आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन) की केंद्रीयता के संदर्भ में। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, "भारत आसियान केंद्रीयता को प्राथमिकता देता है। हम इस बात पर सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) की समीक्षा समय पर पूरी होनी चाहिए।" मलेशिया के दृष्टिकोण से, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत को एक "महत्वपूर्ण साझेदार" बताया और कहा कि यह रिश्ता सच्ची दोस्ती पर आधारित है। इब्राहिम की भारत यात्रा पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली यात्रा है, जो ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश लगभग एक दशक की बढ़ी हुई रणनीतिक साझेदारी का जश्न मना रहे हैं जो पहली बार 2015 में मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान स्थापित हुई थी। दोनों नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध जो 2019 रायसीना वार्ता के दौरान उनकी बातचीत से शुरू हुए हैं, ने भारत-मलेशिया संबंधों के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखी है।

भारत-मलेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में बदलना भी व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक महत्व रखता है। मलेशिया को इस क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है, खासकर आसियान की केंद्रीयता के संदर्भ में। प्रधानमंत्री मोदी ने आसियान केंद्रीयता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कहा, "भारत आसियान केंद्रीयता को प्राथमिकता देता है। हम इस बात पर सहमत हैं कि भारत और आसियान के बीच एफटीए (मुक्त व्यापार समझौते) की समीक्षा समय पर पूरी होनी चाहिए।" मलेशिया के दृष्टिकोण से, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की।

भारत और मलेशिया में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता पहले से ही है। यह समझौता एक तरह से मुक्त व्यापार समझौता है। जब महाथिर मोहम्मद ने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम की कड़ी आलोचना की थी तब उसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना गया था। तब मलेशियाई पाम ऑयल की खरीद अवरुद्ध हो गई थी। राजनयिक कूटनीति के बाद 4 महीने के अंतराल के बाद खरीद-फरोख्त शुरू हुई थी। यद्यपि मलेशियाई प्रधानमंत्री ने इंडियन कौंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के कार्यक्रम में भाग लेते हुए जाकिर नाइक के प्रत्यार्पण संबंधी सवाल का जवाब कूटनीतिक शब्दों में ही दिया और यह भी कहा कि मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा बल्कि अतिवाद की भावनाओं की बात कर रहा हूं। हम आतंकवाद को नजरंदाज नहीं करेंगे और भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करते रहेंगे। अनवर इब्राहिम ने पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी और श्री अरविन्दो जैसे विचारक का उल्लेख भी किया।

भारत-मलेशिया वार्ता के दौरान रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा के मुख्य क्षेत्र रहे। दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के महत्व को पहचाना, खासकर क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में। भारत ने मलेशिया को रक्षा उपकरण आपूर्ति करने में अपनी रुचि व्यक्त की, जिसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) द्वारा निर्मित विमान शामिल हैं। दोनों पक्षों ने रक्षा प्रौद्योगिकी और संयुक्त सैन्य अभ्यास में सहयोग की नई संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया।

अहम बात यह है कि भारत-मलेशिया के बीच व्यापार अब भारतीय रुपए और मलेशियाई रिंगिट में तय किया जा सकता है। मलेशिया में 30 लाख भारतीय रहते हैं जो दोनों देशों के संबंधों में जीवंत सेतु हैं। अनवर इब्राहिम की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। भारत ने 2025 में मलेशिया की सफल आसियान अध्यक्षता को पूरा समर्थन देने का वादा भी किया है।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

बेटियों को बचाएं...

गीता पाढा

"फिर कैसे बेटियों को बचाएं और पढ़ाएं,
जब विद्या के मंदिर में भी वो महफूज रह न पाएं,,
कैसे वो माता-पिता खुद को समझाएं,
जब अपनी फूल जैसी बच्ची के शरीर पर वो अनगिनत घाव पाएं,,
क्यों नहीं फिर सरकारों की नीति निर्देशों पर सवाल उठाए जाएं,
जब किसी ओर की गंदी नीयत का खामियाजा वो बेटियां अपनी जान देकर चुकाएं...।"

मेघवाल ने कहा- संचार कौशल महत्वपूर्ण

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने मंत्रालय में मजबूत संचार कौशल की आवश्यकता पर बुधवार को जोर दिया। उन्होंने अपने वक्तव्य को और अधिक स्पष्ट करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक के मसौदे में उन गलतियों का हवाला भी दिया, जिन्हें दूर करने के लिए अधिकारियों को देर रात तक बैठना पड़ा था। मेघवाल ने कहा कि संचार कौशल विधायी विभाग में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जो मंत्रालयों को विधेयक, अध्यादेश और प्रमुख नीतिगत दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि अल्पविराम और पूर्ण विराम के प्रयोग में छोटी-छोटी गलतियां समस्याएं पैदा कर सकती हैं।

हम से ओलम्पिक अभी दूर है

मर्यादाएं
चन्द्रमोहन
संपादक : वीर प्रताप
chander_m@ hotmail.com
BLOG: chandermohan.net

हमने यह बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी पाल रखी है कि हम ओलम्पिक स्तर के देश हैं। जिस देश को केवल छ: मैडल मिलें हों जिनमें कोई गोल्ड मैडल नहीं है, उसे अभी ओलम्पिक खेलों की दावेदारी के बारे सोचना भी नहीं चाहिए। हमारा प्रदर्शन तो टोक्यो ओलम्पिक से भी बुरा रहा जहां हमें सात मैडल मिले थे जिनमें नीरज चोपड़ा का गोल्ड भी शामिल था। समझा गया कि पेरिस ओलम्पिक हमारे लिए गेम चेंजर होंगे और अपने अच्छे प्रदर्शन के बल पर हम 2036 के ओलम्पिक खेलों की मेज़बानी का दावा कर सकेंगे। इसीलिए 'रूकना नहीं' का नारा दिया गया। पर हमारा खेल क़ाफ़िला छह मैडल पर आ कर रुक गया। 85 देशों में टोक्यो में हम 48वीं पायदान पर थे जो इस बार हम गिर कर 71 पर पहुंच गए। इस से संतोष किया जा रहा कि हमारे छह खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे। पर जैसे नीरज चोपड़ा ने भी कहा है कि 'गोल्ड मैडल की कोई बराबरी नहीं है'। कहने को तो कहा जाएगा कि खेल में हार जीत होती रहती है असली महत्व तो हिस्सा लेने का है, पर ऐसे कथन तो पराजित को सांत्वना देने के लिए कहे जाते हैं जबकि हक़ीक़त है कि ओलम्पिक स्तर पर सब कुछ मैडल है। जीतना ही सब कुछ है। सब जानते हैं, खिलाड़ी तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

ओलम्पिक से पहले लिखे अपने लेख में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत लिखते हैं, " भारत खेलों में अग्रणी देश बनने वाला है जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन भी है...कई खेलों में हम विशिष्ट दावेदार हैं"। यही हम सबने भी सोचा था, पर हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन स्तर का नहीं था। लाल क़िले से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वह चाहते हैं कि 2036 के ओलम्पिक खेलों का आयोजन भारत में हो। उनकी सोच सही है कि ऐसे आयोजन से देश में खेल की भावना और फ़िज़िकल ऐक्टिविटी बढ़ेगी। पर ज़मीनी हक़ीक़त कुछ और है। अभी हम बहुत पिछड़े हैं। अमेरिका को 126 मैडल मिले जिसमें 40 गोल्ड थे, चीन दूसरे नम्बर पर 91 मैडल के साथ है जिनमें भी 40 गोल्ड हैं। फ्रांस के लियोन मारचंद अकेले को चार गोल्ड मैडल (तैराकी) में मिले हैं। विश्व रिकार्ड अमरीकी तैराक माइकल फिल्प्स का है जिसने चार ओलम्पिक में 28 मैडल जीते जिनमें 23 गोल्ड मैडल हैं।

इन सब से तुलना करें तो मालूम हो जाएगा कि हम कितने मामूली हैं। कीनिया जैसे छोटे देश ने भी पेरिस ओलम्पिक में 11 मैडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड हैं। जब से ओलम्पिक खेल शुरू हुईं हैं भारत को कुल 41 मैडल ही मिलें हैं। इसलिए यह सोच कि हम ओलम्पिक स्तर की उभरती महाशक्ति है को सुधारने और हक़ीक़त से जोड़ने की बहुत ज़रूरत है। दुनिया भी हमें खेलों में मामूली ही समझती है। हम एशियन या राष्ट्रमंडल खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं पर ओलम्पिक स्तर के हम अभी नहीं हैं। हमारा और दुनिया के बीच फ़ासला बहुत है। कभी कभार अभिनव बिंद्रा या नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी निकलते हैं जो इस खाई को पाटने में सफल रहते हैं, पर कितने ऐसे हैं? अधिकतर दबाव नहीं झेल पाते। ओलम्पिक खेलों में तो दबाव होगा ही। इसके लिए मैंटल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। हॉकी के पूर्व गोल कीपर श्रीजेश जैसे खिलाड़ी हैं जो दबाव झेल जाते हैं। उसकी रिटायरमेंट का बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसका कहना है कि "कई बार जब पैसे या जनून के बीच चुनाव करना पड़ता है तो पैसा महत्व नहीं रखता"।

हमारा समाज खेलों को महत्व नहीं देता। मां-बाप का सारा ध्यान बच्चे की पढ़ाई और बाद में नौकरी पर रहता है। 'पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे ख़राब', वाली मानसिकता हावी है। कमजोर परिवारों के लिए बच्चों को आधुनिक खेल के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल है इसलिए बहुत प्रतिभा खिलने से पहले निराश होकर बैठ जाती हैं। क्रिकेट में ज़रूर तेजस्वी जयसवाल या मुहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति से जूझ कर शिखर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। क्रिकेट व्यवस्था को यह श्रेय जाता है कि खिलाड़ी का चुनाव बिल्कुल मेरिट पर होता है, उसका धर्म,जाति,भाषा या प्रदेश नहीं देखे जाते। जब शम्मी को पाकिस्तान के खिलाफ बुरे प्रदर्शन पर ट्रोल किया गया तो आलोचकों का मुंह विराट कोहली ने यह कह कर कि " हमारी टीम के अंदर भाईचारा और दोस्ती है इसे कोई हिला नहीं सकता', बंद करवा दिया। पर क्रिकेट के लिए उन्माद बाक़ी खेलों को रौंद रहा है। युवा क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्योंकि ग्लैमर है और पैसा है। संतुलन किस तरह क्रिकेट की तरफ़ झुका है इस बात से पता चलता है कि बीसीसीआई दुनिया के सबसे रईस खेल संगठनों में से एक है। 2023 में इसकी कमाई 18700 करोड़ रूपए थी, जबकि हॉकी जो कभी हमारी राष्ट्रीय खेल थी और हमारी परिस्थिति के अधिक अनुकूल है, के महासंघ की आय केवल 87 करोड़ रुपए थी।

अगर खेल में विश्व स्तर का देश बनना है तो बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। केवल सरकार को कोसने से बात नहीं बनेगी। बैडमिंटन चैम्पियन रहे प्रकाश पादुकोण ने तो ख़राब प्रदर्शन की ज़िम्मेवारी खिलाड़ियों पर डाली है कि, "उन्हें चिंतन करना चाहिए और सही प्रदर्शन करना चाहिए"। उन्होंने सरकार की प्रशंसा की है कि भारत की ओलम्पिक टीम को सबसे अच्छा पैसा और समर्थन मिला है। अभिनव बिंद्रा का भी कहना है कि "पैसा अच्छी मदद का एक हिस्सा है,पर यह कोई एटीएम नहीं जहां मैडल मिलते हैं"। देश के अंदर अलग चुनौती होगी। हमारे लोगों को कई बार सम्भालना मुश्किल हो जाता है। अहमदाबाद में क्रिकेट के वर्ल्ड कप में जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा था जय श्रीराम के नारे लगाए गए। विशेष तौर पर मुहम्मद रिज़वान को निशाना बनाया गया। यह नहीं कि रिज़वान मासूम है। उसके बारे तो वकार यूनुस ने गर्व से कहा था कि 'इसने हिन्दोस्तान के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ी'। लेकिन मेज़बान देश के नाते हमारी ज़िम्मेवारी अधिक बनती थी। हमें पराजय बर्दाश्त करना नहीं आता। वर्ल्ड कप में आस्ट्रेलिया की जीत पर अहमदाबाद का नरेन्द्र मोदी स्टेडियम शांत पड़ गया जबकि ज़रूरत थी कि दर्शक खड़े होकर तालियाँ बजाते। पुणे में बांग्लादेश के खिलाड़ी को नागिन डांस से परेशान करने की कोशिश की गई। यह कैसी बेहूदगी है?

बड़ी समस्या निम्न इंफ्रास्ट्रक्चर की है। 2010 की दिल्ली में राष्ट्र मंडल खेले याद आती है। पुल टूटा, खिलाड़ियों के आवास में पानी टपका, स्विमिंग पूलों में गंदे पानी और मैस में गंदे भोजन की शिकायतें मिली। ऊपर से 70000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली जो कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार के पतन का कारण बनी। कई और टूर्नामेंट में भी निम्न सुविधाओं की शिकायत मिल चुकी है। सरकार शायद अहमदाबाद को ओलम्पिक के लिए तैयार करना चाहती है। अहमदाबाद और गांधीनगर के लिए 6000 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। गुजरात पर जो अनुकम्पा दिखाई जा रही है वह हैरान करने वाली है क्योंकि वहां खेल संस्कृति है ही नहीं। गुजरातियों को पैसा बनाना आता है मैडल जीतना नहीं। हाल ही के बजट में गुजरात को 426 करोड़ रुपए मिले हैं जबकि हरियाणा और पंजाब जो खेलों में अग्रणी प्रदेश हैं, को 66 करोड़ रुपए और 70 करोड़ रुपए मिले। सबसे अधिक मैडल भी हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ी लेकर आए। हमारे 117 खिलाड़ी गए थे जिनमें गुजरात के केवल 2 थे। फिर यह मेहरबानी कैसे जायज़ है? वैसे भी गुजरात खेलों के महोत्सव के लिए उपयुक्त प्रदेश नहीं है। वह खुला वातावरण नहीं जो मुम्बई या दिल्ली में है। खाने-पीने, पहनावे की बहुत बंदिश है जो विदेशी एथलीट बर्दाश्त नहीं करेंगे।

ओलम्पिक खेलों की मेज़बानी करने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अरबों रूपए तो खर्च करने ही पड़ेंगे पर लोगों की और सरकारी मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। स्पोर्ट फ़ेडरेशनों पर राजनीतिक क़ब्ज़ा हटाना पड़ेगा। नौकरशाही को अपना शिकंजा कमजोर करना होगा। समाज को भी तैयार करना पड़ेगा। जिस तरह महिला पहलवानों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया और न्याय नहीं मिला वह सब जानते हैं। विनेश फोगाट को ओलम्पिक में संघर्ष करने से पहले व्यवस्था से टकराना पड़ा। यह अफ़सोस की बात है कि वह मैडल से मामूली नियम के कारण वंचित रह गई पर देश के लिए वह चैम्पियन है। पर इन महिला पहलवानों का उत्पीड़न के खिलाफ जो संघर्ष था वह देश की स्थिति भी बताता है जहां महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। हाल ही में हम कोलकाता में महिला डाक्टर के रेप और हत्या के बारे सुन कर हटें हैं। ठाणे के स्कूल में दो बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। रोज़ ऐसे समाचार आ रहे हैं। सारा देश सुन्न है, यह घटनाएं एक बीमार समाज की तरफ़ भी इशारा करता है। क्या हम यह गारंटी कर सकते हैं कि किसी भी विदेशी महिला खिलाड़ी जो हज़ारों में आएँगी, के साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा ? जो विदेश से आते हैं वह स्वच्छंद वातावरण से आते हैं। क्या हम उसके लिए तैयार हैं?

खेलों में जो देश अव्वल रहते हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊंची है जबकि हम 128 नम्बर पर हैं। यहां ग़रीबी बहुत हैं। आख़िर में पैसा बोलता है। जब जेब में पैसा नहीं होता तो न सही किट मिलती है न सही डॉयट। जब जी- 20 का आयोजन किया गया तो जिन सड़कों से विदेशियों को गुजरना था उनके दोनों तरफ़ बोर्ड लगा दिए गए ताकि वह हमारी बस्तियां न देख सकें। पर जी-20 में किया जा सका वह ओलम्पिक में नहीं हो सकेगा। पहले हमें अपनी हक़ीक़त बदलनी है। अगर ओलम्पिक का कभी आयोजन होता है तो खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए सपना पूरा होने का बराबर होगा। पर अभी वह स्थिति नहीं है। जैसे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपना देखना बुरा नहीं पर सपने में रहना नहीं चाहिए।

पंजाब में बढ़ता धर्म परिवर्तन चिन्तन का विषय

सिख सियासत
सुदीप सिंह
newsreporter.2008@gmail.com

पंजाब में धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामले गंभीर चिन्तन का विषय है। इस पर चिन्ता तो सभी करते हैं पर चिन्तन करने की सोच किसी की नहीं है। यहां तक कि अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह और अनेक धर्म के ठेकेदार बनकर बैठे लोग इस विषय को लेकर समय समय पर चिन्ता करते देखे गए हैं। पंजाब और खासकर अमृतसर साहिब जिसे सिखी का केन्द्र माना जाता है उसके अधीन आने वाले गांवों में सबसे अधिक गिनती में सिख और हिन्दू अपने धर्म का त्याग कर ईसाई धर्म अपना चुके हैं। हालांकि ईसाई मिशनरीयों के मुखियों के द्वारा साफ किया जा रहा है कि उन्होंने जबरन किसी भी शख्स का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया है क्योंकि ऐसा करना उनके धर्म के भी खिलाफ है।

सबसे ज्यादा चिन्तन इस बात का होना चाहिए कि आखिरकार ईसाई धर्म में ऐसा क्या है जो हिन्दू-सिख बड़ी गिनती में उनकी ओर आकर्षित होकर उनका धर्म अपनाते जा रहे हैं। सच्चाई सबको कड़वी लगेगी मगर इसमें सबसे अधिक कसूरवार सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी है जिसका गठन सिखी के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था। कमेटी हर महीने लाखों रुपये सिखी के प्रचार पर खर्च अवश्य करती है मगर वह सिर्फ कागजों में होता है, सच्चाई इससे कोसों दूर ही दिखाई पढ़ती है। कमेटी के प्रचारकों ने अगर अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था उस समय ईसाई मिशनरीयों के नुमाईंदे दिल्ली के हर क्षेत्र में आकर ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु मोटी-मोटी किताबें हर महीने बिना किसी शुल्क के देकर जाते थे। जिन्हें पढ़ने के बाद निश्चत तौर पर किसी का भी मन बदल सकता है। दूसरा ईसाई मिशनरी के अधीन चलने वाले स्कूलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें, वर्दी आदि मुहैया करवाई जाती हैं। बेरोजगारों को रोजगार दिये जाते हैं। क्या शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा इनमें से कोई भी काम किया जाता है। अगर किसी गांव के लोग सिख धर्म छोड़कर चले गए तो क्या सिख प्रचारकों यां धर्म के ठेकेदारों ने उनसे जाकर कारण जानने की कभी कोशिश भी की है कि ऐसा क्या उन्हें वहां दिखाई दिया जो सिख धर्म में नहीं है। धर्म कोई बुरा नहीं है, मगर ईसाई धर्म में केवल ईसा मसीह ने शहादत दी तब से लेकर आज तक उसका पूरी तौर पर प्रचार उनके धर्म के लोग करते हैं। सिखों का तो इतिहास ही शहादतों से भरा हुआ है मगर क्या आज तक किसी ने भी उस इतिहास को दूसरों को तो छोड़ो सिखों को भी बताने की कोशिश की है। अब तो ईसाई धर्म अपनाने के लिए सिखों को सिखी सरुप भी त्यागना नहीं पड़ता, सिर पर पगड़ी बांधकर, गले में कृपाण डालकर भी लोग ईसाई धर्म के कार्यक्रमों में भाग लेते देखे जाते हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पंजाब में हजारों चर्च खुल चुके हैं, लोगों ने अपने घरों की छतों पर प्रचार केन्द्र बनवा दिये हैं जहां हर रविवार को सुबह ईसाई धर्म की प्रार्थना की जाती है। पंजाब में स्वयं को पंथक कहलाने वाली बादल सरकार के कार्यकाल में भी इसे रोकने के बजाए उल्टा बढ़ावा ही दिया गया। एक सवाल और बनता है कि इन मिशनरियों को चलाने के लिए फण्ड कहां से आता है अगर इस पर ही सरकारें सख्त रुख अपना लें तो निश्चित तौर पर इन पर शिकंजा कसा जा सकता है।

तख्त हजूर साहिब में सिख मर्यादा का उलंघन

सिख रहत मर्यादा के अनुसार सिखों के पांच तख्त साहिबान पर किसी भी उस सिख व्यक्ति को सिरोपा नहीं दिया जा सकता जो कि अपने केशों की बेदबी करता हो हां इस श्रेणी में गैर सिख शामिल नहीं हैं। मगर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के तख्त हजूर साहिब नतमस्तक होने पर उन्हें सिरोपा देने के साथ साथ तख्त साहिब की मर्यादित रवायत के हिसाब से चोला पहनाकर सम्मानिन्त भी किया गया। जिसके बाद सिख समुदाय में रोष उत्पन्न होना स्वभाविक था। देश भर से इस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। इससे पहले भगवंत मान परिवार सहित तख्त पटना साहिब भी नतमस्तक होने पहुंचे थे मगर वहां पर उन्हें तख्त साहिब के भीतर सम्मानित नहीं किया गया था। तख्त हजूर साहिब के जत्थेदार ज्ञानी कुलवंत सिंह स्वयं बहुत ही सूझवान व्यक्ति हैं फिर यह चूक कैसे हो गई। तख्त साहिब के प्रशासक डा विजय सतबीर सिंह की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं उनके दबाव में आकर ऐसा किया गया हो। जो भी हो इसके लिए दोषियों को माफी अवश्य मांगनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गल्ती ना हो सके।

सिखी सरुप में खेलने वाले खिलाड़ियों को सम्मान

हॉकी हमारे देश का पारंपरिक खेल है और इसमें ज्यादार खिलाड़ी पंजाब यां फिर हरियाणा से ही आते हैं। एक समय था जब हॉकी खेलते हुए मैदान में दस्तार सजाए युवाओं की भरमार हुआ करती थी। इस बार भी एक युवा खिलाड़ी पूरे सिखी सरुप में मैदान में देखा गया जिसे शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा सम्मानिन्त भी किया गया है। भारतीय हॉकी टीम के सभी खिलाड़ी सिर पर सुन्दर दस्तार सजाकर श्री दरबार साहिब नतमस्तक हुए जहां शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा उनका शानदार स्वागत किया गया मगर अफसोस कि ना तो शिरोमणी कमेटी अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह धामी यां फिर किसी अन्य सदस्य ने उन्हें सिखी सरुप में वापिस आने के लिए प्रेरित किया। आज सिख समुदाय के लोग खेल ही नहीं हर क्षेत्र में सिखी का नाम रोशन करते हैं मगर अफसोस कि उनमें से ज्यादातर के साथ सिंह ही लगा दिखाई पड़ता है सिखी सरुप कहीं दिखाई नहीं देता।पूर्व सांसद तरलोचन सिंह के द्वारा इस पर संज्ञान लेते हुए शिरोमणी कमेटी अध्यक्ष एवं अन्य धार्मिक नेताओं को सवाल किए हैं कि क्यों आज तक सिखी सरुप त्यागने वालों को वापिस सिखी में लाने के लिए कोई मुहिम शुरु नहीं की गई। नासमझी में आकर हो सकता है कि युवा सिखी से दूर हो गए हो, पर अगर उसके परिवार से मिलकर उन्हें समझाया जाए तो हो सकता है कि उनमें से ज्यादातर सिखी में वापिस आ सकते हैं। सिख जत्थेबंदियों के इलावा बड़े बड़े सिख व्यवसाई भी हैं उन्हें भी चाहिए कि सिखी सरुप वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें क्योंकि इस देश के लोगों की मानसिकता बन चुकी है।

सीएए के तहत नागरिकता मिलनी शुरु

केन्द्र की मोदी सरकार के द्वारा 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लाया गया था उस समय विपक्षी दलों सहित कई धार्मिक जत्थेबंदीयों ने भी इसका खुलकर विरोध किया था। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी द्वारा भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए सिखों को भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे थे। कमेटी के महासचिव जगदीप सिंह काहलो जिनके अपने वार्ड में अनेक ऐसे परिवार हैं जो पिछले लम्बे अरसे से भारत में आकर रह रहे हैं मगर उन्हें नागरिकता ना मिलने के चलते बच्चों के दाखिलों से लेकर रोजमर्रा के कार्यों में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने बताया कि 400 के करीब दरखास्त आनलाईन डाली गई थी जिसमें से 20 लोगों को अब नागरिकता मिल गई है। कमेटी के कार्यालय में अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलो के द्वारा उन्हे दस्तावेज सौंपे गए। इससे अन्य लोगों को भी उम्मीद बन गई है कि आने वाले दिनों में उन्हें भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। भाजपा नेता सुखमिन्दर पाल सिंह ग्रेवाल ने देश की मोदी सरकार को सिख हितैषी सरकार बताते हुए सरकार का आभार प्रकट किया गया।

कोविड जितना खतरनाक नहीं है एमपॉक्स का वायरस, डब्ल्यूएचओ ने किया साफ

नई दिल्ली, (आईएएनएस)। दुनियाभर में तेजी से बढ़ते एमपॉक्स यानी मंकीपॉक्स के बढ़ते मामलों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने साफ कर दिया है कि यह कोविड जितना खतरनाक नहीं है। तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि यह एक तरह का पुराना स्ट्रेन है, और इसका कोविड जैसी गंभीर समस्या से कोई लेना-देना नहीं है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एक शोध भी कर चुका है। जिसमें उसने साफ कहा है इसे रोकना आसान है।

● बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं से इस वायरस के फैलने का अधिक खतरा है

यह कोरोना वायरस की तरह खतरनाक और जानलेवा नहीं है। एमपॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ के अधिकारी हंस क्लूज का बयान आया था, 'एमपॉक्स से हम मिलकर निपट सकते हैं और हमें एकजुट होकर इसे कंट्रोल करना चाहिए।' बता दें कि भारत में भी एमपॉक्स के कुछ मामले सामने आए हैं। डब्ल्यूएचओ के इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अब इस पर विशेष तरीके से ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने देशभर के सभी एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर चेतावनी जारी कर दी है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय कह चुका है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमाओं से इस वायरस के फैलने का अधिक खतरा है। इसको लेकर दिल्ली के तीन सरकारी अस्पतालों में इस वायरस से पीड़ित लोगों का इलाज किया जाएगा। इसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज का नाम शामिल है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रेस, 2-प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रेस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

संपादकीय

नई दिल्ली, गुरुवार 22 अगस्त 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

बहुजन जागृति का प्रतीक है भारत बंद

आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये कतिपय निर्णयों के खिलाफ़ बुधवार को आयोजित सफल भारत बन्द इस बात का प्रतीक है कि अपने अधिकारों को लेकर दलित, ओबीसी एवं आदिवासी वर्ग फिर से जागरूक हो चले हैं। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में क्रीमीलेयर को मिल रहे आरक्षण तथा कोटा के भीतर कोटा बाबत शीर्ष न्यायालय के फैसलों से नाराज़ दलित संगठनों ने इस राष्ट्रव्यापी बन्द का ऐलान किया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार चाहे तो कोटे के भीतर कोटा तय कर सकती है। यह संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि राज्य सरकारें इस बाबत मनमर्जी फैसला नहीं कर सकतीं। कोर्ट ने दो शर्तें भी लगाई हैं। उसने साफ किया है कि एससी के भीतर किसी एक ही जाति को शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता और एससी में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिये। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला दिया था जिनमें कहा गया है कि आरक्षण का फायदा कुछ ही जातियों को मिल रहा है और अनेक जातियां इससे वंचित हैं।

दलित संगठनों के इस बंद को बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत आदिवासी पार्टी आदि ने भी समर्थन दिया था। अनेक राज्यों में यह बेहद सफल रहा है। इन संगठनों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बंद में शामिल रहे। उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को वापस ले या पुनर्विचार करे। भारत बंद के अनेक राजनीतिक निहितार्थ हैं। इसे हाल के दिनों की एक महत्वपूर्ण परिघटना मानना चाहिये क्योंकि पिछले लगभग एक दशक से जो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग सड़कों की लड़ाई छोड़ चुका था और उनके नेताओं ने अपने ही वर्गों के हितों को दरकिनार कर दिया था, वे भी साथ खड़े और उनके पक्ष में लड़ाई करते हुए दिखे। बसपा प्रमुख मायावती, जिन पर अक्सर भारतीय जनता पार्टी की 'बी' टीम होने का आरोप लगता रहा है, किसी आंदोलन का सीधा समर्थन करती दिखीं। हालांकि यह आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ़ कहा जा रहा है परन्तु उसका एक सिरा सत्ता में भी जाकर खुलता है क्योंकि केन्द्र ने इसे समय रहते स्पष्ट नहीं किया कि इस फैसले को लेकर वह क्या करने जा रही है और किस तरह से वह आरक्षण पर आंच नहीं आने देगी। अभी उसे संघ लोक सेवा आयोग के जरिये केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिव स्तर के अधिकारियों की सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) का कदम वापस लेना पड़ा था। इस भर्ती में कोई पद आरक्षित नहीं थे। जब इसका सीधा विरोध हुआ तब सरकार को इस भर्ती को रद्द करना पड़ा।

ऐसे निर्णयों के कारण अब जनता के कान खड़े हो गये हैं, खासकर उनके जिन्हें आरक्षण का लाभ मिलता रहा है। सरकार करीब 45 पद लेटरल एंट्री के जरिये भरने जा रही थी। यह बात सामने आई कि अगर वह भर्ती प्रतिस्पर्धा एवं परीक्षा के जरिये होती तो उसके जरिये आधे से ज्यादा पद ओबीसी, दलितों, आदिवासियों एवं अन्य आरक्षित वर्गों को मिलते। इसके खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश यादव आदि ने आवाज़ उठाई जिसका परिणाम यह हुआ कि खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय को आदेश देकर यह विज्ञापन रद्द कराना पड़ा। हालांकि केन्द्रीय मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल का कहना है कि 'सरकार कहीं से भी आरक्षण को खत्म नहीं करने जा रही, लेकिन विपक्ष लोगों को इस बात को लेकर भ्रमित कर रहा है।'

सवाल यह है कि सरकार इस बाबत अपना सीधा व स्पष्ट बयान क्यों अब तक जारी नहीं कर पाई और कोर्ट के सामने भी अपना पक्ष नहीं रख सकी कि आरक्षण की व्यवस्था बनी रहेगी तथा सम्बन्धित वर्गों को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसके पीछे खुद सरकार दोषी है। जनता की यह धारणा बन गई है कि केन्द्र सरकार आरक्षण विरोधी है। यह धारणा विकसित करने में स्वयं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। लोकसभा चुनाव के पहले जब भाजपा ने 370 और 400 पार का नारा लगाना शुरू किया था तो उसका मकसद संविधान को बदलना बतलाया गया था। यह बात भाजपा के कई उम्मीदवार सार्वजनिक तौर पर कहते रहे। अनंत हेगड़े, अरूण गोविल, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा आदि चुनावी रैलियों में ऐलान करते रहे कि भाजपा को इतना बड़ा बहुमत इसलिये चाहिये क्योंकि उसे संविधान बदलना है। कहना न होगा कि भाजपायी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग सदा से इसी विचार के रहे हैं।

भारत बंद को लेकर मायावती ने आरक्षण पर मंडराते खतरे के लिये भाजपा के साथ ही कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि इसके लिये कांग्रेस कैसे जिम्मेदार है, यह तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया पर यह इसलिये गलत है क्योंकि दलितों, ओबीसी एवं आदिवासियों के जिस आरक्षण के अधिकार को हड़पने के लिये भाजपा लालायित रही, उसका सबसे पहले मुकाबला तो कांग्रेस ने किया था, न कि मायावती ने। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में और पांच माह पहले हुए लोकसभा चुनावों में बसपा की जो दुर्गति हुई उसका मुख्य कारण यही था कि उसका वोट बैंक कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी की ओर खिसक गया। भाजपा की आरक्षण विरोधी नीति का मायावती ने कभी भी प्रखर विरोध नहीं किया। जो भी हो, भारत बंद बहुजन चेतना की जागृति ही है।

उन्हें डर है

दुनियादारी

■ सर्वमित्रा सुरजन

समाज में गरीबी और अमीरी, अगड़ों और पिछड़ों की जो व्यवस्था बनी हुई है, वह बनी रहे, यह उच्च और सवर्ण तबके की सोच है। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद इस सोच को और मजबूत किया। इसलिए देश में आर्थिक गैरबराबरी भी पहले से कई गुना बढ़ गई, इसके साथ ही अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचारों में भी बढ़ोत्तरी आई। आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें नए सिरे से भाजपा के शासनकाल में शुरु हुईं।

18वीं लोकसभा के शुरुआती काल में ही देश में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, किसानों, वंचित तबकों के सवालों पर विमर्श तेज होने लगा है, यह एक मजबूत होते लोकतंत्र की पहचान है। सुप्रीम कोर्ट ने अजा जजा वर्ग में उपवर्गों और क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला दिया था, उस पर देश के कई दलित और आदिवासी संगठनों ने अपनी असहमति दर्ज की थी। विपक्ष ने भी इस फैसले को ठीक नहीं बताया था, नतीजा यह हुआ कि केंद्र सरकार को ऐलान करना पड़ा कि वह इसे लागू नहीं करेगी। लेकिन बुधवार 21 अगस्त को इस फैसले को रद्द कराने की मांग पर भारत बंद का सफल आह्वान हुआ। इससे पहले सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री के जरिए प्रवेश का फैसला भी सरकार को वापस लेना पड़ा, क्योंकि विपक्ष ने आरोप लगाया था कि यह फैसला आरक्षण और संविधान विरोधी है। अपने फैसलों से भाजपा जितनी बार पीछे हट रही है, उतनी बार उसकी जुबान पर संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का नाम आ रहा है। भाजपा को अब चीख-चीख कर यह साबित करने की जरूरत पड़ रही है कि श्री मोदी समानता के अधिकार के रक्षक हैं, सामाजिक न्याय में उनका गहरा विश्वास है, संविधान में उनकी गहरी आस्था है। भाजपा की यह कोशिश बता रही है कि वह अब भीतर से असुरक्षित महसूस कर रही है। क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ उसने जो अभियान छेड़ा था, वह असफल हो चुका है। वहीं न राहुल गांधी को उनके मार्ग से भाजपा हटा पाई है, न सोनिया गांधी की गरिमा पर कोई दाग लगा पाई है।

दस बरस पहले जब भाजपा 10 सालों के अंतराल के बाद सत्ता में आई थी, तब कांग्रेस के खिलाफ नफरत गहरी करने का खेल काफी तेज हो गया था। भाजपा के शीर्ष नेताओं नरेन्द्र मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस मुक्त भारत का बाकायदा अभियान चलाया था। जनता को यह समझाने की कोशिश की गई कि इस देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक कुछ है, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस की मौजूदगी को लेकर भाजपा की सतर्कता इस हद तक थी कि उसे सत्ता से हटाकर भी भाजपा निश्चिंत नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद करने पर उसने ध्यान लगाया। इसके लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की छवियों पर गंभीर प्रहार हुए, जो अब तक जारी हैं। इसके अलावा कांग्रेस को तोड़ा गया, उसकी राज्य सरकारों को गिराने के षड्यंत्र हुए और इसमें भाजपा कामयाब भी हुई। दरअसल कांग्रेस को लेकर भाजपा और संघ इसलिए सशंकित रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी तमाम बुराइयों, कमियों और कई गलत फैसलों के बावजूद कांग्रेस कभी भी इस देश की मूल संरचना पर प्रहार नहीं करेगी। न ही कभी नेहरू-गांधी-आजाद-बोस-अंबेडकर-पटेल-भगत सिंह के आदर्श भारत की परिकल्पना को भूलेगी। कांग्रेस हर हाल में संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही देश को चलाएगी। यूपीए शासनकाल के 10 बरस इसका प्रमाण हैं, जिनमें मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कई फैसले लिए गए, जिनसे पूंजीपतियों और सुविधा संपन्न उच्च तबके को उलझन होने लगी। खुद कांग्रेस के भीतर भी इन फैसलों पर अंतर्विरोध हो रहे थे, क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जो प्रगतिशील फैसले ले रही थी, वह संपन्न, सवर्ण तबके की सोच के खिलाफ थे। ये तबका उस सोच का हिमायती रहा है, जहां किसी रिक्शाचालक या दर्जी या मोची या किसान अगर शहरों के मॉल में जाकर अपनी मेहनत की कमाई खर्च करे तो यह उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में दखल लगने लगता है।

समाज में गरीबी और अमीरी, अगड़ों और पिछड़ों की जो व्यवस्था बनी हुई है, वह बनी रहे, यह उच्च और सवर्ण तबके की सोच है। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद इस सोच को और मजबूत किया। इसलिए देश में आर्थिक गैरबराबरी भी पहले से कई गुना बढ़ गई, इसके साथ ही अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचारों में भी बढ़ोत्तरी आई। आरक्षण को खत्म करने की कोशिशें नए सिरे से भाजपा के शासनकाल में शुरु हुईं। 2015 में बिहार विधानसभा चुनावों के वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की समीक्षा करने के विचार प्रकट किए थे, लेकिन इसका नुकसान भाजपा को हुआ तो कुछ वक्त के लिए आरक्षण पर बयान देने से बचा गया। फिर मोहन भागवत जातिगत भेदभाव को समाज के लिए अभिशाप बताने लगे और पिछले साल उन्होंने कहा कि निचली जातियों द्वारा 2,000 वर्षों से झेले गए भेदभाव की भरपाई के लिए अगर आरक्षण को अगले 200 वर्षों तक जारी रखना होगा, तो वह इसका समर्थन करेंगे। मगर अब संघ के ही मुखपत्र पांचजन्य के संपादकीय में संपादक हितेश शंकर ने लिखा है कि जाति व्यवस्था एक चेन सिस्टम की तरह है जो भारत के विभिन्न वर्गों को उनके पेशे और परंपरा के अनुसार वर्गीकृत करने के बाद एक साथ रखती है। पांचजन्य में लिखा है 'भारत के उद्योगों को नष्ट करने के अलावा, आक्रमणकारियों ने भारत की पहचान को बदलने के लिए धर्मांतरण पर ध्यान केंद्रित किया। जब जाति समूह झुके नहीं तो उन्हें अपमानित किया गया।' इसके अलावा जाति जनगणना पर पांचजन्य ने लिखा कि 'हिंदू जीवन, जिसमें गरिमा, नैतिकता, जिम्मेदारी और सांप्रदायिक भाईचारा शामिल है, जाति के इर्द-गिर्द घूमता है। ...तो कांग्रेस ने इसे हिंदू एकता में एक बाधा के रूप में देखा। वह अंग्रेजों की तर्ज पर लोकसभा सीटों को जाति के आधार पर बांटकर देश में बंटवारा बढ़ाना चाहती है। यही कारण है कि वह जाति जनगणना चाहती है।

इस तरह संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि वह न केवल आरक्षण की विरोधी है, बल्कि जाति जनगणना भी वह नहीं चाहता। क्योंकि इससे देश की कई जातियों को अब तक जिन हकों से वंचित रखा गया था, वो उनके लिए आवाज उठाने लगेंगे। दरअसल डरो मत का जो मंत्र राहुल गांधी ने समाज में फूंक दिया है, उसकी काट के लिए भाजपा को कोई और मंत्र नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जिस सहजता के साथ सब्जी विक्रेता को अपने घर बुलाकर सम्मान से बात करते हैं, उतने ही प्यार से मोची से भी मिलते हैं और उतनी ही सहजता के साथ टैक्सीचालक के परिवार से बातें भी करते हैं। मैकेनिक से बाइक सुधारना सीखना, चाय पीते हुए बढ़ई के साथ मेज-कुर्सी बनाना या फुटपाथ पर बैठकर मजदूरों से बात करना। इस तरह की राजनीति का कौन सा और कैसा जवाब भाजपा दे, यह उसकी समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि चायवाले की तथाकथित छवि अब दस लाख के सूट की फ्रेम में जड़ चुकी है। इसलिए अब संघ जाति जनगणना के कांग्रेस या राहुल गांधी के वादे को हिंदू एकता में बाधा की तरह समाज को दिखाना चाह रहा है।

हालांकि 21 अगस्त के भारत बंद ने यह साबित कर दिया कि भाजपा या संघ के नजरिए से अब व्यापक समाज ने असहमति दर्ज करनी शुरु कर दी है। अयोध्या में भाजपा की हार इसका सटीक उदाहरण है, जहां हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उनके सारे मंत्री जितनी बार भी बाबा अंबेडकर और संविधान की माला जप लें, देश के दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को संदेह हो रहा है कि उनके हुकूक की रक्षा भाजपा कर पाएगी। ओमप्रकाश वाल्मिकी की कविता का एक अंश है-

उन्हें डर है
बंजर धरती का सीना चीर कर
अन्न उगा देने वाले सांवले खुरदरे हाथ
उतनी ही दक्षता से जुट जाएँगे
वर्जित क्षेत्र में भी
जहां अभी तक लगा था उनके लिए
नो-एंटरी का बोर्ड

वे जानते हैं
यह एक जंग है
जहां उनकी हार तय है
एक झूठ के रेतीले ढूह की ओट में
खड़े रह कर आख़िर कब तक
बचा जा सकता है बाली के
तीक्ष्ण बाणों से
आसमान से बरसते अंगारों में
उनका झुलसना तय है
फिर भी
अपने पुराने तीरों को वे
तेज़ करने लगे हैं।

हरियाणा में एक दशक बाद भाजपा को अभूतपूर्व चुनौती

■ डॉ. ज्ञान पाठक

जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति बताती है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा होगा, केवल आधा दर्जन सीटों को छोड़कर, जहां बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है, जिसमें जेजेपी, आईएनएलडी, आप (अगर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है) और कुछ निर्दलीय शामिल हैं। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर स्पष्ट है।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा 16 अगस्त को हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही, राष्ट्रीय एवं राज्य की राजनीतिक पार्टियां अपनी-अपनी विशेष राजनीतिक परिस्थितियों से निपटने में लग गई हैं। उनके नेता कई हफ्तों से चुनावी मूड में थे, खासकर 4 जून, 2024 को लोकसभा आम चुनाव के नतीजे आने के बाद से।

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के नेताओं को चुनावी सक्रियता में बनाये रखने वाली बात लोकसभा चुनाव के नतीजों की प्रकृति है। सत्तारूढ़ भाजपा को सीटों और वोटों के मामले में मिली हार ने एक तरफ उनके नेतृत्व में चिंता और अपने गढ़ को बचाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता को जन्म दिया है, वहीं कांग्रेस की जीत ने उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह को दोगुना कर दिया है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि वे राज्य में भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकते हैं।

सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के अलावा जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) और इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) सहित क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के पास अब केवल तीन सप्ताह का समय है, जिसके दौरान उन्हें टिकटों पर फैसला करना है, राजनीतिक अंतर्कलह के कारण उभरी सीमाओं को पाटना है और राज्य में राजनीतिक गठबंधन के मुद्दों को सुलझाना है। इसलिए, उन्हें पहले से ही बरकरार चुनावी सक्रियता में अपनी गति को बनाये रखते हुए चुनावी बारीकियों से निपटना होगा।

भाजपा पिछले 10 वर्षों से राज्य पर शासन कर रही है, लेकिन अब उसे एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसका खुलासा लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से हुआ है। चुनाव से ठीक पहले जेजेपी के साथ उसका गठबंधन टूट गया था। पार्टी ने पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर की जगह ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि, भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर को दूर नहीं किया जा सका।

भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीती गई राज्य की सभी 10 सीटों में से 5 खो दीं और उसका वोट शेयर भी 11.91 प्रतिशत घट गया। इसलिए, अगर पार्टी राज्य में अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहती है, तो इस रुझान को बदलना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भाजपा को अभी भी उम्मीद है कि पार्टी किसानों के गुस्से को कम करने के लिए ओबीसी का लाभ उठा सकेगी।

हालांकि, भाजपा ने अपनी सारी उम्मीदें नहीं खोई हैं, क्योंकि लोकसभा के नतीजों से पता चलता है कि भाजपा ने 44 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है, जबकि विधानसभा चुनाव 2019 में उसने 90 में से 40 सीटें जीती थीं। भाजपा नेतृत्व को उम्मीद है कि थोड़ा और प्रयास करके पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल कर सकती है, भले ही राज्य में एनडीए मजबूत नहीं है क्योंकि भाजपा ने कुछ महीने पहले जेजेपी से नाता तोड़ लिया था। भाजपा नेतृत्व को यह भी उम्मीद है कि इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ सकता है, और इसलिए वे विधानसभा क्षेत्रों की संख्या के मामले में कांग्रेस पर बढ़त हासिल कर सकते हैं।

लोकसभा के नतीजों से पता चलता है कि जेजेपी और इनेलो ने राज्य में अपना प्रभाव काफी हद तक खो दिया है। जेजेपी ने 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती थीं, लेकिन वह लोक सभा चुनाव के दौरान किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल नहीं कर सकी। पार्टी को 1 प्रतिशत से भी कम वोट मिले, जिसे भाजपा के साथ जाने के लिए पार्टी के खिलाफ मतदाताओं के गुस्से के रूप में समझा गया। किसान समुदाय भाजपा से नाराज हैं, जो लगता है कि अपनी वफादारी जेजेपी से दूर कर चुके हैं। इनेलो ने 2019 में 1 सीट जीती थी, लेकिन उसका भी यही हश्र हुआ, और वह किसी भी विधानसभा क्षेत्र में बढ़त हासिल नहीं कर सकी, जो बताता है कि किसान समुदाय इनेलो के साथ भी नहीं है।

हालांकि कांग्रेस ने भाजपा से 5 लोकसभा सीटें छीन ली थीं और अपने वोट शेयर में 15.16 प्रतिशत की वृद्धि की थी, लेकिन उसे केवल 42 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी, जो भाजपा से 2 कम थी। यही कांग्रेस के लिए चुनौती है, जिसे सत्तारूढ़ भाजपा से मुकाबला करने और इंडिया ब्लॉक के लिए बहुमत हासिल करने के लिए स्पष्ट रूप से एक सहयोगी की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से राज्य में फिर से उभर रही है, जो जमीन पर और विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त के मामले में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 30 सीटें जीती थीं।

आम आदमी पार्टी भले ही इंडिया ब्लॉक के हिस्से के रूप में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी हो, लेकिन वह एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई। हालांकि, इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आप ने 4 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है। इस प्रकार, इंडिया ब्लॉक ने कुल 90 में से 46 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है, जो स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है, जो भाजपा की बढ़त से 2 अधिक है। हालांकि, यह अभी भी अनिश्चित है कि आप और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के घटक के रूप में हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे या नहीं। आप नेतृत्व ने कई बार दोहराया है कि कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे की व्यवस्था केवल लोकसभा चुनाव के लिए थी।

फिर भी, जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिति बताती है कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा होगा, केवल आधा दर्जन सीटों को छोड़कर, जहां बहुकोणीय मुकाबला हो सकता है, जिसमें जेजेपी, आईएनएलडी, आप (अगर अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला करती है) और कुछ निर्दलीय शामिल हैं। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर स्पष्ट है और किसान अभी भी पीएम मोदी की किसान विरोधी नीतियों से नाराज हैं, जिससे कांग्रेस को 2024 में राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा से सत्ता छीनने की उम्मीद जगी है।

हरियाणा विधानसभा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए राज्य विधानसभा चुनाव, जिसका कार्यकाल 4 नवंबर, 2024 को समाप्त होना है, 1 अक्टूबर को एक चरण में होंगे। कुल 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव कार्यक्रम इस प्रकार है- अधिसूचना तिथि- 5 सितंबर; नामांकन की अंतिम तिथि- 12 सितंबर; नामांकन की जांच की तिथि- 13 सितंबर; नाम वापसी की अंतिम तिथि- 16 सितंबर; कुल 2.03 करोड़ मतदाता राजनीतिक दलों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें से 4.7 लाख पहली बार मतदाता हैं, जबकि विकलांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाता 1.49 लाख, तीसरे लिंग 455 और 85+ वरिष्ठ नागरिक 2.46 लाख हैं।

आपके पत्र

बंद नहीं है एक मात्र सहारा

भारत बंद का आह्वान करने वालों ने सुबह से ही आवागमन को बाधित कर कानून को आइना दिखाने का जो साहस दिखाया है, वह कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अपनी बात मनवाने का यह तरीका किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता । कानून की परिधि में रहते हुए अपनी बात कहने के लिए तंत्र बना हुआ है। केवल बंद की ही बात नहीं किसी भी तरह के विरोध स्वरूप इस तरह का कदम उठाने से पूर्व विद्रोह करने वालों को यह भी सोचना चाहिए कि उनके द्वारा किए जा रहे काम से उन्हीं के समाज में रहने वालों का कितना नुकसान हो सकता है। अपनी बात रखने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान बनाए गए हैं। न्यायालयों की शरण उनमें से प्रमुख चरण माना जा सकता है। सुबह से ही अपनी ड्यूटी जाने के लिए निकले लोगों की विवशता मैंने स्वयं देखी है। कहीं भी पुलिस प्रशासन के न होने से स्थिति अराजक हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? यह भी ऐसे ज्ञापन के बाद व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए।

भारत बंद के लिए ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन ने किस स्तर पर अपनी तैयारी की यह भी आज सुबह से दिखाई पड़ा। कहीं आंदोलनकारियों से प्रतिभागी अनुनय-विनय करते दिखाई पड़े तो कहीं गरमा-गरमी का माहौल भी बन गया। क्या आज की होने वाली परीक्षाओं को अगले दिन के लिए टाला जा सकता है? क्या आज आपातकालीन स्थिति में मरीजों के इलाज को डॉक्टर और किसी दिन करने की स्थिति में आ सकते हैं? बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर शिक्षक आदि का काम क्या देश की विकास की गति को ग्रहण नहीं लगा जायेगा? इन सारी समस्याओं पर गहन चिंतन की जरूरत स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार को महसूस करनी होगी। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि क्रीमी लेयर की बात करना या इस वर्ग को आरक्षण से बाहर करना उचित है या नही? कहीं न कहीं न्यायाधीशों की बेंच ने आर्थिक संपन्नता को आधार मानकर अपना निर्णय सुनाया है। ऐसे में न्यायविदों की खिलाफत संविधान के अपमान से कम कैसे हो सकता है?

देश की सरकार को ऐसी स्थिति पैदा न हो इसके लिए विशेष प्रावधान बनाने की जरूरत है। संसद के दोनो सदनों में इस तरह के विरोध के लिए कदम न उठा सकने के लिए सख्त कानून बनाना ही होगा। कानून किसी धर्म, जाति,वर्ग से संबंधित न होकर मानवीय समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। जिसे भी ऐसा प्रतीत हो कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, उन्हें न्यायालय की शरण में जाकर अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तब साथ ही साथ कर्तव्यों का ख्याल भी आना चाहिए। किसी भी तरह का बंद किसी वर्ग के लिए उचित नहीं कहा जा सकता है। हम पुलिस को कोसते हैं, जबकि उनके भी हाथ कहीं न कहीं कानून की धाराओं ने जकड़ रखे हैं। जब तक मानवीय समाज खुद अराजकता से दूर रहने का संकल्प नहीं ले लेता है , तब तक इस तरह की समस्याएं समाप्त नहीं होंगी ।

डॉ. सूर्यकांत मिश्रा, राजनांदगांव

ललित सुरजन की कलम से

न्यायमूर्ति दवे के उद्गार

श्री दवे का ध्यान मैं बहुचर्चित अर्थशास्त्री और राजनैतिक विश्लेषक लॉर्ड मेघनाद देसाई की हाल में प्रकाशित पुस्तक %%हू रोट द श्रीमदभागवत卐 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें विद्वान लेखक ने बड़ी बेबाकी के साथ स्थापना की है कि %गीता आज की जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। हम देखना चाहेंगे कि श्री दवे श्री देसाई के तर्कों को किस तरह काटते हैं।

रामायण और महाभारत में भी जो कथाएं और अन्तर्कथाएं हैं वे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े करती हैं जो आधुनिक समाज की न्याय की अवधारणा से टकराते हैं। ऐसे कुछ सवाल हम बिना किसी प्राथमिकता क्रम के सामने रख रहे हैं-

1. *युधिष्ठिर को धर्मराज की पदवी दी गई है, लेकिन क्या द्यूत क्रीड़ा धर्मसम्मत है और अगर है तो कौरव सभा में द्रौपदी को दांव पर लगाना धर्म है या अधर्म?*
2. *इसी तरह युद्ध क्षेत्र में युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को मारने के लिए असत्य का आश्रय क्यों लिया?*
3. *द्रौपदी के चीरहरण के समय भीष्म पितामह सहित किसी भी सभासद ने विरोध क्यों नहीं किया?*
4. *रामायण में शूर्पणखा के साथ परिहास कहां तक उचित था?*
5. *बालीवध को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है?*
6. *सीता की अग्निपरीक्षा और बाद में सीता का परित्याग आज की स्थितियों में क्या न्यायपूर्ण माना जाएगा?*
7. *शंबूक वध का औचित्य कैसे सिद्ध किया जा सकता है?*

(देशबन्धु में 07 अगस्त 2014 को प्रकाशित)

https://lalitsurjan.blogspot.com/2014/08/blog-post.html

पावन प्रसंग

मितव्ययी बनें, आय-व्यय का संतुलन बनाएं

पारिवारिक बंधन का महत्वपूर्ण पहलू धन है। इसी के आधार पर घर की सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखा जाए तो परिवार की सर्वाधिक शक्ति का उपयोग अर्थोपार्जन में ही जाता है। पुराने जमाने की बात नहीं करें। लेकिन जब से महंगाई ने अपना मुंह बड़ा किया है, तब से परिवार के परिजनों का जीवनयापन बड़ी कशमकशपूर्ण परिस्थिति में होने लगा है, क्योंकि आय के स्रोत सीमित हैं- महंगाई आय के अनुपात से अधिक बढ़ गई है। इस कारण घर खर्च पूरा नहीं पड़ता है। दूसरी ओर शान-शौकत के मूल्यों ने जीवन को विलासी बना दिया है। इन मूल्यों को पूरा करने के लिए परिवार के बजट का अधिकांश भाग खर्च होने लगा है। प्राथमिक आवश्यकता रोटी पर आजकल बहुत कम व्यय होता है। कपड़ा और अन्य विलासी सामानों पर भारी व्यय होने से परिवार के सामने अर्थ समस्या हर घड़ी बनी रहती है। इसकी पूर्ति के लिए परिवार के हर परिजन को कुछ-न-कुछ प्रयत्न भी करने पड़ते हैं।

परिवारों में शान-शौकत के पीछे एक दृष्टिकोण पनप गया है कि बढ़िया फर्नीचर, कीमती वस्तुओं टेलीफोन, फ्रीज आदि द्वारा रिश्तेदारों में और अपने संपर्क के लोगों पर अपना प्रभाव डाले रखना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनका परिवार दूसरों के सामने हीन समझा जाए। चाहे पति हो या पत्नी घर में इनमें से कोई एक भी इस शान-शौकत से भरी झूठी जिंदगी का हामी रहा तो घर में बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

विलासी वस्तुओं को अल्प वेतन में तो नहीं खरीद पाता है। अस्तु, वह इन शान-शौकत की वस्तुओं को उधार खरीदने लगता है। इसका परिणाम होता है कि वेतन का दो-तिहाई हिस्सा उधार ब्याज पूरा करने में ही खर्च हो जाता है। शेष वेतन में पत्नी घर का खर्च कैसे चलाए, क्योंकि घर में अच्छा भोजन, अच्छा साधारण रहन-सहन तथा अच्छा वातावरण इन तीनों की पूर्ति के लिए कुछ-न-कुछ वेतन का अधिक भाग व्यय करना पड़ता है। वह सब किस्तों की पूर्ति में खर्च हो जाता है। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा आदि भी होते रहते हैं। किंतु किया क्या जाए?

शान-शौकत भी रखी जा सकती है, किंतु इसका क्रम में रोटी, कपड़ा, मकान आदि के पश्चात आता है। यदि इन पर खर्च होने के बाद कुछ बचता है, तो शान-शौकत इतनी ऊंची भी न हो कि हैसियत की चादर को ही फाड़ डाले। फिर वक्त जरूरत के लिए बचत का भी बजट रहना चाहिए। घर की अनिवार्य आवश्यकताओं के पश्चात कीमती वस्तुएं परिवार के उपयोग में आने वाली हैं, तो किस्तों की अपेक्षा मासिक बचत करके कुछ महीनों के बाद कीमत चुकाकर ही खरीदना अधिक लाभदायक है क्योंकि किस्तों में तो दुकानदार ब्याज-बट्टा खाता आदि सभी गुंजाइश रखकर किस्त बांधता है। अच्छा यही है कि आवश्यक वस्तुओं की ओर दृष्टि जानी चाहिए।

घर में उधार के कारण पत्नी, बच्चे तथा परिवार के परिजनों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बाहर चाहे शान-शौकत दिखाई देती है, किंतु मन के भीतर ऋण का भार कचोटता रहता है। इससे मानसिक अशांति बनी रहती है। इस अशांति का प्रक्षेपण बच्चों-पत्नी पर आए दिन हुआ करता है। कहना चाहिए पारिवारिक जीवन में अव्यवस्थित वातावरण तैयार हो जाता है। क्या ये शान-शौकत की कीमती वस्तुएं मानसिक शांति को दूर कर सकने में मदद कर सकती हैं। प्रदर्शन में दूसरों का अनुकरण न करें। सादगी को आदर्श मानकर अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप खर्च करेंगे तो जीवन सुखी और संतुष्ट बनेगा।

युग निर्माण योजना

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

दैनिक जलते दीप
जोधपुर, गुरुवार 22 अगस्त 2024

फिर यू टर्न

अब इसे गठबंधन सरकार की मजबूरी समझें या फिर विपक्ष का दबाव कि विवाद के बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के तहत नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। दरअसल, निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को शीर्ष सरकारी पदों पर लाने हेतु यह योजना बनी थी। बीते सालों में नौकरशाही में विशेषज्ञों को शामिल करने के कदम को प्रगतिशील सोच कहा गया। लेकिन चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के चलते विरोध के स्वर मुखर हुए। विपक्षी दलों की तीखी आलोचना और राजग के कुछ सहयोगियों की चिंता के बाद सरकार ने योजना को स्थगित कर दिया। निश्चित रूप से शासकीय व्यवस्था में बड़े फैसले गंभीर परामर्श व सहयोग की मांग करते हैं। सत्ता के दंभ से इतर दूरगामी परिणाम वाली नीतियों को आगे बढ़ाने हेतु सभी हितधारकों से व्यापक बातचीत जरूरी होती है। दूसरे शब्दों में सरकार को अपनी इच्छा थोपने के बजाय गठबंधन राजनीति की जटिलताओं के मद्देनजर विपक्ष से सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल, यह तय है कि पिछले दो कार्यकाल में स्वछंद शासन करने वाली मोदी सरकार फिलहाल गठबंधन की मजबूरी के साथ विपक्षी दबाव को भी महसूस कर रही है। पिछले दो सप्ताह में राजग सरकार ने विवाद के बाद न केवल वक्फ विधेयक पर निर्णय बदला बल्कि प्रसारण विधेयक को समीक्षा के लिये एक संसदीय पैनल के पास भेजा है। इसके बाद अब लेटरल एंट्री के फैसले पर यू टर्न ने यह निष्कर्ष भी दिया है कि राजग सरकार पर्याप्त बहुमत न होने पर अब गठबंधन की राजनीति की सीमाओं को स्वीकार करने लगी है। एक हकीकत यह भी है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के सदस्य अभी भी तल्ख चुनावी तेवरों में नजर आ रहे हैं। खासकर ऐसे वक्त में जब हरियाणा व जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और इसी साल महाराष्ट्र व झारखंड में भी चुनाव होने हैं। बहरहाल, केंद्र सरकार ने वक्फ विधेयक व प्रसारण विधेयक के बाद अब लेटरल एंट्री मामले में से हाथ खींचकर यह संकेत देने का प्रयास किया है कि वह टकराव के बजाय बीच का रास्ता अपनाना चाहती है। उसने सतर्क रुख ही अपनाया है। कहा जाता रहा है कि लेटरल एंट्री प्रक्रिया हमारे संविधान में निहित समानता और न्याय के आदर्शों पर केंद्रित होनी चाहिए। इन भर्तियों में आरक्षण के प्रावधान न होने के मुद्दे का कांग्रेस, बसपा, सपा व राजद ने जोरदार तरीके से विरोध किया। उनकी दलील थी कि इस प्रक्रिया में सामाजिक न्याय की अवधारणा की अनदेखी की गई है। दरअसल, 17 अगस्त को यूपीएससी द्वारा 24 केंद्रीय मंत्रालयों में सेक्रेटरी, डायरेक्टर व डिप्टी सेक्रेटरी जैसे पदों के लिये निकाले गए विज्ञापन के कुछ घंटों के बाद विपक्ष ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिये थे। यहां तक कि राजग गठबंधन में शामिल एलजेपी ने भी इस फैसले को लेकर चिंता जतायी थी। विपक्षी दलों की दलील थी कि आरक्षण का प्रावधान न होने से वंचित समाज के हकों की रक्षा नहीं हो सकेगी। वहीं सरकार की दलील है कि लेटरल एंट्री का विचार कांग्रेस सरकार के दौरान 2005 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के बाद सामने आया था और यूआईडीएआई के प्रमुख समेत कई पदों पर विशेषज्ञों की सीधी भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। दरअसल, मोदी सरकार में लेटरल एंट्री की प्रक्रिया वर्ष 2018 में आरंभ हुई थी, जब सीधी भर्तियों के लिये विज्ञापन दिए गए थे। ये नियुक्तियां अनुबंध पर तीन से पांच साल के लिये की गई। लेकिन नियुक्तियों की संख्या कम होने के कारण विवाद नहीं उठा था। इन पदों के लिये राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा निजी क्षेत्र में इस पद से जुड़ा अनुभव रखने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। तर्क दिया गया कि ये नियुक्तियां डेप्यूटेशन जैसी हैं, जिसमें आरक्षण अनिवार्य नहीं है। बहरहाल, इस मुद्दे के विरोध के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, राजग सरकार ने भी आरक्षण विरोधी छवि बनने की आशंका के बीच इस फैसले से हाथ खींचा है। बहरहाल, प्रशासनिक व्यवस्था में विषय विशेषज्ञों का जुड़ना अच्छी बात है लेकिन इस प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता की जरूरत है।

लेटरल एंट्री नाम की बेइंसाफी टली..

मोदी सरकार को अपने एक और फैसले का पेटी-बिस्तरा बांधकर लौट जाना पड़ा है। देश की नौकरशाही में, जहां पर कि लोग कुछ अपवादों को छोडक़र यूपीएससी से चुनकर आते हैं, आईएएस का इम्तिहान देकर भारत सरकार और राज्यों में सरकारी सचिवों के ओहदों तक पहुंचते हैं, वहां पर मोदी सरकार ने लोगों को थोक में सीधे बाहर से उठाकर केन्द्र सरकार में संयुक्त सचिव तक बनाना शुरू कर दिया था। यह अपने आपमें देश के नौजवानों के समानता के अधिकार के खिलाफ था, और यूपीएससी जैसी संस्था का पूरा काम ही मानो गैरजरूरी करार दे दिया गया था क्योंकि भारत सरकार नाम छांटकर यूपीएससी को दे देती थी, और वह इन लोगों को बिना किसी आरक्षण के छांट लेती थी। संविधान में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, यह व्यवस्था उसके भी खिलाफ थी। इस लेटरल एंट्री के तहत मोदी सरकार ने अभी 45 लोगों को सीधे डायरेक्टर या संयुक्त सचिव बनाना तय किया था, और राहुल गांधी ने इसके खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोला था। आरक्षण को लेकर, दलित और आदिवासियों के हक को लेकर, ओबीसी समुदाय को नौकरशाही में जगह न मिलने को लेकर राहुल गांधी पिछले साल भर से लगातार देश में एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत जब बिहार के पल्टूराम के साथ कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां जातीय जनगणना करवाई गई थी। राहुल गांधी ने लगातार यह अभियान वैसे भी चलाया हुआ था कि नौकरशाही में, भारत सरकार के सचिवों के स्तर पर ओबीसी समुदाय से आने वाले अफसरों की कितनी कमी है। यह बात भी समझने की जरूरत है कि जब यूपीएससी के इम्तिहानों में एसटी, एससी, और ओबीसी का आरक्षण होता है, तो फिर भारत सरकार के सचिव स्तर पर पहुंचते हुए इन आरक्षित वर्गों के अफसरों का अनुपात एकदम से कैसे गिर जाता है? बहुत से लोगों का यह मानना है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट, और हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में पिछले जजों के कुनबे जगह पाते रहते हैं, उसी तरह भारत सरकार के तमाम ताकतवर ओहदों पर आमतौर पर सवर्ण कही जाने वाली जातियों का ही बोलबाला रहता है। राहुल गांधी तरह-तरह के मौजूदा आरक्षण, संभावित आरक्षण, और आरक्षण में धोखाधड़ी के कई आरोप लगाते हुए इसे लगातार सामाजिक मोर्चे पर एक आंदोलन की शक्ल देते आए हैं। अब जब केन्द्र सरकार एक साथ करीब 45 पदों पर बाहरी लोगों को बिना किसी आरक्षण के लेटरल एंट्री से नियुक्त करने जा रही थी, तो राहुल गांधी ने इस पर बड़ा हल्ला बोला, और कहा कि यह आरक्षित वर्गों के लोगों के हक मारना है। उन्होंने यह राजनीतिक तोहमत भी लगाई कि मोदी सरकार आरएसएस के विचारधारा के लोगों को सरकार में घुसाने के लिए उस प्रावधान की आड़ ले रही है जिसके तहत पिछली सरकारों ने मनमोहन सिंह जैसे विख्यात अर्थशास्त्री को नियुक्त किया था, कुछ अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को नियुक्त किया था, या आधार कार्ड बनाने वाले नंदन निलेकेणि को नियुक्त किया था। यह बड़ी हँसी की बात है कि मोदी सरकार एक साथ 45 लोगों को ऐसे विशेषज्ञ लोगों की मिसाल गिनाते हुए सरकार में लेटरल एंट्री दे रही है। अगर सचमुच ही कोई सरकार 45 ऐसे महान जानकार ढूंढ सकती है, तो देश तो फिर कामयाबी के अंतरिक्ष में ही पहुंचकर थमेगा।

प्रसंगतः दुख के साथ

एक व्यक्ति हर समय परेशान रहता था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। बाकी सारे लोग सुखी है , एक अकेला वही दुखी है। एक दिन उसने परमात्मा से प्रार्थना की, ‘ मेरे सिवा सभी खुश नजर आते हैं। यह तो नहीं कहता कि तू मुझे दुख मत दे, पर इतना तो मत दे कि सह ही न सकूं। एक कृपा कर, तू मुझे किसी और का दुख दे दे। मेरा दुख किसी और को दे दे। ’ रात में उसने एक स्वप्न देखा। देखा कि एक बहुत बड़े कमरे में हर जगह खूटियां ही खूटियां लगी हैं। उस कमरे में जो भी आता है उसकी पीठ पर दुखों की गठरी बंधी है। सभी आकर अपनी गठरी वहां किसी खूंटी पर टांग देते हैं ओर बैठ जाते हैं। उसे कमरे में जो भी दिखा वह उसका परिचित था। थोड़ी देर में वह खुद भी अपने दुख की गठरी लेकर पहुंचा और उसने भी अपनी गठरी एक खूंटी पर टांग दी। देखने में सभी गठरियां बराबर थीं। थोड़ी देर बाद एक आवाज गूंजी, ‘जिसे भी अपनी गठरी बदलनी है बदल सकता है। चलो एक-एक गठरी उठा लो। ’ सभी गठरियां उठाने दौड़े। पर सभी ने अपनी-अपनी गठरी ही उठाई। किसी ने दूसरे की गठरी को हाथ नहीं लगाया। उसी समय उस व्यक्ति की नींद टूट गई। वह स्वप्न का आशय समझ गया। उसे समझ में आ गया कि दुखी रहने का कोई अर्थ नहीं है। दुनिया में हर कोई दुखी है। बेहतर है कि दुखों से संघर्ष करके सुख की खोज की जाए।

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न

कितने अफसोस की बात है कि शीला दीक्षित को तो बार-बार इस छड़ी से पीटा गया था कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा हुआ। उन्हें निर्भया को श्रद्धांजलि देने तक से रोक दिया गया था। लेकिन बंगाल के मामले में लोगों ने चुप्पी साध रखी है। यही नहीं, निर्भया के बारे में जो तर्क दिए गए थे कि वह इतनी रात बाहर निकली ही क्यों थी। जैसे कि लड़कियां रात में बाहर निकलेंगी तो पुरुषों को यह अधिकार मिल जाएगा कि उनके साथ कुछ भी करो। दुष्कर्म करो, उन्हें मार डालो। कोलकाता में भी ऐसे ही तर्क सत्ताधारी दल के द्वारा दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह लड़की सेमिनार रूम में उस वक्त क्या कर रही थी।

– क्षमा शर्मा

पिछले दिनों से कोलकाता में एक महिला डाक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या चर्चा में है। इसे कोलकाता का निर्भया कांड कहा जा रहा है। निर्भया की दुष्कर्म और हिंसक मारपीट के बाद सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। इस डाक्टर के साथ अपराध वहां किए गए हैं, जहां वह काम करती थी। क्यों सड़कें, घर, अस्पताल, दफ्तर, महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। निर्भया कांड के बाद दिल्ली में तेज आंदोलन हुआ था। उस समय सारा विपक्ष निर्भया के समर्थन में उतर आया था। और एक बेहद गरिमामय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव हार गई थीं। लेकिन कोलकाता के केस में ममता बनर्जी की सरकार और विपक्ष का बड़ा तबका अगर-मगर कर रहा है। देशभर में डाक्टरों के स्वतः स्फूर्त आंदोलनों को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। यहां तक कि डाक्टरों को बीजेपी का सपोर्टर बताया जा रहा है।

कितने अफसोस की बात है कि शीला दीक्षित को तो बार-बार इस छड़ी से पीटा गया था कि एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में ऐसा हुआ। उन्हें निर्भया को श्रद्धांजलि देने तक से रोक दिया गया था। लेकिन बंगाल के मामले में लोगों ने चुप्पी साध रखी है। यही नहीं, निर्भया के बारे में जो तर्क दिए गए थे कि वह इतनी रात बाहर निकली ही क्यों थी। जैसे कि लड़कियां रात में बाहर निकलेंगी तो पुरुषों को यह अधिकार मिल जाएगा कि उनके साथ कुछ भी करो। दुष्कर्म करो, उन्हें मार डालो। कोलकाता में भी ऐसे ही तर्क सत्ताधारी दल के द्वारा दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह लड़की सेमिनार रूम में उस वक्त क्या कर रही थी।

अपराधी से कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे कि वह वहां क्या करने गया था। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि यह मामला मानव अंगों की तस्करी से जुड़ा है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। महिला डाक्टर को इस बारे में पता चल गया था, वह इसकी शिकायत भी करना चाहती थी, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया। सच जो भी हो, लेकिन एक स्त्री ने वहां जान गंवाई है, जहां वह काम करती थी। आखिर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की क्यों नहीं थी। उसके माता-पिता को तीन घंटे तक उसके शव को क्यों नहीं देखने दिया गया। अज्ञात लोगों ने बड़ी संख्या में आकर अस्पताल में तोड़-फोड़ क्यों की। बहुत से सवाल हैं जो अनुत्तरित हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ कोलकाता के सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से हो रही है।

क्या सचमुच हमारे राजनेता, जिनमें स्त्री हों या पुरुष, अपनी-अपनी सत्ता बचाने के लिए इतने अमानवीय हो गए हैं। औरतें सहज शिकार हैं और उनसे कोई सहानुभूति भी नहीं। निर्भया कांड के बाद नए रेप कानून की मांग की गई थी कि उसे इतना कठोर बनाया जाए कि अपराधियों की रूह कांपे। कानून बना, मगर ऐसा हो नहीं सका है। सोचें कि जब पढ़ी-लिखी स्त्रियों के साथ सरेआम ऐसा हो रहा है, तो उन गरीब स्त्रियों का क्या, जिनकी पहुंच न पुलिस तक होती है, न कानून तक। कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों की पोस्ट पढ़कर तो लगता है कि ये भी इंसान कहलाने के लायक नहीं।

एक आम तर्क यह दिया जा रहा है कि कोलकाता पर बोलने वाले उत्तराखंड के दुष्कर्म पर क्यों नहीं बोले, मणिपुर पर क्यों चुप रहे। मान लीजिए कि कोई उस वक्त नहीं बोला, तो क्या इस वक्त उसने अपने बोलने के अधिकार को किसी के पास गिरवी रख दिया कि जब आपकी राजनीति को सूट करे तब आपसे पूछकर कोई बोले।

देश में इन दिनों या तो आप पक्ष में हो सकते हैं, या विपक्ष में। बीच की वह रेखा मिटा दी गई है जहां जब कोई दल अच्छा काम करे, तो उसकी तारीफ की जाए और बुरा करे तो निंदा।

आखिर काम-काज की जगह पर स्त्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने से क्यों बचना चाहिए। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या महिला और महिला के दुष्कर्म में फर्क होता है। महिलाओं के प्रति अपराध कहीं भी हों, देश में किसी भी सत्ताधारी दल की सरकार हो, वह निंदनीय है। लेकिन उंगली अक्सर दूसरे की तरफ ही उठती है।

दफ्तरों में यौन प्रताड़ना की निगरानी करने वाली कमेटियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर महिला सुरक्षा के लिए ही बनाई गई थीं। क्या कोलकाता की डाक्टर के साथ हुआ अपराध इस श्रेणी में नहीं आता। दिल्ली में जब एक महिला की घर से कुछ दूर रात में हत्या कर दी गई थी, तब से यह कानून बनाया गया था कि रात में जो कैब महिला को छोड़ने जाएगी, वहां उसके साथ दफ्तर का कोई आदमी होगा, जो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यही नहीं, जब तक महिला अपने घर के अंदर नहीं चली जाएगी, तब तक कैब वहां से नहीं जाएगी। डाक्टर जो बहत्तर-बहत्तर घंटे ड्यूटी करते हैं, उन्हें सड़क पर तो छोड़िए, अपने काम-काज के स्थान पर सुरक्षा न मिले तो यह कितनी खतरनाक बात है। बहुत-सी महिला डाक्टरों के बयान इस लेखिका ने पढ़े और सुने हैं। उनमें यही चिंता झलक रही थी। लेकिन कुछ दल और उनके समर्थकों को इससे क्या। वे इन महिला डाक्टरों के बयानों से आंखें मूंदकर, ममता बनर्जी का पक्ष लेते रहे।

चुनावों से पहले जब हमारे देश के अधिकांश दल अपने-अपने घोषणापत्रों में महिला सुरक्षा के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनका क्या फायदा, जब किसी ऐसे अवसर पर आप अपने-अपने दल का मुंह ताकते हुए बयानबाजी करें। अपनी कुर्सी की खातिर किसी अपराध को अपराध कहने से बचें।

और वे बुद्धिजीवी जो इस लड़की की निर्मम हत्या पर आंखें मूंदे हैं क्योंकि यह उनकी राजनीति के पक्ष में नहीं जाता, आखिर उन्हें कौन-सा इलेक्शन लड़ना है। वोट की चिंता करनी है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिसे सच कहते हैं, उसका इतना पतन हुआ है कि कोई सच भी बोल रहा हो तो बहुत से लोग अपने-अपने हितों को देखकर उसे झूठ साबित करने पर लग जाते हैं।

महिला डाक्टर की हत्या के मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई जांच में जो कुछ भी पाए, वह लड़की जिसके माता-पिता ने उसे डाक्टर बनाया, उसके परिश्रम ने भी उसका साथ दिया, वह तो अब वापस आने से रही। और तो और उसकी तस्वीरें जगह-जगह दिखाई दे रही हैं। उसका नाम बताया जा रहा है। जबकि कानूनन ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है।

आज जब बड़ी संख्या में लड़कियां काम-काज के लिए बाहर निकल रही हैं, तब सत्ताधारियों द्वारा उनकी हस्ती को मिटा देने के ऐसे षड्यंत्र क्यों सफल हों। कायदे से तो महिलाओं को अपनी सुरक्षा की आवाज के तहत उन दलों से सवाल पूछने चाहिए। पितृसत्ता-पितृसत्ता चिल्लाइए और जब मौका मिले उसकी आड़ में या अपने-अपने दलों की आड़ में छिप जाइए, यह कितना शर्मनाक है।

(लेखिका वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

आर्थिक तरक्की के लिए कार्यकुशलता जरूरी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में भारत सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में ही रहते हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन से भी 47 प्रतिशत ज्यादा। हमारे देश में इस वक्त 138 करोड़ लोग हैं। इनमें से 25 करोड़ 15 से 25 साल के बीच हैं। यानी, कुल आबादी का 18 प्रतिशत से ज्यादा। वहीं, चीन में सिर्फ 17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यूएन के नॉर्म के मुताबिक युवा हैं। मतलब चीन की कुल आबादी 144 करोड़ के हिसाब से वहां 12 फीसदी लोग ही युवा हैं। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी युवा आबादी का भारत क्या सकारात्मक उपयोग कर पा रहा है?? आंकड़ों के मुताबिक साल दर साल बेरोजगारी बढ़ रही है और देश में स्किल्ड युवाओं की भारी संख्या में कमी है।

भारत में नई शिक्षा नीति के माध्यम से ज्ञान को व्यावहारिक बनाने की कवायद चल रही है। नई पहल के तहत अब नान-टेक्निकल पढ़ाई करने वाले छात्रों मसलन बीए, बीकाम, बीएससी करने वालों को अब रोजगार के लिए भटकना नहीं होगा। टेक्निकल स्नातकों की तरह उन्हें भी न्यूनतम धनराशि के साथ अप्रेंटिसशिप का मौका मिलेगा। इसके बाद उन्हें आसानी से रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। हालांकि, इसके लिए उन्हें पढ़ाई पूरी करते ही रोजगार से जुड़े क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद वह अप्रेंटिसशिप या सीधे नौकरी हासिल कर सकेंगे। इस पहल में देश में हर साल उच्च शिक्षा हासिल करके निकलने वाले करीब एक करोड़ छात्रों पर फोकस किया गया है। मौजूदा समय में देश में उच्च शिक्षा से करीब 4.33 करोड़ छात्र जुड़े हैं। शिक्षा मंत्रालय की नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत स्नातकों को हर माह न्यूनतम नौ हजार और डिप्लोमाधारियों को आठ हजार रुपये मिलेंगे। रोजगार के लिए देश में हर साल उच्च शिक्षा हासिल करके निकले एक करोड़ छात्रों पर इस स्कीम का फोकस है।

इसके तहत शिक्षा मंत्रालय ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ ही एक करार किया है। इसके जरिये इन सभी छात्रों को पढ़ाई के बाद रोजगार मुहैया कराने वाले क्षेत्रों की जरूरत को ध्यान में रखकर एक महीने से लेकर छह महीने तक के कोर्स कराए जाएंगे। इसके बाद उन्हें उन क्षेत्रों में रोजगार हासिल करने में सहूलियत होगी। मौजूदा समय में देश में करीब पांच लाख सीएससी हैं। स्नातकों को हर माह न्यूनतम नौ हजार और डिप्लोमाधारियों को आठ हजार रुपये मिलेंगे। इसकी आधी राशि शिक्षा मंत्रालय देगा, बाकी राशि अप्रेंटिसशिप कराने वाली कंपनी देगी। मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत इस साल करीब 2.66 लाख छात्रों को अप्रेंटिसशिप कराई जा रही है। इसकी अवधि छह माह से डेढ़ साल तक की है। नान-टेक्निकल क्षेत्र में स्नातक करते ही छात्रों के पास अप्रेंटिसशिप करने के लिए पांच साल का ही मौका रहेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने की इस नई पहल की शुरुआत करने के साथ छात्रों के इस अप्रेंटिसशिप की पहली किस्त भी जारी की है। इसके तहत अगले सौ दिन में 100 करोड़ रुपये देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, युवाओं के लिए स्किलिंग भी अहम बनाई जाएगी।

ज्ञात हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत अभी तक सिर्फ टेक्निकल यानी बीई, बीटेक या पालीटेक्निक करने वाले छात्रों को ही अप्रेंटिसशिप मुहैया कराई जाती थी। मंत्रालय के मुताबिक, अप्रेंटिसशिप व इंटर्नशिप में मुख्य अंतर यह है कि अप्रेंटिसशिप उन क्षेत्र में छात्रों के अनुभव में जुड़ती है जबकि इंटर्नशिप अनुभव में नहीं जुड़ती है।

मार्च, 2020 के बाद से दुनिया ने कोरोना के साथ रहना सीख लिया है, लेकिन इस दौरान दुनियाभर में बड़े बदलाव देखने को मिले, जीवन से जुड़े लगभग हर क्षेत्र में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। शिक्षा, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में कई तरह के बदलाव एक साथ देखने को मिल रहे हैं। भारत में भी युवाओं के लिए शिक्षा के साथ कौशल विकास पर तेजी से काम हो रहा है।

असल में हमने यह बात समझने में बहुत देर कर दी कि अकादमिक शिक्षा की तरह ही बाजार की मांग के मुताबिक उच्च गुणवत्ता वाली स्किल की शिक्षा देनी भी जरूरी है। एशिया की आर्थिक महाशक्ति दक्षिण कोरिया ने स्किल डेवलपमेंट के मामले में चमत्कार कर दिखाया है और उसके चौंधिया देने वाले विकास के पीछे स्किल डेवलपमेंट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इस मामले में उसने जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्ष 1950 में दक्षिण कोरिया की विकास दर हमसे बेहतर नहीं थी। लेकिन इसके बाद उसने स्किल विकास में निवेश करना शुरू किया। यही वजह है कि 1980 तक वह भारी उद्योगों का हब बन गया। उसके 95 प्रतिशत मजदूर स्किल्ड हैं या वोकेशनली ट्रेंड हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा तीन प्रतिशत है। ऐसी हालत में भारत कैसे आर्थिक महाशक्ति बन सकता है?

स्किल इंडिया बनाने के उद्देश्य से मोदी सरकार ने अलग मंत्रालय बनाया है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन भी बनाया गया है। केन्द्रीय बजट में भी इसके लिए अनुदान दिया गया है। मतलब पहली बार कोई केंद्र सरकार इसके लिए इतनी संजीदगी से काम करने की कोशिश कर रही है। इसे देखते हुए लगता है कि स्किल डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार की सोच और इरादा तो ठीक है लेकिन इसका कितना क्रियान्वयन हो पायेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम केंद्र सरकार की अच्छी योजना है। अगर इसका क्रियान्वयन ठीक से किया गया तो इसके अच्छे परिणाम आएंगे।

– डॉ. शशांक द्विवेदी

कजली तीज माता का प्यार

आया तीज का त्यौहार
करती है सुहागिने श्रगांर,
कजली माँ की करे पुकार
लेती सुख का आशीर्वाद,

तीज पर भूखी रहकर
व्रत रखती बहनों के साथ,
जब तक चँदा नही उगता
उसका भी करती इंतजार,

झूलकर झूला तीज के दिन
पानी पीती सिर्फ एक बार,
दर्शन चाँद का किये बिना
नही खाती खाना फलाहार,

बदली छाने से कभी कभी
दर्शन होते नही तत्काल,
सौभाग्यवती रहने के लिए
माँ पर करती पूरा विश्वास,

उनकी इस त्याग तपस्या से
अंकुरित हो जाते है संस्कार,
तीज माँ की कृपा से मिलता
सुख से रहने का आशीर्वाद

त्यौहारों से पूरी संस्कृति का
बढ़ जाता सबमे प्रेम दुलार
सबको सुखी रखने के लिए
सबको देते रहते हम उपहार,

– गोपाल कृष्ण व्यास
पूर्व अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग

संपादकीय

“ कर्ज में डूबने से बेहतर है, भूखे सो जाना।
-बेंजामिन फ्रेंकलिन

प्राइम डाटाबेस के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी का सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचना आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिहाज से शुभ संकेत है। विदेशी संस्थागत निवेश की हिस्सेदारी कम होना वैश्विक अनिश्चितताओं से उपजी एक अस्थायी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इस पर ध्यान देना होगा।

आत्मनिर्भर बाजार

कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार कई बदलावों से गुजरा है, लेकिन प्राइम डाटाबेस की ताजा रिपोर्ट का यह बताना कि 30 जून, 2024 तक बाजार में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 25.85 फीसदी के सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, न केवल बाजार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के निवेशकों की बढ़ती जागरूकता के साथ आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। इसका श्रेय घरेलू संस्थागत निवेशकों के साथ खुदरा निवेशकों (किसी कंपनी में दो लाख रुपये तक की शेयरधारिता वाले) और उच्च निवल मूल्य वाले (एचएनआई) यानी कंपनी में दो लाख रुपये से ज्यादा शेयरधारिता वाले निवेशकों को भी जाता है, जो अब बाजार में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। पहले शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों का हिस्सा सीमित था, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की उपलब्धता, सोशल मीडिया पर वित्तीय शिक्षा के प्रसार और डीमैट खातों की संख्या में बढ़ोतरी ने स्थितियां बदली हैं। खुदरा निवेशकों की भागीदारी फायदेमंद भी है, जो बाजार में विविधता लाने के साथ इसे अधिक स्थिर व लचीला भी बनाती है। रिपोर्ट का यह कहना भी उत्साह बढ़ाने वाला है कि जून तिमाही के दौरान एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी बढ़कर 9.17 फीसदी के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में एसआईपी के माध्यम से निवेश का चलन बढ़ा है, जो खुदरा निवेशकों को अनुशासित और दीर्घकालिक निवेश की ओर प्रेरित कर रहा है। म्यूचुअल फंड की कामयाबी इसका भी संकेत है कि देश के निवेशक अब पहले की अपेक्षया अधिक समझदार और सतर्क हुए हैं और अब वे अपने निवेश को पेशेवर प्रबंधन के हाथों में सौंपने के महत्व को समझने लगे हैं। घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भारतीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) का बारह वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुंचना भी ध्यान देने योग्य है। वर्षों

से विदेशी संस्थागत निवेश भारतीय बाजार में सबसे बड़ी गैर-प्रवर्तक शेयरधारक श्रेणी रही है, जिनके निवेश-निर्णयों का बाजार की समग्र दिशा पर भारी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब अगली कुछ तिमाहियों में घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) की हिस्सेदारी एफआईआई से आगे निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। एफआईआई में गिरावट वैश्विक स्तर पर छाई आर्थिक अनिश्चितता की वजह से भी हो सकती है। लिहाजा, यह एक अस्थायी प्रवृत्ति हो सकती है, जो वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के साथ बदल भी सकती है। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि घरेलू निवेशकों का प्रभुत्व आर्थिक आत्मनिर्भरता और बाजार व अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिहाज से एक शुभ संकेत है।

चीन खुद एक वैश्विक समस्या है

चीनी कर्ज के चलते वित्तीय संकट में फंसे जांबिया, श्रीलंका और पाकिस्तान को तो छोड़िए, यूरोप की आर्थिक महाशक्ति जर्मनी जैसे धनी देश भी व्यापार में चीन पर अत्यधिक निर्भरता के संकट को महसूस कर रहे हैं। चीनी निर्माताओं को मिल रही भारी सब्सिडी से दुनिया भर के बाजार चीन के सस्ते उत्पादों से भर गए हैं।

वेनेजुएला के भूतपूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने 2000 के दशक में अपने देश का आर्थिक भविष्य उभरते चीन के ऊपर दांव पर लगा दिया, इससे उसे अरबों डॉलर का निवेश मिला और तेल सौदों के लिए कर्ज भी। शुरुआत में इससे फायदा हुआ। चीन ने जमकर वेनेजुएला के तेल का उपभोग किया और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया। लेकिन 2010 के दशक में तेल की कीमतें गिर गईं और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ चीन की ओर से तेल की मांग भी घट गई। नतीजतन वेनेजुएला के तेल निर्यात का राजस्व 2016 में घटकर 22 अरब डॉलर रह गया। उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। लोग कचरे के ढेर में भोजन तलाशने लगे, अस्पतालों में दवाओं की कमी थी और अपराध बढ़ गए थे। तब से, लगभग 80 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं। चीन ने वेनेजुएला को नए ऋण देने से मना कर दिया, जिससे वहां अधूरी परियोजनाओं का ढेर लग गया।

माइकल बेकले
द न्यूयॉर्क टाइम्स

चीन पर वेनेजुएला की अत्यधिक निर्भरता एक चेतावनी थी, जिसकी दुनिया ने अनदेखी की। चीन के उदय से लाभान्वित दर्जनों अन्य देश अब वित्तीय संकट और ऋण न चुका पाने के जोखिम में फंसे हैं, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था ठहर गई है। फिर भी चीन ऋण राहत देने से इन्कार कर रहा है और संरक्षणवादी गतिविधियों पर दोगुना जोर दे रहा है, जबकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त करने और नई शुरुआत के लिए सुधार करने चाहिए। यह बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था के जादुई गुब्बारे का दूसरा पहलू है।

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया को एक रक्षक की जरूरत थी और चीन ने वह भूमिका निभाई। इसका सकारात्मक प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया। वर्ष 2008 से 2021 तक चीन ने वैश्विक विकास में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। विकासशील देशों ने खुद को चीन से जोड़ा, और चीन दुनिया के अधिकांश देशों का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। वेनेजुएला की तरह कई देशों ने पाया कि तेजी से बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था उनके वस्तु निर्यात के लिए एक

आकर्षक बाजार है, और उन्होंने उसमें भारी निवेश किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सुस्ती का सामना करना पड़ा। चीन ने विभिन्न देशों को दस खरब डॉलर से ज्यादा का ऋण दिया है, जिसका बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों द्वारा बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव) के तहत बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचे के लिए है। मगर चीन की तेजी टिकाऊ नहीं थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उद्यमशीलता को दबाया, सुधार का विरोध किया और अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया को उकसाया। शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद चीन के आर्थिक विकास में काफी कमी आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुश्किल से ही बढ़ रहा है। हालांकि चीन ने लगातार बाहरी स्रोतों के अनुमान से ज्यादा विकास का दावा किया है। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है, जिन्होंने अपने आर्थिक विकास को चीन से जोड़ रखा है। कई देशों द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट आई है।

चीन अपनी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए चीनी निर्माताओं को भारी ऋण और सब्सिडी दे रहा है, जिससे दुनिया भर के बाजार सस्ते उत्पादों से भर गए हैं, वैश्विक वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं और दूसरे देशों के निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बेशक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी के लिए सिर्फ चीन ही जिम्मेदार नहीं है, जो महामारी, युद्ध और व्यापार तनावों से प्रभावित है। लेकिन वह नाजुक समय में हालात को और भी बदतर बना रहा है। चीन ने विदेशी ऋण में भारी कटौती की है और विकासशील देशों को अपने मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए मजबूर कर रहा है। जांबिया और श्रीलंका को गहरे वित्तीय संकट में धकेलने में चीनी ऋणों का बहुत बड़ा हाथ था। आंशिक रूप से चीनी ऋण की अपारदर्शी प्रकृति के कारण दोनों देशों के संकट और बढ़ गए।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने चेताया कि विकासशील दुनिया के दर्जनों देश, जिनमें से कई के चीन से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हैं, अब ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान एक गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसे बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए चीन को अरबों डॉलर का ऋण चुकाना है। यहां तक कि यूरोप की आर्थिक महाशक्ति कहे जाने वाले जर्मनी जैसे कुछ धनी राष्ट्र भी चीन के साथ व्यापार करने की अत्यधिक निर्भरता के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल चीन को जर्मनी के निर्यात में नौ फीसदी की गिरावट आई व उसकी अर्थव्यवस्था भी सिकुड़ गई।

ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे प्रमुख कमोडिटी निर्यातक असुरक्षित हैं, क्योंकि चीन को निर्यात उनकी अर्थव्यवस्थाओं का अहम हिस्सा है। अमेरिका सीधे तौर पर कम प्रभावित हुआ है, क्योंकि चीन को विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम है। लेकिन चीनी उत्पादों की अधिकता अमेरिकी निर्माताओं के लिए खतरा है। दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु ऋणदाता चीन ने अक्सर गैर-पारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से कई देशों को कर्ज के बोझ तले दबाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो 1980 के दशक में विकासशील देशों, खासकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के ऋण संकट के समान है।

पिछले दशक में चीन ने पेरिस क्लब (दुनिया के 22 सबसे बड़े ऋणदाता देशों का समूह) से भी ज्यादा ऋण दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अनुमानित रूप से 3.3 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं, जहां ब्याज भुगतान शिक्षा या स्वास्थ्य में निवेश से अधिक है। आर्थिक संकट में फंसे वेनेजुएला के उदाहरण ने दिखाया है कि ये परिस्थितियां आर्थिक पतन, दमन और मानवीय आपदा की ओर ले जा सकती हैं।

हाल में, फ्रांस, पोलैंड, केन्या, बोलीविया, श्रीलंका और कई अन्य देशों में लोगों ने बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। धनी अर्थव्यवस्थाओं और ऋणदाता देशों से ऋण राहत, बाजार पहुंच और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए अन्य तरीकों से सहयोग करने की मांग बढ़ रही है। लेकिन ऐसे कदमों का केवल सीमित प्रभाव होगा, जब तक कि चीन को कठघरे में नहीं खड़ा किया जाता, क्योंकि वह खुद में एक वैश्विक समस्या है।

जीवन धारा

मोपासां

एक जिंदगी, कुछ दिन, और फिर कुछ नहीं। आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, आप खुश होते हैं, आप इंतजार करते हैं, फिर आप खत्म हो जाते हैं। आखिर प्रेम के क्षण ही तो हैं, जो इस निरर्थक जिंदगी को अर्थ देते हैं।

वर्तमान क्षण में रहेंगे, तभी प्रेम को समझ पाएंगे

जीवन एक ढलान है। जब तक आप ऊपर जा रहे हैं, आप हमेशा शीर्ष की ओर देखते हैं और आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो अचानक आप नीचे की ओर जाने वाली सड़क और उसके अंत में मौत को देखने लगते हैं। ऊपर जाना हमेशा धीमा होता है और नीचे उतरना तेज होता है। सांस लेना, सोना, खाना-पीना, सपने देखना, हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं, वह दरअसल मरना है। वास्तव में, जीना ही मरना है। हम सभी एक यात्री हैं, और यात्रा, सपनों की तरह, एक द्वार है, जो वास्तविक दुनिया से एक ऐसी दुनिया में खुलता है, जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। हम सब यात्री ही तो हैं, जो जीवन में मिलते हैं और इसे जीने लायक बनाते हैं। हमारी स्मृति ब्रह्मांड से भी अधिक परिपूर्ण है। यह उन लोगों को जीवन देती है, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। हम हर क्षण मर रहे हैं और ऐसे निरर्थक जीवन को एक ही चीज है, जो अर्थ देती है। वह है प्रेम, जिसका मतलब है शरीर, आत्मा, जीवन, पूरा अस्तित्व। प्रेम को वैसे ही महसूस किया जाना चाहिए, जैसे हम अपने खून की गर्मी को महसूस करते हैं। जीवन की सुंदरता और अच्छाई एक ही चीज में मौजूद है वह प्रेम में है। प्रेम के विचार की हर बुरे विचार से रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि, एक बीमार विचार शरीर को बुखार या किसी बीमारी से भी बुरी तरह से खा सकता है। बुरे विचारों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है कि वर्तमान में रहा जाए। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, इसका एक ही कारण है कि अतीत हमेशा हमें आकर्षित करता है, वर्तमान हमें भयभीत करता है, अंत में जिसे भविष्य कहते हैं, वह मृत्यु होता है।

कई वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने भी बाकी लोगों की तरह ही जिया, खाया, हंसा, प्यार किया, उम्मीदें कीं। और इसके बाद यह सब खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक जिंदगी, कुछ दिन, और फिर कुछ नहीं। आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, आप खुश होते हैं, आप इंतजार करते हैं, फिर आप मर जाते हैं। पुरुष हो या महिला, आप इस धरती पर लौटेंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है। फिर भी हममें से हर कोई अपने भीतर अनंत काल की तीव्र, अवास्तविक लालसा रखता है, लेकिन सच तो यह है कि हममें से हर कोई जल्द ही नए जीवों के कूड़े के ढेर में पूरी तरह से गायब हो जाता है। पौधे, जानवर, इन्सान, तारे, दुनिया, सब कुछ तेजी से बढ़ते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में खुद से और इस पृथ्वी से प्रेम करना चाहिए। एक उम्र के बाद हम अपनों से दूर हो जाते हैं, ताकि हम जीवन को बेहतर बना सकें, लेकिन हम कई बार अपने जीवन की सबसे अनमोल चीजों से भी दूर हो जाते हैं। हमें कई बार मालूम नहीं होता कि हम अपनी मां से अनजाने में ही प्यार करते हैं, और यह एहसास हमें तब होता है कि यह प्यार कितना गहरा है, जब हम उनसे अलग हो जाते हैं।

खुद से प्रेम करें

सूत्र

सबसे पहले खुद से प्रेम करें। बाकी सब खुद-ब-खुद हो जाएगा। जब आप दुनिया में प्रेम फैलाते हैं, तो वह फैलता है, और लोगों को छूता है तथा उन तरीकों से हम तक लौटकर आता है, जिनकी हमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। प्यार ही जीवन की असली पूंजी है।

दूसरा पहलू

जर्मनी के कील को 'जीरो वेस्ट सिटी' (शून्य अपशिष्ट शहर) के रूप में प्रमाणित किया गया है।

'जीरो वेस्ट सिटी' : सतत विकास की नई राह

कील शहर को जर्मनी के पहले शून्य अपशिष्ट शहर (जीरो वेस्ट सिटी) के रूप में प्रमाणित किया गया है। शहर में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर और जगह-जगह कचरे के पहाड़ खड़े होने से रोकने की दिशा में कील की यह उपलब्धि दुनिया के अन्य शहरों के समक्ष मिसाल है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व आर्थिक मंच जैसी वैश्विक संस्थाएं भी 'जीरो वेस्ट सिटी' की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही हैं। 'जीरो वेस्ट सिटी' का अर्थ एक ऐसे शहर से है, जहां अपशिष्ट पदार्थों को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उत्पन्न कचरे का प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाता है, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। शहरी कचरे की समस्या से निपटने के लिए कील शहर में जीरो वेस्ट सिटी योजना लागू है, जिसके तहत वहां के सभी घर, प्रतिष्ठान, स्कूल और सार्वजनिक निकाय अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इस योजना का लक्ष्य 2035 तक प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 15 फीसदी कचरे को कम करना है। शून्य अपशिष्ट की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस शहर में प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल डायपर के बजाय कपड़े के डायपर के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। ये डायपर न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि पुनः प्रयोज्य भी हैं। कपड़े के डायपर की खरीद पर सरकार 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 यूरो तक की सब्सिडी प्रदान करती है। कील शहर भोजन की बर्बादी के भी खिलाफ है। वहां के लोग खाने योग्य भोजन को कूड़े के रूप में कम से कम फेंकते हैं, जिससे संसाधनों की बर्बादी रोकने में मदद मिलती है। यही नहीं, शहर में फल और सब्जी की दुकानों में पुनः प्रयोज्य थैले मुफ्त में दिए जाते हैं। शहर में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति से कचरे के वजन के आधार पर शुल्क लिए जाने की व्यवस्था है। कील की यह व्यवस्था अनुकरणीय है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपशिष्ट का उत्पादन और उसके समुचित निपटान का अभाव जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्राकृतिक विनाश के तिहरे संकट को बढ़ावा दे रहा है। दुनिया के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने के प्रयासों में शून्य अपशिष्ट जीवन एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। कचरा उत्पन्न करने से बचकर हम अपने मूल्यवान संसाधनों की बर्बादी को कम कर सकते हैं।

सुधीर कुमार

योजना का लक्ष्य 2035 तक प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 15 फीसदी कचरा कम करना है। इसलिए बच्चों को प्लास्टिक के बजाय कपड़े के डायपर पहनाते हैं।

कील शहर भोजन की बर्बादी के भी खिलाफ है। वहां के लोग खाने योग्य भोजन को कूड़े के रूप में कम से कम फेंकते हैं। शहर में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति से कचरे के वजन के आधार पर शुल्क लिए जाने की व्यवस्था है।

आंकड़े

डीटीएच ग्राहक घटे

फाइबर केबल के बढ़ते प्रचलन की वजह से पिछले पांच वर्षों में डीटीएच उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। 80 लाख से अधिक डीटीएच सब्सक्राइबर (ग्राहक) इन वर्षों में कम हुए हैं।

2019	6.998
2021	6.957
2023	6.525
2024	6.197

ग्राहकों के आंकड़े करोड़ में हैं। | स्रोत : TRAI

भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे, तब लक्ष्मण के शंका करने पर प्रभु श्रीराम ने कहा, भरत के समान शीलवान भाई विधाता की सृष्टि में न तो कहीं देखा और न सुना है।

भरत की भक्ति

मान्यता है कि भरत का अवतार रामभक्ति का आदर्श स्थापित करने के लिए ही हुआ था। संतों का तो यहां तक कहना है कि भगवान श्रीराम के प्रेम ने ही भरत का रूप धारण किया था। भरत ने 'तत्सुखसुखित्वम' के महान आदर्श को अपने जीवन में खूब निभाया। श्रीराम के अनुकूल आचरण करना ही भरत का एकमात्र ध्येय था। गोस्वामी तुलसीदास ने उनके बारे में लिखा है, '*भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही।*' अर्थात भरत के समान राम को कौन प्यारा होगा, जिन राम का जाप सारा संसार करता है, राम उन भरत का स्मरण करते हैं यानी जपते हैं।

भरत जी जब राम को वन से लौटाने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनकी नीयत पर शंका की थी। उस वक्त प्रभु श्रीराम ने भरत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, 'भरत के समान शीलवान भाई विधाता की सृष्टि में न तो कहीं देखा और न सुना है।' '*विधि प्रपंच महुं सुना न दीसा।*' भगवान भरत के संबंध में सम्मति देते हैं कि भरत को अयोध्या के राज्य की, तो बात ही क्या? ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद प्राप्त होने पर भी मद नहीं हो सकता। चित्रकूट में भरत की स्थिति को देखकर ज्ञानियों में अग्रगण्य राजर्षि जनक ने तो यहां तक कहा, 'भरत की महिमा का वर्णन करना तो दूर, मेरी बुद्धि उनकी छाया को छल से भी नहीं छू सकती।'

अंतर्यात्रा
संकलित

आज का इतिहास

महात्मा गांधी ने जलाई विदेशी कपड़ों की होली

वर्ष के आठवें महीने का यह 22वां दिन कई अच्छी बुरी घटनाओं के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इन घटनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें, तो महात्मा गांधी ने 22 अगस्त को विदेशी कपड़ों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा बुलंद किया था और अंग्रेजों के खिलाफ एक अलग तरह के विरोध की शुरुआत की थी। खेल जगत के लिए भी इस दिन का खास महत्व है। भारत की राही सरनोबत ने 2018 में 22 अगस्त के दिन ही एशियाई खेलों की 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी में स्विवणम सफलता अर्जित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह एशियाई खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। 1320 में गयासुद्दीन तुगलक (गाजी मलिक) ने खिलजी वंश के आखिरी शासक नासिरुद्दीन खुसरो को पराजित किया। 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) की स्थापना की। 1849 में ऑट्रिया ने इटली के शहर वेनिस पर चालक रहित गुब्बारों से इतिहास का पहला हवाई हमला किया।

'जान बचाने वाले' कितने सुरक्षित

कोलकाता की घटना ने दिन-रात सेवारत चिकित्सकों की कार्य परिस्थितियों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं।

विवेक एस अग्रवाल | मुद्दा

अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही जूनियर डॉक्टर की नौ अगस्त को कोलकाता में एक क्रूर घटना में जघन्य हत्या कर दी गई। इससे पूरे राष्ट्र का जनमानस हिल गया है। इसने एक बार पुनः निर्भया हत्याकांड की याद ताजा कर दी, लेकिन यह घटना तो उससे भी कहीं ज्यादा वीभत्स है। निर्भया की हत्या राह चलती बस में यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी, लेकिन हाल में घटित घटना को अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान पर अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम से प्रतीत होता है कि यह पूर्व नियोजित था।

अस्पताल के अंदर कार्यरत चिकित्सक की कार्यावधि के दौरान की गई हत्या जूनियर एवं प्रशिक्षु डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के जरिये राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने में लगी हैं और चिकित्सक के प्रति हिंसा का विषय नेपथ्य में चला गया है। विभिन्न अवसरों पर चिकित्सकों के विरुद्ध हिंसक वारदात के विरोध में चिकित्सक संगठन अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन ज्यादातर अवसरों पर ठंडे छींटे देकर आंदोलन को शांत कर दिया जाता है। चिकित्सकों से सेवा की तो पूर्ण अपेक्षा रखी जाती है, किंतु उनकी सुरक्षा के प्रति जवाबदेही के लिए बनाया जाने वाला कानून वर्ष 2022 से लंबित है। उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा कानून बनाने के बावजूद स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय होने के कारण संपूर्ण दारोमदार राज्यों पर ही आ जाता है। कई राज्यों ने विभिन्न अवसरों पर आंदोलनरत चिकित्सकों को शांत करने के लिए कानून तो बना दिए, लेकिन वे धरातल पर नहीं उतरे। जैसे राजस्थान में कानून तो वर्ष 2008 में बन गया था, किंतु प्रभावी क्रियान्वयन डॉ. अर्चना शर्मा द्वारा दबाव में की गई आत्महत्या के उपरांत वर्ष 2022 में तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पश्चात ही हो पाया है। कोलकाता की घटना ने चिकित्सकों विशेष तौर पर दिन-रात सेवारत सहयोगी चिकित्सकों की कार्य परिस्थितियों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। चिंतनीय है कि जिनके हाथों में जीवन बचाने का दायित्व सौंपा जा रहा है, उनके पास ठीक से उठने-बैठने, आराम करने और निवृत्त होने की उचित व्यवस्था भी नहीं रहती। चिकित्सा के व्यावसायीकरण और विशेष तौर पर कॉरपोरेट संस्कृति में ढलने से वहां कार्यरत चिकित्साकर्मी भी एक सामान्य कर्मी बन कर रह गए हैं। मरीजों के बोझ में दबे सरकारी चिकित्सा संस्थानों का तो हाल और भी चिंताजनक है। विभिन्न राज्यों द्वारा नर्सिंग होम या अस्पताल की स्थापना के मानक तय करने को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किए गए हैं, जिनमें ड्यूटी डॉक्टर हेतु कक्ष एवं शौचालय का भी मानक रखा गया है, किंतु वह अत्यंत अल्प है, जिसमें अनेक चुनौतियां रहती हैं। हाल की घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की पहल पर पुरुष व महिला प्रशिक्षु और ड्यूटी चिकित्सकों के लिए समुचित कक्ष की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन क्रियान्वयन का दायित्व तो राज्य सरकारों एवं चिकित्सा संस्थान संचालकों की नीयत पर है। एक ओर भारत सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की महत्वाकांक्षा के साथ तीव्र गति से कार्य कर रही है, वहीं चिकित्सक इस व्यवसाय के प्रति पुनर्विचार करने लगे हैं। इन सबके मूल में निरंतर असुरक्षा का भाव सबसे प्रमुख है। पूर्व में चिकित्सक का स्वप्न होता था कि अपनी अगली पीढ़ी को भी चिकित्सक बनाना, लेकिन विगत वर्षों में इस चलन में कमी आई है। इस कमी के पीछे जहां आर्थिक कारण एक पक्ष है, वहीं नित्य प्रति घटित होने वाली घटनाएं प्रमुख रूप से दोषी हैं।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 65 ■ अंक 189 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2022-24 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperPaid

एमपाक्स का प्रकोप

सतर्कता जरूरी

एमपाक्स का प्रकोप सारी दुनिया के लिए चिन्ता का विषय है। हालांकि, अभी परेशान होने के बजाय इसके प्रति सतर्कता जरूरी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अब दुनिया एक और बड़ी स्वास्थ्य चुनौती 'एमपाक्स' का सामना कर रही है जिसे पहले 'मंकीपाक्स' के नाम से जाना जाता था। यह वाइरल बीमारी परंपरागत रूप से अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी, पर अब यह परेशान करने वाली गति से दुनिया भर में फैल रही है। इससे दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों में चिन्ता फैल गई है। एमपाक्स मंकीपाक्स वाइरस से फैलता है जो 'आर्थोपाक्स कुल' में शामिल है। चेचक या स्मालपाक्स वाइरस भी इसी कुल का है। अच्छी खबर यह है कि अधिकांश मामलों में यह जानलेवा नहीं होता है और इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि, एमपाक्स का कोई खास इलाज नहीं है, पर अधिकांश पीड़ित कुछ सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। अच्छी प्रतिरक्षण प्रणाली वाले लोगों में सामान्य देखभाल और दर्द नियंत्रण से राहत मिलती है, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली वाले लोगों को इलाज की जरूरत पड़ती है। हालांकि, यह स्मालपाक्स की तुलना में कम घातक है, पर एमपाक्स से खासकर कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली वाले लोगों में गंभीर बीमारी हो सकती है। वाइरस का प्रसार मुख्यत: जानवर-मनुष्य संपर्क तथा मानव-मानव संपर्क से हो सकता है। सीधे संपर्क, शरीर के द्रवों, सांस से निकलने वाली छोटी-छोटी बूंदों या बिस्तर जैसे संक्रमित स्थान से संक्रमण फैल सकता है। एमपाक्स के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, लसीका ग्रंथियों में सूजन, कंपकंपी तथा अक्सर चेहरे से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैलने वाले चकत्ते शामिल हैं।

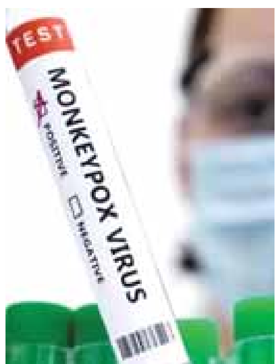

हाल ही में कोरानावायरस वैश्विक महामारी से राहत पाने के बाद लोग एक और वैश्विक महामारी का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि, अभी यह महामारी नहीं है, पर यदि रक्षात्मक कदम न उठाए गए तो यह वैश्विक महामारी में बदल सकती है। दुनिया भर में एमपाक्स मामले बढ़ने के बाद भारतीय हवाईअड्डों पर सतर्कता बढ़ाई गई है तथा वाइरस का प्रसार रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी सलाह जारी कर हवाईअड्डों को जांच प्रक्रिया गहन बनाने तथा संभावित मामलों की पहचान व उनको अलग-थलग करने के प्रोटोकाल कठोरता से सुनिश्चित करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्लूएचओ ने अनेक क्षेत्रों में एमपाक्स मामले बढ़ने की जानकारी दी है। इससे पहले वाइरस को नियंत्रित रखने वाले क्षेत्रों में चिन्ता फैल गई है। बुखार, चकत्ते या लसीका ग्रंथियों में सूजन जैसे लक्षण वाले यात्रियों को और चिकित्सकीय परीक्षणों के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरू जैसे शहरों में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे महत्वपूर्ण रक्षात्मक कदम उठा रहे हैं। त्वरित आंकलन के लिए इन स्थानों पर विशेष चिकित्सा टीमें लगाई गई हैं ताकि एमपाक्स संक्रमित किसी व्यक्ति को अलग कर उसका इलाज किया जा सके। बाहर से आने वाले यात्रियों के अलावा देश से बाहर जाने वाले यात्रियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खासकर वाइरस संक्रमित क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है। हालांकि, भारत में अभी एमपाक्स के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, पर वाइरस को देश में जड़ें जमाने से रोकने के लिए व्यापक सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जोर दिया है कि एमपाक्स का प्रसार रोकने के लिए संक्रमितों की जल्दी पहचान तथा उनको अलग-थलग करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत जैसे घनी बस्तियों वाले देश में एमपाक्स प्रसार के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन

आर्थिक उथलपुथल और सैनिक विद्रोह के कारण बांग्लादेश से भारत के अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध अब अनिश्चितता का शिकार हैं। वहां भारत-विरोधी भावनायें बढ़ रही हैं तथा रणनीतिक हितों पर सवाल उठ रहे हैं।

अशोक के. मेहता
(लेखक, सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं)

आर्थिक उथलपुथल और सैनिक विद्रोह के कारण बांग्लादेश से भारत के अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध अब अनिश्चितता का शिकार बन गए हैं। वर्तमान समय में वहां अनेक कारणों से भारत-विरोधी भावनायें बढ़ रही हैं तथा भारत के उस देश में रणनीतिक हितों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि भारत बांग्लादेश की घटनाओं व खासकर वहां हिंदुओं व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्तित है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के फौरन बाद 'अंतरिम सरकार' के मुखिया प्रोफेसर यूनूस ने मोदी से फोन पर बात कर उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया। ढाका में पिछले 53 साल में हुए चौथे परोक्ष सैनिक विद्रोह का नेतृत्व पूरी तरह छात्र-संचालित आंदोलन के कारण हुआ। इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसका प्रमुख कारण शेख हसीना का जनता से संपर्क टूटना तथा आर्थिक परेशानियों पर लगाम लगाने में विफलता थी। छात्रों द्वारा संचालित आंदोलन में अनेक छात्रों समेत लगभग 200 लोगों और संभवत: इससे भी अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हसीना की सत्ता के लिए 'ऊंट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका' साबित हुई। इसके बाद सेना प्रमुख-सीओएएस जनरल वकार-उज़-ज़मां के सामने केवल एक ही विकल्प बचा और उन्होंने शेख हसीना को देश छोड़ कर जाने के लिए 45 मिनट का समय दिया।

बांग्लादेश के जनरल ने संभवत: 'एक दिन बाद घटने वाली' इस स्थिति का पहले से अनुमान लगा लिया था। यदि ऐसा न होता तो सत्ता का तेजी से और व्यवस्थित हस्तांतरण संभव ही नहीं हो सकता था। बांग्लादेश की सड़कों पर हसीना-विरोधी भावनायें भड़क रही थीं। इसके साथ ही शेख मुजीबुर रहमान की विरासत पर भी सवाल उठ रहे थे जिसे उन्होंने पाकिस्तान से स्वतंत्रता के रूप में पाला-पोसा था। भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में व्यापक सहायता की थी। बांग्लादेश में इस 'विरासत' के प्रति गुस्से की भावना भी बढ़ रही थी जिसे समय पर नहीं पहचाना गया। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तथा मुक्ति संग्राम से जुड़े स्मारक तोड़ने की घटनायें इसके प्रतीक के रूप में सामने आईं। बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनायें भड़कने का एक कारण हसीना सरकार का भारत द्वारा आंख बंद कर समर्थन करना था, जबकि उनकी लोकतांत्रिक पहचान लगातार गिर रही थी। इसके साथ ही बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाओं के अन्य कारण भी थे जिनमें बीएसएफ द्वारा सीमा पर की गई गोलीबारी, तीस्ता जल का साझा न हो पाना तथा सिलीगुड़ी कारीडोर का प्रयोग करने की अनुमति न देना भी शामिल हैं।

भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीएए-एनआरसी की जोरदार पैरोकारी ने भी भारत के प्रति बांग्लादेश में संदेह का वातावरण बना। इन परिस्थितियों में शेख हसीना को भारत में अनिश्चित काल तक शरण देने के निर्णय से भी बांग्लादेश में भारत के प्रति गुस्सा बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त की घटनाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इनमें अनेक षडयंत्र सिद्धान्तों को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ावा दिया गया। इनमें अमेरिका का नाम लेना, सीआईए द्वारा सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे की इच्छा तथा पाकिस्तानी, आईएसआई व चीन का नाम लेना शामिल हैं। सेंट मार्टिन द्वीप पर म्यांमार भी अपना दावा करता है। हालांकि, इनमें से कुछ पक्षों ने निश्चित रूप से परेशानियों का लाभ उठाने का प्रयास किया, पर भारत को 'इस्लामवादी' व 'जिहादी' संगठनों की खासतौर से चिन्ता करनी चाहिए। हालांकि, नोबेल विजेता, उदारवादी लोकतांत्रिक व क्षेत्रीयतावादी मुहम्मद यूनुस 'अंतरिम सरकार' का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे छात्रों व उनके नेताओं नाहीद इस्लाम व आसिफ मुहम्मद द्वारा निर्देशित होंगे। यह रहस्य है कि शेख हसीना के रिश्तेदार जनरल जमां ने इस विद्रोह में क्या भूमिका अदा की। बांग्लादेश में कोई भी सत्ता परिवर्तन बिना सेना की संलिप्तता के कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

शेख हसीना की सबसे बड़ी उपलब्धि एक समय अत्यन्त निर्धन बांग्लादेश को दक्षिण एशिया की सबसे तेज प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। उसके मानव विकास सूचकांक श्रीलंका को छोड़ कर सभी क्षेत्रीय देशों से आगे थे। वेतनों पर विरोध प्रदर्शनों तथा हड़तालों व कोविड में तबाह होने के पहले उसका गारमेंट उद्योग विश्वस्तरीय था। बांग्लादेश ने दो दशक तक 6.5 प्रतिशत की गति से प्रगति की थी और उसकी प्रति व्यक्ति आय 2600 डालर थी जो भारत से भी बहुत अधिक थी। लेकिन उसकी प्रगति की यह गाथा आईएमएफ से 4.76 बिलियन डालर कर्ज लेने और मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से अधिक होने के कारण नष्ट हो गई। भारत के साथ उसका व्यापार तेजी से बढ़ा और वह 18 बिलियन डालर तक पहुंच गया। यदि बांग्लादेश के साथ एफटीए हो जाता तो बांग्लादेश के निर्यात में 182 प्रतिशत वृद्धि होती। बांग्लादेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक है और उन्होंने चिकित्सा पर्यटन को गति दी है। बांग्लादेश के साथ रक्षा संबंध बहुत अच्छे रहे और यह एक प्रकार से दुश्मन को दोस्त में बदलने की कथा है। हालांकि, बांग्लादेश 'वार गेम्स' में भारत को शत्रु की तरह पेश करता था, पर इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को रक्षा खरीद के लिए 500 बिलियन डालर की सहायता दी थी। लेकिन बांग्लादेश की सेना और एक समय जनरल जमां द्वारा नियंत्रित रक्षा खरीद में भारत सबसे निचले स्तर पर जबकि चीन सबसे ऊपर था। वहां विमान, पनडुब्बियां, टैंक, तोपखाना और अन्य उपकरण मुख्यत: चीनी हैं।

वर्तमान समय में बांग्लादेश छात्र नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के कारण परेशानी में फंसा है जिनका क्रियान्वयन अंतरिम सरकार कर रही है। इस प्रकार भारत को ऐसे देश में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे जन्म देने में उसने प्रमुख भूमिका अदा की थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम काल वह था जब भारत के हितों को समुचित रूप से संबोधित किया जाता था। यही कारण है कि बांग्लादेश की नई सरकार शेख हसीना तथा अवामी लीग से जुड़े सभी लोगों पर निशाना लगा रही है।

वर्तमान परिस्थितियों में बांग्लादेश की सेना दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और भारत इसकी उम्मीद भी कर सकता है। यदि बांग्लादेश अपने समक्ष आने वाली आर्थिक चुनौतियों का सामना करना चाहता है तो इसके लिए भी उसे भारत की सहायता अनिवार्य रूप से लेनी होगी। बांग्लादेश और भारत की भौगोलिक स्थिति तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना भी द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। ढाका को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में भयानक आर्थिक संकट और दीवालियापन से नई दिल्ली ने कोलंबो को बाहर निकालने में किस प्रकार सहायता की थी। इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि केवल छात्रों का विरोध आंदोलन ही श्रीलंका की राजनीति बदलने में सक्षम नहीं था। बांग्लादेश के एकमात्र हिंदू पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा को हसीना ने हटा दिया था। सुरेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है वह पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने 'अंतरिम सरकार' द्वारा किए अनेक परिवर्तनों को भी रेखांकित किया है। क्रांति या सैनिक विद्रोह में संविधान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने कहा है कि किसी चुनाव के पहले संविधान समीक्षा समेत संस्थागत सुधार किए जाएंगे। इस सबमें समय लगेगा। सत्ता परिवर्तन के इस शुरुआती समय में अनिश्चितता व्याप्त है। इससे भारत की नई भू-राजनीतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं और अब उसे प्रासांगिक पक्षों से संबंध स्थापित करने होंगे। इन चुनौतियों में शेख हसीना व अवामी लीग से व्यवहार भी शामिल है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

फास्ट फैशन के निहितार्थ

नैतिक रूप से तैयार टिकाऊ वस्त्र हमारे फैशन के केन्द्र में होने चाहिए।

शाइनी शर्मा
(लेखिका शिक्षाविद हैं)

नवीनतम प्रवृत्तियों के आधार पर तेजी से सस्ते वस्त्रों के उत्पादन, यानी 'फास्ट फैशन' ने वैश्विक फैशन उद्योग को बदल दिया है। जारा, एचएंडएम व फारएवर 21 जैसे ब्रांडों ने यह आंदोलन शुरू किया है। इसका उद्देश्य बहुत तेज गति से सस्ते वस्त्र उपलब्ध कराना है। कुछ ही सप्ताह में नई डिजाइनों व स्टोर-रेडी वस्त्रों के कारण लेटेस्ट स्टाइलें बहुत से लोगों, खासकर युवा ग्राहकों तक पहुंच रही हैं। हालांकि, यह फैशन का लोकतांत्रीकरण है, पर इसके गंभीर पर्यावरणीय, सामाजिक व आर्थिक नतीजे सामने आते हैं।

'फास्ट फैशन' माडल तेजी से ग्राहकों से मिल कर सस्ते व ट्रेंडी वस्त्रों का प्रचार करते हैं। बिजनेस की यह रणनीति सक्षम सप्लाई श्रृंखलाओं पर निर्भर करती है जो तेजी से लोकप्रिय शैलियों की नकल करती हैं। इससे ग्राहक लगातार नए उत्पादों से जुड़े रहते हैं। इस दृष्टिकोण से सस्ते फैशन को आगे बढ़ाया हैजिसमें ग्राहकों को विभिन्न ट्रेंड से प्रयोग का अवसर मिलता है और इस पर ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता है। युवा ग्राहकों के लिए अक्सर फैशन आत्माभिव्यक्ति का माध्यम होता है। लेकिन खराब गुणवत्ता और कम जीवन होने के कारण ऐसे वस्त्र अति-उपभोग, बरबादी और पर्यावरणीय नुकसान को जन्म देते हैं।

'फास्ट फैशन' का सबसे बड़ा नुकसान पर्यावरण को होता है। इस उद्योग में ऊर्जा का भारी उपयोग होता है जो वस्त्र उत्पादन और उनके परिवहन के लिए फासिल ईंधनों पर निर्भर करती है। अनुमान है कि फैशन उद्योग विश्व स्तर पर 10 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन का जिम्मेदार है जो सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों तथा समुद्री शिपिंग को मिला कर भी उनसे अधिक है। इसका कारण बड़े पैमाने पर सिंथेटिक रेशों का प्रयोग है जो फासिल ईंधनों से बनते हैं।

इसके साथ ही उनके विनिर्माण व दुनिया भर में वितरण में भी ऊर्जा खर्च होती है। इसके साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर पानी का प्रयोग होता है। यह खासकर काटन के मामले में सर्वाधिक है जो आमतौर से वस्त्रों में प्रयोग होता है। एक किलोग्राम रेशा बनाने में हजारों लीटर पानी खर्च होता है।

इसके साथ ही टेक्सटाइल रंगने और फिनिशिंग में प्रयोग भारी मात्रा में पानी प्रदूषण बढ़ाता है। 'फास्ट फैशन' का पर्यावरणीय फुटप्रिंट कार्बन उत्सर्जन और जल उपभोग से आगे जाता है। 'फास्ट फैशन' सप्लाई श्रृंखलाओं में काम करने वाले कामगार अक्सर खराब कार्यस्थितियों व कम वेतन का शिकार होते हैं। अनेक मामलों में उनके श्रम का दोहन पर्यावरणीय रूप से प्रदूषक गतिविधियों से जुड़ा रहता है।

निर्माता पर्यावरण को नुकसान की चिन्ता किए बिना नियमन कठोरता से लागू नहीं करते हैं। इस प्रकार 'फास्ट फैशन' के सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव एक दूसरे से जुड़े हैं। इन सरोकारों के बावजूद 'फास्ट फैशन' सस्ता होने और लगातार नई शैलियों की चमक के कारण लोकप्रिय बना हुआ है। कम खर्च करने वाले अनेक ग्राहक अपनी खरीद के नैतिक व पर्यावरणीय प्रभावों से परिचित नहीं हैं। लेकिन टिकाऊ फैशन के पक्ष में भी आंदोलन खड़ा हो रहा है जो इन मुद्दों के प्रति बढ़ती जागरूकता से संचालित है। टिकाऊ फैशन मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर जोर देता है, पर्यावरण-हितैषी सामग्रीव नैतिक उत्पादन व्यवहारों का प्रयोग करता है। कुछ ब्रांड 'सर्कुलर इकोनामी' सिद्धान्तों का पालन करते हुए रिसाइक्लिंग, अपसाइक्लिंग व मजबूत उत्पादों की डिजाइनिंग का काम करते हैं।

ग्राहकों को उनकी कपड़ों की पसंद के पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। सरकारों को टेक्सटाइल उत्पादन में कठोर नियमनों को लागू कर रिसाइक्लिंग पहलों पर जोर देना चाहिए। टिकाऊ व्यवहारों को प्रोत्साहन तथा पर्यावरण-हितैषी उत्पादों की मांग को बढ़ावा देने से उद्योग ज्यादा जिम्मेदार उत्पादन विधियों का प्रयोग करेगा। 'फास्ट फैशन' के बजाय टिकाऊ विकल्पों का प्रयोग उद्योग के पर्यावरणीय व सामाजिक नुकसान बचाने के लिए जरूरी है। संक्षेप में कहें तो 'फास्ट फैशन' ने ट्रेंड्स को ज्यादा पहुंच में लाने का काम किया है, पर इसके पर्यावरणीय व सामाजिक नुकसान बहुत अधिक हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वित प्रयासों की जरूरत है जिनमें ग्राहकों, उद्योग प्रमुखों तथा नीति निर्माताओं की सहभागिता जरूरी है ताकि ज्यादा नैतिक व टिकाऊ फैशन व्यवहारों की ओर बढ़ा जा सके।

आप की बात

लैटरल एंट्री

लैटरल एंट्री का विज्ञापन देखते ही विपक्ष ने इसे तुरंत ही आरक्षण विरोध के रूप में लपक लिया और सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा दिया। लेकिन बड़े पेमाने पर विपक्ष को हलचल मचाने के पूर्व ही सरकार ने मोदी के निर्देश पर लैटरल एंट्री के विज्ञापन को वापस ले लिया और यूपीएससी को पत्र लिखकर लैटरल एट्री से नियुक्तियां नहीं करने के निर्देश दिए। इससे लगता है कि सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और वह विपक्ष को बिना वजह उंगली उठाने का कोई मौका देना नहीं चाहती। हालांकि, केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष को आईना दिखाते हुए कहा कि 2014 से पहले भी लैटरल इंट्री में आरक्षण का कोई प्राविधान नहीं था। कहा जाता है कि स्वयं अर्थशास्त्री व प्रोफेसर मनमोहन सिंह लैटरल इंट्री से ही देश के वित्त सचिव बने थे। इसके अलावा उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में भी अनेक लोगों को इसी प्रकार निजी उद्यमों से सरकारी पदों पर आने का अवसर मिला था। मजेदार बात है कि जिन कामों की शुरुआत स्वयं कांग्रेस ने की थी, अब वही काम थोड़ा तेजी से करने पर वह मोदी सरकार की आलोचना कर रही है। वैसे कांग्रेस या विपक्ष की किसी पार्टी ने एक अवधारणा के रूप में लैटरल इंट्री का विरोध नहीं किया है, जबकि वास्तव में यह अनैतिक एवं अनुचित है।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

अमेरिकी चुनाव

अमेरिकी चुनाव में सिर्फ अब ढाई महीने का समय बचा है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के लिए इस हफ़्ते शिकागो में हज़ारों लोग जमा हुए हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले हर चार साल में होने वाला यह कन्वेंशन पिछले सम्मेलनों से थोड़ा अलग है। कमला हैरिस के मैदान में आने से ट्रम्प की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गयीं हैं। ट्रम्प पर हुए कातिलाना हमले के बावजूद उनकी लोकप्रियता में उनके कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसीलिए ट्रम्प ने कमला पर निजी और नस्ली हमला करना शुरू कर दिया है। मगर कमला अपनी भविष्य की आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उन्होंने कॉर्पोरेट कर दर को 21 से बढाकर 28 करने की इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही वे किफायती आवास तक पहुँच के विस्तार, परिवारों के लिए कर छूट में वृद्धि और लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सुनिश्चित करने की बात कर रही हैं। इसके विपरीत ट्रम्प ने कॉर्पोरेट टैक्स 21 से घटाकर 15 फीसद करने की बात की है। इस प्रकार कमला हैरिस ने मध्यवर्ग एवं निम्न मध्यवर्ग का पक्ष लिया है, जबकि ट्रम्प ने अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने की बात कही है। देखें अमेरिकी मतदाता किसे तरजीह देता है।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

यूनुस सरकार की माफी

बांग्लादेश में हिंदू-विरोधी हिंसा पर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं से माफी मांगी है। उनकी सरकार में गृह मंत्रालय के सलाहकार पूर्व ब्रिगेडियर जनरल एमएस हुसैन ने माना है कि हम अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा करने में असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हाथ जोड़कर इसके लिए अपने अल्पसंख्यक भाइयों से दिल से माफी मांगता हूं। अल्पसंख्यक भाइयों की सुरक्षा करना देश के बहुसंख्यक समुदाय का बड़ा फर्ज एवं कर्तव्य है एवं अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हमें इसका विश्व भर में सभी को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा यह हमारे धर्म का भी हिस्सा है कि हम अपने अल्पसंख्यक भाइयों की रक्षा करें। यही कारण है कि मैं इसके लिए अपनी और से हाथ जोड़कर अल्पसंख्यक हिन्दू समुदाय से माफी मांगता हूं। मेरा आग्रह है कि यह बहुसंख्यक आबादी का फर्ज है कि वह अपने अल्पसंख्यक भाइयों की रक्षा एवं सुरक्षा करें क्योंकि आखिर में वे भी तो इसी बंग्लादेश की धरती पर ही जन्मे है तथा हम सब एक साथ.साथ ही यहां बड़े हुए हैं। यूनुस सरकार के गृह मंत्री का यह माफी मांगना निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन अभी बांग्लादेश में स्थिति सामान्य नहीं हुई है तथा हिंदू व अल्पसंख्यक भय के साये में जीने को मजबूर हैं।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

फिल्म उद्योग में महिलायें

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जाहिर करने वाली जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आखिर सार्वजनिक हो गई। रिपोर्ट में दी गई बातें हैरान करती हैं। पहले तो राज्य सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को 5 वर्ष तक दबा कर रखा गया और अंतत: आरटीआई के जरिए भी इसे बाहर लाने में लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। आखिर ऐसी गंभीर रिपोर्टों को सरकारें दबाकर क्यों रख लेती हैं? केवल मलयालम ही नहीं मुंबई व अन्य स्थानों की फिल्म इंडस्ट्रीज के हालत भी इतने ही या इससे भी बदतर हैं। दौलत और शोहरत की चकाचौंध में युवतियां अपना सब कुछ दांव पर लगाकर फिल्म इंडस्ट्रीज में घुसना चाहती है। इस उद्योग में शोषण तो सबका होता है, मगर काम केवल चुनिंदा युवतियों को ही मिलता है। इंडस्ट्री में स्थापित होने के बाद भी कई रूपों में उनका शोषण जारी रहता है। फिल्म उद्योग में महिलाओं का हर प्रकार का शोषण कोई नई बात नहीं है। इसमें अनेक अभिनेता, निर्देशक और निर्माताओं के साथ कभी-कभी राजनेता भी शामिल होते हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक व्यापक संघर्ष की जरूरत है।

–**सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

संपादकीय

असली परीक्षा जम्मू – कश्मीर में है

चुनाव आयोग ने शनिवार को जिस तरह चार में से सिर्फ दो राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान कर कई सवालों को हवा दे दी है, वहीं इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की नीति नीयत और वहां 370 खत्म करने के नतीजों को रेखांकित करने वाले होंगे। क्योंकि आंतकवादग्रस्त इस राज्य में दस साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पिछली बार 2015 में विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। उसके बाद दिल्ली में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जो विपरीत विचारधाराओं की पार्टी का सत्ता के लिए समझौता था। पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद को सीएम बनाया गया। उनके निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा के निर्मलसिंह उपमुख्यमंत्री बने। यह पहला मौका था, जब भाजपा इस राज्य में सरकार में शामिल हुई। मुफ्ती सरकार कैसी चली, यह अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार में शामिल होने से भाजपा को सरकार की कई खामियां पता चल गई। आंतकवादियों के साथ पीडीपी व अन्य स्थानीय दलों के कैसे रिश्ते हैं, यह पता चला। आतंकियों की मदद करने वाले अलगाववादियों के कार्यशैली पता चली। भाजपा ने एक तयशुदा रणनीति के तहत 2018 में मुफ्ती सरकार गिरा दी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। जब 2019 में भाजपा भारी बहुमत से सत्ता में लौटी तो मोदी सरकार ने भाजपा और संघ के बहुप्रतीक्षित एजेंडे को पूरा करते हुए कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया। जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केन्द्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख को अलगकर नया केन्द्रित शासित प्रदेश बनाया गया। कश्मीर घाटी में कर्फ्यू लगा दिया और अलगाववादियों के पूरे नेटवर्क को सख्ती से तोड़ा गया। आंतकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस को खुली छूट दी गई। इसका नतीजा धीरे धीरे दिखने लगा। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी पूरी तरह बंद हो गई। स्थानीय लोगों द्वारा आतंकियों को समर्थन देने की मात्रा में बहुत कमी आई। आंतकी हमलों की संख्या भी घट गई। कश्मीर में पर्यटन बहुत बढ़ गया। स्थानीय लोगों के जीवन में शांति और खुशहाली नजर आने लगी। राज्य में विधानसभा सीटों का नए सिरे से परिसीमन हुआ। इसके बाद सीटों की संख्या 87 से बढ़कर 90 हो गई। साथ ही विस में 5 सीटें मनोनीत होंगी। इसके अलावा राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में 'अलग' होने की भावना काफी कमजोर पड़ी। भले ही राजनीतिक तौर पर स्थानीय कश्मीरी भले संतुष्ट न हों, लेकिन घाटी में अमन से उनकी जिंदगी में सुकून बढ़ा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग राज्य में चुनी हुई सरकार चाहते थे और उनकी यह मांग भी है कि जम्मू कश्मीर को पहले की तरह पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, जहां सर्वोच्च अदालत ने केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि हर हाल में सितंबर के पहले राज्य में चुनाव कराए जाएं। उसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य में तीन चरणों में विस चुनाव की घोषणा की। इसके पूर्व 2024 के लोकसभा चुनाव में कश्मीरियों ने आतंकी धमकियों के आगे न झुकते हुए बंपर मतदान किया। इससे भी सरकार पर दबाव बना कि वह जल्द से जल्द राज्य में विस चुनाव कराएं। अब चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन इसमें मतदाता का रूख क्या होगा, क्या वो राज्य में धारा 370 की समाप्ति पर अपनी मोहर लगाएगा या नहीं, यह देखने की बात है।

खुद को दोहराने को तैयार इतिहास

2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक तनाव बढ़े हैं। जिन राज्यों में उन्हें विधानसभा के चुनाव में भारी बहुमत मिला था और उन राज्यों में भी जिनमें मुख्यमंत्री को श्री नरेंद्र मोदी ने सीधे पर्ची से नाम जद किया था उसको लेकर भी आम स्वीकार्यता नहीं थी। यद्यपि विधानसभा के चुनाव के समय केंद्र के चुनाव नहीं हुए थे इसलिए भाजपा का नेतृत्व और विशेषतः राज्यों के मुख्यमंत्रीपद के दावेदार प्रधानमंत्री की ताकत व प्रचारित लोकप्रियता से भयभीत थे।

रघु ठाकुर

एक आम राय यह थी कि भाजपा को विशाल बहुमत मिलेगा और अयोध्या में रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने अबकी बार 400 के पार के नारा का उद्घोष किया था इससे भी दल के भीतर व बाहर के लोग भयभीत थे। और विशेषता उनकी पार्टी के अंदरूनी उनके प्रतिद्वंदी लोग। परंतु उस समय वे बोलने का साहस नहीं कर सकते थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब भाजपा घटकर 240 पर रह गई और मोदी मिथ टूट गया तो अब अंदर के विरोधियों ने भी कुछ बोलने का साहस दिखाना शुरू किया है। भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान और उत्तर प्रदेश से विशेष आघात लगा है। कोई भी भाजपा का नेता या आम जानकार व्यक्ति यह मानने को तैयार नहीं था की उत्तर प्रदेश में भाजपा को 60 से कम सीट मिलेंगी और इसी प्रकार राजस्थान में भी लगभग अधिकांश सीटों के पाने की उम्मीद थी, जैसा कि पिछली बार हुआ था। परंतु इन दोनों राज्यों ने न केवल श्री नरेंद्र मोदी जी को निराश किया है, बल्कि उनके थोथे नारे 400 के पार की पोल खोल दी है।

यद्यपि श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं परंतु यह जोड़-तोड़ की लंगड़ी सरकार है जिसमें दो सहयोगी दलों की संख्या महत्वपूर्ण है और इस परिस्थिति में उनके अंदर का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद की जवाबदारी लेने को तैयार नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था-मैं नहीं बनना चाहता परंतु उन्हें उनके पार्टी और सहयोगी दलों ने बाध्य किया। श्री मोहन भागवत का एक बयान अवश्य मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी लोग पूरी ताकत से श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग करें। उनका यह बयान वास्तविक था या समय की लाचारी का बयान था यह कहना कठिन है। एक घटना तो यह महत्वपूर्ण हुई है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य कई प्रदेशों में राजपूत समाज ने श्री मोदी के खिलाफवोट दिया है जो अभी तक आम तौर पर भाजपा व संघ का समर्थक था। चुनाव के पहले से ही एक अभियान शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत पहले गुजरात से हुई थी और वह श्री पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के आधार पर हुई थी। हालांकि श्री रूपाला ने दो बार सार्वजनिक रूप से माफी मांगी परंतु राजपूत समाज ने ना उन्हें माफकिया और ना ही मोदी को माफकिया तथा भाजपा के खिलाफ भी वोट दिया।

उत्तर प्रदेश में भी बताया जाता है की राजपूत समाज ने आम तौर पर भाजपा के खिलाफही वोट दिया और कहा जाता है कि श्री योगी आदित्यनाथ की भी इच्छा यही थी कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ज्यादा सीटें हारे। क्योंकि उन्हें यह खतरा हो गया था कि, अगर भाजपा को विशाल बहुमत मिलता है तो उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके भी कुछ छुट पुट प्रमाण भी मिले हैं परंतु किसी बाहरी व्यक्ति का ज्यादा कहना संभव नहीं है। हालांकि जो घटनाक्रम हुआ है उससे यही निष्कर्ष निकलता है। चुनाव के परिणाम आने के बाद भाजपा की सांसदों की संख्या भी कम हुई और श्री नरेंद्र मोदी भी हारते-हारते बचे। वस्तुतः उनकी जीत मात्र 1 लाख के वोटों से हुई है जबकि उनके लोगों का दावा 6 लाख वोटों से जीतने का था। आरंभ के चार-पांच राउंड में भी वह पीछे थे और यह एक प्रकार से उनकी गणितीय हार तो नहीं थी परंतु नैतिक हार तो है। इन घटनाओं के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा में तनाव बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र का हाथ है। एक तो भाजपा में हार के कारणों पर चर्चा शुरू हुई तो यह कहा गया की लोकसभा के टिकट वितरण में श्री अमित शाह ने मनमानी की। जिन 12 लोगों को टिकट देने की सिफारिश श्री योगी ने की थी उन्हें टिकट नहीं दिए गए। इससे भी श्री योगी के मन में यह खतरा पैदा हुआ की यह उन्हें हटाने की तैयारी है और हो सकता है कि योगी ने अपनी ताकत अप्रत्यक्ष रूप से उन दोनों व्यक्तियों को कमजोर करने में लगाई हो जो उन्हें हटाने के के लिए षड्यंत्र कर रहे थे।

अभी भी ऐसा लगता है कि भाजपा में कुछ ठीक-ठाक नहीं है, विशेषतः उत्तर प्रदेश में। झारखंड के गुमला में श्री मोहन भागवत ने बयान दिया है कि कुछ लोग भगवान बनना चाहते हैं और वह अपनी असलियत भूल जाते हैं। भगवान बनने को क्या करना पड़ता है यह भूल जाते हैं। लोगों ने उनके इस बयान को श्री मोदी के चुनाव के पूर्व दिए गए बयान से जोड़कर देखा है जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं भगवान के द्वारा भेजा गया हूं यद्यपि जैविक रूप से नहीं यानी वह अपने आप को एक प्रकार का अवतार जैसा सिद्ध कर रहे थे।

दूसरी घटना हुई है कि श्री योगी मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें दोनों उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य और श्री बृजेश पाठक शामिल नहीं हुए परंतु दिल्ली में भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक उनके केन्द्रीय कार्यालय में हुई जिसमें श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह आदि भाजपा आला कमान शामिल हुए थे उसमें मुख्यमंत्री श्री योगी के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री भी शामिल हुए। जबकि मध्य प्रदेश राजस्थान में भी दो दो उपमुख्यमंत्री हैं, छत्तीसगढ़ में भी दो उप मुख्यमंत्री हैं परंतु इन राज्यों के उपमुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए और शायद उन्हें बुलाया भी नहीं गया हो। अकेले उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों को बुलाने का मतलब यही संकेत देता है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और विशेषतः प्रधानमंत्री और उनकी जमात अब श्री योगी को गिराने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद 10 विधानसभाओं के उप चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है और तब तक शायद कोई परिवर्तन या बदलाव की बात ना हो परंतु अगर इन उपचुनाव में योगी के विपरीत परिणाम आते हैं तो यह उनके खिलाफ मुहिम के लिए एक ताकतवर तर्क होगा कि श्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा भी नहीं जीता पाए ना उपचुनाव जिता पाए और भविष्य में भी होने वाले चुनावों को भी वह नहीं जिता पाएंगे।

ऐसा लगता है कि भाजपा का इतिहास दोहराया जा रहा है। वैसे भी कहावत है कि इतिहास अपने आप को कुछ समय के बाद दोहराता है। स्व. अटल बिहारी वाजपेई जब प्रधानमंत्री बने थे और लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उस समय श्री लालकृष्ण आडवाणी जो भीतर से प्रधानमंत्री पद के इच्छुक थे। बताया जाता है कि उनके इशारे पर स्वर्गीय कल्याण सिंह ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई को हराने का प्रयास किया था। जो उनकी बिरादरी के मतदान केंद्र थे उनमें अधिकांश से स्व अटल बिहारी वाजपेई हारे थे। यह तो उन्होंने अपनी केंद्रीय सरकार के अधिकारों का इस्तेमाल कर स्व जगमोहन जो उस समय नगरीय विकास मंत्री थे के माध्यम से दिल्ली के शिया नेताओं के साथ एक समझौता किया। ओखला के व जामिया मिलिया पास की मस्जिद जिसके कब्जे मे बहुत सी सरकारी जमीन थी और डीडीए ने मस्जिद के बाहर ताला लगा दिया था वह खुलवाकर उसकी चाबी मस्जिद के इमाम साहब को सौंप दी थी। परिणाम स्वरूप लखनऊ के उनके समर्थकों ने पूरी ताकत से स्व अटल बिहारी वाजपेई को वोट दिया और वह इसी प्रकार हारते-हारते बचे थे जिस प्रकार 2024 में बनारस से श्री नरेंद्र मोदी। अटल जी उस हार के खतरे को और उस षड्यंत्र को पचा नहीं पाए थे और जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भाजपा नेतृत्व के ऊपर दवाब डाला कि स्व कल्याण सिंह को हटाया जाए। श्री आडवाणी तत्कालीन अध्यक्ष स्व कुशाभाऊ ठाकरे और उनका समूह उन्हें हटाने के पक्ष में नहीं था। तथा पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में जब अटल जी की ओर से यह प्रस्ताव आया तो उनके समकक्ष केंद्रीय नेतृत्व के सदस्यों ने कहा कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जाए। पर इसका उत्तर बाद में श्री अटल बिहारी वाजपेई ने दिया और अगली बैठक में कहा श्कोई बात नहीं कि अगर आप मुख्यमंत्री को नहीं हटा सकते तो न हटाएं परंतु प्रधानमंत्री को तो हटा सकते हैं।य्य यह बात मुझे स्व कुशाभाऊ ठाकरे ने खुद बताई थी। और फिर स्व अटल बिहारी वाजपेई के संदेश को समझ कर बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने श्री कल्याण सिंह को हटाने का फैसला किया। हालांकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ और आगामी चुनाव में स्व मुलायम सिंह की वापसी हुई। संभव है कि श्री मोदी की पहल पर भाजपा भी इसी प्रकार का निर्णय देर सबेर करें और अपने स्थायित्व की स्वत विरोधी बनने का काम करें। यह स्थिति दिल्ली में भी देखी जा चुकी है जहां पर पहले मुख्यमंत्री भाजपा के स्व मदनलाल खुराना बने थे, क्योंकि वह स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के समर्थक माने जाते थे अतरू आडवाणी कैंप की ओर से उन्हें हटाया गया और फिर बाद में श्री साहिब सिंह वर्मा तदउपरांत श्रीमती सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी परंतु फिर भाजपा की सरकार नहीं बनी।

शायद इतिहास अपने आप को दोहराने के लिए तैयार है। देखना है कि भाजपा नेतृत्व, संघ का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी और उनका समूह क्या चुनता है? वैसे भी उप्र में अब सरकारी तंत्र का दबदबा कम हो रहा है । मंत्रीमंडल भीतर से दो हिस्सों में विभाजित है। मोदी शाह की जोड़ी ने पिछले दस वर्षों में विरोधियों की सरकारें जिस प्रकार षड्यंत्रों या अन्य असंवैधानिक तरीकों से गिराई हैं उसने उनकी छवि और जन समर्थन को कम किया है तथा अब अगर भाजपा सरकारें गिरेंगी तो एक बड़ा जन समूह प्रति हिंसात्मक खुशी मनाएगा । भाजपा का हिंदू कार्ड भी अब लगभग बेअसर हो रहा है। और हिंदू समाज का एक बड़ा हिस्सा भी यह मानने लगा है कि यह भाजपा का राजनैतिक प्रचार मात्र है। कुल मिलाकर उप्र में भाजपा अब कठिन दौर में है और उप्र जाने का मतलब देश से विदाई होती है, जिसकी शुरुआत इस लोक सभा से हो चुकी है।

अध्यात्म

मन लगा कर काम करने से मिलती है सफलता

एक गांव एक कुम्भार रहता था ! वह मिट्टी के बर्तन और तरह तरह के सामग्री बनाता था ! उसे मिट्टी के सामग्री बनाना बहुत ही अच्छा लगता था और वह अपने काम में हमेशा खुश रहता था ! मिट्टी के बर्तन का काम नही मिल पाने के कारण वह अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था ! परिवार की दशा बिगड़े देख कर उसे अपना मन पसंद का काम छोड़ना पड़ा और वह शहर में काम की तलाश में आया ! शहर में उसे छोटा सा काम मिल गया ! वह अपने मालिक का छोटा-मोटा काम करता था और उससे जो भी तनखा मिलती थी उससे वह अपने गांव में घर का पालन पोषण करता था ! अपने परिवार का दो वक्त का भोजन करा सके उतना तो वह कमा ही लेता था ! एक बार मालिक के बच्चे का जन्मदिन होता है तो वह उस व्यक्ति को भी आमंत्रित करता है ! व्यक्ति सोचता है कि मैं बच्चे के लिए मिट्टी का खिलौना बना देता हूं और उसे मैं वह भेट कर दुगा ! वह व्यक्ति उस बच्चे को मिट्टी का खिलौना देता है ! वह छोटा सा बालक उस मिट्टी के खिलौनों से इतना खुश होता है की मालिक भी खुश हो जाते हैं ! मालिक उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुमने इतना प्यारा खिलौना कहां से लाया ? वह कहता है कि, मालिक जी जहां मैंने खुद ने बनाया है ! मालिक आश्चर्यचकित हो जाता है और एक-दो दिन विचार में पड़ जाता है कि जो मेरे साथ कम पगार में काम कर रहा है वह करोड़ का मालिक बन सकता है ! मालिक उसे कहते कि आज से तू मेरे छोटे-मोटे काम नहीं दिखेगा ! हम खिलौना का भी व्यापार करेंगे मेरा पूरा सहयोग आपके साथ होगा ! यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों खुशी के आंसू आ जाते है और वह सच्चे लगन से मालिक के साथ काम करता है और वह भी बहुत बड़ा मालिक बन जाता है ! शिक्षाप्रद प्रेरक प्रसंग से सिख मिलती है की जिस व्यक्ति में जुनून हो काम करने का उसका हर काम चमत्कार से कम नहीं होता ! उसका काम ही इतना प्रभावशाली होता है की उसका हुनर उस काम में झलकता है ! जिस व्यक्ति में जो भी पैशन है जो भी टैलेंट है अगर उसे सही मौका मिले तो वह हर एक चीज हासिल कर सकता है जो उसे सपने भी नहीं सोचा हो !

राशन से पोषण तक : पोषण सुरक्षा के लिए उचित दर की दुकानों का पुनर्अभिविन्यास

संजीव चोपड़ा

चमन प्रकाश, एक उचित दर दुकान (एफपीएस) डीलर हैं जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के प्रताप विहार ब्लॉक में पिछले 11 वर्षों से खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं। इस क्षेत्र में एक मात्र एफपीएस डीलर होने के कारण वे 1,500 से अधिक परिवारों को सेवा प्रदान करते हैं। समुदाय में एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधानों के दौरान और भी महत्वपूर्ण हो गई, जब लाभार्थी अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़ी पात्रताओं पर बहुत अधिक निर्भर थे। प्रकाश, देश भर के उन 5.3 लाख डीलरों में से एक हैं, जो अंतिम छोर तक खाद्यान्न वितरण एजेंट के रूप में कार्य करते हैं और पीडीएस के माध्यम से 80 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इन एफपीएस को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिया जाता है और इनका प्रबंधन भी किया जाता है तथा डीलरों को अपनी दुकानों पर प्रति क्विंटल लेन-देन के आधार पर डीलर मार्जिन के माध्यम से मुआवजा मिलता है। तथापि, एफपीएस के माध्यम से खाद्यान्न वितरण प्रत्येक माह 7-10 दिनों की अवधि में केंद्रित होता है। माह के शेष दिनों में, ये दुकानें कम उपयोग में रहती हैं, जिससे डीलरों को कोई अतिरिक्त आय का अवसर नहीं मिलता है। एफपीएस में भौतिक और मानव संसाधनों का इस प्रकार से उपेष्टीतम उपयोग से, आवश्यक अंतिम छोर तक वितरण नेटवर्क की आर्थिक व्यवहार्यता और स्थिरता को खतरा पहुंचता है।

पिछले एक दशक में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एफपीएस को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप लागू किए हैं। सभी एफपीएस में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) डिवाइस लगाए गए हैं, और लगभग 100त्न लेन-देन अब आधार द्वारा बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित होते हैं। खाद्यान्नों का सही वजन सुनिश्चित करने के लिए ई-पीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसे 2024 के अंत तक पूरा किया जाना है। राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मॉडल एफपीएस विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें लाभार्थियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी जैसी सुविधाएं हों। राज्य सरकारों को एफपीएस डीलरों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवाओं और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) सेवाओं जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया गया है। जनवरी, 2024 में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में एफपीएस को ऑनबोर्ड करने के लिए एक प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य एफपीएस के ग्राहक आधार को विस्तार देना और उसकी व्यहवहार्यता को बढ़ाना है। यद्यपि, एफपीएस की आर्थिक स्थिरता डीलरों और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

एक अन्य गंभीर चुनौती लाभार्थियों की पोषण सुरक्षा रही है। वर्तमान में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग केवल पीडीएस के माध्यम से ऊर्जा देने वाले (एनर्जी रिच) अनाज (चावल और गेहूं) प्रदान करता है, जबकि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पोषण संबंधी कमियों का सामना कर रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़े उच्च एनीमिया दरों को दर्शाते हैं= 6 से 59 महीने की आयु के बच्चों में 67.1त्न, 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में 57त्न और 15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों में 25त्न। इसके अतिरिक्त, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन के मुद्दे बने हुए हैं। अतः, एफपीएस डीलरों के लिए आय के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ आहार विविधीकरण के माध्यम से जनसंख्या के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने जैसे दोहरे दृष्टिकोण (डुअल अप्रोच) की आवश्यकता है।

इन दो चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 60 एफपीएस-गाजियाबाद, जयपुर, अहमदाबाद और हैदराबाद प्रत्येक में 15 एफपीएस को'जनपोषण केंद्र'(जेपीके) में परिवर्तित करने के लिए एक प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम शुरू किया है। ये केंद्र, अन्य मदों के अलावा, खुले बाजार की तुलना में प्रतिस्पर्धी कीमतों पर पोषक तत्वों से भरपूर वस्तुओं जैसे मिलेट्स (श्री अन्न), दालें, खाद्य तेल और सोयाबीन की एक विविध रेंज पेश करेंगे। जेपीके का उद्देश्य लाभार्थियों और स्थानीय आबादी के बीच पोषण संबंधी अंतर को दूर करते हुए डीलरों के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोत और बेहतर मार्जिन प्रदान करना है।

एफपीएस का जेपीके में बदलाव चार प्रमुख स्तंभों पर निर्भर करता है= द्ब) एफपीएस डीलरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, द्बद्ब) चालान वित्तसपोषण (इन्वॉइस फाइनैन्सिंग) के माध्यम से एफपीएस डीलरों के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच, द्बद्बद्ब) बी2बी एग्रीगेटर्स के माध्यम से बाजार संपर्क, और द्ब1) पोषण संबंधी साक्षरता को बढ़ावा देना।

एफपीएस डीलरों की क्षमता बढ़ाने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कौशल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, पोषण संबंधी साक्षरता और व्यवसाय प्रबंधन पर केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना है। प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम में भाग लेने वाले एफपीएस डीलरों के लिए प्रशिक्षण सत्र मई और जून 2024 के दौरान दो बैचों में आयोजित किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने %एफपीएस-सहाय%, एक मोबाइल एप्लिकेशन जो एफपीएस डीलरों को गैर-पीडीएस वस्तुओं की खरीद के लिए इन्वॉइस फाइनैन्सिंग की अनुमति देता है, को बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक और अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रमुख बी2बी एग्रीगेटर्स को इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि एफपीएस डीलरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाईई चैन) लिंकेज स्थापित करने में सहायता की जा सके। इसके अलावा, एफपीएस डीलरों को पोषण मित्र के रूप में सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो लाभार्थियों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन और संतुलित भोजन बनाने के लाभों पर बुनियादी मार्गदर्शन प्रदान कर रहें हैं। इन चार स्तंभों के माध्यम से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एक स्थायी मॉडल के लिए आधार तैयार कर रहा है जो डीलरों और उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों दोनों को लाभान्वित करता है।

इस पहल के साथ, चमन प्रकाश का पेशेवर जीवन परिवर्तन के लिए तैयार है, जिससे उन्हें अपनी पेशकशों में विविधता लाने, अपनी आय बढ़ाने और समुदाय के पोषण स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायता मिलेगी। यह विकास न केवल उनकी आजीविका को बढ़ाएगा बल्कि पूरे भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने में एफपीएस की महत्वपूर्ण भूमिका को भी सुदृढ़ करेगा। (लेखक भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव हैं)

आज का कार्टून

राशिफल

मेष
आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ अच्छे समय का आनन्द लेंगे। नया भवन या वाहन खरीदने का विचार बना सकते हैं।

वृषभ
जीवनसाथी से अपने मन की बातें शेयर करना उत्तम होगा। नयी जॉब को लेकर योजना बना सकते हैं। विचारों में लचीलापन हमेशा बनाकर रखें।

मिथुन
पुराना रुका हुआ काम आपको तनाव का अनुभव करायेगा। अपरिचित लोगों पर ज्यादा विश्वास न करें। दिनचर्या थोड़ी असन्तुलित रहेगी।

कर्क
दिन आपके लिये काफी अच्छा रहेगा। आपके स्वभाव में परोपकार की भावना रहेगी। आप जरूरतमन्द लोगों की मदद करेंगे। व्यापार में बढ़ोत्तरी होगी।

सिंह
अपने करियर को लेकर थोड़ा असन्तुष्ट रहेंगे। परिवार के लोग आपका काफी ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर ही आप अपने सभी कार्य निष्ठापूर्वक करेंगे।

कन्या
पुरुष जातकों को महिलाओं के सहयोग से लाभ मिल सकता है। बच्चे आज मस्ती के मूड में रहेंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे जातक लम्बी छुट्टी की मांग कर सकते हैं।

तुला
आज आपको अचानक धन खर्च करना पड़ सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शरीर में किसी तरह का संक्रमण परेशान कर सकता है।

वृश्चिक
आज अपने विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। व्यवसाय में बड़ी बिक्री होने की सम्भावना बन रही है। गम्भीर विषयों के अध्ययन का प्रयास करेंगे।

धनु
आज आपको कुछ नकारात्मक समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य थोड़ा नरम-गरम रहेगा। शब्दों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें इससे विवादों से बचे रहेंगे। अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर न करें।

मकर
आज सभी काम आपकी आशा के अनुरूप होते रहेंगे। व्यवसाय में पुराने अनुभवों का आप बेहतर लाभ उठा पायेंगे। स्वादिष्ट भोजन व व्यञ्जनों का आनन्द उठायेंगे।

कुंभ
विरोधी आपके विरुद्ध कुछ गलत बातें फैला सकते हैं। घरेलू खर्च बढ़ने से आपका बजट गड़बड़ा सकता है। नये प्रोजेक्ट्स को लेकर मित्रों से चर्चा कर सकते हैं।

मीन
राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद मिल सकता है। व्यवसाय में आपको पहले की गयी मेहनत का उत्तम परिणाम प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहने वाला है।

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति चिंताजनक

5 वर्षों के बाद आखिरकार जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो ही गई। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। रिपोर्ट हैरान करने वाली है। इस रिपोर्ट को सामने लाने के लिए जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ी, वह भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कमिटी का गठन 2017 में मलयालम फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री के अपहरण और सेक्शुअल असॉल्ट की घटना के बाद किया गया था। कमेटी ने 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदनों के जरिए पांच साल के लंबे और कठिन संघर्ष के बाद यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में लाई जा सकी। रिपोर्ट का कंटेंट देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि क्यों वहां की ताकतवर लॉबी इसे सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ थी और क्यों उसने इसे लोगों की नजरों से छुपाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। रिपोर्ट में कम से कम 17 तरह के शोषण गिनाए गए हैं, जिनसे केरल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं को गुजरना पड़ता है। इनमें लेडीज टॉयलेट और चेंजिंग रूम जैसी सुविधाओं की कमी और पारिश्रमिक में भेदभाव से लेकर काम के बदले में सेक्स की डिमांड तक तमाम तरह के शोषण शामिल हैं। रिपोर्ट में ठीक ही कहा गया है कि सेक्शुअल हरासमेंट ऑफ विमिन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल) एक्ट 2013 जैसे कानून और इसके तहत अनिवार्य बताए गए इंटरनल कमेटी गठित करने जैसे प्रावधान इन मामलों में ज्यादा मदद नहीं करते। इसकी एक वजह यह है कि ये वर्कप्लेस पर हैरासमेंट की बात करते हैं जबकि फिल्म इंडस्ट्री में शोषण अक्सर काम मिलने से पहले ही शुरू हो जाता है। दूसरी बात यह कि शोषण करने वाले लोगों की लॉबी इतनी ताकतवर है कि शिकायत करने की हिम्मत दिखाने पर भी करियर खत्म हो जाता है। भले जस्टिस हेमा कमिटी की यह रिपोर्ट सिर्फ केरल फिल्म इंडस्ट्री की बात करती हो, अन्य फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी ऐसे आरोप लगते रहे हैं। इसे भी महज संयोग नहीं कहा जा सकता कि जिस समय यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, कोलकाता में एक डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना को लेकर पूरा देश उद्वेलित है। ऐसी घटनाएं अलग-अलग इलाकों और पेशों में महिलाओं की असुरक्षा का सवाल पेश करती रहती हैं। ऐसे में कोई एक कानून, कोई एक आयोग या प्राधिकरण इसका इलाज नहीं हो सकता। पुलिस-प्रशासन, कानून-अदालत और परिवार-समाज सभी स्तरों पर दीर्घकालीन प्रयास ही बेहतरी सुनिश्चित कर सकते हैं।

सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री पर हंगामा क्यों?

डॉ. आरके सिन्हा

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों में अहम पदों को संभालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में लैटरल एंट्री या कहें कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए एक विज्ञापन अखबारों में निकलवाया था। इसी को लेकर देशभर में गैर-जरूरी हंगामा खड़ा हो गया या निहित स्वार्थ से भरे लोगों द्वारा खड़ा कर दिया गया था। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो लैटरल एंट्री से नियुक्ति न करे। कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

बात बस इतनी सी थी कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ पदों पर काम करने के लिए प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों की तलाश है। इन पदों में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के शामिल हैं, जिनमें कुल 45 पदों पर भर्ती होनी है। इस विज्ञापन के छपने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सबसे ज्यादा हंगामा काट रहे थे। कह रहे थे कि केन्द्र सरकार सरकारी विभागों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को भर्ती करना चाहती है। हालांकि हमेशा की तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए किसी तरह के प्रमाण देने की जरूरत तक नहीं महसूस नहीं की। वे वैसे भी राहुल गाँधी जी हवाई बातें-दावे करने में माहिर हैं।

काश, राहुल गांधी को यह पता तो होगा ही कि देश के दस सालों तक प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह को देश का वित्त सचिव तक लेटरल एंट्री के माध्यम से ही बनाया गया था। वह तो तब तक तो वे दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे। इसी तरह से मोंटेक सिंह अहलूवालिया को भी कांग्रेस सरकार ने ही योजना आयोग का चेयरमैन बना दिया था। उनकी नियुक्ति भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से डॉ मनमोहन सिंह की खुद की हुई थी। इसलिए यह कहना सरासर गलत है कि मौजूदा सरकार कुछ विभागों के लिए बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी देकर गलत कर रही है।

न जाने क्यों यूपीएससी के इस कदम ने नौकरशाही में लैटरल एंट्री पर बहस छेड़ दी। राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि यूपीएससी की भर्ती की यह प्रक्रिया ₹पीछे के दरवाजे से भर्ती₹ है। इसे अंग्रेजी में बैक एंट्री भी कहा जा रहा है। अब कांग्रेस के नेताओं से यह तो पूछा ही पूछा जाना चाहिए कि सैम पित्रोदा और रघुराम राजन कौन थे ? उन्हें किस आधार पर सरकार में लैटरल एंट्री के तहत ऊंचे पदों पर नौकरी दी गई थी?

अब जान लेते हैं कि लैटरल एंट्री होता क्या है? दरअसल नौकरशाही में लेटरल एंट्री का मतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) जैसे पारंपरिक सरकारी सेवा कैडर के बाहर के व्यक्तियों को सरकारी विभागों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों पर उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर भर्ती करना। इससे पहले लैटरल एंट्री के जरिए 2018 में पहली बार रिक्तियों की घोषणा की गई थी। लैटरल एंट्री करने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर तीन से पांच साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन और सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर विस्तार की संभावना होती है। इन व्यक्तियों से ऐसी विशेषज्ञता लाने की उम्मीद की जाती है जो शासन और नीति कार्यान्वयन में जटिल चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सके।

यूपीएससी के हालिया विज्ञापन से साफ था कि उसे तीन स्तरों पर योग्य उम्मीदवारों की तलाश थीः संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। इन पदों पर तैनात अफसर अक्सर विभागों के भीतर विशिष्ट विंगों के प्रशासनिक प्रमुख या उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं और प्रमुख निर्णय लेने वाले होते हैं। लैटरल एंट्री के पीछे सरकार का तर्क यह रहा है कि नई प्रतिभा लाना और प्रशासन में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना।

आप गौर करें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलते हैं, वे तब सरकार को सदैव कोसते ही रहते हैं। लोकतंत्र में सदा स्वस्थ वाद-विवाद और सार्थक संवाद जारी रहना चाहिए। हमेशा ही बेवजह विवाद नहीं खड़े करने चाहिए। खड़गे जी कह रहे हैं कि लैटरल एंट्री से सरकारी नौकरियों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को नुकसान होगा। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी लैटरेल एंट्री पर आपत्ति है। अब इन ज्ञानी नेताओं को कोई बताए कि लैटरल एंट्री का विचार तो सर्वप्रथम कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान ही विकसित किया गया था। लैटरल एंट्री पर महाभारत करने वालों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है। इसलिए इस मसले पर विवाद खड़ा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसा करने वाले संवैधानिक संस्थाओं पर आघात कर रहे हैं।

यह तो कहना पड़ेगा देश में सियासत के संसार का माहौल बहुत विषाक्त हो चुका है। सरकार के हरेक कदम का विपक्ष माखौल उड़ाता रहता है या उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता रहता है। अगर यही रणनीति विपक्ष अपनाता रहा तो सरकार अपना कोई काम कर ही नहीं सकेगी। यकीन मानिए कि विपक्ष से यह कोई नहीं कह रहा है कि वह सरकार को उसकी किसी जन विरोधी नीतियों पर न घेरे। अवश्य घेरे और उसकी जितनी चाहे निंदा करे। पर विपक्ष को सरकार के फैसलों की सोच-समझकर ही आलोचना करनी चाहिए। अगर उसने यह न किया तो उसकी जनता के बीच छवि तार-तार हो जाएगी और वह एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने से वंचित हो जायेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मोदी के लक्ष्य और सियासी 'चक्रव्यूह'

महेश खरे

(वरिष्ठ पत्रकार)

जून माह में मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही कैबिनेट और राज्यमंत्री के मसले पर असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। वरिष्ठता का मुद्दा उठा कर महाराष्ट्र के प्रफुल्ल पटेल ने राज्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र के ही शिंदे गुट से भी मंत्री पद को लेकर तल्ख स्वर उठे। समय रहते उन्हें समझा लिया गया। आंध्र की टीडीपी में भी मंत्री पद के कोटे पर खुसर फुसर हुई लेकिन एनडीए की सत्ता के नए दौर के ताकतवर साथी चंद्रबाबू नायडू को तो अपने राज्य के विकास और राजधानी अमरावती के लिए केन्द्र से मोटी रकम चाहिए। इसलिए उन्होंने इस तरह की चर्चा को हवा ही नहीं लगने दी। नतीजतन टीडीपी नेताओं का असंतोष कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। ऐसी चचाएं बिहार के मित्रों के मन में भी खदबदाती दिखीं लेकिन सियासी नफा नुकसान के गुणा- भाग में जब अपने पाले में नफा दिखता है तब बोल भी उसी अनुसार निकलने लगते हैं। मित्र दल यह समझ गए हैं कि इस समय हर हाल में मोदी के साथ रहने में ही ज्यादा भलाई है। यही कारण है कि बड़े से बड़े विवादों में भी सरकार और एनडीए में खामोशी बनी रही है। विरोध छन छन कर बाहर उतना ही आया जितनश आटे में नमक होना चाहिए। फिर चाहे मामला उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति (लेटरल एंट्री) का हो अथवा वक्फ बोर्ड संबंधी विधेयक का।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छुप कर खेल नहीं खेलते। उनके लक्ष्य और इरादे खुली किताब की तरह हैं। गुजरात में भी उनकी कार्यशैली को लोगों ने टकटकी लगाकर देखा और अब दस साल से केन्द्र में भी उनके काम जनता के सामने हैं। लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम ग्यारहवें संबोधन में भी उन्होंने अपने इरादों की स्पष्ट तस्वीर रख दी है। इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी सहयोगियों के भरोसे जरूर हैं पर कमजोर नहीं हैं। तीसरे कार्यकाल के शुरूआती दौर में जो कुछ घटा या घट रहा है उसे देखकर मोदी को कमजोर समझना बहुत बड़ी भूल होगी। राजनीति में वैसे भी जो कुछ दिखाई देता है हकीकत उसके उलट होती है। मेरे विचार से दस साल बाद संसद में मजबूत बन कर उभरे प्रतिपक्ष को हाल के सियासी घटनाक्रमों से फिलहाल ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है।

समझदार और परिपक्व राजनेता परिस्थितियों से सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। जिनका लक्ष्य बड़ा होता है वे समय-समय पर वक्त की नजाकत को परखते रहते हैं और जो नतीजे निकलते हैं उसी के अनुसार भावी राजनीति के 'चक्रव्यूह' भी रचते रहते हैं। राजनीति की चौसर और उसके मोहरे सामान्य से कुछ अलग ही होते हैं। इसमें कभी-कभी प्यादे भी वजीर की चाल चल लेते हैं। कभी वजीर भी एक घर चल कर घिरता हुआ नजर आता है। जीतने वाला भी हार जाता है और हारने वाला भी जीत जाता है।

मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बनी एनडीए सरकार को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। बीते दस साल की बात अलग थी। तब भाजपा को संसद में स्पष्ट बहुमत था। मोदी सर्वशक्तिमान थे। जो चाहे कर सकते थे। अब 240 के अल्पमत के साथ पांच साल एनडीए सरकार चलाने में वजीर को अपने कदमों की पदचाप को परखते और उस पर कान लगाए रहना जरूरी है। सियासी चालों के नतीजों का पूर्वानुमान लगाना और समझना होगा। बीते ढ़ाई- तीन महीनों से यही तो हो रहा है। सरकार के मित्र दल भी देश को समय-समय पर एहसास कराते रहते हैं कि यह किसी एक दल की नहीं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार है। गठबंधन की सरकार में किसी एक की नहीं, सामूहिक सहमति से काम होना भी चाहिए।

जून माह में मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही कैबिनेट और राज्यमंत्री के मसले पर असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। वरिष्ठता का मुद्दा उठा कर महाराष्ट्र के प्रफुल्ल पटेल ने राज्यमंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। महाराष्ट्र के ही शिंदे गुट से भी मंत्री पद को लेकर तल्ख स्वर उठे। समय रहते उन्हें समझा लिया गया। आंध्र की टीडीपी में भी मंत्री पद के कोटे पर खुसर फुसर हुई लेकिन एनडीए की सत्ता के नए दौर के ताकतवर साथी चंद्रबाबू नायडू को तो अपने राज्य के विकास और राजधानी अमरावती के लिए केन्द्र से मोटी रकम चाहिए। इसलिए उन्होंने इस तरह की चर्चा को हवा ही नहीं लगने दी। नतीजतन टीडीपी नेताओं का असंतोष कब गायब हो गया पता ही नहीं चला। ऐसी चचाएं बिहार के मित्रों के मन में भी खदबदाती दिखीं लेकिन सियासी नफा नुकसान के गुणा- भाग में जब अपने पाले में नफा दिखता है तब बोल भी उसी अनुसार निकलने लगते हैं। मित्र दल यह समझ गए हैं कि इस समय हर हाल में मोदी के साथ रहने में ही ज्यादा भलाई है। यही कारण है कि बड़े से बड़े विवादों में भी सरकार और एनडीए में खामोशी बनी रही है। विरोध छन छन कर बाहर उतना ही आया जितना आटे में नमक होना चाहिए। फिर चाहे मामला उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति (लेटरल एंट्री) का हो अथवा वक्फ बोर्ड संबंधी विधेयक का।

वह 8 अगस्त का दिन ही था जब एनडीए सरकार ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित एक विधेयक लोकसभा में पेश किया। लेकिन एनडीए के भीतर और बाहर भारी विरोध को देखते हुए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का फैसला ले लिया गया। पिछले 10 सालों में यानी नरेंद्र मोदी की सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है, जब सदन में कोई बिल अटक गया हो और उसे जेपीसी को विचारार्थ भेजा गया हो।

सरकार में शीर्ष पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के विचार से भी सरकार को हाथ खींचना पड़ा। अब तक तो यही होता था कि सरकारी विभागों में नीचे के पदों से तरक्की पाकर अफसर बड़े पदों पर पहुंचते थे। लेकिन कुछ खास सरकारी पदों पर पदोन्नति के बजाय सीधी नियुक्ति के जरिए अनुभवी और विशेषज्ञों की नियुक्ति का विचार भी जरूरी महसूस किया जाता रहा है।

आखिर लेटरल एंट्री पर बवाल क्यों मचा? इस पर जब विचार करेंगे तो पहले कहानी है क्या यह जानना जरूरी है। सरकार ने 45 शीर्ष पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए सीधी भर्ती निकाली। ये ऐसे पद हैं जिनपर काम करने वाले अधिकारियों को महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसले लेने का अधिकार है। सरकार की मंशा साफ थी। इन नियुक्तियों को आरक्षण की सीमा से बाहर रखना। इसे सरकार की चतुराई भी कहा जा सकता है। नियुक्तियों का विज्ञापन एक साथ निकला लेकिन हरेक पद का अलग अलग। सिंगल पद पर भर्ती में आरक्षण संभव ही नहीं। इस फैसले का सरकार के अंदर और बाहर खूब विरोध हुआ। अक्सर मेरे प्रधानमंत्री कहते रहने वाले चिराग पासवान भी नाराज दिखे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे इसके खिलाफ हैं। मुद्दा आरक्षण का था। सरकार की इस पहल से आरक्षण का जिन्न एक बार फिर बाहर निकल आया। एनडीए में भाजपा के सहयोगी दलों का कहना था कि लेटरल एंट्री का कदम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी मिलने में बाधक होगा। साथ ही गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार में बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा।

भाजपा ने हालांकि लेटरल एंट्री का ठीकरा पूर्व की कांग्रेस सरकारों के सिर पर फोड़ना चाहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रस्तावों का हवाला दिया। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाला यह आयोग 2005 में यूपीए सरकार के दौरान ही अस्तित्व में आया था। मोदी के एक और मंत्री जितेंद्र सिंह ने आंकड़े सार्वजनिक करके बताया कि मोदी सरकार ऐसा पहले भी करती रही है। पिछले पांच सालों में लेटरल एंट्री के जरिए 63 नियुक्तियां की गई हैं। वर्तमान में 57 अफसर कई मंत्रालयों और विभागों में काम भी कर रहे हैं। दरअसल यह समझाने की कोशिश की गई कि सरकारी कामकाज सुचारू रूप से चलाने के लिए योग्य और भरोसे की प्रशासनिक टीम बहुत जरूरी होती है। इस सबके बावजूद बात नहीं बनी और मोदी सरकार को इस मुद्दे पर अपने कदम पीछे लेने पड़े।

अब बात कर लें उस उत्तर प्रदेश की जिसने मोदी की भाजपा को 272 के जादुई आंकड़े को छूने से रोक दिया। लोकसभा में उम्मीद के अनुरूप नतीजे नहीं मिलने के बाद यूपी में संगठन और सरकार के नाम पर वर्चस्व की तकरार शुरू हुई। मनभेद ऐसा बढ़ा कि आंतरिक झगड़े की हांडी चौराहे पर फूटती नजर आई और नेतृत्व कभी पार्टी बनता दिखा तो कभी तटस्थ। बीते दस सालों में ऐसी तू-तू मैं-मैं की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मनभेद बढ़ता रहा। यहां तक कि समीक्षा बैठकों में ना जाकर दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश प्रमुख अलग अलग बैठक करते रहे। यही नहीं दिल्ली दरबार में हाजिरी भी बजाते रहे। भाजपा संगठन में ऐसी अनुशासनहीनता पहली बार दिखी। तकरार इस कदर बढ़ी कि विधानसभा में पारित सरकारी विधेयक को विधान परिषद में रोकने का काम सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने ही किया। यह विधेयक सीएम की अनिच्छा के बावजूद समिति को विचारार्थ भेज दिया गया। सवाल यही है कि क्या यह लड़ाई स्थानीय स्तर की थी अथवा इसके तार दिल्ली से जुड़े थे? शायद इस सवाल का जवाब सर्वविदित है। जो सामने है उसे खोजना अज्ञानता ही कहा जाएगा। वैसे इन दिनों योगी और मौर्य के स्वर 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' की तर्ज पर सुनाई देने लगे हैं। राजनीति का यही आनंद है। हम भी ले रहे हैं और आप भी लीजिए।

सुभाषित

ज्ञान धनसे उत्तम है, क्योंकि धनकी तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, परन्तु ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। ❑ **भर्तृहरि शतक**

मोदीकी पोलैण्ड-यूक्रेन यात्रा

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीकी पोलैण्ड और यूक्रेनकी यात्रा विशेष रूपसे महत्वपूर्ण है और इसके दूरगामी परिणाम भी निकलनेकी सम्भावना है। मोदी २१ और २२ अगस्तको पोलैण्डमें और २३ अगस्तको यूक्रेनमें रहेंगे। पिछले ४५ वर्षोंमें किसी भारतीय प्रधान मंत्रीकी यह पहली पोलैण्ड यात्रा है। इसके पूर्व १९७९ में तत्कालीन प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई पोलैण्ड गये थे। भारतसे प्रस्थान करनेसे पूर्व प्रधान मंत्री मोदीने कहा कि पोलैण्डके साथ राजनयिक सम्बन्धोंके ७० वर्ष पूरा होनेके अवसरपर मेरी यह यात्रा हो रही है। पोलैण्ड मध्य यूरोपका हमारा साझीदार है। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब दोनों देशोंके बीच कूटनीतिक सम्बन्धोंकी स्थापनाके ७० वर्ष पूर्व हो रहे हैं। वे पोलैण्डमें भारतीय समुदायके लोगोंसे भी मिलेंगे। भारत और पोलैण्डके पारस्परिक सम्बन्धोंका समृद्ध इतिहास है। निवेश, व्यापार, तकनीक, संस्कृति और शिक्षाके अतिरिक्त द्वितीय विश्वयुद्धके दौरान महाराजा दिग्विजय सिंहने हजारों पोलिश बच्चोंको शरण दी थी। वहां उनके स्मारक भी हैं। भारत और पोलैण्डके बीच दस वर्षोंमें १९२ प्रतिशत व्यापार बढ़ा है। २०२३ में भारतने पोलैण्डके साथ ३.९५ बिलियन डालरका निर्यात और १.७६ बिलियन डालरका आयात किया था। भारतका पोलैण्डमें तीन बिलियन डालरसे अधिकका निवेश है। वहीं, पोलैण्डका भारतमें ६८५ मिलियन डालरका निवेश है। भारत पोलैण्डसे रक्षा व्यापार भी करता है। ऊर्जा और तकनीकके क्षेत्रमें कई समझौते भी हुए हैं। अगले वर्ष पोलैण्ड यूरोपीय यूनियन कौंसिलका अध्यक्ष बननेवाला है। पोलैण्डके राजदूतका यह कथन भी काफी महत्वपूर्ण है कि भारत दुनियाकी आवाज है। मोदीकी यात्रा एक मजबूत सन्देश देगी कि भारत शान्तिके पक्षमें है। प्रधान मंत्री मोदी २३ अगस्तको पोलैण्डसे दस घण्टेकी ट्रेन यात्रा कर यूक्रेन जायंगे। रूस-यूक्रेन युद्धके बीच उनका यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन १९९१ में अलग देश बना था। उसके बाद किसी भारतीय प्रधान मंत्रीने वहांकी यात्रा नहीं की। मोदीकी यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब यूक्रेनने कुछ दिनोंसे रूसकी सीमामें घुसकर हमले शुरू कर दिये हैं। यूक्रेनने रूसके कुछ इलाकोंपर कब्जा भी कर लिया है। ऐसी स्थितिमें रूस यूक्रेनपर जल्द बड़ा हमला कर सकता है। प्रधान मंत्री मोदीने कहा है कि वह यूक्रेन संकटका शान्तिपूर्ण समाधान निकालनेका प्रयास करेंगे इसमें कितनी सफलता मिलेगी, यह अभी अनिश्चित है। वैसे रूस और यूक्रेन दोनोंके साथ भारतके स्वतंत्र सम्बन्ध हैं। मोदी शान्तिका फार्मूला लेकर यूक्रेन जा रहे हैं। यदि इसपर सहमति बनती है तो वह बड़ी उपलब्धि होगी।

सीधी भर्तीपर रोक उचित

केन्द्र सरकारका उच्च विशेषज्ञ पदोंपर सीधी भर्ती रद कर दी गयी है। इसके साथ ही संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने २४ मंत्रालयोंमें संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवके ४५ प्रशासनिक पदोंपर विशेषज्ञोंकी नियुक्तिके विज्ञापनको रद कर दिया है। विज्ञापन जारी होनेके बाद विपक्षी दलोंके साथ ही सरकारके कुछ सहयोगी दलोंने भी इसका विरोध किया था जिसके मूलमें आरक्षण मुख्य मुद्दा था, क्योंकि इस भर्तीमें एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षणका प्राविधान नहीं है। सहयोगी दलोंके विरोधसे ऐसा लगता है कि केन्द्रने उच्च पदोंपर सीधी भर्तीका निर्णय लेनेसे पूर्व सहयोगी दलोंसे विचार-विमर्श नहीं किया जिसे रणनीतिक चूक ही कहा जा सकता है। सरकारको इस बातका अहसास था कि उसके निर्णयसे सियासी पारा चढ़ेगा और स्थिति असहज हो जायगी। ऐसेमें सहयोगी दलोंका समर्थन मिलना जरूरी था लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकारको अपना कदम पीछे खींचना पड़ा। कहनेको तो सीधी भर्तीपर रोक केन्द्रका दबावमें आना है लेकिन इसके निहितार्थको समझना होगा। राजनीतिक लाभके लिए देशमें आरक्षणका मुद्दा पहलेसे ही गर्माया हुआ है। यहांतक कि संविधानपर खतरेकी बात की जा रही है और इसका लाभ विपक्षको मिल भी रहा है जो सर्वविदित है। पिछले आम चुनावमें भाजपा और उसके गठबन्धनको इससे काफी नुकसान पहुंचा था। आरक्षणका मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभाओंके चुनाव अगले महीने होनेवाले हैं। इसके तत्काल बाद झारखण्ड और महाराष्ट्रके विधान सभाओंके चुनाव होनेवाले हैं, जहां आरक्षण बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस दृष्टिकोणसे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीका सीधी भर्तीपर हस्तक्षेपका निर्णय सरकारकी दूरदर्शिता ही कहा जायगा। आरक्षित वर्गके लोग सीधी भर्तीका हिस्सा नहीं बन सकते हैं। विपक्ष और अन्य विरोध करनेवाले राजनीतिक दलोंको इसपर मंथनकी जरूरत है।

लोक संवाद

बंगलादेशमें मानवाधिकार

महोदय,-बंगलादेशमें हिन्दुओंका कत्लेआमसे मानवाधिकारका हनन भारतके लिए अत्यंत पीड़ादायक रहा है। बंगलादेशवाली घटनासे सबक लेकर हमे अलर्ट रहनेकी आवश्यकता है। अफगानिस्तानमें बंदूककी नोंकपर देशमें तालिबानी आकाओंने राज छीन लिया। बंगलादेश, श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देशोंके तख्तापलटकी अंतरराष्ट्रीय साजिश बहुत कुछ बयां करनेके लिए तैयार है। प्रधान मंत्री शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारतमें रह रही है, जबकि बंगलादेशमें हिन्दुओंके लिए सरकारने औपचारिकता पूरी नहीं की है। बेसहारा छोड़े गये हिन्दू और हिन्दुओंके मंदिरमें तोड़फोड़ कर हिंसात्मक प्रवृत्तिको आज भी आगे बढ़ानेके लिए सोची-समझी चाल है। उपद्रवियोंने कत्लेआम करके कट्टरपंथी ताकतोंको बढ़ावा दिया गया है। हर नागरिककी जानमालकी गारंटी सरकारकी होनी चाहिए। बंगलादेशमें तख्तापलटके बाद नये बने प्रधान मंत्रीने आश्वासन जरूर दिया है लेकिन हिन्दुओपर हो रहे जुल्मोसितम आज भी बन्द नहीं हुए है। मुस्लिम बहुसंख्यक देशोंमें हिन्दू होना बहुत बड़ा गुनाह है। देशकी स्थिति समय आनेपर जरूर सुधरती दिखाई देगी। स्थायी शांति भी होगी, लेकिन ७५० लोगोंकी हत्याका जिम्मेदार कौन है। कानून व्यवस्थाको नहीं संभाला जाना वहांके हुक्मरानोंकी सबसे बड़ी भूल है। ६५ थानोंमें ताला लगा दिया गया था। वहांपर पुलिस नहीं थी। जहांपर अल्पसंख्यक समुदायके लोगोंकी आबादी थी। मुस्लिम देशोंमें हिन्दू सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तानमें भी हिन्दू और हिन्दू मन्दिरोंकी क्या दशा है। यह सोचनीय बाबत है। किसी भी धर्मके लोग क्यों नहीं है। दरअसल वह हिंसाका शिकार नहीं होना चाहिए। प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षाकी जिम्मेदारी सरकारकी होनी चाहिए है। विपक्षी दल गाजापट्टीकी चिंता करता है लेकिन हिन्दुओंपर होनेवाले जुल्मोसितमका विरोध नहीं किया है। सांत्वनाके दो शब्द भी नहीं बोले हैं। -**कांतिलाल मांडोत, वाया ईमेल।**

जलवायु परिवर्तनका भूजलपर प्रभाव

विश्वमें लगभग हर चारमेंसे एक व्यक्ति सतहके नीचे मौजूद जलाशयोंपर निर्भर है, क्योंकि साफ पानीकी झीलों, नदियों और बांधोंतक सभी लोगोंकी पहुंच नहीं है। वैज्ञानिकोंने चेताया है कि सदीके अंततक लाखों लोग पानीकी मामूली आपूर्तिसे भी वंचित हो सकते हैं, क्योंकि बढ़ते तापमानसे उथले भूजलके विषाक्त होनेका खतरा है।

❑ **मुकुल व्यास**

शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीमने वैश्विक तापमान वृद्धिके विभिन्न परिदृश्योंके तहत दुनियाभरमें भूजल स्रोतोंके तापमान परिवर्तनोंको सटीक संख्यामें बतानेके लिए ऊष्मा परिवहनका एक विश्वस्तरीय मॉडल विकसित किया है। सबसे खराब स्थितिमें, २१०० में लगभग ५९ करोड़ लोग ऐसे जल स्रोतोंपर निर्भर हो सकते हैं जो पीने योग्य पानीके लिए सबसे कड़े मानकोंको पूरा नहीं करते हैं। इस समय गर्मीकी लहरें, बर्फकी पिघलती हुई टोपियां और समुद्रोंका बढ़ता स्तर नियमित रूपसे सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान भूमिपर ग्लोबल वार्मिंगके प्रभावोंकी तरफ नहीं जाता। जलवायु परिवर्तनपर चर्चा करते हुए हमारा फोकस मौसमकी घटनाओं और पानीकी उपलब्धतापर रहता है। लेकिन हमें भूजलपर पड़नेवाले जलवायु परिवर्तनके प्रभावके बारेमें अधिक व्यापक रूपसे सोचनेकी आवश्यकता है। यह सच है कि हमारे पैरोंके नीचेकी चट्टान और मिट्टीकी परतें समुद्री जलकी गर्मीको अवशोषित करनेकी क्षमतासे मेल नहीं खाती हैं। फिर भी, यह आश्चर्यजनक है कि भूजलके गर्म होनेके परिणामोंपर इतना कम ध्यान दिया गया है, खासकर जब पानीकी कमी और रिचार्ज (पुनर्भरण) दरपर इतनी अधिक चर्चा होती है। सतहके ठीक नीचे छिद्रपूर्ण चट्टानोंके भीतर फंसा पानी घुले हुए खनिजों, प्रदूषकों और संभावित रोगजनकोंसे भरा हो सकता है। लेकिन बहुत बड़ी आबादीके समक्ष इस प्रदूषित जलपर निर्भर रहनेके सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। इन भूमिगत जलाशयोंको सिर्फ एक या दो डिग्री गर्म करनेसे परिणाम भयावह हो सकते हैं। इससे पर्यावरणमें आक्सीजनकी कमी हो सकती है और खतरनाक बैक्टीरियाके विकासको बढ़ावा मिल सकता है या आर्सेनिक और मैंगनीज जैसी भारी धातुओंकी अत्यधिक मात्रा पानीमे घुल सकती है।

जलवायु परिवर्तनको सीमित करनेके लिए विश्वके प्रयास मुख्य रूपसे कार्बन डाइआक्साइडपर केन्द्रित हैं। चूंकि मानव जाति कई दशकोंसे जलवायु परिवर्तनको पर्याप्त रूपसे निबटनेमें विफल रही है इसलिए अब वार्मिंगको तय लक्ष्योंसे नीचे रखनेके लिए हमें सभी प्रमुख जलवायु प्रदूषकोंपर अंकुश लगाने पड़ेंगे। इस समय वायुमंडलमें कार्बन डाइआक्साइडकी तुलनामें मीथेनकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मीथेन अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। दुनियाके गर्म होनेमें मीथेनका बड़ा योगदान है जो कार्बन डाइआक्साइडकी तरह ही गर्मीको कैद करती है।

इस अध्ययनकी मुख्य लेखिका और जर्मनीके कार्लश्रु इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीकी भू-विज्ञानी सुजैन बेंजके अनुसार दुनियामें पहलेसे ही लगभग तीन करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रोंमें रह रहे हैं, जहां भूजल पीनेके पानीके सख्त दिशा-निर्देशोंमें निर्धारित तापमानसे ज्यादा गर्म है। इसका मतलब है कि बिना ट्रीटमेंटके वहांका पानी पीना सुरक्षित नहीं है। आसपास पर्याप्त आकारके सतही जलाशयोंवाली आबादीके लिए भी गर्म भूजल उन प्रमुख कारकोंको बदल सकता है जो पानीको मानव उपभोगके लिए सुरक्षित रखते हैं। ७.७ करोड़से १८.८ करोड़ लोगोंके ऐसे क्षेत्रमें रहनेका अनुमान है जहां भूजल २१०० तक पीने योग्य मानकोंको पूरा नहीं कर पायगा। इस अध्ययनके नतीजे बताते हैं कि भूजलकी रक्षाके लिए काररवाई करना और भूजलपर जलवायु परिवर्तनके नकारात्मक प्रभावका मुकाबला करनेके लिए स्थायी समाधान खोजना कितना आवश्यक है। इस बीच, जलवायु परिवर्तनसे संबंधित एक अन्य अध्ययनमें वैज्ञानिकोंने दुनियामें मीथेन उत्सर्जनमें वृद्धिपर चिन्ता व्यक्त की है। रिकार्डतोड़ गर्मी, लोगोंकी गिरती सेहत, गायब होती बर्फकी चादरों और अप्रत्याशित मौसमके रूपमें जलवायु परिवर्तनकी बड़ी चेतावनियां हमें लगातार मिल रही हैं। फिर भी हम वायुमंडलमें ग्रीनहाउस गैसोंकी बढ़ती मात्राको उत्सर्जित कर रहे हैं। इससे हमारा अस्तित्व खतरेमें पड़ रहा है। विशेषज्ञोंकी एक अंतरराष्ट्रीय टीम द्वारा किये गये एक नये अध्ययनमें बताया गया है कि २००६ से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन बढ़ रहा है। २०२० से इसमें तेजी आयी है। यदि हम बहुत जल्द कुछ कठोर कदम नहीं उठायंगे तो उत्सर्जनकी यह प्रवृत्ति जारी रहेगी।

नये अध्ययनके शोधकर्ताओंने मीथेन उत्सर्जन रोकनेके लिए रणनीतियां तैयार की हैं जिनका उपयोग विभिन्न देश उचित काररवाई करनेके लिए कर सकते हैं। इसमें मदद करनेके लिए उन्होंने एक ऑनलाइन टूल भी विकसित किया है। शोधकर्ताओंका कहना है कि मीथेन उत्सर्जनमें यह निरन्तर वृद्धि मुख्य रूपसे जीवाश्म ईंधनके लगातार उपयोगके कारण है। मीथेन सीधे तेल, गैस और कोयलेकी ड्रिलिंग और प्रोसेसिंग द्वारा उत्पादित होती है। अब एक नयी बात यह है कि गर्म जलवायुके कारण प्राकृतिक आर्द्रभूमिसे मीथेनका बढ़ता उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसोंमें वृद्धि कर रहे हैं। लैंडफिल, पिघलते हुए पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी तुषार भूमि) और पशुधनसे भी मीथेनका उत्पादन होता है। अमेरिकामें ड्यूक विश्वविद्यालयके जलवायु विशेषज्ञ ड्रू शिंडेलका कहना है कि फिलहाल इन स्रोतोंसे उत्सर्जनमें योगदान मामूली है। हालांकि इनपर भी बारीकीसे नजर रखनेकी जरूरत है।

शोधकर्ताओंने अपने पेपरमें लिखा है कि जलवायु परिवर्तनको सीमित करनेके लिए दुनियाभरके प्रयास मुख्य रूपसे कार्बन डाइऑक्साइडपर केंद्रित हैं। चूंकि मानव जाति कई दशकोंसे जलवायु परिवर्तनको पर्याप्त रूपसे निबटनेमें विफल रही है, इसलिए अब वार्मिंगको तय लक्ष्योंसे नीचे रखनेके लिए हमें सभी प्रमुख जलवायु प्रदूषकोंपर अंकुश लगाने पड़ेंगे। इस समय हमारे वायुमंडलमें कार्बन डाइऑक्साइडकी तुलनामें मीथेनकी मात्रा बहुत कम है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मीथेन एक अधिक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। हम जानते हैं कि दुनियाके गर्म होनेमें मीथेनका भी एक बड़ा योगदान है जो कार्बन डाइऑक्साइडकी तरह ही गर्मीको कैद करती है। यह जमीनपर ओजोनके निर्माणमें भी योगदान देती है, जिससे श्वसन संबंधी बीमारियों और हृदय रोगोंके कारण मृत्युका जोखिम बढ़ जाता है। अध्ययनमें पाया गया है कि इन सभी मीथेन स्रोतोंपर तत्काल ध्यान देनेकी आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइडमें कमी लानेके लक्ष्योंके साथ-साथ मीथेनमें कमीके लक्ष्योंको भी लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए नयी प्रौद्योगिकियों और नीतियोंको लागू करनेकी आवश्यकता है। शोधकर्ताओंने लिखा है कि इस दशकमें मीथेन उत्सर्जनमें तेजीसे कमी लाना निकट भविष्यमें गर्मीको धीमा करने और कम वार्मिंगके कार्बन बजटको पहुंचके भीतर रखनेके लिए आवश्यक है। कार्बन बजटसे अभिप्राय प्रति व्यक्ति कार्बन डाइआक्साइडकी औसत मात्रासे है, जिसे वैश्विक तापमान वृद्धिको १.५ सेल्सियसतक सीमित रखनेके लिए उत्पादित किया जा सकता है।

समान नागरिक संहितापर सहमति बने

भारतीय संविधानके अनुच्छेद ४४ में समान नागरिक संहिताकी चर्चा की गयी है। यह अनुच्छेद राज्यके नीति-निर्देशक तत्वसे संबंधित है। संविधानके ३६ से ५१ तकके अनुच्छेदोंमें नीति निर्देशक तत्वोंका प्रावधान है।

❑ **मुनीष त्रिपाठी**

स्वतंत्रता दिवसके अवसरपर लाल किलेके प्राचीरसे प्रधान मंत्री मोदीने सेक्युलर सिविल कोडकी आवश्यकतापर बल दिया। इसके पहले देशमें आम सहमति बनानेके लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन कर दिया गया। जेपीसी इसके लिए इस मसलेपर आम सहमतिके लिए शीघ्र ही रास्ता तालाशेगी। दुनियाके कई ऐसे देश है जहां समान नागरिक सहिंता जैसी संहिता (यूसीसी) बहुत पहलेसे लागू की गयी है। अमेरिका, आयरलैंड, बंगलादेश, मलयेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, जैसे कई देश हैं, जिन्होंने समान नागरिक संहिता जैसे कानूनको लागू किया है। अमेरिका जहां विश्व लगभग सभी देशोंके कुछ न कुछ अथवा ज्यादा संख्यामें नागरिक स्थायी रूपसे रहते हैं। इसके अलावा विश्वके सभी धर्मों, सम्प्रदायोंके लोग निवास करते हैं उस विविधतावाले देशमें भी यूसीसी लागू है कहीं कोई विवाद नहीं है। कट्टरपंथी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तानने १९६१ में ही एक परिवार कानून अधिनियम पारित किया गया था, जिसने मुसलमानोंके लिए कुछ व्यक्तिगत कानूनोंको नियंत्रित किया था, जैसे कि शादी, तलाक और विरासत।

भारतीय संविधानके अनुच्छेद ४४ में समान नागरिक संहिताकी चर्चा की गयी है। यह अनुच्छेद राज्यके नीति-निर्देशक तत्वसे संबंधित है। संविधानके ३६ से ५१ तकके अनुच्छेदोंमें नीति निर्देशक तत्वोंका प्रावधान किया गया है। ये भारत सरकार अथवा राज्यके लिए बाध्यकारी नहीं है। पर्यावरण, गोरक्षा, समान नागरिक संहिता आदिकी चर्चा और सरंक्षणकी व्याख्या की गयी है। इसके अनुसार परिस्थितिके अनुसार राज्य अथवा भारत सरकार समस्त राज्यक्षेत्रमें नागरिकोंके लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करानेका प्रयास करेगा। समान नागरिक संहितामें देशके प्रत्येक नागरिकके लिए एक समान कानून होता है, चाहे वह किसी भी धर्म या जातिका क्यों न हो। इसमें निजी धर्मके कानून गौण हो जाते है। समान नागरिक संहिता लागू होनेपर शादी, तलाक तथा जमीन-जायदादके बंटवारे आदिमें सभी धर्मोंके लिए एक ही कानून लागू होता है। अभी देशमें जो स्थिति है उसमें धर्मोंके लिए अलग-अलग नियम हैं। संपत्ति, विवाह और तलाकके नियम हिन्दू, मुस्लिम, पारसियों और ईसाइयोंके लिए अलग-अलग हैं, जबकि हिन्दू, जैनों, सिखोंके लिए एक ही भारत सरकारका हिन्दू बिल संहिता लागू है। इस समय देशमें ईसाई, मुस्लिम, पारसी धर्मके लोग विवाह, संपत्ति और गोद लेने आदिमें अपने पर्सनल लॉका पालन करते हैं। मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायका अपना-अपना पर्सनल लॉ है जबकि हिन्दू सिविल लॉके तहत हिन्दू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। समान नागरिक संहिता लागू करनेके विरोधमें यह तर्क लागू किया जाता है कि सैकड़ों पुराने जैसे इस्लामके १४०० और ईसाइयोंके २००० पुराने कानूनोंका हवाला दिया जाता है कि इतने पुराने निजी आस्थावाले कानूनोंको कैसे बदला जा सकता है। कई हजार साल पुराने हिन्दू धर्ममें हजारों साल पुरानी प्रचलित बहुविवाहकी कुप्रथाको १९५५-५६ में हिन्दू बिल कोडके द्वारा परिवर्तन कर दिया गया था। एक ही झटकेमें सदियों पुरानी प्रचलित बहुविवाहको समाप्त कर एक विवाह अथवा एक पत्नी, उत्तराधिकार कानूनको कानूनी मान्यता प्रदान की गयी। ऐसा नहीं था कि इसका तीखा विरोध न हुआ हो, नेहरू और आंबेडकरको इसके लिए लम्बी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। इस अधिनियमका तीखा विरोध रामराज्य परिषद जैसी कट्टरपंथी संस्थाओंके अलावा तत्कालीन संविधान सभाके अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद, प्रख्यात संत करपात्री जी महाराज जैसे दिग्गजोंने किया था। आंबेडकर और नेहरू दोनों ही भारतमें समान नागरिक संहिता लागू करनेके पक्षधर थे। परन्तु इनका मानना था कि हिन्दू धर्ममें सुधारवादी तत्व मौजूद है परन्तु इस्लाममें नहीं। यह सच भी था उस दौरान और कुछ पहले हिन्दू धर्मके अन्दरसे आर्यसमाज, ब्रह्म समाज, सहित सहित कई सुधारवादी संघटनों, लोगोंने हिन्दू धर्ममें पुरानी कुप्रथाओंके खिलाफ सफलतापूर्वक आन्दोलन चलाये थे परन्तु इस्लाममें कमोवेश अपवादके अलावा इस प्रकारके सुधारवादी कृत्य देखनेको नहीं मिले था। इसलिए नेहरू और आम्बेडकरने पहले हिन्दू धर्ममें व्याप्त बुराइयोंको समाप्त करनेके लिए कानून बनानेका निर्णय लिया। १९४८ में संविधान सभाने नये हिन्दू संहिताके मसौदेकी समीक्षाके लिए एक चयन समितिका गठन किया। इसके अन्दर सिखों, बौद्धों, जैनियोंको भी समाहित किया जाना था। समितिके द्वारा बदलावके समर्थनके बाद संविधान सभाके अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसादने नेहरूका जबरदस्त विरोध किया था और इस सम्बंधमें दोनोंके बीच तीखी झड़पें भी हुई थीं। १९५० से ५१ के बीच कामचलाऊ संसदने कई बार निजी हिन्दू कानूनोंको परिवर्तनके लिए प्रयास किये परन्तु प्रबल विरोधके कारण सफल नहीं हो सके। खिन्न होकर आंबेडकरने नेहरूपर कट्टरपंथियोंके दबावके आगे झुकनेका आरोप लगाते हुए मंत्री पदसे त्यागपत्र दे दिया था। हालांकि उनके मंत्री पदके त्यागके पीछे कुछ अन्य कारण भी थे लेकिन यह कारण मुख्य था। आखिर लम्बी जद्दोजहदके बाद आंबेडकरके दबावके चलते ही उन्हींका बनाया हुआ हिन्दू बिल कोड १९५५-५६ में पारित हो गया। इसका मतलब यह है कि जब किसी भी राष्ट्रके भीतर मौजूद किसी भी धर्मके अन्दर व्याप्त दकियानूसी, प्रतिगामी मान्यताएं जड़ बनी हो और उस समाज और राष्ट्रकी प्रगतिमें बाधक हो तो फिर उसमें परिवर्तनके लिए लम्बा इन्तजार उचित नहीं होता है। भारतकी आजादीके इतने सालोंके बीतनेके बाद भी यदि अब समान नागरिक संहिता लागू नहीं होती तो फिर भारतको इसके लिए लम्बे समयतक इन्तजार करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वमें शाहबानो प्रकरणमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा समान नागरिक संहिताके निर्माणके आदेशके बाद भी तत्कालीन भारत सरकारने कानून बनाकर इसे खारिज कर दिया था। इसके अतिरिक्त २०१९ में सुप्रीम कोर्टने समान नागरिक संहिताके निर्माणमें प्रयास न करनेके सम्बंधमें केन्द्र सरकारके प्रति नाराजगी भी जतायी थी। अब जब मौजूदा सरकार इसके लागू करनेके लिए संसदके द्वारा कानून बनाना चाहती है तो फिर इसका विरोध तुष्टीकरण और वोटबैंकके लिए उचित नहीं है। भारतके गोआ जैसे ईसाई प्रभावित राज्यमें लम्बे अरसेसे समान नागरिक संहिता बिना विवादके लागू है तो फिर सम्पूर्ण भारतमें भी इसे आसानीसे लागू किया जा सकता है, जबकि भारतीय संविधानके अनुच्छेद ४४ में लिखा गया है कि समान नागरिक संहिता बनानेके लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। एक ही मसलेपर बार-बार सुप्रीम कोर्टकी अनदेखी भी ठीक नहीं है। समान नागरिक संहिताका निर्माणका कार्य संविधानकी भावनाके अनुरूप विधिसम्मत तो है ही साथ ही एक बड़े समुदायके भीतरकी कुरीतियां मिटानेवाला हो और जब यह समाज, राष्ट्रके हितमें हो तो फिर देरी कैसी।

आध्यात्मिक साधना

❑ **श्रीश्री रविशंकर**

हर घटना चाहे कितनी भी सुखद क्यों न हो, अंतमें दर्द देती है। जितनी ज्यादा खुशी होगी, उतना ही ज्यादा दर्द भी होगा। किसी घटनाकी चाहत या किसी सुखद घटनाका इन्तजार करना भी दर्द ही है। किसी चीजको चाहनेसे पहले उसे पानेकी तीव्र इच्छा, दर्द देती है। जब वह चीज आपके पास होती है तो उसे खोनेका डर दर्द देता है। जब वह चली जाती है तो उसके आनन्दकी याद, दर्द देती है। दर्द और प्यार एक ही सिक्केके दो पहलू हैं। प्यार बहुत ज्यादा दर्द पैदा करता है और जुदाई भी बहुत ज्यादा दर्द पैदा करती है। एक चाहत मनमें बहुत ज्यादा दबाव पैदा करती है। किसीको खुश करनेकी कोशिश करना दर्द पैदा करता है, यह जानना और समझना कि वे खुश हैं या नहीं, भी दर्द पैदा करता है। आप जानना चाहते हैं कि दूसरे व्यक्तिका मन कैसा है, जबकि आप अब भी अपने मनको नहीं जानते। आध्यात्मिक साधना करनेके लिए आपको प्रयास करनेकी जरूरत होती है और यह दर्दनाक है। ऐसा न करना और भी ज्यादा दर्द पैदा करता है। यदि आप वाकई बुद्धिमानोंकी नजरसे देखें तो इस सृष्टिमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्दसे रहित हो। दर्द इस दुनियामें हर चीजकी पूंछ है। जब आपको यह अहसास हो जाय कि सब कुछ दुख ही है तो क्या करें। दुखके मूल कारणको खत्म करना होगा। जो दुख अभीतक जीवनमें नहीं आया है और जो अंकुरित नहीं हुआ है, उसे शुरूमें ही काट देना चाहिए। आप ऐसा कैसे करते हैं। अपने आपको अपने परिवेशसे अलग समझना ही दर्दका मुख्य कारण है। बोधकी कमी दर्दका कारण बनती है। तीन चीजें हैं स्वयं, द्रष्टा और देखना। लोग अपना जीवन कहीं और रखते हैं, वे अपना जीवन अपने भीतर नहीं रखते। आप जीवनमें जिस चीजको ज्यादा महत्व देते हैं, वही दर्दका कारण बन जाती है। इसलिए जब आप अंतर देखते हैं कि द्रष्टा अपने आसपाससे अलग है तो यह दर्दको खत्म करनेमें मदद करता है। पूरी सृष्टि पांच तत्वों और दस इंद्रियोंसे बनी है, पांच ज्ञानेंद्रियां और पांच कर्मेन्द्रियां। यह पूरी सृष्टि आपको आनन्द और राहत देनेके लिए है। जो आपको आनन्द देता है, उसे आपको राहत भी देनी चाहिए। अन्यथा वही आनन्द दुख बन जाता है। दर्दके मूल कारणको खत्म करनेके लिए एक निश्चित समझ जरूरी है। शरीर, मन और यह पूरी दुनिया हर समय बदलावसे गुजर रही है। सम्पूर्ण ब्रह्मांड तरलताके रूपमें है। निश्चित ज्ञान यह है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अंतरिक्ष हूं, मैं अविनाशी हूं, इस संसारसे अछूता हूं, इस शरीर और मनका हर कण बदल रहा है। केवल यह निश्चित ज्ञान ही इस चक्रसे बाहर निकलनेका रास्ता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्थाकी मुख्य धुरी हिन्द-प्रशांत क्षेत्र

❑ **अरविंद जयतिलक**

गत दिवस पहले क्वॉड (क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलॉग) देशों द्वारा चीनको स्पष्ट रूपसे चेताया जाना कि हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें उसकी दबंगई और दादागिरीको बर्दाश्त नहीं किया जायगा, दुनियाके लिए शुभ संकेत है। क्वॉडके सदस्य देशोंमें शामिल जापान, अमेरिका, भारत और आस्ट्रेलियाके विदेश मंत्रियोंने तोक्योंमें संपन्न बैठकमें ठान लिया है कि खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें मिलकर काम करेंगे और किसी भी चुनौतीका मिलकर मुकाबला करेंगे। गौर करें तो सदस्य देशोंका इशारा उस चीनकी तरफ है जो लगातार इस क्षेत्रमें अपने प्रभावका विस्तार कर क्षेत्रीय संप्रभुताको चुनौती परोस रहा है। सदस्य देशोंने न सिर्फ हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें, बल्कि दक्षिण चीन सागरमें भी चीनके कुत्सित दांव-पेंचको लेकर चिंता जतायी है। दरअसल चीन इस इलाकेमें उन ज्यादतर हिस्सोंपर अपना दावा पेश करता है जिसे लेकर फिलीपींस, मलयेशिया, ब्रूनेई और वियतनामका कहना है कि यह इलाका उनका है। चीन यहां नकली द्वीप बनाकर अपने सैनिकोंको तैनात कर रहा है। इसी खतरेको भांपते हुए क्वॉडके सदस्य देशोंने रणनीतिके तहत इस क्षेत्रमें संतुलन बनाये रखनेकी नीतिमें तेजी लायी है। देखें तो क्वाडके सदस्य देशोंमें कोई ऐसा नहीं है जिसका चीनसे तनातनी न हो। हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें क्वॉड देशोंकी नयी गोलबंदीसे चीन उत्तेजित है और नाराजगी जाहिर करते हुए बार-बार कह रहा है कि क्वॉड देश इस क्षेत्रमें तनाव बढ़ा रहे हैं। जबकि सचाई यह है कि इस क्षेत्रकी संप्रभुताको मिल रही चुनौतीके लिए एकमात्र चीन ही जिम्मेदार है। उसके द्वारा निर्मित इस परिस्थितिसे निबटनेके लिए ही क्वॉड जैसे संघटनकी जरूरत महसूस की गयी। याद होगा २००७ में भारतीय संसदको संबोधित करते हुए जापानके तत्कालीन प्रधान मंत्री शिंजो अबेने स्पष्ट रूपसे कहा था कि हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें उभरती सामरिक चुनौतियोंसे निबटनेके लिए हम सभीको तैयार रहना होगा। उनकी दूरदर्शी सोच और परिकल्पना ही आगे चलकर क्वॉडके गठनका आधार बनी। गौर करें तो क्वॉडके गठनकालसे ही चीनकी बेचैनी बढ़ी हुई है। उसे लग रहा है कि क्वाडमें शामिल देश उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वह क्वाडको एक उभरता हुआ 'एशियाई नाटो' के तौरपर देख रहा है। वह जानता है कि क्वाडकी मजबूतीसे इस क्षेत्रमें उसकी मनमानीपर नियंत्रण लगेगा और समुद्रके जरिये दुनियापर राज करनेकी उसकी मनोकामना पूरी नहीं होगी। यह सचाई भी है कि क्वॉडका लक्ष्य प्रशांत महासागर, अमेरिका और आस्ट्रेलियामें विस्तृत नेटवर्कके जरिये जापान और भारतके साथ मिलकर इस क्षेत्रमें एक ऐसा वातावरण निर्मित करना है जिससे एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी विकासका मार्ग प्रशस्त हो। नेविगेशनकी स्वतंत्रता हो तथा ओवर-फ्लाइट एवं आसियानके निर्माणको लेकर काम किया जाय। क्वाडके सदस्य देश अपने पहले वर्चुअल सम्मेलनके दौरान ही चीनको अपने हदमें रहनेकी सलाह दे चुके हैं। तब अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवनने कहा था कि आस्ट्रेलियाके साथ चीनकी आक्रामकता, जापानके सेनकाकू द्वीपोंके आसपास उत्पीड़न और भारतके साथ सीमापर तनातनीको लेकर अमेरिका किसी भ्रममें नहीं है। वह हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें हर परिस्थितियोंसे निबटनेको तैयार है। याद होगा गत वर्ष इसी क्षेत्रमें अमेरिका समेत १३ देशोंने 'हिंद-प्रशांत आर्थिक समूह' (आईपीईएफ) व्यापारिक समझौतेको आकार देकर चीनकी बढ़ती दादागीरी और धौंसबाजीपर निर्णायक लगाम लगानेकी कवायद की थी। इस आर्थिक ढांचेसे जुड़नेवाले देशोंमें अमेरिकाके अलावा आस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, न्यूजीलैंड, फिलिपीन, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम शामिल हैं। किसीसे छिपा नहीं है कि दुनियाभरके प्राकृतिक संसाधनोंपर गिद्ध दृष्टि लगा बैठे चीन इस क्षेत्रमें चोरी-छिपे मछलियोंका बड़े पैमानेपर शिकार कर रहा है। इस क्षेत्रमें नब्बे फीसदीसे अधिक मछलियोंके शिकारके लिए एकमात्र बीजिंग ही जिम्मेदार है। उसके जहाज जबरन विशेष आर्थिक जोनकी सीमामें प्रवेश कर जाते हैं और पर्यावरणके साथ-साथ बड़े पैमानेपर आर्थिक नुकसानको अंजाम देते हैं। चीनकी इस हरकतसे सभी देश परेशान हैं। दूसरी ओर वह इस इलाकेमें सुरक्षा बेड़ा खड़ा कर अन्य देशोंकी संप्रभुता और सुरक्षाको चुनौती दे रहा है। ऐसेमें उसपर नकेल कसना बेहद जरूरी हो गया है। अच्छी बात है कि इस क्षेत्रके सदस्य देशोंके बीच सहमति बनती जा रही है। सभी देश सैटेलाइट सिस्टमका इस्तेमाल कर चीनकी हरकतोंपर लगाम कसनेको तैयार हैं। द्वीपीय देशोंका भारतके साथ आनेसे चीनकी छटपटाहट और बढ़ेगी। अब चीनकी दादागीरी नहीं चलने वाली है। चीनके खिलाफ यह पहल इसलिए भी आवश्यक है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक अर्थव्यवस्थाकी मुख्य धुरी है। मौजूदा समयमें यह क्षेत्र भू-राजनीतिक एवं सामरिक रूपसे वैश्विक शक्तियोंके मध्य रणका क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्रकी जनसंख्या विश्वकी जनसंख्याके तकरीबन एक-तिहाईसे ज्यादा है। विश्वके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग ६० फीसदी और विश्व व्यापारका ७५ फीसदी कारोबार इसी क्षेत्रसे होता है। देखें तो इस क्षेत्रमें अवस्थित बंदरगाह विश्वके व्यस्ततम बंदरगाहोंमें शुमार हैं। यह क्षेत्र इसलिए भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यहां उपभोक्ताओंको लाभ पहुंचानेवाले क्षेत्रीय व्यापार और निवेशकी अपार संभावनाएं हैं। किसीसे छिपा नहीं है कि यह क्षेत्र ऊर्जा व्यापारके लिहाजसे भी इस क्षेत्रके देशोंके लिए अति संवेदनशील है। ऐसेमें इस क्षेत्रको आर्थिक एवं सामरिक दृष्टिसे सुरक्षित रखनेके लिए ही क्वाडके अलावा 'हिंद-प्रशांत आर्थिक समूह' और 'भारत-प्रशांत द्वीप सहयोग' जैसे नये-नये गठजोड़ आकार ले रहे हैं। तथ्य यह भी कि हिंद-प्रशांत क्षेत्रको 'मुक्त एवं स्वतंत्र' क्षेत्र बनानेके लिए अमेरिका भारत-जापान संबंधोंके महत्वको सार्वजनिक रूपसे स्वीकार चुका है तथा साथ ही अमेरिकाके लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्रकी नीति सर्वोच्च प्राथमिकतामें है। दो राय नहीं कि विगत दशकोंमें अंतरराष्ट्रीय राजनीतिके मंचपर चीनकी विशिष्ट पहचान बनी है और वह आर्थिक सुधारोंके जरिये विश्वकी एक बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। लेकिन अब वह जिस आक्रामक तरीकेसे हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें अपनी दखलदांजी बढ़ा रहा है उससे अमेरिका, भारत, आस्ट्रेलिया, जापानके अलावा इस क्षेत्रसे जुड़े अन्य देशोंका चिंतित होना लाजिमी है। पाश्चात्य अर्थशास्त्रियों और रक्षा विषेशज्ञोंकी मानें तो चीन भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्थाके समानान्तर ध्रुवके एक नये धुमकेतुके रूपमें उभरकर अपने पड़ोसियोंको परेशान करनेकी योजनापर काम कर रहा है। उसके निशानेपर मुख्य रूपसे भारत, फ्रांस, आस्ट्रेलिया और जापान है। चीन मौजूदा गोलबंदीको समझ रहा है उसकी मंशा हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें भारत, आस्ट्रेलिया, फ्रांस और जापानकी भूमिकाको सीमित कर अपने प्रभावका विस्तार करना है। उसे भय है कि यदि इस क्षेत्रमें इन देशोंकी निकटता बढ़ी तो परिस्थितियां उसके प्रतिकूल हो सकती है। जापान 'एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग' (एपीईसी) संघटनमें भारतकी सदस्यताका लगातार वकालत कर रहा है। चीन अच्छी तरह जानता है कि यदि भारत इस संघटनका सदस्य बनता है तो उसकी मनमानी और विस्तारवादी नीतिपर लगाम लग सकता है। चीन इस तथ्यसे भी सुपरिचित है कि भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्रमें अपनी स्थिति मजबूत करनेके लिए आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंडसे भी द्विपक्षीय सहयोगके साथ-साथ बहुपक्षीय मंचों जैसे आसियान, हिंद महासागर रिम, विश्व व्यापार संघटन इत्यादि मंचोंपर सुचारू रूपसे सहयोग विकसित कर रहा है। हिंद-प्रशांत क्षेत्रमें आसियानको भारतीय नीतिका केन्द्रीय बिन्दु माना जाता है। ऐसेमें भारतकी भूमिकाका विस्तार होना लाजिमी है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मानव विकास जीरो,भौतिक विकास हीरो

अस्पताल में अपने पुत्र के इलाज के लिए गए मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि बेटे के बेड के सामने ही दो बच्चे अपने पिताजी का भी इलाज आयुष्मान कार्ड से करा रहे थे और परेशान थे। इसी परेशानी में जब मित्र ने उनसे बातचीत शुरू की और पूछा कि बेटा कहां तक पढ़ाई की है?तो उन्होंने बताया कि वे पढ़ाई छोड़ चुके हैं। मेरे मित्र ने आश्चर्य से पूछा कि क्यों ?तो उसने कहा कि उसके कई मित्र पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी 15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, इतना पैसा तो मजदूरी करके भी कमाया जा सकता है फिर पढ़ने की क्या जरूरत है ? यह धारणा कितने प्रतिशत बच्चों में घर कर चुकी है यह तो कहना मुश्किल है लेकिन सरकारी आंकड़ों में मध्य प्रदेश के कॉलेज में लाखों खाली पड़ी सीटें संकेत जरूर देती हैं कि यह सोच और यह धारणा धीरे-धीरे समाज में पैर पसार रही है। पैसा ही विकास का मापदंड बन गया है अगर आप पेट भर पा रहे हैं तो आप सफल हैं ।संतोष का यह स्तर किसी भी समाज को आगे बढ़ाने की बजाय किसी खाई खंदक की तरफ भी ले जा सकता है। शिक्षा समझ और रोजगार पैदा कर सकती है इन दोनों चीजों पर शासकीय नीतियों ने भरोसा कम कर दिया है अब उदर पोषण ही भरण पोषण बन रहा है। देश की सल्तनत में भी यह विचार निरंतर घर करता जा रहा है कि भौतिक विकास ही दर्शनीय विकास है और विकास के नाम पर अगर हमें लोकप्रियता अर्जित करना है तो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं, भवन और सड़कों का विकास ही विकास के प्रयासों का वास्तविक प्रदर्शन हो सकता है। यही कारण है कि अस्पतालों के नाम पर भवन बन रहे हैं लेकिन डाक्टर नहीं हैं।डेढ-दो हजार करोड़ के मेडीकल कालेज बन रहे हैं किंतु पढाने वाले दो दर्जन प्रोफेसर भी नहीं हैं।उपचार के लिये 1500 डाक्टरों की भी भर्ती नहीं हो पा रही है जबकि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 4 हजार डाक्टर तैयार होते हैं। कालेज खोले जा रहे हैं किंतु अतिथियों के भरोसे पढाई चल रही है।इंजीनियरिंग कालेजों में हजारों सीट खाली हैं।मानव विकास को उपेक्षित करके भौतिक विकास केवल भ्रष्टाचार और पिलफिरेज का ही माडल बन सकता है,वह स्थाई और सर्वस्पर्शी विकास नहीं बन सकता न ही ऐसा विकास मानव जीवन में बदलाव ला सकता है।

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक

आरती कुमारी

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी एवं खैफनाक है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। कई घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है। यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में दो छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का घिनौना एवं घातक रूप है। बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है! पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मनःस्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर गंभीर काम किया जाए। उदयपुर की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया? इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिमेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिमेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा। 'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वच्छन्द हो जाते हैं। 'मूड ठीक नहीं' की स्थिति में घटना सिर्फ घटना होती है, वह न सुख देती है और न दुःख। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी अनंत शक्तियों को बौना बना देता है। यह दकियानूसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मर्यादा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं। शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। कई बार टी.वी. पर हिंसक कार्यक्रम देखने आदि से बच्चों में हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। घर में लगातार बंदूकें, चाकू आदि देखते रहने से भी बच्चों का व्यवहार हिंसक हो जाता है। वैसे भी अगर बच्चों को किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगें, टोकेंगें नहीं तो उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान कैसे होगी। एक ऑनलाइन सर्वे में माता-पिता ने कहा था कि बच्चों को गलत काम की सजा भी मिलनी चाहिए, वरना उनके मन में किसी भी बात के लिए डर नहीं रहेगा और हो सकता है वे ऐसे अपराधों को भी अंजाम देने लगें, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता नहीं। स्कूली बच्चों में पिछले कुछ समय से हिंसक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जो समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मोबाइल पर पबजी जैसे खतरनाक गेम और वेब सीरिज बच्चों को हिंसक बना रही है। लेकिन, इसके पीछे न सिर्फ स्कूल का वातावरण, बल्कि लाड-प्यार में अंधे अभिभावकों का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। बच्चों में हिंसक व्यवहार के संकेत, जैसे गलत भाषा का प्रयोग करना, समझाने पर भी गुस्सा करना, कोई भी बात समझाने पर चीजें फैंकने लगना, मां-बाप को ही मारने दौडना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत आदतों में पडना, भाई-बहन के लिए स्नेह न रखना, लड़ाकू प्रवृत्ति का होना, हमेशा उदास रहना, संवेदनहीन और चिड़चिड़े रहना, बार-बार जोश में आना आपको नजर आ सकते हैं। एकल परिवारों में माता-पिता इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास बच्चों से बात करने का ज्यादा समय नहीं होता। वे अक्सर इस बात पर भी नजर नहीं रख पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनके दोस्त कौन-कौन से हैं। दोस्त उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि अरे! तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं, जो तुम्हें ऑनलाइन खेल भी नहीं खेलने देते। इससे बच्चों में हीनता और अपने घर वालों के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है, जो अपराध के रूप में बाहर निकलता है। फिजिकल, ओरल या सैक्सुअल रूप में गलत व्यवहार, घरेलू वातावरण न मिलना, माता-पिता द्वारा बच्चों की अनदेखी, दर्दनाक घटना होने या फिर स्ट्रैस होना, बच्चों को धमकाना, फैमिली प्रॉब्लम, नशीली चीजों का सेवन, शराब और अन्य गलत चीजों के सेवन से बच्चों में आक्रामकता बढ़ सकती है और वे हिंसक हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। घर में बच्चों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने के साथ अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझें और उनका समाधान कर सकें। सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षकों को बच्चों के आचरण और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। ऐसा करने पर वे बच्चों के चाल-चलन की बारीकी से निगरानी कर सकेंगे। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों से जुड़ी हिंसा की इन वीभत्स एवं त्रासद घटनाओं से जिन्दगी इतनी सहम गयी है कि गलत धारणाओं को मिटाने के लिये इस तरह की विकृत सोच एवं तथाकथित विकास से जुड़े शत्रु को पीठ के पीछे नहीं, सामने रखना होगा। सोचना होगा कि खुशहाली का पैमाना सिर्फ आर्थिक सम्पन्नता, शक्ति एवं सत्ता नहीं हो सकता। हमें मानवीय मूल्यों के लिहाज से भी विकास की परख करनी होगी। बच्चों के भीतर हिंसा मनोरंजन की जगह ले रही है। इसी का नतीजा है कि छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी अपने किसी सहपाठी से रंजिश के चलते उस पर गोली चलाते देखे गये हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड -यूक्रेन की यात्रा के अनेक महत्त्व है

अशोक भाटिया , मुंबई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय पोलैंड दौरे पर हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वागत किया था और बाद में वे पोलैंड के लिए रवाना हो गए। 45 साल में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। 1955 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को 70 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है।आखिरी बार 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 अगस्त से 22 अगस्त तक का रहेगा। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रहने वाली रहेगी , जिसमें रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि इसके बाद मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। यह यात्रा उनके साथ पहले की चर्चाओं को आगे बढ़ाने और भारत-यूक्रेन मैत्री को और गहरा करने का अवसर होगा। हम चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी अपने विचार साझा करेंगे। एक मित्र और साझेदार के रूप में, हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं।' बीबीसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोंस्की ने कहा कि पॉलिटिक्स और बिजनेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा हमारे लिए काफी अहम है।भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 21-23 अगस्त तक पोलैंड आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन रवाना हो जाएंगे। पोलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का दौरा भी कर सकते हैं। यह भारत और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों की निशानी है। महाराजा दिग्विजय सिंहजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश शरणार्थियों को शरण दी थी। प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे पर पोलैंड के राजदूत सेबेस्टियन डोमजाल्स्की ने कहना है कि भारत दुनिया की आवाज है। मोदी की यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर संदेश देगी कि भारत शांति के पक्ष में हैं। उनके यात्रा के दौरान, तकनीक, डिफेंस और सुरक्षा बातचीत के अहम मुद्दें रहेंगे।आपको बता दें कि सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 25 जून 1955 को पोलैंड गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी 8 अक्टूबर 1967 को पोलैंड यात्रा पर गई थी। फिर मोरारजी देसाई 14 जून 1979 को पोलैंड यात्रा पर जाने वाले आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री थे। इसके 45 साल बाद अब मोदी वहां जा रहे हैं। पोलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। मोदी पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। रूस-यूक्रेन जंग के बीच उनका यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर भी गए थे।प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। भारत और पोलैंड के बीच 2023 में 5172 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ 3195 बिलियन डॉलर का निर्यात और 1176 बिलियन डॉलर का आयात किया था।भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती है। वहीं, पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का निवेश है। गौरतलब है कि भले ही 45 सालों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पोलैंड के साथ खराब रिश्ते हैं।भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से दोस्ती वाले रिश्ते हैं। दोनों देशों ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद 1957 में वारसॉ में भारतीय दूतावास खोला गया।पंडित नेहरू की 1954 में पोलैंड विजिट के बाद 1979 तक भारत के VVIP का पोलैंड राजनीतिक दौरा होता रहा। 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक मार्ग चुनने के बाद भी संबंध घनिष्ठ बने रहे। 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे और मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का एक मुख्य भागीदार के रूप में उभरा। भारत और पोलैंड कई क्षेत्रों में साझेदार जिसमें कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विदेश कार्यालय, आतंक और क्राइम, डिफेंस, आर्थिक सहयोग, हेल्थ केयर और कोल एंड माइनिंग आदि शामिल हैं।इसके अलावा पोलैंड ने 1989 में लोकतंत्र अपनाने के बाद एक डेलिगेशन भारत भेजा था, जिसने भारत के विशाल लोकतंत्र को समझा और अपने देश में भारत जैसा लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की। भारत के लोकतंत्र को समझने के लिए पोलैंड ने 1992, 2000, 2002 और 2003 अपने डेलिगेशन भारत भेजे हैं। 2002 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पोलैंड का दौरा किया था। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश पार्टनर है। 2013-2023 के बीच पोलैंड के साथ कुल द्विपक्षीय कारोबार में 192 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है, जोकि 2013 में 1195 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 5172 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।भारत से पोलैंड एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में कपड़ा, बैस मेटल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स, फुटवियर और हेडगेयर, प्लास्टिक, रबर और उनसे बने समान, सिरेमक, फूड आइटम्स और वनस्पति शामिल हैं। अगर इंवेस्टमेंट की बात करें तो भारत में पोलैंड का कुल निवेश 685 मिलियन डॉलर का है। वहीं भारत का पोलैंड में निवेश भी साल दर साल बढ़ रहा है और अब वे करीब 3 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत की कई कंपनियां पोलैंड के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। पोलैंड के लोगों का योग करने में भी पुराना इतिहास है। पोलैंड का योगा इतिहास लगभग 100 साल पुराना है और भारत की तरह ही यहां भी लोग योगा की खूब दीवाने हैं। पोलैंड में करीब 3 लाख लोग योगा करते हैं। हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पोलैंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पोलैंड में करीब 25 हजार भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनमे से ज्यादातर व्यापारी और नौकर पेशा है जो कम्यूनिज्म के पतन के बाद यहां आए हैं। इसके अलावा करीब 5 हजार भारतीय छात्र पोलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं और 1 हजार के करीब यहां भारतीय रेस्तरां हैं। पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वे 23 अगस्त को यूक्रेन राजधानी कीव पहुंचेंगे और करीब सात घंटे तक वहां रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के दौरे के बाद ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय करेंगे और कीव पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था। यूक्रेन और रूस के बीच करीब ढाई साल से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में डटी हैं। सोमवार को भारत ने एक बयान में कहा, हम रूस-यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हरसंभव मदद देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की 23 अगस्त की यात्रा की घोषणा की और कहा, यह एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। यूक्रेन की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीब 10 घंटे लगेंगे। वापसी भी उतनी ही अवधि की होगी। रूसी क्षेत्र में कीव के ताजा सैन्य हमले के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा हो रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वैश्विक नेता भी ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। ये नेता यूक्रेनी बॉर्डर के पास पोलिश ट्रेन स्टेशन से ट्रेन के जरिए कीव की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा, मॉस्को की उनकी हाई-प्रोफाइल यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है। उस समय अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगियों ने आलोचना की भी थी। विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताने के अनुसार भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ठोस और स्वतंत्र संबंध हैं और ये साझेदारियां अपने दम पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत और यूक्रेन के बीच निरंतर जुड़ाव को आगे बढ़ाएगी। लाल ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस यात्रा का उद्देश्य दूसरे के नुकसान से अपना फायदा पाना नहीं है। प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा भी की थी। कई विचारों पर चर्चा की गई थी।उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले एक साल में कुछ मौकों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की और अब वे यूक्रेन में फिर से मिलेंगे। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि ये स्वतंत्र व्यापक संबंध हैं और निश्चित रूप से जारी संघर्ष भी चर्चा का हिस्सा होगा। यूक्रेन में संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर लाल बताते है कि भारत इस जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हरसंभव सहायता और योगदान देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने मोदी और जेलेंस्की के बीच वार्ता के नतीजे का पूर्वानुमान लगाने से इनकार कर दिया। लाल ने कहा, भारत ने बहुत स्पष्ट और सुसंगत रुख बनाए रखा है कि कूटनीति और बातचीत से इस संघर्ष को हल किया जा सकता है जिससे स्थायी शांति हो सकती है। उन्होंने कहा, इसलिए बातचीत बिल्कुल जरूरी है। स्थायी शांति सिर्फ उन विकल्पों के जरिए हासिल की जा सकती है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों और सिर्फ बातचीत से ही समाधान हो सकता है। भारत सभी हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। लाल ने यह भी कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचने के लिए लगातार कूटनीति और बातचीत की वकालत करता रहा है। लाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढे जा सकते। यह एक स्पष्ट और सुसंगत स्थिति है जिसे भारत ने अपनाया है और हमारा मानना है कि अधिकांश देश इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं। यूक्रेन के साथ भारत के संबंधों पर उन्होंने कहा कि यह संबंध निरंतर और दीर्घकालिक हैं। लाल ने कहा, यह एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों में यह पहली बार होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी-जेलेंस्की वार्ता में कृषि, बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य और शिक्षा, रक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित भारत-यूक्रेन संबंधों के संपूर्ण आयाम पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन आने का दिया था न्योता- मोदी ने जून में इटली के अपुलीया में जी7 शिखर सम्मेलन से इतर जेलेंस्की के साथ बातचीत की थी। बैठक में मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बताया कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रखेगा और शांति का रास्ता संवाद और कूटनीति के माध्यम से है। मोदी ने जेलेंस्की को यह भी बताया कि भारत यूक्रेन में संघर्ष का समाधान खोजने के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है। बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को कीव आने का निमंत्रण दिया था।

https://t.me/AIINewsPaper

मेष राशिःआज आपका दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज परिवार के साथ समय बितायेंगें, इससे घर में खुशियों का माहौल बनेगा। आज आपकी कड़ी मेहनत से आसपास के लोग प्रभावित होंगे और आपका अनुसरण करेंगे। आज रोज की अपेक्षा व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत रहेगा। स्वास्थ्य फिट रखने के लिए ताजे फल खायें, फायदा मिलेगा । धार्मिक कामों में मन लगाने से आपको मानसिक शांति मिलेगी ।

वृष राशिःआज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देगा। अगर आप नयी जमीन लेने का प्लान बना रहे हैं तो घर के बड़ों की राय जरूर ले । इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन संतोषजनक रहेगा कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप जीवनसाथी से अपने दिल की बात शेयर करेंगे, इससे रिश्ते में मधुरता बनेगी। शाम को परिवार के साथ किसी जरूरी मामले पर बात होगी जहाँ आप खुलकर अपनी राय रखेंगे, आपकी राय को अहमियत मिलेगी।

मिथुन राशिःआज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपको किसी बुजुर्ग की सेवा का अवसर मिलेगा, इसे आप सौभाग्य के रूप में समझे। आज आप हर तरह के काम निपटाने के लिए तैयार रहेंगे। आपको सोचे हुए कामों से फायदा हो सकता है। कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। अपनी स्थिति और योग्यता के हिसाब से ही काम करेंगे। लवमेट का आज रिश्ता तय हो सकता है।

कर्क राशिःआज आपका दिन आपके लिए नई खुशियां लाया है। राजनीति से जुडे लोगो के लिए दिन अच्छा है समाज हित में किये गये कामों की तारीफ़ हो सकती है। आज आपको उच्चाधिकारी के सामने बात रखने पर.. पॉजीटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज आपको रोजगार में नई उपलब्धि मिलने के योग हैं। घरेलू जरूरत की चीजों की खरीददारी करेंगे आपका लेन-देन भी तेज हो सकता है। कोई भरोसेमंद और खास व्यक्ति आपको हर्ट कर सकता है। आज आप पिता और बच्चों के साथ अच्छा समय बितायेंगे।

सिंह राशिःआज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिन्हे आप बखूबी निभायेंगे। आप जिस काम को करने का प्रयास करेंगे, उस काम में आपको कामयाबी मिलेगी। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा इससे आपका हौसला बढेगा। आज किसी काम को पूरा करने के लिए आस-पास के कई लोग आपको सलाह देगें ,इससे गलती से भी आप सुरक्षित रहेगें।

कन्या राशिःआज का दिन सामान्य रहेगा। आज आपके सामने चुनौतियां भी आएंगी आप इनका डटकर मुकाबला करेंगे सफलता हासिल होगी। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा सामान्य रहेगा। करियर संबंधी चुनाव आपको थोड़ी परेशानी में डाल सकता है, लेकिन सही पॉइन्ट का चुनाव करना बेहतर रहेगा। माता पिता से आशीर्वाद लेने से आपकी सभी परेशानियों से राहत मिल जाएगी। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

तुला राशिःआज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि की महिलाए जो कोई बिजनेस करने की सोच रही है, उनके लिए आज का दिन अच्छा है। किसी भी काम को करने में जल्दबाजी न करें ,अन्यथा वह काम दोबारा करना पड़ सकता है। अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा समय ईश्वर की आराधना के लिए निकालने से आपका मन शांत रहेगा 7 किसी दोस्त से कामकाज के मामले में आपको कुछ नए आइडिया मिल सकते हैं।

वृश्चिक राशिःआज का दिन सामान्य रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदा देने वाला है। करियर में उतार-चढ़ाव से आप परेशान हो सकते हैं लेकिन किसी अनुभवी सीनियर्स की मदद से आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आज घर में बच्चों के साथ आपका अच्छा टाइम बितेगा। माता पिता बच्चो को कोई अच्छी सलाह भी दे सकते है। छात्रो को आज ऑनलाईन कुछ नया सीखने को मिलेगा।

धनु राशिःआज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। नौकरी कर रहे लोगो को आज पदोन्नती के अवसर मिलेंगे। ऑफिस में अच्छे परफोर्मेंस के लिए आपको सम्मानित किया जा सकता है। आज आपके तय किए काम समय से पूरे होते हुए नजर आयेंगे साथ ही कुछ काम वक्त से पहले पूरे करने की वजह से खुद के लिए ख़ुशी मिलेगी।

मकर राशिःआज का दिन ठीक - ठाक रहेगा। इस राशि की महिलाओं के लिए आज का दिन बहुत ही खास है आप दिन का अधिक समय शॉपिंग में बिता सकती हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगो को आज किसी कम्पनी से मेल आ सकती है। दाम्पत्य जीवन में आज मधुरता बनी रहेगी। आज आपके पास बिजनेस को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका है। कम्पटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी जारी रखनी चाहिए।

कुंभ राशिःआज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। लोगों के विचार और आपके बारे में बोली गई बातों के कारण आप मन ही मन परेशान हो सकते है। इस राशि के स्टूडेंट आज अपनी पढाई को लेकर उत्साहित होंगे और ज्यादा समय पढाई में बीतेगा, यह देखकर आपके घरवालों को भी ख़ुशी होगी। इस राशि के टैक्सटाइल व्यापारी वर्ग को आज अचानक से कोई बड़ा फायदा हो सकता है, आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत बना रहेगा।

मीन राशिःआज आपका दिन खुशनुमा पल लेकर आया है। आज कोई बुजुर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति आपको सही सलाह दे सकता है। आज आपको पुरानी बातें भी याद आ सकती हैं। आज व्यापारिक मामलों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से सामान्य होगी।

शब्द सामर्थ्य -154

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. संघर्ष, दौड़धूप (उर्दू) 5. सुपुत्र, लायक पुत्र 7. ताकतवर, बलशाली 9. खुशबू, सुरभि, सुगंध 10. अकारण, व्यर्थ, बेवजह 12. गर्म तेल आदि में खाद्य वस्तु छोड़कर पकाना 13. यात्रा 15. मृत, जो मर गया हो 16. छोटे कद का, वामन, बौना 18. सांप का सिर, गुण, कला, कौशल 20. निरुत्तर, बेमिसाल 23. गोल हरे दानों वाला एक प्रसिद्ध पौधा, या इस पौधे की फली 24.माता, जननी 25. संतान, औलाद 26. अधीन, अधीनस्थ, कर्मचारी 27. चिड़िया, खग तरफदार।

ऊपर से नीचे

1.पानी में डूबा हुआ, जल प्लावित 2. पाकेटमार, जेब काटने वाला 3. समाधान, खेत जोतने का यंत्र 4. औषधालय 6. युक्ति, उपाय 8. गीला, तर, भीगा हुआ 11. झटके से मुंह से आवाज के साथ हवा बाहर आना, बलगम आदि का बाहर आना 14. तुरंत, झटपट 15. स्त्री, नारी, अबला 17. एक और एक चौथाई 19. आदमखोर 21. दुनिया, संसार, जग 22. वर्ष की छः ऋतुओं में एक ऋतु जिसमें मौसम सुहावना रहता है 23. बुद्धि, दिमाग।

1		2	3	4	■	5		6
	■	7			8	■	■	
9			■	10		11	■	
	■	12			■	13	14	
■	15		■	■	■	16		■
■		■	17	■	■	■	18	19
■	20	21		22	■	23		
24	■		■	25			■	
■	26				■	■	27	

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 153 का हल

पी	चि	दं	ब	र	म	■	■	स
ट	■	भ	ला	ई	■	अ	स	म
ना	म	■	■	स	मा	धि	■	झ
■	ज	■	बे	■	न	का	र	ना
बा	बू	■	आ	य	क	र	■	■
■	र	की	ब	■	■	■	प्र	था
ज	■	■	रू	प	क	■	ज	न
हा	■	पा	■	ना	म	ची	न	■
ज	हां	प	ना	ह	■	ता	न	ना

सूडोकु नवताल- 7165

★★★★☆ मध्यम

		5			3			
	2			9	5			
9						6		
			9				3	5
	6						7	
4	8				1		6	2
		7						3
			2	4			9	
			8			2		

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7164 का हल

2	7	6	4	9	5	8	1	3
5	8	1	7	2	3	9	6	4
9	3	4	8	1	6	2	5	7
6	5	9	2	4	8	3	7	1
8	4	7	9	3	1	6	2	5
1	2	3	5	6	7	4	9	8
3	6	5	1	8	2	7	4	9
7	9	2	3	5	4	1	8	6
4	1	8	6	7	9	5	3	2

सम्पादकीय

रोजगार संकट का कोई त्वरित समाधान नहीं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वियतनाम से सीखने की जरूरत

बेरोजगारी पर आने वाली सभी नकारात्मक रिपोर्टों को लंबे अरसे तक खारिज करने के बाद सरकार ने आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में यह बात स्वीकार की है कि उसके सामने बेरोजगारी की समस्या है। मुख्य आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार की गई आर्थिक समीक्षा में भी रोजगार सृजन और बेरोजगारी के मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पांच योजनाओं की घोषणा की जिनमें से अधिकांश ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करने पर नियोक्ताओं को अधिक प्रोत्साहन देने की बात करती हैं। इनमें से एक योजना खास तौर पर दिलचस्प थी। वित्त मंत्री चाहती हैं कि देश की शीर्ष 500 कंपनियां प्रशिक्षुओं की भर्ती करें और उन्हें प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षुओं को हर महीने 5,000 रुपये देने की बात है और उन्हें एक बार 6,000 रुपये की एकमुश्त सहयोग राशि भी मिलेगी। सरकार प्रशिक्षुओं की छात्रवृत्ति पर होने वाले ज्यादातर खर्च की भरपाई करेगी। कंपनियां उसका बचा हिस्सा देंगी और प्रशिक्षण पर होने वाला खर्च उठाएंगी। इसका अंतिम ब्योरा अभी आना है। ये विचार बहुत व्यावहारिक नहीं हैं। इनसे यह भी लगता है कि सरकार इस समस्या को पूरी तरह समझ ही नहीं पा रही है। भारत में बेरोजगारी समस्या है, युवा बेरोजगारी ज्यादा बड़ी समस्या है, रोजगार सृजन समस्या है और युवाओं में उपयुक्त कौशल की कमी भी समस्या है। इनसे दो बातें सामने आती हैं। पहली, हर वर्ष भारी तादाद में कार्य बल में शामिल हो रहे युवाओं को या उनमें से ज्यादातर को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नौकरियां सुनिश्चित की जाएं। दूसरी बात, यह सुनिश्चित किया जाए कि रोजगार तलाश रहे युवा वाकई में भर्ती के योग्य हैं। दुनिया के सभी देश रोजगार के पर्याप्त मौके तैयार करने की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन बड़ी आबादी और युवाओं की ज्यादा तादाद के कारण भारत सबसे ज्यादा प्रभावित है। आप किस तरह के आंकड़े उठाते हैं, उसके हिसाब से भारत में कामकाजी आबादी 1 करोड़ से 1.4 करोड़ हो जाती है। इनकी भर्ती के लिए रोजगार के मौके तैयार करना मुश्किल है चाहे अर्थव्यवस्था सालाना 7-8 प्रतिशत की दर से ही क्यों न बढ़ रही हो। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि की हरेक इकाई के बदले सृजित रोजगार की संख्या पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में काफी कम हुई है क्योंकि तकनीकी प्रगति और दूसके कारणों से उत्पादकता में तेजी से इजाफा हुआ है। 1970 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था में आबादी के लिए रोजगार के मौके तैयार करने की क्षमता जीडीपी वृद्धि की लगभग 1 प्रतिशत थी और उस समय आबादी भी बहुत कम थी। वर्तमान दशक में रोजगार देने की क्षमता घटकर 0.1 फीसदी रह गई है। इस प्रकार 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि भी रोजगार के पर्याप्त मौके शायद ही तैयार कर पाएगी। बड़ी तादाद में नई नौकरियां तैयार करने का एक ही तरीका है- भारत को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की नई क्षमताओं का आकर्षक केंद्र बनाया जाए। कारोबारी सुगमता बढ़ने की तमाम बातों के बावजूद हकीकत यह है कि भारत में कारोबारियों को अनुपालन, नियमन और दूसरी कई बाधाओं से निपटना पड़ता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड-यूक्रेन की यात्रा के अनेक महत्त्व है

प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि इसके बाद मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। यह यात्रा उनके साथ पहले की चर्चाओं को आगे बढ़ाने और भारत-यूक्रेन मैत्री को और गहरा करने का अवसर होगा। हम चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी अपने विचार साझा करेंगे। एक मित्र और साझेदार के रूप में, हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं।'बीबीसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोंस्की ने कहा कि पॉलिटिक्स और बिजनेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा हमारे लिए काफी अहम है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 21-23 अगस्त तक पोलैंड आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन रवाना हो जाएंगे।

अशोक भाटिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय पोलैंड दौरे पर हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वागत किया था और बाद में वे पोलैंड के लिए रवाना हो गए। 45 साल में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। 1955 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को 70 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है।आखिरी बार 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 अगस्त से 22 अगस्त तक का रहेगा। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रहने वाली रहेगी , जिसमें रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। पोलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का दौरा भी कर सकते हैं। यह भारत और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों की निशानी है। महाराजा दिग्विजय सिंहजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश शरणार्थियों को शरण दी थी।प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे पर पोलैंड के राजदूत सेबेस्टियन डोमजाल्स्की ने कहना है कि भारत दुनिया की आवाज है। मोदी की यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर संदेश देगी कि भारत शांति के पक्ष में हैं। उनके यात्रा के दौरान, तकनीक, डिफेंस और सुरक्षा बातचीत के अहम मुद्दें रहेंगे।आपको बता दें कि सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 25 जून 1955 को पोलैंड गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी 8 अक्टूबर 1967 को पोलैंड यात्रा पर गई थी। फिर मोरारजी देसाई 14 जून 1979 को पोलैंड यात्रा पर जाने वाले आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री थे। इसके 45 साल बाद अब मोदी वहां जा रहे हैं।

पोलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। मोदी पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। रूस-यूक्रेन जंग के बीच उनका यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर भी गए थे।प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है।भारत और पोलैंड के बीच 2023 में 5.72 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ 3.95 बिलियन डॉलर का निर्यात और 1.76 बिलियन डॉलर का आयात किया था।भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती है। वहीं, पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का निवेश है। गौरतलब है कि भले ही 45 सालों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पोलैंड के साथ खराब रिश्ते हैं।भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से दोस्ती वाले रिश्ते हैं। दोनों देशों ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद 1957 में वारसॉ में भारतीय दूतावास खोला गया।पंडित नेहरू की 1954 में पोलैंड विजिट के बाद 1979 तक भारत के ङ्कङ्कढ्ढक्क का पोलैंड राजनीतिक दौरा होता रहा। 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक मार्ग चुनने के बाद भी संबंध घनिष्ठ बने रहे। 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे और मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का एक मुख्य भागीदार के रूप में उभरा। भारत और पोलैंड कई क्षेत्रों में साझेदार जिसमें कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विदेश कार्यालय, आतंक और क्राइम, डिफेंस, आर्थिक सहयोग, हेल्थ केयर और कोल एंड माइनिंग आदि शामिल हैं।इसके अलावा पोलैंड ने 1989 में लोकतंत्र अपनाने के बाद एक डेलिगेशन भारत भेजा था, जिसने भारत के विशाल लोकतंत्र को समझा और अपने देश में भारत जैसा लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की। भारत के लोकतंत्र को समझने के लिए पोलैंड ने 1992, 2000, 2002 और 2003 अपने डेलिगेशन भारत भेजे हैं। 2002 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पोलैंड का दौरा किया था।पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश पार्टनर है। 2013-2023 के बीच पोलैंड के साथ कुल द्विपक्षीय कारोबार में 192 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है, जोकि 2013 में 1।95 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 5.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।भारत से पोलैंड एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में कपड़ा, बैस मेटल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स, फुटवियर और हेडगेयर, प्लास्टिक, रबर और उनसे बने समान, सिरेमक, फूड आइटम्स और वनस्पति शामिल हैं।अगर इंवेस्टमेंट की बात करें तो भारत में पोलैंड का कुल निवेश 685 मिलियन डॉलर का है। वहीं भारत का पोलैंड में निवेश भी साल दर साल बढ़ रहा है और अब वे करीब 3 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत की कई कंपनियां पोलैंड के विकास में अपना योगदान दे रही हैं।पौलेंड के लोगों का योग करने में भी पुराना इतिहास है। पौलेंड का योगा इतिहास लगभग 100 साल पुराना है और भारत की तरह ही यहां भी लोग योगा की खूब दीवाने हैं। पौलेंड में करीब 3 लाख लोग योगा करते हैं। हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पौलेंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।पौलेंड में करीब 25 हजार भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनमे से ज्यादातर व्यापारी और नौकर पेशा है जो कम्यूनिज्म के पतन के बाद यहां आए हैं। इसके अलावा करीब 5 हजार भारतीय छात्र पोलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं और 1 हजार के करीब यहां भारतीय रेस्तरां हैं। पौलेंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वे 23 अगस्त को यूक्रेन राजधानी कीव पहुंचेंगे और करीब सात घंटे तक वहां रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के दौरे के बाद ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय करेंगे और कीव पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था। यूक्रेन और रूस के बीच करीब ढाई साल से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में डटी हैं।सोमवार को भारत ने एक बयान में कहा, हम रूस-यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हरसंभव मदद देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की 23 अगस्त की यात्रा की घोषणा की और कहा, यह एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। यूक्रेन की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीब 10 घंटे लगेंगे। वापसी भी उतनी ही अवधि की होगी। रूसी क्षेत्र में कीव के ताजा सैन्य हमले के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा हो रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वैश्विक नेता भी ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। ये नेता यूक्रेनी बॉर्डर के पास पोलिश ट्रेन स्टेशन से ट्रेन के जरिए कीव की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा, मॉस्को की उनकी हाई-प्रोफाइल यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है। उस समय अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगियों ने आलोचना की भी थी।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद रहेंगे और दूसरी तरफ, आपको किस बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ हमारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाते वक्त सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह स्थानान्तरण हमें संताप और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष
आज आप के लिए नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। आप पर अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। परिवार में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहेगा। मन में भावनात्मकता बढ़ेगी। मां की ओर से फायदा होगा।

वृष
मित्रों के साथ आनंददायक प्रवास होगा, तो दांपत्यजीवन में भी आप ज्यादा निकटता बना सकेंगे। महिला मित्रों से विशेष लाभ होगा। अविवाहितों को जीवनसाथी की तलाश में सफलता मिलेगी। काम समय से पूरा नहीं होगा।

मिथुन
काम का बोझ ज्यादा रहेगा। नए काम की शुरुआत न करें। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मन बेचैन एवं चिंतित रहेगा। वाणी पर संयम रखें। खर्च ज्यादा होगा। आज आपका दिन शुभ है। व्यापार बढ़ाने को लेकर आपके प्रयास रंग लाएंगे।

कर्क
मानसिक व्यग्रता को दूर करने के लिए आध्यात्मिकता, योग का सहारा लें। महिला और पानी से बचकर रहें। अभ्यास के लिए समय मध्यम है। आज आप को ज्यादा संवेदनशील एवं भावुकता भरे विचार आएंगे। धनप्राप्ति के लिए भी शुभ समय है।

सिंह
महिलाओं के बारे में विशेष ध्यान रखें। वाणी एवं व्यवहार में सावधानी बरतें। विदेश से कोई समाचार मिल सकता है। कानूनी बातों का निर्णय सोच-समझकर करें। आज घर, परिवार एवं व्यापार जैसे तमाम क्षेत्रों में आको लाभ होगा।

कन्या
अधिकारियों का रवैया नकारात्मक रहेगा। विरोधियों के साथ वाद-विवाद न करें। संतान से मतभेद हो सकते हैं। यात्रा की संभावना है। धनखर्च होगा। कार्य सफलता में विलंब होने के कारण निराशा का अनुभव होगा। कमिशन, ब्याज से आपकी आय में वृद्धि होगी।

तुला
अनुकूल वातावरण रहेगा और साथियों का सहयोग मिलेगा। आज आप प्यार एवं भावना के प्रवाह में रहेंगे। दोस्त, स्वजनों और रिश्तेदारों की ओर से कोई उपहार मिल सकता है। आप उनके साथ अपना दिन खुशी में गुजार सकेंगे।

वृश्चिक
आज रिश्तेदार एवं मित्रों के साथ मुलाकात से आप आनंद का अनुभव करेंगे। आर्थिक योजना में आपको पहले थोड़ी मुसीबत हो सकती है, आपके जरूरी काम भी शुरुआती विलंब के बाद आसानी से पूरे होने पर शांति का अहसास करेंगे।

धनु
प्रवास, सुंदर भोजन एवं प्रियजन के साथ से आप रोमांचित रहेंगे। पत्नी के संग से मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों के लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आज मन भावनाओं से व्यथित रहेगा।

मकर
जमीन-जायदाद के दस्तावेजी काम कर सकेंगे। आपका आज का दिन प्रतिकूलताओं एवं अनुकूलताओं से भरा होगा। लेखन-साहित्य से जुड़े काम कर सकेंगे। हांलाकि, व्यवसायिक स्थल पर प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी।

कुंभ
दूसरों की ओर से चिंता कम होगी। इस कारण आप का मन खुश रहेगा। परिजनों या दोस्तों के साथ अच्छे भोजन का अवसर मिलेगा। कोई आकस्मिक यात्रा हो सकती है। आर्थिक मामलों से संबंधित व्यवस्था कर सकेंगे।

मीन
आज आपको काफी संवेदनशीलता का अनुभव होगा। इस कारण किसी के द्वारा आपकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। आज आपको मां की बीमारी की चिंता होगी। मकान या जमीन के दस्तावेजी काम आज न करें। इससे आपका आर्थिक स्तर मजबूत बनेगा।

शख्सियत

'जीवन मे लक्ष्य वहींन जीवन ऐसे है जैसे एक इंसान चौराहे पर खड़ा है, चारों सड़क नजर आ रही हैं फिर भी उसके कदम नहीं उठ पा रहे क्योंकि उसे पता ही नही जाना कहाँ है'
मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया..

जी हां कुछ ऐसी ही व्यवस्थाओं को साथ मे लेकर चलने वाले हमारी आज की शख्सियत कॉलम के सुपर डुपर स्टार है सबके चहते और सबके लिए हमेशा खड़े रहने वाले अरिहंत पब्लिसिटी के डायरेक्टर नीरज जैन। 17 नवम्बर सन 1976 को जन्मे नीरज जैन बचपन से ही कुछ बड़ा कर गुजरने का सपना दिल मे संजोय रखे थे। स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से हुई चूंकि माता पिता दोनों ही राजकीय सेवा के अधिकारी रहे। ऐसे में सरकार की प्रसासनिक सेवा की नोकरी करने की बजाय छोटा काम सही पर खुद का बिज़नेस करने का मन बनाया और साबित कर दिया कि व्यक्ति यदि सोच बलशाली रखे तो सोचा हुआ काम पूर्ण होता ही है। जंगल मे मोर नाचा किसने देखा उस कहावत को पूर्णत्या चरितार्थ किया। मार्केटिंग का बिजनेस का स्टार्टअप किया उस समय जब लोग मार्केटिंग की अ ब स नहीं जानते थे। पूरे राजस्थान भर में आउटडोर मीडिया(होर्डिंग्स) व अन्य संसाधनो के जरिये लोगों के व्यपार को आसमां की ऊंचाइयों तक छुआ देने का आत्मविश्वास इस व्यक्तित्व में ही है। ऊर्जा से लबरेज सभी लोगों की मदद के उठने वाले हाथ हमेशा संकट के समय भी हाथ पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। माध्यम टीवी के चैनल हैड होने के नाते मीडिया की समाज मे सशक्त भूमिका व सकारात्मक संदेश दिया। अपनी टीम को कीचड़ में कमल ढूंढने के लिए प्रेरित किया। आज नीरज जैन किसी परिचय के मोहताज नहीं। ऐसे कोई संगठन व सामाजिक मंच नहीं जहां इनकी कमी को पूरा किया जा सके। रोटरी क्लब अलवर के अध्यक्ष पद पर रहते हुए अनेकों सामाजिक कार्य व नवाचार किये। सबको साथ बनाए रखना और नए लोगों को जीवन मे जोड़ना इनकी जीवन शैली का एक पार्ट है। हमेशा मधुर मुस्कान बिखेरना व सामाजिक कार्यों के लिए समय की अनुपलब्धता के बाद भी पूरा समय देना इनके बड़प्पन को बयां करता है। अपने कार्य के प्रति निष्ठा व अनुशासन इनकी कार्यशैली को एक नए आयाम देता है। आजकल ये श्री आदिनाथ जैन शिक्षण संस्थान में वाइस चेयरमैन के पद को सुशोभित भी कर रहे हैं। अलवर में इवेंट सिस्टम को सबसे पहले लाने वाले,अलवर की प्रतिभाओं को बड़ा मंच दिलाने वाले भी ये पहले शख्स हैं। अलवर को बड़े पर्यटन हब के रूप में देखना इनकी महत्वकांशा हैं। अविरल अविचल छवि वाले इस व्यक्तित्व की समाज को हर कदम पर जरूरत महसूस होती है। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है।

नीरज जैन
(डायरेक्टर अरिहंत पब्लिसिटी)

जय हिंद

आज का इतिहास

22 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- फ्रांस के कैथोलिक और प्रोटेस्टेन्ट ईसाइयों के बीच अंतिम युद्ध 1627 में हुआ।
- ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई (तत्कालीन मद्रास) की स्थापना की।
- रुस, डेनमार्क और पोलैंड के बीच 1698 में त्रिकोणीय संधि हुई जो स्वीडन के विरोध में थी।
- एन। फ्रेंकलिन 1762 में अमेरिकी अखबार न्यूपोर्ट आर आई, मर्करी की पहली महिला संपादक बनी।
- अमेरिका ने 1848 में न्यू मैक्सिको पर कब्जा किया।
- ऑस्ट्रिया ने 1849 में इटली के शहर वेनिस में चालक रहित गुब्बारों से पहला हवाई हमला किया।
- ऑस्ट्रेलिया में सोने के क्षेत्रों की खोज 1851 में हुई।
- नेटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना महात्मा गाँधी द्वारा 1894 को की गई थी।
- जापान ने पांच साल तक कोरिया का संरक्षण करने के बाद उस पर 1910 में कब्जा किया।
- ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों के बीच 1914 को बेल्जियम में पहली मुठभेड़ हुई।
- भारत के पहले प्रवीण पायलट इन्द्रलाल राय 1918 में प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए।
- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1921 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई।
- जनरल माइकल कोलिन्स की पश्चिम कॉर्क में 1922 को हत्या कर दी गई।
- अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन के प्रतिनिधियों ने 1944 में संयुक्त राष्ट्र के गठन की योजनाओं को लेकर मुलाकात की।
- विश्व के पहले परमाणु सम्पन्न समुद्री जहाज़ ने 1962 में वर्जीनिया से जॉर्जिया तक की यात्रा पूरी की।
- अमेरिका में 1969 को समुद्री तूफान आने से 255 लोगों की मौत।
- केन्या के पहले राष्ट्रपति जोमो केन्याता का 1978 में 83 साल की उम्र में निधन हुआ।
- राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में लोकसभा भंग की।
- राज्य सरकार ने 1996 में मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कर दिया।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक की कार्य योजना 1999 को लागू हुई।
- काठमांडू में सार्क विदेश मंत्रियों का सम्मेलन 2002 को सम्पन्न, नेपाल में हवाई दुर्घटना में 16 व्यक्ति मारे गये।
- मिस्त्र के पुरातत्त्वविदों ने 2007 में पश्चिम रेगिस्तान के सिवा क्षेत्र में लगभग 20 लाख साल पुराने मानव के पद-चिह्नों का पता लगाया।
- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत के लिए दो सप्ताह के मिशन पर गया अंतरिक्ष यान एण्डेवर फ़्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर पर 2007 को सुरक्षित उतरा।

विशेष आलेख

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक

ललित गर्ग

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी एवं खैफनाक है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। कई घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है। यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में दो छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का घिनौना एवं घातक रूप है।

बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है! पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच-समझ को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मन:स्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर गंभीर काम किया जाए। उदयपुर की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया? इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिमेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिमेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

'मन जो चाहे वही करो' की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वछन्द हो जाते हैं। 'मूड ठीक नहीं' की स्थिति में घटना सिर्फ घटना होती है, वह न सुख देती है और न दु:ख। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी अनंत शक्तियों को बौना बना देता है। यह दकियानूसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मर्यादा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं। शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। कई बार टी.वी. पर हिंसक कार्यक्रम देखने आदि से बच्चों में हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। घर में लगातार बंदूकें, चाकू आदि देखते रहने से भी बच्चों का व्यवहार हिंसक हो जाता है। वैसे भी अगर बच्चों को किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगें, टोकेंगें नहीं तो उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान कैसे होगी। एक ऑनलाइन सर्वे में माता-पिता ने कहा था कि बच्चों को गलत काम की सजा भी मिलनी चाहिए, वरना उनके मन में किसी भी बात के लिए डर नहीं रहेगा और हो सकता है वे ऐसे अपराधों को भी अंजाम देने लगें, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता नहीं। स्कूली बच्चों में पिछले कुछ समय से हिंसक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जो समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मोबाइल पर पबजी जैसे खतरनाक गेम और वेब सीरिज बच्चों को हिंसक बना रही है। लेकिन, इसके पीछे न सिर्फ स्कूल का वातावरण, बल्कि लाड-प्यार में अंधे अभिभावकों का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। बच्चों में हिंसक व्यवहार के संकेत, जैसे गलत भाषा का प्रयोग करना, समझाने पर भी गुस्सा करना, कोई भी बात समझाने पर चीजें फैंकने लगना, मां-बाप को ही मारने दौडना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत आदतों में पडना, भाई-बहन के लिए स्नेह न रखना, लड़ाकू प्रवृत्ति का होना, हमेशा उदास रहना, संवेदनहीन और चिड़चिड़े रहना, बार-बार जोश में आना आपको नजर आ सकते हैं। एकल परिवारों में माता-पिता इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास बच्चों से बात करने का ज्यादा समय नहीं होता। वे अक्सर इस बात पर भी नजर नहीं रख पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनके दोस्त कौन-कौन से हैं। दोस्त उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि अरे! तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं, जो तुम्हें ऑनलाइन खेल भी नहीं खेलने देते। इससे बच्चों में हीनता और अपने घर वालों के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है, जो अपराध के रूप में बाहर निकलता है। फिजिकल, ओरल या सैक्सुअल रूप में गलत व्यवहार, घरेलू वातावरण न मिलना, माता-पिता द्वारा बच्चों की अनदेखी, दर्दनाक घटना होने या फिर स्ट्रैस होना, बच्चों को धमकाना, फैमिली प्रॉब्लम, नशीली चीजों का सेवन, शराब और अन्य गलत चीजों के सेवन से बच्चों में आक्रामकता बढ़ सकती है और वे हिंसक हो सकते हैं। ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। घर में बच्चों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने के साथ अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझें और उनका समाधान कर सकें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक

-ललित गर्ग

भारतीय बच्चों में बढ़ रही हिंसक प्रवृत्ति चिन्ताजनक है। पिछले कुछ समय से स्कूली बच्चों में बढ़ती हिंसा की प्रवृत्ति निश्चित रूप से डरावनी एवं खैफनाक है। चिंता का बड़ा कारण इसलिए भी है क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास की नींव रखी जाती है, उसी उम्र में कई बच्चों में आक्रामकता घर करने लगी है और उनका व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई-लिखाई और खेलकूद में व्यस्त रहना चाहिए, उसमें उनमें बढ़ती आक्रामकता, हिंसा एवं क्रूरता एक अस्वाभाविक और परेशान करने वाली बात है। कई घटनाओं में स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे ने अपने सहपाठी पर चाकू या किसी घातक हथियार से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अमेरिका की तर्ज पर भारत के बच्चों में हिंसक मानसिकता का पनपना हमारी शिक्षा, पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना पर कई सवाल खड़े करती है। यह दुष्प्रवृत्ति बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर तो नकारात्मक प्रभाव डाल ही रही है, इसे भविष्य में समाज की शांति के लिए बड़ा खतरा भी मानना चाहिए। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में दो छात्रों के आपसी विवाद में चाकू मारने से एक छात्र की मौत भी बच्चों में पनप रहे इसी हिंसक बर्ताव का घिनौना एवं घातक रूप है।

बड़ा सवाल है कि जिन वजहों से बच्चों के भीतर आक्रामकता एवं हिंसा पैदा हो रही है, उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है! पाठ्यक्रमों का स्वरूप, पढ़ाई-लिखाई के तौर-तरीके, बच्चों के साथ घर से लेकर स्कूलों में हो रहा व्यवहार, उनकी रोजमर्रा की गतिविधियों का दायरा, संगति, सोशल मीडिया या टीवी से लेकर उसकी सोच-समझ को

प्रभावित करने वाले अन्य कारकों से तैयार होने वाली उनकी मनःस्थितियों के बारे में सरकार, समाजकर्मी एवं अभिभावक क्या समाधान खोज रहे हैं। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों के बस्ते की औचक जांच की व्यवस्था की अपनी अहमियत हो सकती है। मगर जरूरत इस बात की है कि बच्चों के भीतर बढ़ती हिंसा और आक्रामकता के कारणों को दूर करने को लेकर गंभीर काम किया जाए। उदयपुर की घटना के पूरे मामले की पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन किशोर अवस्था में ऐसी घटना को अंजाम देने के पीछे बच्चे की मानसिकता का पता लगाना भी ज्यादा जरूरी है। तहकीकात स्कूल की व्यवस्थाओं की भी होनी चाहिए कि आखिर बच्चा स्कूल में हथियार लेकर कैसे आ गया? इसमें दो राय नहीं कि किशोरवय में राह भटकने का खतरा ज्यादा रहता है। उम्र के इस पड़ाव पर उनको सही राह दिखाने की जिमेदारी परिजन और शिक्षक की ही होती है। आज दोनों ही कहीं न कहीं अपनी जिमेदारी से दूर होते नजर आ रहे हैं। स्कूल में केवल किताबी ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। वहीं अर्थप्रधान दुनिया में माता-पिता के पास बच्चों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं बच पा रहा।

ह्यमन जो चाहे वही करोह्ल की मानसिकता वहां पनपती है जहां इंसानी रिश्तों के मूल्य समाप्त हो चुके होते हैं, जहां व्यक्तिवादी व्यवस्था में बच्चे बड़े होते-होते स्वच्छन्द हो जाते हैं। ह्यमूड ठीक नहींह्ल की स्थिति में घटना सिर्फ घटना होती है, वह न सुख देती है और न दुःख। ऐसी स्थिति में बच्चे अपनी अनंत शक्तियों को बौना बना देता है। यह दकियानूसी ढंग है भीतर की अस्तव्यस्तता को प्रकट करने का। पारिवारिक एवं सामाजिक उदासीनता एवं संवादहीनता से ऐसे बच्चों के पास सही जीने का शिष्ट एवं अहिंसक सलीका नहीं होता। वक्त की पहचान नहीं होती। ऐसे बच्चों में मान-मयार्दा, शिष्टाचार, संबंधों की आत्मीयता, शांतिपूर्ण सहजीवन आदि का कोई खास ख्याल नहीं रहता। भौतिक सुख-सुविधाएं ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाता है। भारतीय बच्चों में इस तरह का एकाकीपन उनमें गहरी हताशा, तीव्र आक्रोश और विषैले प्रतिशोध का भाव भर रहा है। वे मानसिक तौर पर बीमार बन रहे हैं और अपने पास उपलब्ध खतरनाक एवं घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हत्याकांड कर बैठते हैं। शिक्षकों और परिजनों से संवादहीनता के चलते बच्चों ने मोबाइल फोन और सोशल मीडिया को संवाद का जरिया बना लिया है। कई बार टी.वी. पर हिंसक कार्यक्रम देखने आदि से बच्चों में हिंसक व्यवहार बढ़ जाता है। घर में लगातार बंदूकें, चाकू आदि देखते रहने से भी बच्चों का व्यवहार हिंसक हो जाता है। वैसे भी अगर बच्चों को किसी भी बात के लिए मना नहीं करेंगें, टोकेंगें नहीं तो उन्हें अच्छे-बुरे की पहचान कैसे होगी। एक ऑनलाइन सर्वे में माता-पिता ने कहा था कि बच्चों को गलत काम की सजा भी मिलनी चाहिए, वरना उनके मन में किसी भी बात के लिए डर नहीं रहेगा और हो सकता है वे ऐसे अपराधों को भी अंजाम देने लगें, जिनके परिणामों के बारे में उन्हें पता नहीं।

स्कूली बच्चों में पिछले कुछ समय से हिंसक प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जो समाज के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि मोबाइल पर पबजी जैसे खतरनाक गेम और वेब सीरिज बच्चों को हिंसक बना रही है। लेकिन, इसके पीछे न सिर्फ स्कूल का वातावरण, बल्कि लाड-प्यार में अंधे अभिभावकों का रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। बच्चों में हिंसक व्यवहार के संकेत, जैसे गलत भाषा का प्रयोग करना, समझाने पर भी गुस्सा करना, कोई भी बात समझाने पर चीजें फैंकने लगना, मां-बाप को ही मारने दौडना, लोगों के बारे में गलत बोलना, गलत आदतों में पडना, भाई-बहन के लिए स्नेह न रखना, लड़ाकू प्रवृत्ति का होना, हमेशा उदास रहना, संवेदनहीन और चिड़चिड़े रहना, बार-बार जोश में आना आपको नजर आ सकते हैं। एकल परिवारों में माता-पिता इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास बच्चों से बात करने का ज्यादा समय नहीं होता। वे अक्सर इस बात पर भी नजर नहीं रख पाते कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, उनके दोस्त कौन-कौन से हैं। दोस्त उन्हें चिढ़ाते भी हैं कि अरे! तुम्हारे माता-पिता कैसे हैं, जो तुम्हें ऑनलाइन खेल भी नहीं खेलने देते। इससे बच्चों में हीनता और अपने घर वालों के प्रति नफरत का भाव पैदा होता है, जो अपराध के रूप में बाहर निकलता है। फिजिकल, ओरल या सैक्सुअल रूप में गलत व्यवहार, घरेलू वातावरण न मिलना, माता-पिता द्वारा बच्चों की अनदेखी, दर्दनाक घटना होने या फिर स्ट्रैस होना, बच्चों को धमकाना, फैमिली प्रॉब्लम, नशीली चीजों का सेवन, शराब और अन्य गलत चीजों के सेवन से बच्चों में आक्रामकता बढ़ सकती है और वे हिंसक हो सकते हैं।

ऑस्ट्रिया के क्लागेनफर्ट विश्वविद्यालय की ओर से किशोरों पर किए गए अध्ययन में पता चला है कि दुनिया भर में 35.8 प्रतिशत से ज्यादा किशोर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अकारण भय, पारिवारिक अथवा सामाजिक हिंसा, चिड़चिड़ापन अथवा अन्य कारणों से जूझ रहे हैं। एकाकीपन बढ़ने से वे ज्यादा आक्रामक और विध्वंसक सोच की तरफ बढ़ने लगे हैं। घर में बच्चों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित, और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने के साथ अभिभावकों को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। स्कूलों में काउंसलर और मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाता की व्यवस्था होनी चाहिए, जो बच्चों की मानसिक समस्याओं को समझें और उनका समाधान कर सकें। सबसे बड़ी बात यह कि शिक्षकों को बच्चों के आचरण और उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण देना होगा। ऐसा करने पर वे बच्चों के चाल-चलन की बारीकी से निगरानी कर सकेंगे। बच्चों के व्यवहार और उनके भीतर घर करती प्रवृत्तियों पर मनोवैज्ञानिक पहलू से विचार किए बिना समस्या को कैसे दूर किया जा सकेगा? बच्चों से जुड़ी हिंसा की इन वीभत्स एवं त्रासद घटनाओं से जिन्दगी इतनी सहम गयी है कि गलत धारणाओं को मिटाने के लिये इस तरह की विकृत सोच एवं तथाकथित विकास से जुड़े शत्रु को पीठ के पीछे नहीं, सामने रखना होगा। सोचना होगा कि खुशहाली का पैमाना सिर्फ आर्थिक सम्पन्नता, शक्ति एवं सत्ता नहीं हो सकता। हमें मानवीय मूल्यों के लिहाज से भी विकास की परख करनी होगी। बच्चों के भीतर हिंसा मनोरंजन की जगह ले रही है। इसी का नतीजा है कि छोटे-छोटे स्कूली बच्चे भी अपने किसी सहपाठी से रंजिश के चलते उस पर गोली चलाते देखे गये हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड -यूक्रेन की यात्रा के अनेक महत्त्व है

अशोक भाटिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय पोलैंड दौरे पर हैं। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का स्वागत किया था और बाद में वे पोलैंड के लिए रवाना हो गए। 45 साल में यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। 1955 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के संबंधों को 70 साल पूरे होने के मौके पर हो रहा है।आखिरी बार 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री का ये दौरा 21 अगस्त से 22 अगस्त तक का रहेगा। ये यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित रहने वाली रहेगी , जिसमें रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सहित कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि इसके बाद मैं राष्ट्रपति जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन जाऊंगा। यह यात्रा उनके साथ पहले की चचाओं को आगे बढ़ाने और भारत-यूक्रेन मैत्री को और गहरा करने का अवसर होगा। हम चल रहे यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भी अपने विचार साझा करेंगे। एक मित्र और साझेदार के रूप में, हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र वापसी की आशा करते हैं।

बीबीसी के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोंस्की ने कहा कि पॉलिटिक्स और बिजनेस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा हमारे लिए काफी अहम है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी 21-23 अगस्त तक पोलैंड आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 23 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन रवाना हो जाएंगे। पोलैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड जामनगर और कोल्हापुर के महाराजाओं के स्मारकों का दौरा भी कर सकते हैं। यह भारत और पोलैंड के बीच ऐतिहासिक संबंधों की निशानी है। महाराजा दिग्विजय सिंहजी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हजारों पोलिश शरणार्थियों को शरण दी थी।

प्रधानमंत्री मोदी के पोलैंड दौरे पर पोलैंड के राजदूत सेबेस्टियन डोमजाल्स्की ने कहना है कि भारत दुनिया की आवाज है। मोदी की यात्रा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ताकतवर संदेश देगी कि भारत शांति के पक्ष में हैं। उनके यात्रा के दौरान, तकनीक, डिफेंस और सुरक्षा बातचीत के अहम मुद्दें रहेंगे।आपको बता दें कि सबसे पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 25 जून 1955 को पोलैंड गए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी 8 अक्टूबर 1967 को पोलैंड यात्रा पर गई थी। फिर मोरारजी देसाई 14 जून 1979 को पोलैंड यात्रा पर जाने वाले आखिरी भारतीय प्रधानमंत्री थे। इसके 45 साल बाद अब मोदी वहां जा रहे हैं।

पोलैंड यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। मोदी पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन जाएंगे। रूस-यूक्रेन जंग के बीच उनका यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर भी गए थे।प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है, जब यूक्रेन ने कुछ दिनों से रूस की सीमा में घुसकर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने रूस के कुछ इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है।

भारत और पोलैंड के बीच 2023 में 5।72 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। 2013 से 2023 तक दोनों देशों के बीच 192% व्यापार बढ़ा है। 2023 में भारत ने पोलैंड के साथ 3।95 बिलियन डॉलर का निर्यात और 1।76 बिलियन डॉलर का आयात किया था।भारत का पोलैंड में 3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का निवेश है। भारतीय आईटी कंपनियां पोलैंड में लगभग 10,000 लोगों को रोजगार देती है। वहीं, पोलैंड का भारत में 685 मिलियन डॉलर का निवेश है।

गौरतलब है कि भले ही 45 सालों से कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पोलैंड के साथ खराब रिश्ते हैं।भारत और पोलैंड के बीच लंबे समय से दोस्ती वाले रिश्ते हैं। दोनों देशों ने 1954 में राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद 1957 में वारसॉ में भारतीय दूतावास खोला गया।पंडित नेहरू की 1954 में पोलैंड विजिट के बाद 1979 तक भारत के श्क्ख्ढ का पोलैंड राजनीतिक दौरा होता रहा। 1989 में पोलैंड द्वारा लोकतांत्रिक मार्ग चुनने के बाद भी संबंध घनिष्ठ बने रहे। 2004 में पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद भी दोनों देशों के बीच रिश्ते अच्छे रहे और मध्य यूरोप में पोलैंड भारत का एक मुख्य भागीदार के रूप में उभरा।

भारत और पोलैंड कई क्षेत्रों में साझेदार जिसमें कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विदेश कार्यालय, आतंक और क्राइम, डिफेंस, आर्थिक सहयोग, हेल्थ केयर और कोल एंड माइनिंग आदि शामिल हैं।इसके अलावा पोलैंड ने 1989 में लोकतंत्र अपनाने के बाद एक डेलिगेशन भारत भेजा था, जिसने भारत के विशाल लोकतंत्र को समझा और अपने देश में भारत जैसा लोकतंत्र स्थापित करने की कोशिश की। भारत के लोकतंत्र को समझने के लिए पोलैंड ने 1992, 2000, 2002 और 2003 अपने डेलिगेशन भारत भेजे हैं। 2002 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी के नेतृत्व में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भी पोलैंड का दौरा किया था।

पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश पार्टनर है। 2013-2023 के बीच पोलैंड के साथ कुल द्विपक्षीय कारोबार में 192 फीसद की बढ़ोतरी देखी गई है, जोकि 2013 में 1।95 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2023 में 5।72 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।भारत से पोलैंड एक्सपोर्ट होने वाले सामानों में कपड़ा, बैस मेटल, केमिकल प्रोडक्ट्स, मैकेनिकल प्रोडक्ट्स, फुटवियर और हेडगेयर, प्लास्टिक, रबर और उनसे बने समान, सिरेमक, फूड आइटम्स और वनस्पति शामिल हैं। अगर इंवेस्टमेंट की बात करें तो भारत में पोलैंड का कुल निवेश 685 मिलियन डॉलर का है। वहीं भारत का पोलैंड में निवेश भी साल दर साल बढ़ रहा है और अब वे करीब 3 बिलियन डॉलर का हो गया है। भारत की कई कंपनियां पोलैंड के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। पौलेंड के लोगों का योग करने में भी पुराना इतिहास है। पौलेंड का योगा इतिहास लगभग 100 साल पुराना है और भारत की तरह ही यहां भी लोग योगा की खूब दीवाने हैं। पौलेंड में करीब 3 लाख लोग योगा करते हैं। हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पौलेंड में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौलेंड में करीब 25 हजार भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। इनमे से ज्यादातर व्यापारी और नौकर पेशा है जो कम्यूनिज्म के पतन के बाद यहां आए हैं। इसके अलावा करीब 5 हजार भारतीय छात्र पोलैंड में पढ़ाई कर रहे हैं और 1 हजार के करीब यहां भारतीय रेस्तरां हैं।

पोलैंड के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वे 23 अगस्त को यूक्रेन राजधानी कीव पहुंचेंगे और करीब सात घंटे तक वहां रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड के दौरे के बाद ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय करेंगे और कीव पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस का दौरा किया था। यूक्रेन और रूस के बीच करीब ढाई साल से युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में डटी हैं।

सोमवार को भारत ने एक बयान में कहा, हम रूस-यूक्रेन के बीच शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हरसंभव मदद देने के लिए तैयार हैं। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मोदी की 23 अगस्त की यात्रा की घोषणा की और कहा, यह एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। यूक्रेन की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की दो दिवसीय यात्रा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड से कीव तक ट्रेन से यात्रा करेंगे, जिसमें करीब 10 घंटे लगेंगे। वापसी भी उतनी ही अवधि की होगी। रूसी क्षेत्र में कीव के ताजा सैन्य हमले के बीच प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा हो रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत कई वैश्विक नेता भी ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे। ये नेता यूक्रेनी बॉर्डर के पास पोलिश ट्रेन स्टेशन से ट्रेन के जरिए कीव की यात्रा पर गए। प्रधानमंत्री मोदी की कीव यात्रा, मॉस्को की उनकी हाई-प्रोफाइल यात्रा के कुछ सप्ताह बाद हो रही है। उस समय अमेरिका और उसके कुछ पश्चिमी सहयोगियों ने आलोचना की भी थी।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताने के अनुसार भारत के रूस और यूक्रेन दोनों के साथ ठोस और स्वतंत्र संबंध हैं और ये साझेदारियां अपने दम पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत और यूक्रेन के बीच निरंतर जुड़ाव को आगे बढ़ाएगी। लाल ने कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस यात्रा का उद्देश्य दूसरे के नुकसान से अपना फायदा पाना नहीं है। प्रधानमंत्री ने रूस की यात्रा भी की थी। कई विचारों पर चर्चा की गई थी।उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने पिछले एक साल में कुछ मौकों पर राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात की और अब वे यूक्रेन में फिर से मिलेंगे। उन्होंने कहा, मैं कहना चाहूंगा कि ये स्वतंत्र व्यापक संबंध हैं और निश्चित रूप से जारी संघर्ष भी चर्चा का हिस्सा होगा।

यूक्रेन में संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर लाल बताते है कि भारत इस जटिल मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में मदद के लिए हरसंभव सहायता और योगदान देने को तैयार है। साथ ही उन्होंने मोदी और जेलेंस्की के बीच वार्ता के नतीजे का पूवार्नुमान लगाने से इनकार कर दिया। लाल ने कहा, भारत ने बहुत स्पष्ट और सुसंगत रुख बनाए रखा है कि कूटनीति और बातचीत से इस संघर्ष को हल किया जा सकता है जिससे स्थायी शांति हो सकती है।

उन्होंने कहा, इसलिए बातचीत बिल्कुल जरूरी है। स्थायी शांति सिर्फ उन विकल्पों के जरिए हासिल की जा सकती है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हों और सिर्फ बातचीत से ही समाधान हो सकता है। भारत सभी हितधारकों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है।

लाल ने यह भी कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के बातचीत के जरिए समाधान तक पहुंचने के लिए लगातार कूटनीति और बातचीत की वकालत करता रहा है। लाल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। युद्ध के मैदान में समाधान नहीं ढूंढे जा सकते। यह एक स्पष्ट और सुसंगत स्थिति है जिसे भारत ने अपनाया है और हमारा मानना है कि अधिकांश देश इस दृष्टिकोण को साझा करते हैं।

यूक्रेन के साथ भारत के संबंधों पर उन्होंने कहा कि यह संबंध निरंतर और दीर्घकालिक हैं। लाल ने कहा, यह एक ऐतिहासिक यात्रा है क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद 30 से ज्यादा वर्षों में यह पहली बार होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी-जेलेंस्की वार्ता में कृषि, बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य और शिक्षा, रक्षा और लोगों से लोगों के संबंधों सहित भारत-यूक्रेन संबंधों के संपूर्ण आयाम पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।

जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन आने का दिया था न्योता

मोदी ने जून में इटली के अपुलीया में जी7 शिखर सम्मेलन से इतर जेलेंस्की के साथ बातचीत की थी। बैठक में मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति को बताया कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपने साधनों के भीतर सब कुछ करना जारी रखेगा और शांति का रास्ता संवाद और कूटनीति के माध्यम से है। मोदी ने जेलेंस्की को यह भी बताया कि भारत यूक्रेन में संघर्ष का समाधान खोजने के लिए मानव-केंद्रित दृष्टिकोण में विश्वास करता है। बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को कीव आने का निमंत्रण दिया था।

राजपूताना की अदम्य साहसी, और रूपवती राजकुमारी रत्नावती

-सुरेश सिंह बैस शाश्वत

जैसलमेर के बड़े प्रतापी राजा नरेश महारावल रत्नसिंह का राज्य अजमेर भानगढ़ में चहुँ ओर अमन चैन के साथ स्थापित था। रत्नसिंह ने एक बार जैसलमेर भानगढ़ किले की रक्षा अपनी पुत्री राजकुमारी रत्नावती को सौंप दी थी। इसी दौरान दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन की सेना ने किले को घेर लिया जिसका सेनापति मलिक काफूर था। राजकुमारी रत्नावती ने अपने पिता को चिंतामुक्त होने को कहा की आप दुर्ग की तनिक भी चिंता ना करे। जब तक मुझमे प्राण है तब तक अल्लाउदीन इस दुर्ग की एक ईंट भी नहीं उठा पायेगा।अपनी पुत्री के इस साहस भरे शब्दों को सुन रावल रत्नसिंह जी ने अस्त्र-शस्त्र धारण किये और निकल पड़े तुकीर्यों से लोहा लेने। किले के सभी सामंत निकल चुके थे। केसरिया धारण कर रण करने। किले के द्वार से निकलते ही दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ।किले के चारों ओर मुगल सेना ने घेरा डाल लिया किंतु राजकुमारी रत्नावती इससे घबराई नहीं और सैनिक वेश में घोड़े पर बैठी किले के बुर्जों व अन्य स्थानों पर घूम-घूमकर सेना का संचालन करती रहीं। तुर्की समझ गये थे, कि दुर्ग विजय करना हंसीहट्टा नहीं हैं. दुर्ग रक्षिणी राजनन्दिनी रत्नवती निर्भय अपने दुर्ग में सुरक्षित शत्रुओ के दांत खट्टे कर रही थी. उसकी सेना में पुराने विश्वस्त राजपूत थे, जो मृत्य और जीवन का खेल समझते थे। वे अपनी सखियों समेत दुर्ग के किसी बुर्ज पर चढ़ जाती थी, और यवनों का ठट्ठा उड़ाती हुई वह वहा से सनसनाते तिरो की वर्षा करती`वह कहती - मै स्त्री हू, पर अबला नही` मुझमे मर्दों जैसा साहस और हिम्मत है। मेरी सहेलियाँ भी देखने भर की स्त्रिया है। मै इन पापिष्ठ यवनों को समझती क्या समझूँ। ₹उसकी बाते सुनकर सहेलिया ठठाकर हंस देती थी प्रबल यवनदल द्वारा आक्रांत दुर्ग में बैठना राजकुमारी के लिए एक विनोद था। मलिक काफूर एक गुलाम था जो यवन सेना का अधिपति था वह द्रढ़ता और शांति से राजकुमारी की चोटें सह रहा था उसने सोचा था कि जब किले में खाद्य पदार्थ कम हो जाएगे, तब इन्हें हथियार डालने पर मजबूर किया? जा सकता है। लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजकुमारी रत्नावती ने सेनापति काफूर सहित सौ सैनिकों को ही बंधक बना लिया। अब इस दौरान किले में रसद की काफी किल्लत हो गई। बाहर अलाउद्दीन खिलजी भारी सैनिकों के साथ घेरा डाले मौजूद हो गया था। ऐसे में राजकुमारी रत्नावती भूख से दुर्बल होकर पीली पड़ गईं किंतु ऐसे संकट में भी राजकुमारी रत्नावती द्वारा राजधर्म का पालन करते हुए अपने सैनिकों को रोज एक मुट्ठी और मुगल बंदियों को दो मुट्ठी अन्न रोज दिया जाता रहा। अलाउद्दीन को जब पता लगा कि जैसलमेर किले में सेनापति कैद है और किले को जीतने की आशा नहीं है तो उसने महारावल रत्नसिंह के पास संधि-प्रस्ताव भेजा। राजकुमारी ने एक दिन देखा कि मुगल सेना अपने तम्बू-डेरे उखाड़ रही है और उसके पिता अपने सैनिकों के साथ चले आ रहे हैं। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति जब किले से छोड़ा गया तो वह रोने लगा और उसने कहा- 'यह राजकुमारी साधारण लड़की नहीं, यह तो वीरांगना के साथ देवी भी हैं। इन्होंने खुद भूखी रहकर हम लोगों का पालन किया है। ये पूजा करने योग्य आदरणीय हैं।' ये थी भारत भूमि की वो वीरांगना जिसने अपने पराक्रम और बहादुरी से अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में हमेशा के लिए दर्ज करा लिया, इन को हमारा शत-शत नमन है। भानगढ़ के किले से जुड़ा एक बड़ा रहस्य है। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती जो केवल दस वर्ष की थी और वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमारी के सुंदरता के चर्चे दूर-दूर तक फैले थे। इसलिए देश के हर कोने का राजकुमार उनसे शादी करना चाहता था। एक बार एक तांत्रिक ने राजकुमारी को देखा तो वह राजकुमारी के प्रति आसक्त हो गया। वह राजकुमारी को देखकर इतना मोहित हो गया कि अपने काले जादू के दम पर पाने की सोच बैठा। एक दिन राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ किले से बाहर निकली और हाट गई। उसी वक्त तांत्रिक ने राजकुमारी को पाने के लिए एक दुकान से इत्र की शीशी और उससे राजकुमारी पर काला जादू करना चाहा। इसके बाद तांत्रिक इत्र की दुकान से थोड़ा दूर खड़ा हो गया। जब राजकुमारी ने उस इत्र की शीशी को खोला, जिससे राजकुमारी को कैद करने की कोशिश की गई थी। वह तुरंत समझ गई कि इसमें तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया है। इसके बाद राजकुमारी ने इत्र की बोतल को उठाकर पास ही एक पत्थर पर दे मारा। किस्मत से उसी पत्थर के पास वह तांत्रिक बैठा था। बोतल टूट गई और पूरा इत्र पत्थर पर बिखर गया। शीशी टूट जाने पर पत्थर से तांत्रिक की मौके ही मौत हो गई। लेकिन मरने से तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे। वे फिर से पैदा नहीं हो पाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मृत्यु के कुछ दिन बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सभी लोग मारे गए। यहां तक कि राजकुमारी भी तांत्रिक के श्राप से खुद को नहीं बचा पाई और उनकी भी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तबसे भानगढ़ आत्माओं का किला बना हुआ है। बाद में अजबगढ़ और भानगढ़ के बीच लड़ाई के दौरान रानी रत्नावती की हत्या कर दी गई और ऐसा माना जाता है कि रानी और जादूगर का भूत अभी भी परिसर में घूम रहा है और सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में रहने या प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस तरह भानगढ़ भारत की सबसे प्रेतबाधित जगहों में से एक बन गया है। ऐसा कहा जाता है कि रात में भानगढ़ किले में आत्माएं घूमती हैं और कई तरह की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही, जैसा कि कहा जाता है, जो कोई भी रात में किले में प्रवेश करता है, वह सुबह वापस नहीं आ पाता। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कोई उनकी हरकतों पर नजर रख रहा है, और हवा में चक्कर आने जैसा भारीपन है।

एक हत्याकांड से सहारे राहुल की फिर हिन्दुओं को बांटने की साजिश

-संजय सक्सेना

कांग्रेस के ब्रांड अम्बेसडर और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जिस तरह की जातिवादी राजनीति कर रहे है,वह देश और समाज के लिये काफी घातक है। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिये हिन्दू समाज को बांटने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। यह सिलसिला राहुल ने काफी पहले शुरू कर दिया था। इस साल हुये आम चुनाव के बाद तो राहुल ने हिंदुओं को बांटने की साजिशें और भी तेज कर दी हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पारसी दादा फिरोज घांडी के पौत्र राहुल गांधी अपनी जाति धर्म तो छिपाते हैं पर हर हर हिन्दू युवक से उसकी जाति पूछना वह अपना अधिकार समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि राहुल गांधी के दादा फिरोज घांडी को गांधी उपनाम कैसे मिला? कई किताबें कहती हैं कि घांडी फिरोज का कुलनाम था, जो पारसी धर्म में एक जाति विशेष का उपनाम होता है। फिरोज का उपनाम घांडी लोगों की जुबान पर नहीं चढ़ा था,एक तो घांडी उपजाति वाले पारसियों की आबादी बेहद कम थी दूसरे उस समय तो सब गांधी के पीछे भाग रहे थे। अज्ञानतावश लोग फिरोज घांडी को भी फिरोज गांधी कहकर बुलाने लगे,जिसका फिरोज को फायदा भी मिला,इसलिये उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन यह भी हकीकत है कि वह मरते दम तक पारसी ही रहे उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। पारसी समाज के रीतिरिवाज के अनुसार ही उनकी अंतिम क्रिया हुई थी।

खैर, यह सब इस लिये याद आ गया क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हुई एक हत्या के सहारे हिन्दुओं को आपस में लड़ाने के लिये बिसात बिछा रहे हैं। बता दें पिछले दिनों राबयरेली में आपसी लड़ाई झगड़े में पासी समाज के युवक अर्जुन की हत्या कर दी गई थी। यह एक आपरधिक घटना थी जिसे राहुल गांधी ने दलित बनाम सवर्ण सियासत में बदल दिया।अपनी इसी सियासी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिये 20 अगस्त मंगलवार को रायबरेली पहुंचे। उन्होंने यहां अर्जुन पासी के परिजनों से मुलाकात की। भरोसा दिया कि उत्पीड़न के मामले को सड़क से सदन तक उठाया जाएगा। राहुल गांधी इस हत्याकांड के सहारे अगड़ों और दलितों के बीच खाई पैदा करने का कुच्रक रचने लगे।बता दें राहुल गांधी दलित समाज के युवक अर्जुन पासी के मामले को लेकर विधानसभा की 103 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं।उनकी पार्टी यह भी रणनीति बना रही है कि दलितों से जुड़े मुद्दे पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भी अब अर्जुन पासी की हत्या का मुद्दा उठाया उत्तर प्रदेश में जाटवों के बाद पासी दूसरा सबसे बड़ा दलित समुदाय है, जो राज्य की कुल अनुसूचित जाति आबादी का लगभग 16 प्रतिशत है। समाज के लोगों का दावा है कि वे करीब 103 सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिसमें 70 सीटें ऐसी हैं, जहां पासी समाज ही निर्याणक भूमिका में हैं। राहुल गांधी यह सब तब कर रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही गोली मारकर अर्जुन पासी की हत्या के मामले में परिजनों की शिकायत पर पांच लोगों पर नामजद एफआईआर की जा चुकी है और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। बाकी का काम अदालत को करना है। इस मामले में बाद में ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि पर भी कुछ संगठनों ने हत्याकांड में शामिल होने का आरोप जड़ दिया. हालांकि, इस संबंध में पुलिस ने कहा है कि परिजनों ने जिसके खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज करवाई है उन पर कार्रवाई की गई है।

उधर, रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, यहां पर जो सभी लोग हैं, वो न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि एक दलित युवक को जान से मारा गया है. पूरे परिवार को धमकाया गया है. एक शख्स को मारा गया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. यहां के पुलिस अधीक्षक हत्याकांड के मास्टरमाइंड पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. छोटे-छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं. उत्तर प्रदेश में हर वर्ग का आदर हो और न्याय सबको मिले. जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं. संगठनों के दबाव में पुलिस द्वारा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का नाम हत्याकांड में न जोड़े जाने पर रायबरेली में इस मामले को दलित बनाम सवर्ण बना दिया गया है। पुलिस ने छह आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है और मुख्य आरोपी विशाल सिंह की गिरफ्तारी की मांग उठाते हुए लोगों का प्रदर्शन जारी है।

अपोलो सर्वश्रेष्ठ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सम्मानित

नवी मुंबई। अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई प्रतिष्ठित नवभारत हेल्थ केयर समिट एंड अवॉर्ड्स 2024 में मुंबई के सर्वश्रेष्ठ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सम्मानित हुआ। यह पुरस्कार न केवल उत्कृष्टता का प्रतीक है, बल्कि प्रदान करने के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता की हार्दिक स्वीकृति है। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल जो करुणा और मानवीय संबंध में गहराई से निहित है। यह हमारे मरीजों के हम पर विश्वास और प्यार को दशार्ता है, जो हमें सहानुभूति, समर्पण और देखभाल के साथ उपचार के अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करता है। रुणेश पुनेठा, क्षेत्रीय सीईओ - पश्चिमी क्षेत्र, अपोलो अस्पताल,यह पुरस्कार अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में हमारी पूरी टीम के समर्पण और जुनून का प्रतिबिंब है। हर दिन, हम जीवन को छूने, ठीक करने और अपने रोगियों और उनके परिवारों में आशा लाने का प्रयास करते हैं। सर्वश्रेष्ठ सुपर के रूप में पहचाना जा रहा है मुंबई में स्पेशलिटी अस्पताल हमारे अस्पताल के लिए सिर्फ एक प्रशंसा नहीं है, बल्कि हमारे मरीजों द्वारा हम पर रखे गए प्यार और विश्वास का प्रमाण है। हम करुणा और सहानुभूति के साथ स्वास्थ्य देखभाल के उच्चतम मानकों को प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर मरीज को यह सुविधा मिले हमारे दरवाजों को यथासंभव सर्वोत्तम देखभाल मिलती है। डॉ. किरण शिंगोटे, यूनिट प्रमुख, अपोलो अस्पताल, नवी मुंबई ने कहा,₹यह पुरस्कार उन अनगिनत जिंदगियों की याद दिलाता है जिन्हें हमने छुआ है और जो मुस्कान हम अपने मरीजों के चेहरे पर वापस लाए हैं। हमारा यह यात्रा पुनर्प्राप्ति, लचीलेपन और आशा की कहानियों से प्रेरित है जो हमारे मरीज हमारे साथ साझा करते हैं। यह मान्यता हमें न केवल सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है बल्कि प्रत्येक मरीज के लिए उपचार और आराम का स्थान भी प्रदान करती है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

महिलाओं की सुरक्षा है जरुरी

कोलकाता के आरजी कर हॉस्टिल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप मर्डर मामले में सियासत चरम पर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गुरुवार को राजभवन पहुंचीं। लेकिन चाय पार्टी के बाद उन्होंने बीजेपी और वामपंथी दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा, बुधवार रात हॉस्पिटल में जो कुछ उपद्रव हुआ, उसके लिए यही दोनों दल जिम्मेदार हैं। लेकिन बोलते-बोलते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया। ममता ने कहा, बीती रात अस्पताल में जो कुछ हुआ वह 'बाम और राम' का कारनामा है। इसमें भगवान राम का नाम लेना अनुचित है जिस नाम पर को सत्य और तारनहार कहा जाता है जो हमारे समझ से बाहर है उसपर राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐ नाम तो ऐसा है जो हर हिन्दू के लिए मरने जीने का सबाल हो जाता है वो एक दीन दु:खियों की रक्षा करते हैं उनके नाम को बदनाम करना अनुचित है और पाप के भागीदार ही बन सकते हैं मान्यताओं के अनुसार, भगवान राम का नाम ही छोटा सा शक्तिशाली महामंत्र है, जिसके सिर्फ जपने से ही व्यक्ति को सही मार्ग दिखने लगता है। हिंदू धर्म के अनुसार, राम का नाम इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक लिया जाता है। भगवान राम का जाप करने से व्यक्ति को सही कार्य करने की शिक्षा मिलती है। राम केवल एक नाम भर नहीं, बल्कि वे जन-जन के कंठहार हैं, मन-प्राण हैं, जीवन-आधार हैं। उनसे भारत अर्थ पाता है। वे भारत के प्रतिरूप हैं और भारत उनका। उनमें कोटि-कोटि जन जीवन की सार्थकता पाता है। भारत का कोटि-कोटि जन उनकी आँखों से जग-जीवन को देखता है। उनके दृष्टिकोण से जीवन के दर्भों-परिप्रेक्ष्यों-स्थितियों-परिस्थितियों-घटनाओं-प्रतिघटनाओं का मूल्यांकन-विश्लेषण करता है। भारत से राम और राम से भारत को विलग करने के भले कितने कुचक्र-कलंक रचे जाएँ, भले कितनी *वामी-विदेशी* चालें चली जायँ, यह संभव होता नहीं दिखता। क्योंकि राम भारत की आत्मा हैं। राम भारत के पर्याय हैं। राम निर्विकल्प हैं, उनका कोई विकल्प नहीं। जिस प्रकार आत्मा को शरीर से और शरीर को आत्मा से कोई विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार राम को भारत से विलग नहीं किया जा सकता। राम के सुख में भारत के जन-जन का सुख आश्रय पाता है, उनके दु:ख में भारत का कोटि-कोटि जन आँसुओं के सागर में डूबने लगता है और वे अश्रु-धार भी ऐसे परम-पुनीत हैं कि तन-मन को निर्मल बना जाते हैं। अश्रुओं की उस निर्मल-अविरल धारा में न कोई ईर्ष्या शेष रहती है, न कोई अहंकार, न कोई लोभ, न कोई मोह, न कोई अपना, न कोई पराया। कैसा अद्भुत है यह चरित-काव्य, जिसे बार-बार सुनकर भी और सुनने की चाह बची रहती है और रसपान की प्यास बनी की बनी रह जाती है! कैसा अद्भुत है यह नाम जिसके स्मरण मात्र से नयन-चकोर उस मुख-चंद्र की ओर टकटकी लगाए एकटक निहारते रह जाते हैं! उस चरित्र को अभिनीत करने वाले, उस चरित्र को जीने वाले, लिखने वाले हमारी आत्यंतिक श्रद्धा के सर्वोच्च केंद्रबिंदु बन जाते हैं। उसके सुख-दु:ख, हार-जीत, मान-अपमान में हमें अपना सुख-दु:ख, हार-जीत, मान-अपमान प्रतीत होने लगता है। उसकी प्रसन्नता में सारा जग हँसता प्रतीत होता है और उसके विषाद में सारा जग रोता। कोलकाता में डॉक्टर लेडी का रैप और मर्डर का मामला को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को सख्त सजा देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी भी घटना को पार्टी के हित में नहीं जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए क्योंकि जनता के वोटो से ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है अत: पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए।

मन एक बीज है, इसे वृक्ष बनने दें

– आत्माराम यादव पीव

यह सारी सृष्टि अपना विशाल फन फैलाये धरा से क्षितिज तक फुँकार मार रही है। यहा धरा पर सभी ओर सभी जगह अपना अपना पाप ओर पुण्य की गठरी लिए मनुज गिंजाइयों की तरह तीर्थों मे अपने मन के तारों से अपनी साधना का करंट विस्तारित कर रहे है। तीर्थों में स्नान ध्यान पूजा सहित चारों धाम के अलावा सारे ज्योतिर्लिंग-शक्तिपीठ एवं स्थानीय प्रसिद्धि लिए मंदिरों में अपनी मनौती की उम्मीद लिए भावनाओं के सैलाब में डूबे हुए लोगों की भीड़ देखकर लगता है ये सभी लोग अपने अपने आराध्य को मन से ह्रदय से जान चुके है, समझ चुके है तभी पैदल नंगे पाँव भूख प्यास त्यागकर भक्ति से खिंचे चले आ रहे है। अगर इन सभी के मन के अंदर झाँका जाये तो जो यथार्थ का प्रतिबिंब दिखेगा वह चौकाने वाला होगा, इनके मन में कहीं भी अपने आराध्य या देवी देवताओं के प्रति सच्चा प्रेम नही मिलेगा। सुबह जागने से सोने तक प्रतिदिन की दिनचर्या में कितना समय वह अपने आत्मकल्याण हेतु त्रिसंध्या साधना के साथ अपने मन को एकाग्र कर अपने चरित्र निर्माण के लिए लगाता है तो उत्तर नकारात्मक होगा। कारण आज सोने से लेकर जागने तक मोबाइल उसके जीवन में उसका संगी साथी ओर गहरा मित्र हो गया है, इस मोबाइल ने सभी से भावनात्मक सम्बन्धों को बिगाड़ने का काम किया है ओर उसे घर परिवार से मिलने वाले आचरण में दया, करुणा, प्रेम-संतोष आदि भावनाओं से दूर किया है इसलिए आज इन व्यवहारिक प्रवृत्तियों के स्थान पर उसके मन में भ्रम, कुंठा ओर प्रलोभन एक विराट सत्य की तरह बस गए है, जिसे पोषित करने, फलित करने के लिए ये नवांकुर पीढ़ी अपने अहंकार के दलदल में गले तक डूबे हुए है।

अज्ञानता के रहते हमने मन को अंधेरे से डरना सिखाया है इसलिए वह अंधेरे से डरता है। हमारे पूर्वजों ने अंधेरे से प्यार किया है पर हम सभी मिलकर अंधेरे को जहर देकर मारना चाहते है। हम अधूरे सत्यों को ग्रहण करते है ओर उसे अपनी कृपणता से उसे आपस में बांट लेते है जैसे आदमी को वर्गों में काटकर जातियो में बाँटने का जघन्य अपराध किया है। मन को हमेशा मनजीत होना चाहिए, जो सभी के मनों को जीतकर मनजीत हुआ जा सकता है। मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं है इसलिए मन को कैसे जीते इसके लिए मनरूपी दर्पण पर जो अहंकार छा गया है, उसे दूर करने के लिए अंधश्रद्धा को मत थामिए, भीड़ अन्धो की होती है, भीड़ मतवाली पागल होती है, धर्म के नाम इनसे बचिए ओर मन को अपने में एकाग्र कर मन की शक्ति को जगाईये, अपने को पहचानिए आप कौन है, आपका चरित्र क्या है, अपने मूल चरित्र के स्वामी बनिए।

चरित्र किसी को उत्तराधिकार में नहीं मिलता है, माता पिता से व्यावहारिक बातें सीखने को मिलती है, आज शिक्षण संस्थाओं में मिलने वाले किताबी ज्ञान ने गुरु की महत्ता को कम किया है, आए दिन जो माँ सरस्वती के देवालय समझे जाने वाले इन स्कूलों में गुरु ओर शिष्य के बीच संस्कार का क्षय होना, ज्ञान के व्यावसायिक स्वरूप के कारण है। पहले गुरु को चरित्र निर्माता के साथ भाग्य का सृजक भी माना जाता था किन्तु आज शिक्षा के इस व्यवसाय में प्रत्येक बच्चे को प्रतिस्पर्धा का रोगी बना दिया है ओर माता पिता इस विषमय परिणामों के लिए अपने बच्चों से शत प्रतिशत अंक लाने की अपेक्षा में गर्व महसूस करते है, एक दो प्रतिशत कम लाने पर उन्हे शर्म महसूस होती है, बस इसी प्रकार की आशाओं के पूरा न होने पर बच्चे निराशावादी हो जाते है। उनका मन सहानुभूति ओर परोपकार से पूर्ण होना चाहिए किन्तु अपने घर परिवार के सदस्य या मित्र के बीच एक दो प्रतिशत कम आने पर हीनता का भाव जाग जाता है, जो आगे चलके उसके चरित्र को प्रभावित करता है। अगर उसे जरा भी आभासित होता है की उसका तिरस्कार किया जा रहा है या उसके साथ भेदभाव कर उसे नजरअंदाज किया जा रहा है तो वह मन में कुंठा लिए अपने घर परिवार ओर समाज के प्रति परस्पर विपरीत विचार लाकर या तो घातक कदम उठाकर आत्महत्या कर लेता है या अपने मन को विपरीत दिशा में खाद पानी देकर तैयार करना शुरू करता है, भले आपकी दृष्टि में वह कदाचरण हो, लेकिन उसके इस तरह के चरित्र निर्माण के लिए वह नहीं आप ओर हम सभी दोषी होते है जो उसके बाल सुलभ मन को एक विशाल छायादार फलदार बीज के रूप में अंकुरित कर सकते थे, वह सब करने से हम चूक गए ओर उसके मन में जहर घोलकर उसकी निर्णात्मक चेतना को जागने से पूर्व सुलाने में सफल हुये। इन हालात ओर परिस्थितियों से उबरने के लिए अगर घर परिवार या मित्रों में कोई सहानुभूति ओर सहयोग मिल जाये तो वह अपने चरित्र का निर्माता तो होगा ही वही वह देश दुनिया में अपनी पृथक पहचान बनाने में सफल होगा ओर जो इससे वंचित रहा वह अब पूरे जीवन इसी चरित्र को अपने मन की कुंजी समझ कर वह खुदके लिए निर्णय लेकर अपने मन पर विजय हासिल नहीं कर सकेगा, वह उदण्डता के मार्ग पर बेखौफ भागेगा। जिसका मन, अपने ह्रदय के निवासी अहंकार को जीत लेता है वह नाभि में स्थित चित्त के अनुकूल होकर बुद्धि ओर अहंकारजयी हो जाता है, मन के द्वारा बुद्धि ओर अहंकार को जीतना मनजीत होना है ओर जो मनजीत होता है उसके जीवन में महावृक्ष बनने की सारी बाधाए समाप्त हो जाती है। मन को जीतने वाला अपना दीपक आप हो जाता है।

(वरिष्ठ पत्रकार श्रीजगन्नाथ धाम काली मंदिर के पीछे ग्वालटोली नर्मदापुरम मध्यप्रदेश)

सस्ती एवं नकारात्मक राजनीति है लेटरल एंट्री का विरोध

यह आश्चर्जनक है कि ऐसे देश-विकास एवं राष्ट्र-निर्माण के निर्णयों एवं मुद्दों का विरोध करने की राजनीति की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। कम से कम उन्हें तो इससे बचना चाहिए,क्योंकि राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त सचिव के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति लेटरल एंट्री ही थी और वह भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के। भारत में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है।

– ललित गर्ग –

भारतीय नौकरशाही संरचना के प्रभावी एवं परिणामकारी प्रदर्शन को निश्चित रूप से लेटरल एंट्री प्रक्रिया के साथ पूरक किया जा सकता है। लेटरल एंट्री नई बाहरी प्रतिभाओं को लाकर, सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक कल्याण के लिए और अधिक काम एवं प्रभावी काम करने के लिए प्रेरित करके नियमित सरकारी अधिकारियों को पूरक कर सकते हैं, लेकिन लेटरल एंट्री की प्रणाली को अधिक समावेशी, पारदर्शी और असरदार बनाने के लिए एक निश्चित नीति के साथ आगे बढ़ने एवं इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक रवैया अपनाना देश विकास के लिये जरूरी प्रतीत होता है। इसके लिये वर्तमान नरेन्द्र मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर राजनीति करने करने की बजाय उसमें देशहित को सामने रखा जाना चाहिए।

वैश्वीकरण ने शासन के काम को अत्यंत जटिल बना दिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और कौशल की मांग पहले से बहुत अधिक बढ़ गई है। अर्थव्यवस्था और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में थिंक-टैंकों की आवश्यकता के मद्देनजर तथा अन्य ऐसे विभागों में जहाँ विशिष्ट प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता होती है, लेटरल एंट्री से संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की जानी प्रांसगिक एवं उपयोगी कदम है। संघ लोकसेवा आयोग ने केंद्र सरकार के 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव की भूमिकाओं के लिए प्रतिभाशाली, कार्यक्षम और दक्ष भारतीय नागरिकों से 45 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करके सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री (सीधी भर्ती) का स्वागतयोग्य एवं सराहनीय प्रयोग कर रहा है। भले ही इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। वैसे भी ऐसे राजनीतिक लोगों एवं दलों की आंखों में किरणें आंज दी जाये तो भी वे यथार्थ को नहीं देख सकते। क्योंकि उन्हें उजाले के नाम से एलर्जी है। विपक्षी दलों विशेषत: कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों के आरक्षण की उपेक्षा के लिए सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री नीति की आलोचना की है। जबकि भारत में सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री का तात्पर्य सरकार के मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर पेशेवरों एवं प्रतिभाशाली कर्मियों की भर्ती से है। जिसमें प्रतिभाशाली एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य विशिष्ट कौशल और विशेषज्ञता लाना है जो पारंपरिक नौकरशाही ढांचे में उतनी प्रभावी प्रतीत नहीं हो रही है। कई संभावित और अच्छे प्रशासक हैं जो अपनी कम उम्र के दौरान सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग नहीं लेते हैं। लेटरल एंट्री उन्हें शासन तंत्र का हिस्सा बनने और राष्ट्र निर्माण में योगदान करने का अवसर प्रदान करता है। नया भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत निर्मित करने में इन प्रतिभाओं का उपयोग होना राष्ट्र में एक नयी रोशनी का अवतरण हो सकता है। देखा यह गया है कि जब भी ब्यूरोक्रेसी में सुधार की चर्चा होती है, तो इसका विरोध होने लगता है, जो विरोधाभासी एवं विडम्बनापूर्ण होने के साथ-साथ संकीर्ण राजनीति का द्योतक हैं।

कांग्रेस और कुछ अन्य दलों की ओर से जिस तरह लेटरल एंट्री पर आपत्ति जताई जा रही है, वह यही बताती है कि नकारात्मक राजनीति की जा रही है। यह आश्चर्जनक है कि ऐसे देश-विकास एवं राष्ट्र-निर्माण के निर्णयों एवं मुद्दों का विरोध करने की राजनीति की कमान राहुल गांधी अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। कम से कम उन्हें तो इससे बचना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी को यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त सचिव के रूप में मनमोहन सिंह की नियुक्ति लेटरल एंट्री ही थी और वह भी बिना किसी निर्धारित प्रक्रिया के। भारत में लेटरल एंट्री कोई नई बात नहीं है। पहले भी भारत में इसका फायदा उठाया जा चुका है। मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति लेटरल एंट्री से ही की जाती रही है। पूर्व आर्थिक सलाहकार मोंटेक सिंह अहलूवालिया, आधार की नींव रखने वाले नंदन नीलेकणि जैसी बड़ी हस्तियां इसी के जरिए प्रशासन में शामिल हुईं। यह व्यवस्था तदर्थ आधार पर की गई है, यह संस्थागत नहीं है। लेटरल एंट्री की व्यवस्था सिर्फ भारत में ही है। ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे पश्चिमी देशों में पहले से ही सभी क्षेत्रों के योग्य कर्मियों के लिए विशिष्ट सरकारी पदों को खोल दिया है। यह नौकरी के लिए बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने का एक बेहतर तरीका पाया गया है।

स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। इसके विपरीत वर्तमान सरकार एक तय प्रक्रिया के तहत लेटरल एंट्री कर रही है। इसी कारण इसकी जिम्मेदारी संघ लोक सेवा आयोग को दी गई है। कांग्रेस एवं विपक्षी दलों को यह भी पता होना चाहिए कि लेटरल एंट्री के जरिये जो नियुक्तियां की जा रही हैं, वे अस्थायी हैं। ये नियुक्तियां केवल तीन वर्ष के लिए हैं और उनमें अधिकतम दो वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। प्रशासन में सुधार की हर पहल को आरक्षण से जोड़ना केवल यही नहीं बताता कि वोट बैंक की सस्ती राजनीति अनियंत्रित हो रही है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि आरक्षण को हर मर्ज की दवा मान लिया गया है। यह ठीक नहीं कि होनी को अनहोनी बनाने का प्रयत्न हो। वैसे लेटरल एंट्री राष्ट्रहित का मुद्दा है। जिस पर 2002 की संविधान समीक्षा आयोग ने भी सिफ़ारिश वकालत की। मनमोहन सिंह के समय 2005 की द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लेटरल एंट्री के लिए एक संस्थागत और पारदर्शी प्रक्रिया की सिफारिश की। स्पष्ट है कि कांग्रेस एक बार फिर अपने शासन के समय सुधार की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध कर रही है। नीति आयोग ने अपने तीन-वर्षीय कार्य एजेंडा में लेटरल एंट्री के विचार का समर्थन किया। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि लेटरल एंट्री से विशेष ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को शामिल करके शासन में सुधार की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। शासन में सचिवों का क्षेत्रीय समूह ने भी लेटरल एंट्री प्रणाली का समर्थन किया। यह तर्क दिया गया कि लेटरल एंट्री प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले पेशेवरों को पेश करके सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावशीलता को बढ़ाया सकता है और उसे उच्च परिणामकारी बनाया जा सकता है। विरोध के लिये विरोध करने की सोच एवं उद्देश्यहीन, उच्छृंखल, विध्वंसात्मक नीति के द्वारा किसी का भी हित सधता हो, ऐसा प्रतीत नहीं होती। राहुल गांधी और कुछ अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से यह जो माहौल बनाया जा रहा है कि लेटरल एंट्री के जरिये विभिन्न मंत्रालयों में विशेषज्ञों की नियुक्तियों से आरक्षित वर्गों के हितों को नुकसान होगा, उसका इसलिए कोई औचित्य नहीं, क्योंकि यह कहीं नहीं कहा गया है कि इन वर्गों के लोग आवेदन नहीं कर सकते। राहुल गांधी किस तरह अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए एक झूठा विमर्श खड़ा रहे हैं, इसका पता इससे भी चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के समय स्वयं उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों को लेटरल एंट्री के जरिये सिविल सेवाओं में शामिल करने का वादा किया था। लेटरल एंट्री का उद्देश्य है कि जहां कहीं भी कुशल और जानकार लोग हों, उनकी प्रशासन के संचालन में सेवाएं ली जाएं, ताकि सरकारी नीतियों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसमें कोई दो राय नहीं कि ब्यूरोक्रेसी में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की भी आवश्यकता है। राजनीतिक रूप से मजबूत और स्थिर नरेंद्र मोदी की सरकार ने कंपनियों के दिवालिया होने से जुड़े विवादों के निपटारे, जीएसटी लागू करने, नोटबंदी और कृषि क्षेत्र जैसे कई अहम सुधार किए हैं। मोदी सरकार ने श्रम कानूनों को भी सरल बनाया है। लेकिन, इन सुधारों को लेकर उन्हें उस वक्त के मुकाबले कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है, जब पहले पहल इन सुधारों का प्रस्ताव रखा गया था। लेटरल एंट्री जैसे मुद्दे पर भारी विरोध के बादल मंडरा सकते हैं, इसके लिये भाजपा और साथ ही मोदी सरकार को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि विपक्षी दल उसके खिलाफ झूठा नरेटिव खड़ा कर जनता को गुमराह न करने पाएं।

(लेखक,पत्रकार, स्तंभकार ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92)

विकराल हुई मुख की बीमारियां

– बाल मुकुन्द ओझा

एक हालिया अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है मुंह का कैंसर बेहद खतरनाक है। अनुमान है कि पूरी दुनिया में हर घंटे एक इंसान की माउथ कैंसर से मौत हो रही है। ज्यादातर मुंह के कैंसर का कारण तंबाकू होता है। इसके अलावा कुछ लोगों में पुराने घाव या छालों की वजह से भी मुंह का कैंसर हो सकता है। तंबाकू, सिगरेट, सिगार, हुक्का पीने वालों में ओरल कैंसर का खतरा करीब 60 प्रतिशत ज्यादा होता है।

गुटखा, खैनी, तंबाकू सिगरेट, शराब, और पान मसाला मुख रोगों के लिए बेहद घातक और खतरनाक साबित हो रहे है। इनके सेवन से मुंह में जलन, छाले, मुंह के कम खुलने की समस्या आम है। मुंह के छाले यानी माउथ अल्सर यूं तो एक बहुत ही सामान्य परेशानी है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि यह किसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। भारत में बच्चे से बुजुर्ग तक को सरे आम इनका सेवन करते देखा जा सकता है। यह शोक अमीर से गरीब तक सभी आयु वर्ग के लोगों में है। हमारे देश में लाखों लोग आज मुख की विभिन्न बीमारियों से ग्रसित है। यह बीमारी धीरे धीरे कैंसर का रूप ले रही है जिनका इलाज असाध्य हो चला है। आईसीएमआर की रिपोर्ट को देखें तो मुख के कैंसर से मरने वालों की तादाद में हर साल वृद्धि हो रही है जो हमारे लिए बेहद चिंतनीय है। यह स्थिति तो तब है जब अनेक राज्य सरकारों ने अपने यहाँ गुटखा और पान मसाला पर रोक लगा रखी है। भारत में मुंह के कैंसर के मामले सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। यह कैंसर पुरुषों को ज्यादा होता है। मुंह के कैंसर की पहचान सामान्य जांच से हो जाती है। तम्बाकू के गुटके के रूप में खाने से सफेद दाग, मुँह का नहीं खुल पाना तथा कैंसर रोग भी हो सकता है। लगातार गुटखे या तम्बाकू का सेवन आपके दांत को ढीले और कमजोर बना देते हैं बैक्टीरिया दांतों में जगह बना लेते हैं जिससे दांतों का रंग बदलने लगता है और धीरे-धीरे दांत गलने भी लगते हैं। तम्बाकू या गुटखा लगातार खाने वालों की जीभ, जबड़ों और गालों के अंदर सेंसेटिव सफेद पेच बनने लगते हैं और उसी से मुंह में कैंसर की शुरुआत होती है जिसके बाद धीरे-धीरे मुंह का खुलना बंद हो जाता है और मुंह में कैंसर फैल जाता है।

मुँह के कैंसर का अर्थ है मौखिक गुहा (होठों से शुरू होकर पीछे टॉन्सिल तक का हिस्सा) अथवा ओरोफैरिन्क्स (गले का अंदरूनी हिस्सा) के ऊतकों में होने वाला कैंसर। जब शरीर के ओरल कैविटी के किसी भी भाग में कैंसर होता है तो इसे ओरल कैंसर कहा जाता है। ओरल कैविटी में होंठ, गाल, लार ग्रंथिया, कोमल व हार्ड तालू, यूवुला, मसूडों, टॉन्सिल, जीभ और जीभ के अंदर का हिस्सा आते हैं। इस कैंसर के होने का कारण ओरल कैविटी के भागों में कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि होती है। ओरल कैंसर होने का जोखिम उम्र के साथ बढ़ता है। ओरल कैंसर आज हमारे देश की एक प्रमुख समस्या के रुप में बीमारी उभरी है सबसे ज्यादा पुरुषों में पाया जाता है इसका मुख्य कारण पान मसाला, तंबाकू बीड़ी सिगरेट का प्रयोग करना है। एल्कोहल, सुपारी, मुंह की ढंग से सफाई ना करना और खानपान भी इसका कारण है। मुंह के अंदर गाल और जीभ में सफेद दाने होना, गुटखा और पान मसाला खाने वाले का मुंह दांत के बीच चार सेमी से कम खुलना और मुंह का कोई भी छाला या घाव इलाज के बाद भी ठीक न होना। डिब्बाबंद भोजन, तंबाकू का प्रचलन, पाउच और विभिन्न तरीके से तंबाकू की जो वैरायटी मिल रही है, उससे नई युवा पीढ़ी ज्यादा ग्रसित है। तंबाकू और पान-मसाले विभिन्न कैमिकल मिले होते हैं, उससे मुँह के भीतर की स्थिति विकट होती चली जाती है। पहली स्टेज में फाइब्रोसिस का शिकार हो जाता है। यह स्थिति प्री-कैंसर की होती है। इस स्थिति में मरीज का उपचार और निदान संभव है। फाइब्रोसिस के लक्षण यह होते हैं कि मुँह के भीतर कुछ सफेद स्पॉट आ जाते हैं या मुँह में जलन होने लगती है। मुख से संबंधित ज्यादातर बीमारी खान-पान व खासकर नशे के कारण होती है। भारत में किए गए अनुसन्धानों से पता चला है कि मुख में होने वाले कैंसर का प्रधान कारण खैनी अथवा जीभ के नीचे रखनी जाने वाली, चबाने वाली तंबाकू है। इसी प्रकार ऊपरी भाग में, जीभ में और पीठ में होने वाला कैंसर बीड़ी पीने के कारण होता है। सिगरेट गले के निचले भाग में कैंसर करती है और आंतड़ियों के कैंसर की भी संभावना पैदा कर देती है। यदि हमें एक स्वस्थ एवं खुशहाल जिन्दगी हासिल करनी है तो हमें तम्बाकू का प्रयोग हर हालत में छोड़ना ही होगा। ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तंबाकू का प्रयोग दृढ़ निश्चय करके ही छोड़ा जा सकता है।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

कविता

कृष्ण जन्माष्टमी

मोर मुकुट वाले
कान्हा की छवि
अति प्यारी
पालना झुलावे
सखियां सारी
चंहुओर खुशियां छाई
माखन मिश्री की
प्रसाद पाई
कीर्तन संग
बंसी बजाई
नृत्य कर
जन्माष्टमी मनाई
मेरा कान्हा
सबका प्यारा
घर मंदिर सजे
और सजे
यमुना तट किनारा।

संजय वर्मा 'दृष्टि'
(मनावर जिला धार मप्र)

नौकरशाही में लेटरल एंट्री का मतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) जैसे पारंपरिक सरकारी सेवा कैडर के बाहर के व्यक्तियों को सरकारी विभागों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों पर उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर भर्ती करना। इससे पहले लैटरल एंट्री के जरिए 2018 में पहली बार रिक्तियों की घोषणा की गई थी। लैटरल एंट्री करने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर तीन से पांच साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है,जिसमें प्रदर्शन और सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर विस्तार की संभावना होती है।

सरकारी नौकरियों में लैटरल एंट्री पर हंगामा गलत

– डॉ. आर.के. सिन्हा

केन्द्र सरकार के विभिन्नविभागों में अहम पदों को संभालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने हाल ही में लैटरल एंट्री या कहें कि पार्श्व प्रवेश के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए एक विज्ञापन अखबारों में निकलवाया था। इसी को लेकर देशभर में गैर-जरूरी हंगामा खड़ा हो गया या निहित स्वार्थ से भरे लोगों द्वारा खड़ा कर दिया गया था। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार में लैटरल एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यूपीएससी से कहा गया है कि वो लैटरल एंट्री से नियुक्ति न करे।

कार्मिक विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखकर कहा है कि इस नीति को लागू करने में सामाजिक न्याय और आरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए। बात बस इतनी सी थी कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने एक विज्ञापन जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ पदों पर काम करने के लिए 'प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों' की तलाश है। इन पदों में 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के शामिल हैं, जिनमें कुल 45 पदों पर भर्ती होनी है। इस विज्ञापन के छपने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सबसे ज्यादा हंगामा काट रहे थे। कह रहे थे कि केन्द्र सरकार सरकारी विभागों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े लोगों को भर्ती करना चाहती है। हालांकि हमेशा की तरह राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए किसी तरह के प्रमाण देने की जरूरत तक नहीं महसूस नहीं की। वे वैसे भी राहुल गाँधी जी हवाई बातें-दावे करने में माहिर हैं।

काश, राहुल गांधी को यह पता तो होगा ही कि देश के दस सालों तक प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह को देश का वित्त सचिव तक लेटरल एंट्री के माध्यम से ही बनाया गया था। वह तो तब तक तो वे दिल्ली विश्व विद्लाय में पढ़ा रहे थे। इसी तरह से मंटेक सिंह आहलूवालिया को भी कांग्रेस सरकार ने ही योजना आयोग का चेयरमेन बना दिया था। उनकी नियुक्ति भी उसी तरह से हुई थी जिस तरह से डॉ मनमोहन सिंह की खुद की हुई थी। इसलिए यह कहना सरासर गलत है कि मौजूदा सरकार कुछ विभागों के लिए बाहरी अभ्यर्थियों को नौकरी देकर गलत कर रही है। न जाने क्यों यूपीएससी के इस कदम ने नौकरशाही में लैटरल एंट्री पर बहस छेड़ दी। राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे थे कि यूपीएससी की भर्ती की यह प्रक्रिया 'पीछे के दरवाजे से भर्ती' है। इसे अंग्रेजी में बैक एंट्री भी कहा जा रहा है।

अब कांग्रेस के नेताओं से यह तो पूछा ही पूछा जाना चाहिए कि सैम पित्रोदा और रघुरामन राजन कौन थे ? उन्हें किस आधार पर सरकार में लैटरल एंट्री के तहत ऊंचे पदों पर नौकरी दी गई थी ?

अब जान लेते हैं कि लैटरल एंट्री होता क्या है? दरअसल नौकरशाही में लेटरल एंट्री का मतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) जैसे पारंपरिक सरकारी सेवा कैडर के बाहर के व्यक्तियों को सरकारी विभागों में मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पदों पर उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर भर्ती करना। इससे पहले लैटरल एंट्री के जरिए 2018 में पहली बार रिक्तियों की घोषणा की गई थी। लैटरल एंट्री करने वाले व्यक्तियों को आमतौर पर तीन से पांच साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, जिसमें प्रदर्शन और सरकार की आवश्यकताओं के आधार पर विस्तार की संभावना होती है। इन व्यक्तियों से ऐसी विशेषज्ञता लाने की उम्मीद की जाती है जो शासन और नीति कार्यान्वयन में जटिल चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सके। यूपीएससी के हालिया विज्ञापन से साफ था कि उसे तीन स्तरों पर योग्य उम्मीदवारों की तलाश थी- संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव। इन पदों पर तैनात अफसर अक्सर विभागों के भीतर विशिष्ट विंगों के प्रशासनिक प्रमुख या उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं और प्रमुख निर्णय लेने वाले होते हैं। लैटरल एंट्री के पीछे सरकार का तर्क यह रहा है कि नई प्रतिभा लाना और प्रशासन में कुशल जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना। आप गौर करें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब बोलते हैं, वे तब सरकार को सदैव कोसते ही रहते हैं। लोकतंत्र में सदा स्वस्थ्य वाद-विवाद और सार्थक संवाद जारी रहना चाहिए। हमेशा ही बेवजह विवाद नहीं खड़े करने चाहिए। खडगे जी कह रहे हैं कि लैटरल एंट्री से सरकारी नौकरियों में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को नुकसान होगा। राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को भी लैटरेल एंट्री पर आपत्ति है। अब इन ज्ञानी नेताओं को कोई बताए कि लैटरल एंट्री का विचार तो सर्वप्रथम कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान ही विकसित किया गया था। लैटरल एंट्री पर महाभारत करने वालों को पता होना चाहिए कि यूपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है। इसलिए इस मसले पर विवाद खड़ा करने का कोई ठोस आधार नहीं है। ऐसा करने वाले संवैधानिक संस्थानों पर आघात कर रहे हैं। दरअसल यह तो कहना पड़ेगा देश में सियासत के संसार का माहौल बहुत विषाक्त हो चुका है। सरकार के हरेक कदम का विपक्ष माखौल उड़ाता रहता है या उसमें कमियां निकालने की कोशिश करता रहता है। अगर यही रणनीति विपक्ष अपनाता रहा तो सरकार अपना कोई काम कर ही नहीं सकेगी। यकीन मानिए कि विपक्ष से यह कोई नहीं कह रहा है कि वह सरकार को उसकी किसी जन विरोधी नीतियों पर न घेरे। अवश्य घेरे और उसकी जितनी चाहे निंदा करे। पर विपक्ष को सरकार के फैसलों की सोच-समझकर ही आलोचना करनी चाहिए। अगर उसने यह न किया तो उसकी जनता के बीच छवि तार-तार हो जाएगी और वह एक ज़िम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने से वंचित हो जायेगा।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। गुरुवार, 22 अगस्त 2024

रिश्तों में संतुलन

पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को दो यूरोपीय देशों- पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पर रवाना हो गए। पहले वह पोलैंड जाएंगे। लेकिन सबकी नजरें उनके यूक्रेन दौरे पर टिकी हैं जहां युद्ध विशेष दौर में पहुंच चुका है।

रिश्तों के 70 साल | पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वह पिछले 45 वर्षों में पोलैंड जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उनकी इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होगी। ध्यान रहे, पोलैंड में रह रहे भारतीयों की संख्या करीब 25 हजार है, जिनमें 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद जब वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने की चुनौती सामने आई थी, तो पोलैंड का सहयोग अहम साबित हुआ था। तब 'ऑपरेशन गंगा' के दौरान करीब 4000 स्टूडेंट्स पोलैंड के रास्ते ही स्वदेश लाए गए थे।

पीएम की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा

मॉस्को के बाद कीव | 23 अगस्त को पोलैंड से ही ट्रेन के जरिए पीएम मोदी यूक्रेन जाएंगे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। खासकर रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में इस यात्रा की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। पिछले महीने जब पीएम मोदी रूस यात्रा पर गए थे और वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन से मुलाकात की थी, तो उस पर निराशा जताने वालों में यूक्रेन के जेलेंस्की भी थे। एक महीने के अंदर हो रही प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भारत रूस और यूक्रेन, दोनों के साथ रिश्तों को लेकर गंभीर है और युद्ध का असर अपने किसी रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहता।

युद्ध के उतार-चढ़ाव | दिलचस्प है कि जब पीएम मोदी कीव पहुंच रहे हैं तब यूक्रेन की सेना ने कुछ रूसी क्षेत्रों में दबाव बढ़ा रखा है। लेकिन भारत युद्ध के उतार-चढ़ावों से खुद को अलग रखे हुए है। उसका शुरू से कहना है कि कूटनीतिक बातचीत के जरिए ही सारे विवाद हल किए जाने चाहिए। पीएम मोदी जब 2022 में समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पूतिन से मिले थे, तब भी उनसे कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है और जब हालिया रूसी यात्रा के दौरान उनसे मिले तब भी कहा कि युद्ध के मैदान में कोई हल नहीं निकलने वाला।

स्वतंत्र और संतुलित नीति | चाहे रूस और यूक्रेन हों या अमेरिका और अन्य यूरोपीय देश, भारत किसी के भी दबाव में आए बगैर अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप स्वतंत्र और संतुलित नीति पर कायम है। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी आज भी यह उम्मीद बनाए हुए है कि दोनों देशों से करीबी की बदौलत भारत शांति प्रयासों को अंजाम तक पहुंचाने में विशेष भूमिका निभा सकता है।

साड्डी दिल्ली

मराठी समाज से दूरी

विवेक शुक्ला

पहाड़गंज के 1931 में स्थापित नूतन मराठी स्कूल के मराठी स्टाफ में आजकल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर लगातार चर्चा होती है। इस चर्चा में महाराष्ट्र के दो पूर्व मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चव्हाण और देवेंद्र फडणवीस अक्सर आ जाते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण तो कुछ हद तक दिल्ली वाले ही माने जाएंगे। उनकी स्कूली शिक्षा नूतन मराठी स्कूल में ही हुई थी। उनके पिता सांसद थे, तब उन्होंने अपने पुत्र का नूतन मराठी स्कूल में दाखिला करवाया था। लेकिन, मौजूदा पीढ़ी को देवेंद्र फडणवीस प्रभावित करते हैं। वह यहां लोकल मराठियों से भी मिलते-जुलते हैं, उनके मसले सुनते हैं।

दिल्ली हाट में लंबे समय से हो रहे गणेशोत्सव के आयोजन में यहां के हजारों मराठी भाग लेते हैं। इस बार दिल्ली हाट मैनेजमेंट ने गणेशोत्सव के आयोजन की अनुमति नहीं दी। उसका कहना है कि गणेशोत्सव के समय ही नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलजी (निफ्ट) यहां अपना कोई कार्यक्रम कर रहा है। वीरेंद्र उपाध्ये कोंकण क्षेत्र से हैं। वह राजधानी के मराठियों के बीच सक्रिय रहते हैं। उन्हें यकीन है कि कोई रास्ता निकलेगा। देवेंद्र फडणवीस से संपर्क किया जा रहा है, इस उम्मीद में कि वह उनकी मदद करेंगे। उन्हें भविष्य के यशवंतराव चव्हाण के रूप में देखने वाले भी हैं। यशवंतराव यहां के मराठी समाज के संरक्षक हुआ करते थे। वह 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद दिल्ली शिफ्ट कर गए थे। वह स्थानीय मराठियों को अपनी परंपराओं से जुड़े रहने के लिए प्रेरित करते। मराठियों की पहली संस्था महाराष्ट्रीय स्नेह संवर्धक समाज की गतिविधियों में भी वह दिलचस्पी लेते थे। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसे लाहौरी गेट के आसपास रहने वाले मराठी परिवारों ने शुरू किया था। ये सब रेलवे में थे। मूर्तिकार अनिल सूतार कहते हैं कि नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस काम करके दिखाते हैं, इसलिए उन्हें पसंद किया जाता है। यहां के मराठियों का किसी दल या गठबंधन विशेष को लेकर झुकाव नजर नहीं आता है।

दिल्ली के राजधानी बनने के बाद यहां दर्जनों मराठी परिवार आ गए थे। इन्हीं के प्रयास से करोल बाग में चोगले हाई स्कूल की स्थापना हुई। नूतन मराठी स्कूल की तरह यहां भी मराठी की कक्षाएं लगती हैं। वसंत साठे, शंकरराव चव्हाण और सुमित्रा महाजन भी स्थानीय मराठियों से मेल-मिलाप रखते थे। फिलहाल अभी कोई सांसद या मंत्री नहीं है, जो यहां के मराठियों से सीधा संपर्क रखता हो। वीरेंद्र उपाध्ये की बातों से लगता है कि महाराष्ट्र के अधिकतर नेताओं की बेरुखी से अब स्थानीय मराठी समाज उनसे दूर होता जा रहा है।

एकदा

शांति की तलाश

एक दिन एक जिज्ञासु महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, 'भगवन, आप कई वर्षों से शांति का उपदेश दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अब तक आपके उपदेशों से कितने लोगों को शांति प्राप्त हुई है।' बुद्ध मुस्कुराए और समझ गए कि यह व्यक्ति मेरी परीक्षा लेना चाहता है। वह बड़े प्रेम से बोले, 'प्रियवर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम अपने सभी परिवारजनों और मित्रों से पूछकर आओ कि वे अपने जीवन में क्या चाहते हैं?' जिज्ञासु तुरंत अपने घर गया और परिवार के सभी सदस्यों से पूछा कि वे अपने जीवन में क्या चाहते हैं? परिवार वालों की बातें सुनकर वह हैरान रह गया। किसी ने संतान की कामना की, किसी ने धन-दौलत की। कोई विवाह का इच्छुक मिला। उसने मित्रों से भी उनकी इच्छाएं पूछीं, तो उन्होंने भी इसी प्रकार भिन्न-भिन्न कामनाएं व्यक्त कीं। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी ने अपने जीवन में शांति प्राप्त करने की इच्छा जाहिर नहीं की।

Subrata Dhar

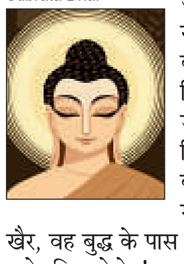

खैर, वह बुद्ध के पास पहुंचा और सबकी इच्छाएं बताईं। बुद्ध मुस्कुराने लगे। फिर बोले, 'आज संसार में अधिकतर लोग शांति चाहते ही नहीं हैं। सभी तरह-तरह की कामनाएं करते रहते हैं, और उनकी पूर्ति न होने पर दुखी होते रहते हैं। वास्तविक शांति चाहने वाले तो विरल ही होते हैं। जब तक मनुष्य को अंदर से शांति पाने की लालसा नहीं जागेगी, तब तक वह संसार में भटकता ही रहेगा। जिसे शांति की तलाश है, वह इधर-उधर की कामनाओं और उलझनों से दूर रहकर बस एकाग्र चित्त होकर शांति की खोज में ही रहता है। और एक दिन वह शांति प्राप्त कर ही लेता है।' जिज्ञासु प्रसन्न हुआ और नतमस्तक होकर चला गया।

संकलन : **रमेश जैन**

बढ़ी हुई बेरोज़गारी दर BJP के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है, पर कांग्रेस में है अंतर्कलह

हरियाणा चुनाव में किसका पलड़ा भारी?

राज कुमार सिंह

हरियाणा की सत्ता के दंगल का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि मतदाताओं ने राज्य की सत्ता की चाबी किसके हाथों दी। वैसे, हाथ कांग्रेस का चुनाव चिह्न है, जो 10 साल से राज्य की सत्ता से बाहर है और चाबी उस JJP का चुनावी चिह्न, जो गठन के साल भर के अंदर ही हरियाणा में 'किंग मेकर' बनकर तो उभरी, पर अब बिखराव के कगार पर है।

चौथे लाल का कारनामा | हरियाणा की राजनीति दशकों तक तीन चर्चित लालोंः बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के इर्दगिर्द घूमती रही। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के चलते BJP ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर सीएम के रूप में जिन मनोहर लाल को चुना, चौथे लाल के रूप में वह राज्य की राजनीति की चाल बदलने वाले साबित हुए। आज तीनों चर्चित लाल परिवार के सदस्य BJP का झंडा उठाए हुए हैं।

कांग्रेस को बढ़त | 2014 में देवीलाल परिवार की पार्टी INLD ने 15 सीटों वाली कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 19 सीटों के साथ मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया, लेकिन 2019 आते-आते सब कुछ बदल गया। देवीलाल परिवार में विभाजन से JJP जन्मी और INLD में ऐसी भगदड़ मची कि कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल गया। अब JJP में भी वैसी ही भगदड़ है। 10 में सात विधायक उसे अलविदा कह चुके हैं। हाल के लोकसभा चुनाव में JJP उम्मीदवार जमानत तक नहीं बचा पाए, जबकि कांग्रेस ने 10 में से पांच लोकसभा सीटें जीत लीं। विधानसभा क्षेत्रों की दृष्टि से देखें तो कांग्रेस ने कुल 90 में से 46 में बढ़त हासिल की, जबकि BJP ने 44 में।

हर चुनाव अलग | फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि हर चुनाव और उसके मुद्दे अलग होते हैं। 2019 के चुनाव पर ही नजर डाल लें। BJP ने लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतीं, लेकिन चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में 46 सीटों का बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। इसलिए हालिया लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 46 विधानसभा क्षेत्रों में मिली बढ़त को एक हद से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। इसलिए भी कि लोकसभा चुनाव से दो महीने पहले अचानक ही मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया, नायब सिंह सैनी

विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, किसानों की मांग और खिलाड़ियों के मुद्दे अहम रहेंगे

क्या हैं बड़े सवाल
- किसान आंदोलन का कितना असर
- अग्निपथ से असंतोष कितना निर्णायक
- पहलवानों के मुद्दे कितने प्रभावी होंगे

नए सीएम बने और JJP से गठबंधन भी टूट गया। ऐसे घटनाक्रम का अप्रत्याशित चुनावी प्रभाव और परिणाम होता है।

कांग्रेस में कलह | ऐन चुनाव से पहले होने वाले पाला-बदल का लाभ BJP के साथ ही कांग्रेस को भी हुआ है, लेकिन दस साल पहले जिस अंतर्कलह के चलते कांग्रेस की दुर्गति हुई थी, उससे वह आज भी मुक्त नहीं। दस साल मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष और उन्हीं की पसंद से उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बना कर आलाकमान ने उन्हें 'फ्री हैंड' का ही संदेश दिया है। ऐसे में हुड्डा विरोधियों के समक्ष कमल थामने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, लेकिन अभी भी कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के रूप में दो दिग्गज ऐसे मौजूद हैं, जिनकी आलाकमान तक सीधी पहुंच है। दोनों ही राष्ट्रीय महासचिव हैं।

सीएम पद पर रस्साकशी | सिरसा से सांसद चुने जाने के बावजूद सैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने का संकेत देकर साफ कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। कांग्रेस द्वारा किसी को 'सीएम फेस' पेश करने के आसार कम ही हैं, लेकिन रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह 'हरियाणा मांगे हिसाब' यात्रा निकाल रहे हैं, उसे भूपेंद्र हुड्डा द्वारा अपने बेटे को स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है। सैलजा भी अलग यात्रा निकाल रही हैं। यह खेमेबाजी टिकट वितरण में भी दिखेगी।

अन्य दलों की भूमिका | लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ने वाली AAP विधानसभा चुनाव अलग लड़ रही है, तो INLD ने BSP के साथ गठबंधन किया है। पिछले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए।

तीन स्पीडब्रेकर | इस सियासी दंगल में सबसे अहम होंगे मुद्दे। हरियाणा में बेरोजगारी की उच्च दर अरसे से चर्चा का विषय है। लेकिन BJP के लिए असल चुनौती तीन बड़े 'स्पीडब्रेकर' पार करने की होगीः किसान आंदोलन, महिला पहलवानों के दिल्ली में अनशन से बना माहौल और 'अग्निवीर' के नाम से चर्चित 'अग्निपथ' योजना। विवादास्पद कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमा पर साल से भी लंबे चले किसान आंदोलन का ठिकाना हरियाणा ही था। कांग्रेस इन सबका चुनावी लाभ उठाना चाहेगी।

सुधारात्मक कदम | BJP को इन चुनौतियों का अहसास है। इसीलिए सुधारात्मक कदम उठा कर सकारात्मक संदेश देने की कोशिश हो रही है, पर इतनी देर से की जानेवाली ये 'कुछ कोशिशें' क्या जनता का मन बदल पाएंगी- हरियाणा का जनादेश बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

कभी-कभी तो सुना है, हिला दिए हैं महल...

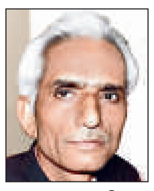

कृष्ण प्रताप सिंह

मुगल बादशाह अकबर (15 अक्टूबर, 1542-27 अक्टूबर, 1605) के वक्त उनके सबसे भरोसेमंद गवर्नर शेख अब्दुर्रहीम ने लखनऊ में छब्बीस दरवाजों वाला आलीशान किला बनवाया तो उसमें अवस्थित पांच महलों के कारण उसे 'पंचमहला' कहा गया। लेकिन यह नाम लखनवियों की जुबान पर नहीं चढ़ा और आगे चलकर वे उसे 'मच्छी भवन' कहने लगे। दरअसल, इस किले के दरवाजों की मेहराबों पर एक दूजे के दाएं-बाएं प्रसन्नमुद्रा में दो-दो मच्छियां यानी मछलियां उकेरी गई थीं, जो अरब व फारस के प्रसिद्ध 'माही मरातिब' (दि आर्डर आफ फिश) का 'नया रूप' थीं। फारस में 591 से 628 ईसवी के बीच कभी वहां के शासक और उसके साम्राज्य की आन-बान-शान से जोड़कर 'माही मरातिब' की कल्पना की गई थी- दृढ़ता, बहादुरी, शक्ति और जवानी की प्रतीक के तौर पर।

लखनवियों के 'पंचमहला' को 'मच्छी भवन' कहने के पीछे मुख्य बात यह थी कि ऐसे 'मत्स्य प्रतीकों' को प्रायः सारे धर्मों में हासिल प्रमुखता थी। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छिपा दिया, तो भगवान विष्णु ने उसके वध के लिए मत्स्यावतार लिया था। यह अवतार उनके दस अवतारों में पहला था। दूसरी ओर बौद्धधर्म में मत्स्य प्रतीक जल के जीवनदायी गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

यही कारण है कि 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में गोरे व बागी सैनिकों के बीच दो-दो हाथ का गवाह बना मच्छी भवन अब भले ही अस्तित्व में न हो, लेकिन अवध की वाराणसी की ओर की सीमा पर जौनपुर जिले के पश्चिमी भाग में पूरा 'मछली शहर' बसा हुआ है। गौरतलब है कि इस कस्बानुमा शहर को न तो नवाबों ने बसाया, न ही उस पर उनका लंबा आधिपत्य रहा। अलबत्ता, कोई डेढ़ सौ साल मुगल सल्तनत का अंग रहने के बाद जब 1722 में जौनपुर अवध के नवाब को सौंपा गया तो मछली शहर को भी उसके बाद की आधी शताब्दी यानी 1775 में बनारस के राजा के अधीन कर दिए जाने तक नवाबी हुकूमत का स्वाद मिला।

इससे पहले 1389 में दिल्ली की गद्दी पर बैठने के चार साल बाद महमूदशाह तुगलक ने अपने एक मंत्री को 'मलिक-उस-शर्क' की उपाधि और कन्नौज से बिहार तक का बड़ा क्षेत्र दे दिया तो उसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाकर शर्की राजवंश की नींव डाली थी। अवध की तहजीब के संदर्भ में इस राजवंश की नवाबों जितनी चर्चा नहीं होती, तो संभवतः उसकी छोटी-सी अवधि और सीमा के कारण। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस वंश के शासनकाल में मछली शहर में हिंदू-मुस्लिम सद्भाव, ज्ञान और कलाओं के संरक्षण का ऐसा अनूठा स्वरूप निखरा, जिसकी गंध आज भी महसूस की जाती है।

AI Image

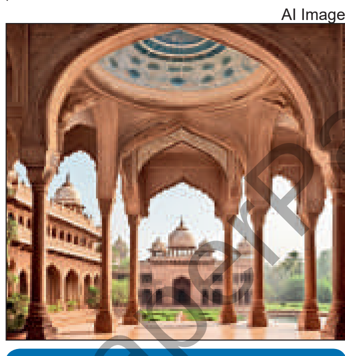

अवधनामा

अतीत में थोड़ा और पीछे जाएं तो पता चलता है कि बौद्धकाल में मछलीशहर को 'मच्छिका संड' कहा जाता था और गौतम बुद्ध को यह बहुत प्रिय था। इस्लाम आया तो जल्दी ही यह शहर सूफी संतों की आमदरफ्त का केंद्र भी बन गया। बताते हैं कि एक सूफी संत ने कभी शर्की राजवंश के सुल्तान हुसैनशाह को एक 'शुभ' मछली भेंट की, तो उन्होंने इसका नाम मछलीशहर रख दिया और यहां जामा मस्जिद बनवाई। अठारहवीं शताब्दी में यह फतेह मुहम्मद उर्फ मंगली मियां के अधिकार में आया तो उन्होंने ईदगाह और किले का निर्माण कराया। एक किंवदंती के अनुसार मछली शहर से पहले इसका नाम 'मझला शहर' था, जबकि दूसरी के अनुसार राजभर राजाओं के वक्त उनके राजा घीसू के समय इसका नाम 'घिसुआ' भी रखा गया था। मगर लखनऊ के 'पंचमहला' की तरह वह चला नहीं।

आज की तारीख में नैशनल हाइवे-231 पर जौनपुर से 30 किलोमीटर पश्चिम स्थित यह शहर कई बड़ी शख्सियतों की जन्म व कर्मभूमि भी रहा है। उर्दू के अपने वक्त के सबसे ज्यादा पढ़े और सुने जाने वाले शायर सलाम मछलीशहरी (एक जुलाई, 1921-19 नवंबर, 1972) भी यहीं जनमे थे। उनका एक शे'र बहुत गुनगुनाया जाता हैः कभी-कभी तो सुना है हिला दिये हैं महल, हमारे जैसे गरीबों की इल्तिजाओं ने।

अफ़वाह से मिला नादिर को मौक़ा

अरुण सिंह

10 मार्च 1739 को शाम का पहर, दिल्ली की सड़कों और गलियों में नादिरशाह के सैनिक बड़ी बेफिक्री से घूम रहे थे। आखिर दुनिया का सबसे अमीर शहर उनके बादशाह के कब्जे में जो था। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह ने अपनी जान और गद्दी बख्शे जाने के एवज में अपने पुरखों का खजाना नादिर शाह के कदमों में रख दिया था। इसी बीच, किसी ने अफवाह उड़ा दी कि नादिर शाह जब मुगल बादशाह से मिलकर लौट रहा था, तो उसकी तुर्की महिला अंगरक्षकों ने उसे कत्ल कर दिया। अफवाह जंगली आग की तरह फैल गई। शहर के कुछ बदमाशों ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने हथियार उठाए और शहर की सड़कों और गलियों में घूम रहे ईरानी सिपाहियों को मारना शुरू कर दिया। वे रात भर ईरानी सैनिकों को कत्ल करते रहे। सुबह तक करीब तीन हजार सैनिक मारे जा चुके थे।

AI Image

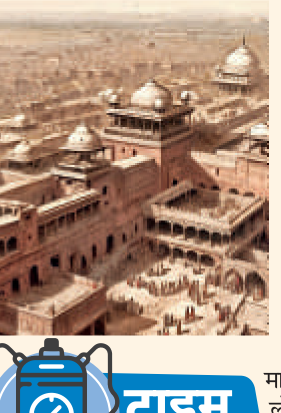

टाइम मशीन

पूरे शहर में उपद्रव | नादिर को रात के पहले पहर में ही अपने सैनिकों पर हमले की खबर मिल गई थी, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी फौज के ही कुछ खुराफाती लोगों ने अफवाह फैलाई है ताकि उन्हें शहर में लूटपाट का मौका मिल जाए। लेकिन, खबर आने का सिलसिला नहीं थमा तो उसे चिंता हुई। उसने अपने एक नुमाइंदे को भेजा। वह किले के बाहर निकला ही था कि वहां जमा भीड़ ने उसे कत्ल कर दिया। दूसरे नुमाइंदे का भी यही हाल हुआ। तब नादिर ने एक हजार बंदूकधारी सैनिकों को रवाना किया। लेकिन, तब तक यह उपद्रव शहर के बड़े हिस्से में फैल चुका था। इतने फौजी उस पर काबू पाने के लिए काफी नहीं थे। जब नादिर को इसकी जानकारी मिली तो उसने अपने फौजियों को हुक्म दिया कि वे पूरी रात अपनी-अपनी जगहों पर तैनात रहें। वे तभी हमला करें, जब उनके ठिकाने पर हमला हो।

बदले का आदेश | अगला दिन रविवार था, 11 मार्च। सुबह होते ही फिर हंगामा शुरू हुआ। नादिर पूरे जंगी लिबास में अपने सिपाहियों को साथ लिए चांदनी चौक के बीच में मौजूद रोशन-उद-दौला की सुनहरी मस्जिद पर पहुंचा। उसने अपनी तलवार निकाली और कत्लेआम का हुक्म दे दिया। उसके सैनिकों के हाथ अब तक बंधे हुए थे। वे बदला लेने के लिए बेचैन थे। जैसे ही आदेश मिला, वे टूट पड़े।

घर-घर मौत | सबसे खौफनाक कत्लेआम चांदनी चौक के लाल किले, दरीबा और जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हुआ। यहीं पर सबसे महंगी दुकानें और जौहरियों के घर थे। नादिरशाह के सैनिक घर-घर जाकर लोगों को मार रहे थे। कत्लेआम करते हुए वे लोगों का माल-असबाब लूट रहे थे और उनकी बहू-बेटियों को उठा ले रहे थे। बच्चे, बूढ़े किसी को भी नहीं छोड़ा। यह कत्लेआम सुबह नौ बजे शुरू हुआ और दोपहर 2 बजे तक बेरोकटोक चलता रहा। तब मुहम्मद शाह ने निजाम और वजीर को नादिर के पास माफी मांगने के लिए भेजा।

लाशों के ढेर | निजाम के माफी मांगने के बाद नादिर ने अपने सैनिकों को रोका। तब तक भयानक तबाही हो चुकी थी। शहर कोतवाल के मुताबिक, 8000 लोग मारे गए थे। नादिर शाह के ईरानी सचिव के मुताबिक, 30 हजार लोगों की जान गई। एक मराठी समाचारपत्र ने बताया कि 50 हजार मारे गए और कहीं-कहीं तो यह आंकड़ा 3-4 लाख का भी था। कई दिनों बाद तक दिल्ली की सड़कें और गलियां, घर और कुएं लाशों से पटे रहे।

मॉनसूनी दुल्हनें

प्रणव प्रियदर्शी

मॉनसून के बादल किसी के लिए खुशियों की सौगात लाते हैं तो किसी के लिए आफत। लेकिन पाकिस्तान के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की नाबालिग बच्चियों के लिए ये नरक का द्वार ही खोल देते हैं। इनकी दस्तक होते ही न जाने कितनी नाबालिग बच्चियों की अधेड़ उम्र के लोगों के साथ शादी कर दी जाती है। पिछले दो-तीन वर्षों से यह नया दस्तूर बनता जा रहा है। इन मासूम, लाचार बच्चियों को 'मॉनसूनी दुल्हन' का नाम मिल गया है। यह सब शुरू हुआ 2022 में आई भीषण बाढ़ के बाद, जिसमें देश का एक तिहाई हिस्सा डूब गया था और लाखों लोग विस्थापित हुए थे। आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस बर्बादी से उबर ही नहीं पाया। उसके बाद से मॉनसून इन परिवारों के लिए ऐसी मुसीबत होता है जिससे पार पाना एक बड़ी चुनौती होती है। मॉनसून के बाद भी जिंदगी चलती रहे, इसके लिए इन परिवारों को अपने किसी न किसी सदस्य की जिंदगी दांव पर लगानी होती है। जैसा कि तमाम पितृसत्तात्मक समाजों का अनलिखा कानून है, जिंदगी दांव पर लगाने की यह जिम्मेदारी लड़कियों के सिर आ जाती है। परिवार नाबालिग बेटियों को अधेड़ों के हाथों ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। ऊंची कीमत का मतलब? औसतन दो लाख पाकिस्तानी रुपये यानी करीब 720 डॉलर। रोजाना 1 डॉलर की औसत आमदनी पर गुजर करने वाले इन पाकिस्तानी परिवारों को यह मामूली रकम भी खासी ऊंची लगती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट इन सबकी पुष्टि करते हुए बताती है कि 2022 की बाढ़ के बाद पाकिस्तान में नाबालिग लड़कियों की शादी में 18% बढ़ोतरी का अनुमान है। सबसे कड़वा सच यह है कि इस तरह से बिक रही लड़कियों की जिंदगी का आगे क्या होता है, यह सोचने की फुरसत किसी को नहीं। परिवार तो इनकी जिंदगियों की ही कीमत पर अपने लिए कुछ महीने की मोहलत खरीदकर संतुष्ट है, जिसने इन्हें खरीदा, उसके लिए इनका मोल बाजार में बिकने वाले एक सामान से ज्यादा नहीं।

AI Image

आधी दुनिया

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

कबाड़ से मोह लग गया, तो घर रहने लायक नहीं बचेगा

सलिल पांडेय

जब हम कोई नया सामान खरीदते हैं, तो जानना चाहते हैं कि वह कितने दिनों तक चलेगा? उसका एक वॉरंटी पीरियड होता है या फिर एक्सपायरी डेट दी गई होती है। कुल मिलाकर, सामान महंगा हो या सस्ता, एक समय बाद बेकार हो ही जाता है। फिर घर के बाहर कूड़े के ढेर पर उसे रख दिया जाता है। सफाईकर्मी आता है और उसे उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर के लिए अगर यह विचार आ जाए कि अपने पैसे से खरीदे सामान को ऐसे क्यों फेंक दिया जाए और मोह में आकर उसे घर के किसी कमरे में रख दें, तो एक दिन वह कमरा कूड़े से भर जाएगा। मोह का यह सिलसिला अगर खत्म नहीं हुआ तो एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा कमरा भी कबाड़ से भर जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि घर में उठने, बैठने और सोने की दिक्कत होने लगेगी। खराब वस्तुओं से घर का वातावरण दूषित होने लगेगा। इसका बुरा असर मन और स्वास्थ्य, दोनों पर पड़ना तय है।

यही स्थिति अंतर्जगत में भी होती है। अंतर्जगत में ज्ञानेंद्रियों के रूप में पांच कमरे हैं। इन्हीं पांच कमरों के बीच मन का एक बड़ा आंगन होता है। मन के आंगन पर पांचों ज्ञानेंद्रियों वाले कमरे का असर पड़ता है। आंखों से यदि कूड़े का दृश्य मन के आंगन में आए और उसे सहेज कर रख लिया जाए, तो पहले स्तर पर कूड़े का जमाव शुरू होने लगेगा। फिर घटिया दृश्य देखकर मन को पीड़ा होगी, लेकिन उस दृश्य से खुशी मिलने लगे, तो धीरे-धीरे घटिया दृश्यों को देखने की आदत बनने लगेगी। इसी तरह कानों से निंदा-चुगली, जिह्वा से अखाद्य पदार्थों का सेवन, नाक जिस गंध को सह न सके उस वातावरण में रहना और त्वचा से गलत तरीके का स्पर्श किसी कूड़े से कम नहीं है।

आदतों की गुलामी जल्दी छूटती नहीं। बाहरी गुलामी देश-काल और परिस्थिति के चलते छोड़ने में कम दिक्कत होती, लेकिन मन की आदतों से मुक्ति पाने में कठिनाई होती है। यहां एक प्रश्न उठता है कि क्या मन जंगल के शेर जैसा है? पहले तो उत्तर मिलता है हां। लेकिन एक उदाहरण यह भी है कि जंगल का बेकाबू शेर सर्कस में रिंग मास्टर के इशारे पर करतब भी करता है। जब अंतर्जगत को आकांक्षाओं और लालच की झाड़ियों की तरह जंगल बना दिया जाएगा, तब मन काबू में न आने वाला शेर बन ही जाएगा। और वह सात्विक विचारों को वैसे ही निगलने लगेगा जैसे जंगल में शेर अन्य जानवरों को निगल जाता है। रिंग मास्टर की तरह बुद्धि-विवेक को जागृत रखा जाए तो मन का शेर जरूर काबू में आ जाएगा।

मन के शेर को काबू में करने के लिए चिंतन और विचार के चाबुक को संभालना होगा। ये दोनों तत्व तराजू के दो पलड़े की तरह हैं। इसके लिए दोनों सतहों पर तालमेल बैठाने की सोच बनानी पड़ेगी। पहले पलड़े पर भौतिक जरूरतों के लिए सांसारिक चीजों का संग्रह करना और दूसरे पलड़े पर आत्मिक ऊर्जा को स्थान देना। भौतिक पदार्थों के संग्रह में जब आत्मिक ऊर्जा की उपेक्षा की जाती है तो आत्मिक ऊर्जा बुझते हुए दीपक की तरह मलीन पड़ने लगती है, जो अंधकार की ओर ले जाती है। आत्मिक ऊर्जा को जागृत रखने की जरूरत है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ स्त्रियों की सुरक्षा

20 अगस्त का लेख 'स्त्री सुरक्षा के लिए कानून काफी नहीं' समाज के उस दोहरे रूप को दर्शाता है, जहां स्त्रियों की सुरक्षा के सवाल खत्म नहीं हो रहे। हिंदुस्तान आज अर्थव्यवस्था के मामले में भले दुनिया में पांचवें पायदान पर है, पर सामाजिक और पारंपरिक मूल्यों में देश की आधी आबादी यानी हमारी बेटियां आज भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। आए दिन हो रही रेप जैसी घटनाएं निराश करती हैं। 9 अगस्त को कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज में हुई घटना और उसके बाद उत्तराखंड के ऊधमपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले गंभीर हैं।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

■ क़ानून का असर दिखे

यह पत्र 14 अगस्त के संपादकीय 'कानून नहीं समस्या' से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या ने पूरे देश को शर्मसार किया है। हालांकि इस मामले को CBI को सौंप दिया गया है। डॉक्टर इस घटना से डरे हुए हैं। वे अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने एक केंद्रीय कानून की मांग की है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि डॉक्टरों की तरह महिला मरीज भी असुरक्षित हैं। मसला यह नहीं है कि कानून बनाया जाए। मसला यह है कि कानून का प्रभाव पूरी तरह से अमल में आए ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों।

वारिस अली, ईमेल से

■ क्राइम क्यों दिखाते हैं

आजकल रेप, चाकूबाजी और मासूमों के साथ अमानवीय व्यवहार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिनेमा और विज्ञापन इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। सिनेमा में स्कूल-कॉलेजों में शिक्षा की बातें नहीं दिखाई जातीं, बल्कि उसे क्राइम के अड्डे के तौर पर दिखाया जाता है। विज्ञापनों में छोटी-छोटी बच्चियों को अश्लील ढंग से पेश करते हैं, जिससे गलत संदेश जाता है। गुंडों और मवालियों को 'डॉन' और 'भाई' जैसे संबोधन से उसका मान ही बढ़ाते हैं।

आर.पी. सिंह, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

बारिश की वजह से सब्जियों के रेट में आया उछाल - एक खबर
- सब्जियों को बहाना चाहिए,
उछलना तो उन्हें खूब आता है!

प्रीति गोयल

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 22 अगस्त • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

श्रद्धा और विश्वास ऐसी जड़ी-बूटियां हैं कि जो एक बार घोल कर पी लेता है, वह चाहने पर मृत्यु को भी पीछे धकेल देता है।

-अमृतलाल नागर

शीर्ष अदालत का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता में डॉक्टर से दरिंदगी को भयावह घटना बताते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सबसे बड़ी अदालत ने घटना को चिकित्सकों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थागत विफलता पर चिंता जताई। सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं करने की भी बात की। अदालत ने कहा कि जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। देश भर के डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए काम पर लौटने की अपील की और चौदह सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स भी गठित की। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यदि महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए काम की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।

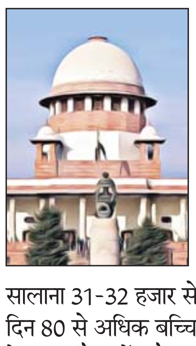

एफआईआर में देरी, पीड़िता की तस्वीरों/नाम का खुलासा होने और मृतका के माता-पिता को गलत सूचना देने पर भी अदालत ने कड़ी फटकार लगाई है। प्रशिक्षु चिकित्सक का शव कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में गंभीर चोटों के साथ अस्त-व्यस्त हाल में मिलने के बाद से देश भर में चिकित्सकों, अस्पतालकर्मियों समेत जनता में गहरे आक्रोश को देखते हुए शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में सालाना 31-32 हजार से ज्यादा बलात्कार होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो प्रति दिन 80 से अधिक बच्चियां/महिलाएं यौन हिंसा की शिकार होती हैं। अदालतों के सख्त फैसलों और कड़े कानूनों के बावजूद बलात्कार की घटनाओं पर अंकुश लगाने में सरकार और व्यवस्था बुरी तरह असफल साबित हुई हैं। अदालत ने भले ही यहां सिर्फ चिकित्सा पेशेवरों की चर्चा की है, असल में तो नन्हीं-नन्हीं बच्चियां तक यौन हमलों की शिकार हो रही हैं जिनको सुरक्षित रखने में हम बुरी तरह असफल हैं। राज्य सरकारों और पुलिस को चौकस बनाने के साथ ही जरूरी है कि सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर लैंगिक विभेद की गहरी जड़ों पर जोरदार प्रहार किया जाए। कहना न होगा कि जीने और सुरक्षित रहने का अधिकार भी मौलिक है। देश में शिक्षा और वंचना का जो स्तर है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि देश की हर महिला अदालत की शरण में नहीं जा सकती। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था चरमराने न पाए। यदि सरकारें इस काम में नाकाम रहती हैं, तो यकीनन वैसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी जैसी से आज हम रूबरू हैं।

सीधी भर्ती पर किरकिरी

भाजपा की अगुवाई वाले सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को विवाद के बाद लेटरल एंट्री (सीधी भर्ती) से 45 विशेषज्ञों की नियुक्ति का फैसला वापस लेना पड़ा। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सीधी भर्ती से अधिकारियों को नियुक्त किए जाने का विज्ञापन जारी किया था जिसे सरकार ने अब रद्द कर दिया है। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरी पदों की सीधी भर्ती के लिए था। इसके जारी होते ही सरकार के भीतर और बाहर विरोध के स्वर फूटने लगे थे। कांग्रेस, सपा सहित सत्तारूढ़ एनडीए के घटक दलों एलजेपी और जदयू ने भी सीधी भर्ती का विरोध करना शुरू कर दिया था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने चालाकी के साथ इन पदों को विशिष्ट मानते हुए एकल-कैडर पद के रूप में नामित किया जिससे नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान को समाप्त कर दिया जाए अर्थात सरकार चोर दरवाजे से आरक्षण को खत्म करना चाहती है।

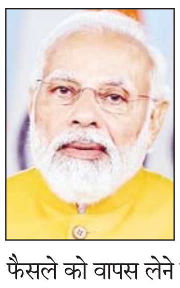

हाल में संपन्न लोक सभा चुनावों में विपक्षी दलों ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है। भाजपा के नारा 400 पार के संदर्भ में हवा बनाई गई कि प्रचंड बहुमत के जरिए वह संविधान बदलना चाहती है। एक तरह से भाजपा को दलित और ओबीसी के विरोधी के रूप में रेखांकित किया गया। चुनाव में भाजपा अपने बूते बहुमत जुटाने में भी असफल रही। प्रतीत होता है कि सीधी भर्ती के फैसले को वापस लेने का एक बड़ा कारण यही है। वैसे भी कोई राजनीतिक दल या सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी छवि पिछड़ा और दलित विरोधी हो। वस्तुतः सीधी भर्ती वांछित हैं। पहले भी ऐसी भर्तियां होती रही हैं। सरकारों के कामकाज इतने जटिल हो गए हैं कि तकनीकी विशेषज्ञता व श्रेष्ठता की जरूरत पड़ने लगी है। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब सामाजिक न्याय व समानता की अनिवार्यता के विरुद्ध विशेषज्ञता व योग्यता की मांग उठती है। हालांकि कैसे इंकार किया जा सकता है कि विशेषज्ञता के बगैर आधुनिक राज्यों का काम चल जाएगा। तथ्य है कि लोक सभा चुनाव में भाजपा को पहले के मुकाबले कम सीटें मिलीं। नई परिस्थितियों में मोदी सरकार को विपक्ष के साथ अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लेकर सरकार चलानी पड़ेगी। जनादेश का यही निहितार्थ है वरना सरकार को अपनी किरकिरी कराने के लिए तैयार रहना चाहिए।

कटाक्ष/ सहीराम

बजट और गणना

वैसे तो जी, बजट और गणना का बड़ा गहरा रिश्ता है। गणना ही नहीं होगी तो बजट क्या होगा। लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बार बजट में देश के दो ही राज्यों की गिनती हुई, बाकी किसी गिनती में नहीं। वैसे तो सरकार अब तक विपक्ष को ही कहां गिनती थी। अब उसकी गिनती थोड़ी बढ़ी है तो कुछ गिनने लगी है, लेकिन इतना भी नहीं कि विपक्ष शासित राज्यों को भी इतना दे दे कि गिनती ही न हो। आंध्र और बिहार के शासक दलों ने सरकार की गिनती, सरकार होने लायक बनाई तो उन्हें उसने अनगिनत राशि दे दी। इसमें बुरा क्या है। अब विपक्ष इसे सरकार बचाओ बजट बताए तो बताए। आप ही बताइए कि आंध्र और बिहार के बिना क्या गिनती रह जाएगी। खैर,अच्छी बात यह है कि अब तक जिन टूटने वाले पुलों की गिनती नहीं हो रही थी, उनकी गिनती और बढ़ जाएगी। पैसा मिलेगा तो नये पुल बनेंगे कि नहीं। और बनेंगे तो टूटेंगे भी। गिनते रहना। नहीं, सरकार और बिहार वाले सहयोगी दल के बीच बने पुल की बात नहीं हो रही। लेकिन बिहार में अगर पुल टूटेंगे तो उधर आंध्र में नई राजधानी भी तो बनेगी। अलबत्ता, यह बाद में पता चलेगा कि किस गिनती में रकम किधर गई।

लेकिन इधर पता चला कि बजट और गणना के बीच भी कुछ झगड़ा सा हो गया। वैसे होना नहीं चाहिए था क्योंकि जिस जनगणना के आधार पर बजट और नीतियां बनती हैं, वह जनगणना तो सरकार ने कराई ही नहीं। सरकार का कहना है कि पहले कोरोना आ गया तो नहीं कराई। उसके बाद उसे लगने लगा होगा कि सरकार चलाने के लिए आंकड़ों की कोई खास जरूरत तो होती नहीं, अगर जरूरत पड़ भी जाए तो कुछ भी बता दो क्या फर्क पड़ता है, सो, नहीं कराई होगी। वैसे भी मुफ्त में रिकॉर्ड बन रहा है-भारत दुनिया के उन चार देशों में शामिल हो गया है, जिन्होंने जनगणना नहीं कराई। इधर राहुल गांधी अड़े हुए हैं कि वे तो जातिगत जनगणना करवा कर ही मानेंगे। जातिगत जनगणना के प्रति उनका यह अनुराग, अनुराग ठाकुर जी को पंसद नहीं आया। सो, उन्होंने कह दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं, वे गणना की बात करते हैं। इसका फायदा उन्हें यह हुआ कि भाजपा नेताओं में उनकी गणना होने लगी और इसका सर्टिफिकेट उन्हें स्वयं प्रधानमंत्री ने दिया।

भारत की बदलती तस्वीर

विनिर्माण क्षेत्र

प्रह्लाद सबनानी

भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और रोजगार के लिए सामान्यतः कृषि पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 16-18 प्रतिशत के आसपास बना रहता है। यदि 60 प्रतिशत आबादी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 16-18 प्रतिशत तक योगदान ही दे पा रही है तो स्वाभाविक रूप से इस क्षेत्र में गरीबी तो बनी ही रहेगी परंतु यह स्थिति अब धीरे-धीरे बदल रही है क्योंकि हाल के वर्षों में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के नागरिक शहरी क्षेत्रों में स्थापित विनिर्माण इकाइयों में रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।

विनिर्माण क्षेत्र में कई ऐसे नये क्षेत्र उभरे हैं जिनमें भारत में उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता रहा है। रक्षा, दवा, सेमीकंडक्टर निर्माण एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र आदि का वर्णन यहां प्रमुख रूप से किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में रक्षा क्षेत्र उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपये का रहा जो उससे पूर्व वर्ष की तुलना में 16.7 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान में रक्षा क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां संयुक्त रूप से प्रयास कर रही हैं। हर्ष का विषय है कि रक्षा क्षेत्र में भारत निर्मित उत्पादों की अन्य देशों में भारी मांग निकल रही है। वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात भारत से विभिन्न देशों में किया गया जो पूर्व वर्ष की तुलना में 32.5 प्रतिशत अधिक है। निर्यात में वृद्धि न केवल वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की बढ़त दर्शाती है, बल्कि आत्मनिर्भरता और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के उद्देश्य से हाल में कई रणनीतिक पहल भी सरकार ने की हैं जैसे मजबूत नीतिगत ढांचा विकसित करना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, अनुसंधान एवं विकास कार्यों में पर्याप्त निवेश आदि। स्वदेशीकरण की नीति के अनुपालन का असर भी रक्षा क्षेत्र में उत्पादन एवं निर्यात में भारी-भरकम वृद्धि के रूप में दिखाई देने लगा है। रक्षा क्षेत्र में उपयोग होने वाले सैकड़ों उत्पादों के आयात पर रोक लगा कर इन उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने के निर्णय का असर भी धरातल पर दिखाई देने लगा है। रक्षा क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का उत्पादन भारत में ही करने की नीति लागू करने से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश में आर्थिक प्रगति, तकनीकी उन्नति एवं रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

रक्षा क्षेत्र की तरह ही हाल के समय में भारत ने उत्पादन के कई नये क्षेत्रों में भी प्रवेश किया है। कुछ वर्ष पूर्व तक दवा निर्माण क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एपीआई (एक्टिव

फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट) नामक कच्चे माल का लगभग पूरे तौर पर चीन से आयात किया जाता था परंतु कोरोना महामारी के दौरान भारत को अहसास हुआ कि यदि चीन इस कच्चे माल का निर्यात भारत को करना कम कर दे अथवा बंद कर दे तो भारत में तो दवा उद्योग की इकाइयों में निर्माण कार्य ही ठप पड़ जाएगा। इसके बाद सरकार ने एपीआई का उत्पादन भारत में ही करने का फैसला किया। आज स्थितियां बदल गई हैं एवं एपीआई का निर्माण भारत में ही किया जाने लगा है। संभव है कि आने वाले समय में एपीआई निर्माण में भी भारत आत्मनिर्भरता हासिल कर ले। भारत एपीआई का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है एवं वैश्विक एपीआई उद्योग में उसकी हिस्सेदारी 8 प्रतिशत हो गई है। आज देश में 500 से अधिक प्रकार के एपीआई का उत्पादन किया जा रहा है। एपीआई का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दवा उद्योग में तेज गति से वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है और आज यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में 1.72 प्रतिशत का योगदान देने लगा है एवं रोजगार के करोड़ों अवसर निर्मित कर रहा है। भारतीय दवा उद्योग के 2024 के अंत तक 6,500 करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक 13,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। 2013-14 के बाद से 2021-22 तक भारतीय दवा निर्यात में 103 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है। जेनेरिक दवाओं के वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 20 प्रतिशत हो गई है, जिससे भारत को 'विश्व का फार्मेसी हब' भी कहा जाने लगा है। सरकार एपीआई के उत्पादन को देश में बढ़ाने के उद्देश्य से समग्र एवं अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने पर जोर दे रही है। 2020 में सरकार ने एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए 6,940 करोड़ की राशि निर्धारित की थी। 2022 के बाद से भारत के फार्मास्यूटिकल व्यवसाय में जबरदस्त बदलाव आया है एवं भारत अब वॉल्यूम उत्पादक से मूल्यवान आपूर्तिकर्ता बन गया है।

लगभग चार वर्ष पूर्व वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की उपलब्धता में आई भारी कमी के चलते वाहनों का उत्पादन घटाना पड़ा था परंतु इसके बाद सरकार ने बीड़ा उठाया कि सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाया जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर का बाजार 2,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का है, जो 2025 तक बढ़कर 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो जाने की संभावना है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां देश में अधिक से अधिक स्थापित हों इसके लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वैश्विक स्तर पर कई प्रौद्योगिकी फर्मों से देश में सेमीकंडक्टर इकाई लगाने के लिए सीधे चर्चा भी कर चुके हैं। काउंटरप्वॉइंट रिसर्च और इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2026 तक 6,400 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा जो 2019 के बाजार से तीन गुना अधिक होगा। इसी प्रकार, भारत में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में खासा शोध चल रहा है ताकि आने वाले समय में विश्व में भारत इस क्षेत्र में अपनी सर्वश्रेष्ठता सिद्ध कर सके।

कुल मिला कर कहा जा सकता है कि भारत विनिर्माण क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है जिनमें कभी उसका प्रभुत्व ही नहीं रहा। इससे भारत में रोजगार के लाखों नये अवसर निर्मित हो रहे हैं एवं ग्रामीण क्षेत्र पर नागरिकों का दबाव भी कम हो रहा है।

> विनिर्माण क्षेत्र में ऐसे नये क्षेत्र उभरे हैं जिनमें हाल के समय में भारत ने खासी प्रगति की है। भारत निर्मित रक्षा उत्पादों की अन्य देशों में भारी मांग निकल रही है। दवा निर्माण के क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले एपीआई (एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट) का भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में प्रगति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में भी खासा शोध चल रहा है ताकि इस क्षेत्र में बढ़त ली जा सके

- भारत को दालों और तेल जैसी कम पानी की खपत वाली फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति-2 की जरूरत है।
- आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार इन फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की गारंटी दे सकती है
- जीटीआरआई का कहना है कि हरित क्रांति-2 अनिवार्य रूप से हरित क्रांति-1 से पहले मौजूद फसल मिश्रण को बहाल करेगी

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

लगता है कि राहुल गांधी ने वीपी सिंह को आदर्श बना लिया है। तीसरी बार चुनाव हराने के बाद अब वे 'आरक्षण' से सत्ता पाना चाहते हैं। 50 फीसद की सीमा से सामाजिक न्याय और समानता के अवसर के बीच 50:50 का संतुलन था। ठीक है कि भीड़ तंत्र में तर्क और न्याय नहीं चलता मगर इतिहास न्याय जरूर करता है।

रंगनाथ सिंह, पत्रकार
@rangnathsingh_

नये भूगोल में विधानसभा चुनाव

जम्मू-कश्मीर | **प्रमोद भार्गव**

जम्मू-कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार समग्र समाजों को मिले मतदान के अधिकार के साथ विधानसभा चुनाव होगा। अभी तक यहां दलित एवं जनजातीय समुदायों को मताधिकार ही प्राप्त नहीं था जबकि अब उन्हें आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। यहां का भूपरिदृश्य बदलने एवं धारा-370 और 35-ए हटने के बाद 18 एवं 25 सितम्बर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। 4 अक्टूबर को चुनाव परिणाम घोषित होंगे। जहां तक केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का सवाल है, वहां 10 साल बाद चुनाव होने जा रहा है। 2014 में चुनाव हुए थे जिनमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। नतीजतन, भाजपा और पीडीपी ने मिलकर कुछ समय तक गठबंधन सरकार बनाकर चलाई।

2019 में जम्मू-कश्मीर में लागू विशेष अनुच्छेद 370 संसदीय कार्यवाही पूरी कर खत्म कर दिए जाने पर कांग्रेस समेत कश्मीर के दो राजनैतिक-पारिवारिक दल फारुक और मुफ्ती परिवार के मुखियाओं ने घाटी में अशांति बढ़ने की आशंका जताई थी लेकिन वहां तब से शांति की बहाली तो हुई ही अर्थव्यवस्था में भी गति आई। कितना विडंबनापूर्ण है कि जिस पाकिस्तान में लोकतंत्र फौज की कठपुतली बना रह कर भुखमरी के कगार पर खड़ा है, वह भारत से आतंकवाद के बहाने छायायुद्ध लड़ने से बाज नहीं आ रहा है। आशंका है कि चुनाव की घोषणा के बाद आतंकी घटनाओं की संख्या बढ़ती दिखे? लेकिन यही समय होगा जब कश्मीर की जनता न केवल पाकिस्तान को जवाब देगी, बल्कि कश्मीर में अलगाव और परिवारवाद का खेल खेलते रहे मुखौटाधारियों को भी सबक सिखाएगी। 25 जुलाई, 2024 की स्थिति में जम्मू-कश्मीर में कुल मतदाता 87.09 लाख हैं, जो तीन चरणों में होने वाले चुनाव में मतदान कर नई सरकार चुनेंगे। 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश घोषित करने के साथ राज्य दो हिस्सों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख-में विभाजित कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर को विधानसभा का दर्जा दिया गया है, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। यहां दिल्ली एवं चंडीगढ़ की तरह राज्यपाल सत्ता शक्ति के प्रमुख केंद्र बनाए गए। जम्मू-कश्मीर के बंटवारे और विधानसभा

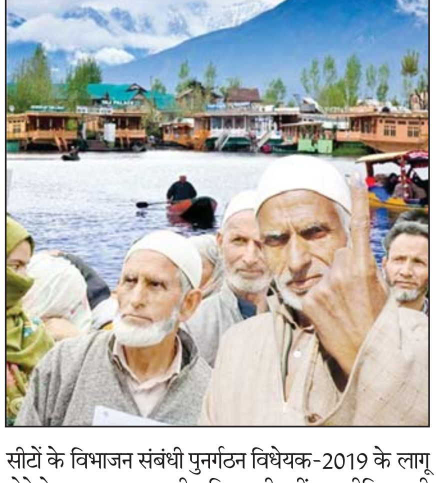

सीटों के विभाजन संबंधी पुनर्गठन विधेयक-2019 के लागू होने के बाद इस राज्य की भूमि का ही नहीं, राजनीति का भी भूगोल बदल गया है। नये सिरे से किए गए परिसीमन के बाद यहां सात विधानसभा सीटों की बढ़ोतरी हुई है।

राज्य में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को सुरक्षित करने का भी अहम निर्णय लिया यानी सही मायनों में परिसीमन के नये परिणामों से भौगोलिक, सांप्रदायिक और जातिगत असमानताएं तो दूर हुई ही हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए सीटें भी आरक्षित कर दी गई हैं। अब जम्मू-कश्मीर में कुल 114 सीटें हैं, जिनमें से 90 सीटों पर चुनाव होंगे। इनमें 43 सीटें जम्मू और 47 सीटें कश्मीर में हैं। 24 सीटें गुलाम जम्मू-कश्मीर के लिए सुरक्षित हैं जिन पर चुनाव नहीं होना है। सोलह सीटें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इनमें से सात अनुसूचित जाति एवं नौ अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। विधानसभा के पांच सदस्य उपराज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार भी दिया गया है। इनमें से दो कश्मीरी प्रवासी यानी कश्मीरी पंडित होंगे। एक गुलाम कश्मीर से विस्थापित व्यक्ति को मनोनीत किया जाएगा। दो सदस्य महिलाएं मनोनीत होंगी।

कश्मीर का प्रवासी उन्हें माना जाएगा, जिन्होंने 1 नवम्बर, 1989 के बाद घाटी से पलायन किया हो और उनका नाम राहत आयुक्त के रजिस्टर में दर्ज हो। जो व्यक्ति 1947-48, 1965 और 1971 के बाद वहां से पलायन कर भारत आए हैं, उन्हें विस्थापित माना जाएगा। आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार होगा कि वाल्मीकि, गोरखा समाज और पाकिस्तान से विस्थापित पहली बार मतदान करेंगे। अन्य राज्यों के ऐसे लोग भी मतदान कर सकेंगे, जिनके पास प्रदेश का अधिवास पत्र और मतदान का अधिकार है। गुज्जर-बक्करवाल और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला जनजातीय समुदाय (अनुसूचित जनजाति) के लिए नौ सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति के लिए भी सात विधानसभा सीटें सुरक्षित हैं। इन लोगों को बीते 78 साल से घाटी के मूल निवासी होने के बावजूद न तो चुनाव लड़ने का अधिकार था और न ही मतदान का, अब तक कश्मीर में एक भी सीट पर जातिगत आरक्षण की सुविधा नहीं थी, जबकि इस क्षेत्र में 11 प्रतिशत गुज्जर-बक्करवाल और गद्दी जनजाति समुदायों की बड़ी आबादी निवास करती है। अब ये समुदाय बढ़-चढ़कर चुनाव में भागीदारी कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए परिवार और अलगाववाद के लिए चुनौती बनते दिखाई दे सकते हैं।

नश्वरता | **डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी**

एक मुमुक्षु गुरु के पास गया और पूछा, 'गुरुजी! मेरे पास धन है, समृद्धि है, कीर्ति है, सुशील पत्नी और आज्ञाकारी पुत्र-पुत्रियां हैं, फिर भी मैं चिंता में रहता हूं। मैंने हर तरह से प्रयास किए किंतु इसकी क्या वजह है, समझ नहीं पा रहा हूं। यह चिंता मुझे रोज दीमक की तरह खा रही है। मैं इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें।' यह प्रश्न कई लोगों का हो सकता है। गुरु ने कहा, 'मनुष्य अहम और ममत्व की गांठ से बंधा हुआ है, जिससे उसकी आंतरिक स्वतंत्र आत्मिक शक्ति दब जाती है। फलस्वरूप वह हर परिस्थिति का मूल्यांकन अपने अहंकार के पराधीन होकर करता है। ऐसे लोग वर्तमान से अधिक भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं और सदा काल चिंतित रहते हैं।' गीता में भी अर्जुन का अहम और ममत्व स्वजनों के प्रति प्रेम और आसक्ति के रूप में अभिव्यक्त हुआ था और चिंता का कारण बना था। भगवान कृष्ण ने उसके अहंकारी अज्ञान को दूर करने के लिए उपदेश शुरू किया था। अर्जुन जिन स्वजनों की मृत्यु की बात करते हुए चिंतित था, उनके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं-'ऐसा नहीं है कि किसी समय मैं नहीं था, न तुम थे, न ये राजा थे, ऐसा भी नहीं कि हम सब इसके बाद नहीं होंगे। ये सब पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। तुम चाहो या न चाहो एक दिन ये सब जाने वाले हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और अपना कर्त्तव्य करो।' अर्जुन के प्रश्नों की शृंखला के उत्तर में, भगवान शरीर की नश्वरता की बात बताते हैं। महंतस्वामी महाराज भी कहते हैं, 'संसार अनित्य है, नाशवंत है। यही समझ हमें भूत, भविष्य और वर्तमान की चिंताओं से मुक्त कर सकती है। जो निश्चय ही नाश होने वाला है, उसकी चिंता करने से क्या लाभ?' यदि संसार की नश्वरता और अनित्यता के ज्ञान को जीवन में पिरो लिया जाए तो उन समस्याओं का समाधान आसानी से हो सकता है। धन, सत्ता, समृद्धि और कीर्ति का सूरज एक दिन अस्त जरूर होगा। फिर भी संसार सांसारिक सुख को चाहता है और अंततः समस्याओं के जाल में फंस जाता है क्योंकि इस सुख की मृगतृष्णा दुःख का द्वार खोलती है। सो, अहंकार छोड़ प्रभु सेवक बन कर जीने में ही सच्चा सुख है।

रीडर्स मेल

खानापूर्ति न हो पौधरोपण

वैसे तो प्रत्येक वर्ष इस मौसम में पूरे देश में लगभग करोड़ों पौधे अभियान चला कर सरकार द्वारा लगवाए जाते हैं, लेकिन ये पौधे कितने दिनों तक, कितने सुरक्षित रह पाते हैं, यह जगजाहिर है। पौधे लगाने की खानापूर्ति तो कर दी जाती है, लेकिन उनके रख-रखाव की उचित व्यवस्था न होने से अधिकांश पौधे या तो सूख जाते हैं, या जानवरों द्वारा चर लिए जाते हैं, जिससे पौधे लगाने का जो पर्यावरणीय उद्देश्य होता है, वह एक तरह से विफल रहता है, जबकि इस अभियान में करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन परिणाम अंततोगत्वा ढाक के वही तीन पात ही निकलते हैं। हाल में केंद्र सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण और अनोखी पहल करते हुए 'एक पौधा मां के नाम' लगाने का अभियान प्रारंभ किया है। मैं सभी से अपील करता हूं कि पर्यावरणीय समस्या को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपनी मां के नाम पर कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प अवश्य ले और उसकी उचित देखभाल भी अपनी मां की तरह ही करना सुनिश्चित कर ले तो बहुत कुछ बदल जाएगा।

रतन कुमार श्रीवास्तव 'रतन', लखनऊ

आंख खोलने वाले हालात

मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की स्थिति को जाहिर करने वाली जस्टिस हेमा कमिटी की रिपोर्ट आखिर सोमवार को सार्वजनिक हो गई। रिपोर्ट में दी गईं बातें हैरान करती हैं। पहले तो राज्य सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को 5 वर्ष तक दबा कर रखा गया और अंततः आरटीआई के जरिए भी इसे बाहर लाने में लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी। समझ में नहीं आता कि ऐसी गंभीर रिपोर्ट को क्यों दबाकर रख लिया जाता है? मलयालम ही नहीं मुंबई और अन्य स्थानों की फिल्म इंडस्ट्रीज के हालात भी बदतर हैं। दौलत और शोहरत की चकाचौंध में युवतियां अपना सब कुछ दांव पर लगा कर फिल्म इंडस्ट्री में घुसना चाहती हैं, जिनमें शोषण तो सबका होता है मगर काम चुनिंदा को मिलता है।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम, मप्र

ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज में घबराहट

अमेरिकी चुनाव में ढाई महीने का समय बच गया है। जिस तरह से एक महीने पहले तक ट्रंप ने हर क्षेत्र में बाइडेन की तुलना में बढ़त बना ली थी वो मंजर अब न सिर्फ बदल गया है, बल्कि कमला हेरिस के आ जाने से ट्रंप की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि वे कमला हेरिस से मुकाबला करने में झिझक रहे हैं। उन पर कातिलाना हमले के बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसीलिए शायद ट्रंप ने कमला पर निजी और नस्लीय हमले करना शुरू कर दिया है। मगर कमला हेरिस अपनी मंजिल की तरफ फोकस करते हुए भविष्य की अपनी आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। कमला ने मध्यम वर्ग एवं निम्न मध्यम वर्ग के साथ खड़े होने की बात की है वहीं ट्रंप ने अमीरों को फायदा पहुंचाने की बात की है। देखें, अमेरिकी मतदाता किसे तरजीह देता है। आर्थिक रूप में दुनिया का सुपर पावर देश होने के नाते क्या वहां की अर्थ नीति सच में चुनावी मुद्दा बन सकती है? आने वाले समय में ही इस प्रश्न का जवाब मिल पाएगा।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-34, अंक 8

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

भारत बंद का संदेश

दलित और आदिवासी संगठनों द्वारा बुधवार को आयोजित भारत बंद का देश के अनेक क्षेत्रों में मिला-जुला असर दिखा है। आरक्षण को लेकर इन संगठनों की सजगता की तारीफ करनी चाहिए। यह यथोचित ही है कि ये संगठन नौकरियों, शिक्षा में हाशिये पर खड़े समुदायों के व्यापक प्रतिनिधित्व की मांग पर जोर दे रहे हैं। अपने सांविधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही उन्होंने भारत बंद का आयोजन किया। इन संगठनों की चिंता पर कान देने के साथ ही इनकी आशंकाओं को दूर करने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने बिना समय गंवाए ऐसा किया भी है, पर सत्ता पक्ष के बारे में जो आरक्षण विरोधी छवि बनाने की चेष्टा विगत महीनों में हुई है, शायद वह काम कर रही है। यह गौर करने की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद विपक्ष ने दलित-आदिवासी संगठनों का पूरा साथ दिया है। नतीजतन, देश में जहां-जहां दलितों और आदिवासियों की बहुलता है, वहां-वहां भारत बंद का असर ज्यादा दिखा है। कहीं यातायात में बाधा पड़ी, तो कहीं प्रदर्शनकारियों में उग्रता भी दिखी।

उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों में मार्च निकाला गया है। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी बंद को अपना समर्थन दिया, तो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भारत बंद का समर्थन किया। कुछ जगहों पर पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी, लेकिन इस बार पुलिस को एक सबक भी मिला है। बिना सोचे-समझे लाठी चला देने की उसकी आदत ने पुलिस की जगहंसाई कराई है। बिहार में पटना के एसडीएम पर एक पुलिसकर्मी ने बंद समर्थक समझकर लाठीचार्ज कर दिया। यह गलती पुलिस वालों को याद रहनी चाहिए। पुलिस के पास ताकत है, पर यह ताकत जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, तो ही प्रशंसा की जा सकती है। क्या प्रदर्शनकारियों को समझाया नहीं जा सकता था? यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अनेक बड़े अधिकारियों ने पुलिस को अनुशासित रखने के लिए कुछ भी नहीं किया है। पुलिस की गुणवत्ता के बारे में सभी को पता है। अधिकारियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पुलिस सुधार कितना जरूरी है। निहत्थे लोगों पर लाठी का प्रयोग भी अंतिम विकल्प ही है। कोई भी सभ्य समाज किसी भी महकमे को लाठी भांजने की इजाजत नहीं देता। साथ ही, प्रदर्शनकारियों को भी शिकायत की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी मांग रखना, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना उनके सांविधानिक अधिकारों के तहत आता है, पर दूसरों को होने वाली परेशानी नजरंदाज नहीं होनी चाहिए। पुलिस के साथ ही प्रदर्शनकारियों से भी शालीनता और सभ्यता की उम्मीद की जाती है।

आज यह बहुत जरूरी हो गया है कि आरक्षण के बारे में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जाए, ताकि कम से कम सड़क पर उतरने की नौबत न आए।

अब यह बहुत जरूरी हो गया है कि आरक्षण के बारे में फैल रही भ्रांतियों को दूर किया जाए। व्यवस्था के साथ अनावश्यक छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) समूहों के लिए कोटा के भीतर कोटा या आरक्षण के उप-वर्गीकरण के मामले को जल्दी से सुलझा लेना चाहिए। संसद से न्यायालय तक आरक्षण के विषय पर ऐसा कोई भी हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, जिससे प्रभावित लोगों की भावनाएं आहत होती हों। आरक्षण सबके लिए चिंता का विषय है, पर यहां उग्रता की नौबत नहीं आनी चाहिए। जो भी बदलाव किए जाने हैं, वे समाज को पूरे विश्वास में लेकर ही किए जाने चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
22 अगस्त, 1949

हिन्दी और नागरी

नई दिल्ली, २१ अगस्त। ज्ञात हुआ है कि भारतीय विधान परिषद की राष्ट्रभाषा मसविदा समिति ने आज अपनी बैठक में अन्तिम रूप से यह निर्णय कर लिया कि भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि नागरी हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी विशेष आमंत्रण पर बैठक में उपस्थित थे। समिति ने यह भी निर्णय किया बताते हैं कि विधान स्वीकृत होने के पश्चात शीघ्र ही सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में कार्य प्रारम्भ कर दिया जाये, लेकिन यह कार्य किस तरह और किस क्षेत्र में प्रारम्भ किया जाये इसका निर्णय करने का भार सरकार पर छोड़ दिया गया है।

इसके साथ ही यह भी निर्णय किया गया है कि इस कार्य में सहायता पहुंचाने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया जायेगा जो सरकार को उसके विभागों में हिन्दी प्रारम्भ करने में परामर्श देगा और समय-समय पर विचार करेगा कि सरकारी विभागों में कहां तक हिन्दी के प्रयोग में प्रगति हो चुकी है। जैसे ही सभी काम हिन्दी में करना सम्भव हो जायेगा, वैसे ही अंग्रेजी से काम लेना पूर्णतः बन्द कर दिया जायेगा। इस तरह अंग्रेजी को १५ वर्ष तक जारी रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। उचित ढंग से प्रगति करने पर हो सकता है कि १० वर्ष में ही हिन्दी पूर्णतः अंग्रेजी का स्थान ले ले। इस कमीशन में सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे।

अब मसविदा समिति के सामने एक महत्वपूर्ण विचारणीय प्रश्न यह रह गया है कि अंक नागरी लिपि के हों या अरबी। अंक का प्रश्न गत एक-दो सप्ताह में ही खड़ा किया गया है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो देश के सामने था ही नहीं और आज भी कुछ राजनीतिज्ञों तक सीमित रहने के सिवा और कहीं नहीं है। इससे देश की जनता को बड़ा आश्चर्य हुआ है कि कुछ राजनीतिज्ञ अपनी जिद पूरी करने के लिए कहां तक गलत रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं। अंग्रेजी को लम्बे अर्से तक राजभाषा बनाये रखने के समर्थकों ने जब देखा कि अंग्रेजी अधिक समय तक राजभाषा नहीं रह सकती तब सोचा कि कम से कम अंक तो अंग्रेजी के ही रखे जायें। स्मरण रहे अंग्रेजी में जो अंक लिखे जाते हैं, वे अरबी अंक हैं। अब जनता यह जानने को उत्सुक है कि आखिर किस सिद्धान्त से अरबी अंक की हिमायत की जाये।

तीसरी पारी में बदली हुई तस्वीर

यहां स्कैन करें

राज कुमार सिंह | वरिष्ठ पत्रकार

नई पारी के महज ढाई महीने में चौथी बार राजग सरकार को फैसले से कदम वापस खींचने पड़े हैं। क्या विपक्ष दस साल बाद वैचारिक लड़ाई में फिर मजबूत दिखने लगा है?

लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार और विपक्ष की भी तस्वीर बदली-बदली-सी नजर आ रही है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों से बहुमत के लिए राजग के सहयोगी दलों पर बढ़ी निर्भरता के बावजूद नरेंद्र मोदी ने इसे निरंतरता का जनादेश बताया था। विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की 234 सीटों के मुकाबले राजग को मिली 293 सीटों के मद्देनजर वह गलत भी नहीं थे, मगर भाजपा के बहुमत से चूक जाने पर विपक्ष के तेवर इतने आक्रामक हो जाएंगे, इसका अनुमान शायद उन्हें भी न रहा होगा। सरकार में प्रमुख मंत्री वही हैं। विपक्ष में भी ज्यादातर नेता वही हैं, लेकिन समीकरण और संतुलन बदल गया दिखता है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को छोड़ भी दें, तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह ग्यारहवां साल है। पिछले दस साल के प्रधानमंत्रित्व काल में यह कल्पना भी मुश्किल लगी कि विपक्ष उनके ऊपर किसी मुद्दे पर दबाव भी बना सकता है, लेकिन महज ढाई महीने की तीसरी पारी में चौथी बार सरकार को अपने फैसले से कदम वापस खींचने पड़े हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लेना ऐसा ही चौथा कदम है।

ध्यान रहे कि इससे पहले लांग टर्म कैपिटल गेन संबंधी अपने बजटीय प्रावधान में सरकार को संशोधन करना पड़ा, तो वक्फ बोर्ड संबंधी विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजना पड़ा। चर्चित ब्रॉडकास्टर्स बिल भी फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल देना पड़ा है। मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल के मद्देनजर देखें, तो ये कोई बहुत बड़े फैसले नहीं नजर आते। दूसरे कार्यकाल में तो विवादास्पद कृषि कानूनों से लेकर तीन तलाक और अनुच्छेद-370 की समाप्ति जैसे दूरगामी असर वाले निर्णय लिए गए थे। बेशक तीनों विवादास्पद कृषि कानून वापस लिए गए, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर साल भर से भी ज्यादा चले किसान आंदोलन के दबाव में, न कि विपक्ष के। सीएए जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष के बजाय नागरिक संगठनों का विरोध ज्यादा मुखर नजर आया, पर वह भी बेअसर ही साबित हुआ। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की बात करें, तो नोटबंदी और जीएसटी के फैसलों पर भी विपक्ष ने शोर तो मचाया, पर उसकी सुनी नहीं गई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरकार के सारे फैसले सही नहीं थे। कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जिनके सही या गलत होने का आकलन इतिहास करता है। फिर भी, तीसरी पारी में सरकार और विपक्ष के तेवर परस्पर बदल गए लगते हैं, तो उसका कारण 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम के अलावा दूसरा नहीं दिखता। पहले कार्यकाल में भाजपा को 282 सीटों के साथ अकेले दम बहुमत हासिल था, तो दूसरे कार्यकाल में उसकी सीटें बढ़कर 303 हो गईं। राज्यसभा में भी गणित अनुकूल था।

इसीलिए नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के उस परंपरागत एजेंडे पर भी बेहिचक आगे बढ़ते दिखे, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी सरीखे विराट व्यक्तित्व ने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में सहयोगियों के समर्थन की खातिर 'शासन के एजेंडे' के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया था। 16वीं और 17वीं लोकसभा के मुकाबले 18वीं लोकसभा में निरंतरता के जनादेश के बावजूद यह समीकरण तो बदला ही है कि 240 सीटों पर सिमट गई भाजपा 272 के बहुमत के आंकड़े के लिए तेलुगु देशम पार्टी, जद-यू और लोजपा (रामविलास) जैसे सहयोगी दलों पर निर्भर है, जबकि 'इंडिया' गठबंधन की 234 सीटों के साथ लोकसभा में विपक्ष मजबूत स्थिति में है। नई लोकसभा के पहले और दूसरे सत्र में विपक्ष की तकरीरों और तेवरों से भी साफ है कि वह आक्रामकता के मामले में सत्ता पक्ष से आगे निकलने को बेताब है। शायद बदले समीकरण का परिणाम है कि पिछली लोकसभा में अडानी समूह की बाबत हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी की मांग अनसुनी कर देने वाली मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड संबंधी बिल को जेपीसी को भेजने में ज्यादा ना-नुकुर नहीं की।

वैसे वक्फ बोर्ड और लेटरल एंट्री के मुद्दे पर भाजपा को सहयोगी दलों का समर्थन भी हासिल नहीं हुआ। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर तो चिराग पासवान ही मुखर दिखे, पर लेटरल एंट्री के मुद्दे पर जद-यू के स्वर भी विरोध में सुनाई दिए। हालांकि, तेलुगु देशम पार्टी विशेषज्ञता के नाम पर लेटरल एंट्री के पक्ष में नजर आई। विरोधियों की चिंता सरकारी नौकरियों में आरक्षण और सामाजिक न्याय को लेकर मुखर हुई, लेकिन जद-यू नेता के सी त्यागी ने साफ कहा कि हम विपक्ष को ऐसा मुद्दा तश्तरी में रखकर नहीं दे सकते। उन्होंने यह भी आशंका जता दी कि इससे तो राहुल गांधी सामाजिक रूप से वंचितों के चैंपियन बन जाएंगे, हम विपक्ष के हाथों में ऐसा हथियार नहीं दे सकते। ध्यान रहे कि सबसे पहले राहुल गांधी ने ही आरक्षण समाप्त करने की साजिश बताते हुए संघ लोक सेवा आयोग के उस विज्ञापन का विरोध किया था, जिसके जरिये 24 मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, निदेशक और उप-सचिव स्तर पर 45 लोगों की सीधी भर्ती होनी थी। ये पद मूलतः आईएएस के लिए हैं, जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग एक तय प्रक्रिया से करता है और उसमें बाकायदा आरक्षण लागू रहता है। लेटरल एंट्री में सिर्फ साक्षात्कार के जरिये सीधी भर्ती होती है, जिसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। इसीलिए यह मुद्दा भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ ही आरक्षण से भी जुड़ा था। आरक्षण सीधा वोट बैंक से जुड़ता है, इसलिए यह मुख्य मुद्दा बन गया।

दरअसल, लेटरल एंट्री के मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा कदम पीछे खींचने के मूल में विपक्ष व सहयोगियों के विरोध से ज्यादा आरक्षण के मुद्दे पर खुद को कठघरे में खड़ा किए जाने के राजनीतिक नुकसान की चिंता रही है। जाति गणना समेत तमाम मुद्दों के जरिये मोदी सरकार और भाजपा पर आरक्षण समाप्त करने और संविधान बदलने की साजिश के आरोप 18वीं लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए थे। चुनावी पंडितों के साथ ही संघ और भाजपा से जुड़े वरिष्ठ लोग भी मानते हैं कि इस बार अकेले दम बहुमत से चूक जाने में विपक्ष के प्रचार की बड़ी भूमिका रही। सही है कि लेटरल एंट्री से पहले भी विशेषज्ञ नौकरशाही में आते रहे हैं। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की थीं और छठे वेतन आयोग ने भी, पर ऐसे संवेदनशील विषय को चर्चा से दूर रखने के राजनीतिक परिणाम गंभीर हो सकते हैं, यह सरकार को तीन दिन में ही समझ में आ गया और 17 अगस्त को जारी विज्ञापन 20 अगस्त को वापस ले लिया गया।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आरक्षण पर विवाद नहीं, बस स्वस्थ संवाद की जरूरत

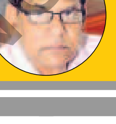

यहां स्कैन करें

श्यौराज सिंह 'बेचैन' | हिंदी विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों यानी एससी/एसटी में उपजाति-वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर कई संगठन बुधवार को सड़कों पर उतर आए। उनकी चिंता को समझने की जरूरत है। अनुसूचित जातियों को अपनी स्थिति का बोध होना अच्छी बात है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर भी कहते थे, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो। बुद्ध कहा करते थे कि दुख का कारण जानो। बड़ा सवाल तो यही है कि इनमें कुछ उपजातियां विकास की मुख्यधारा में क्यों पिछड़ी हैं? विभाजन में समाधान ढूंढ़ने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद उपजाति-वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर संवाद और भाईचारे पर अमल करना चाहिए। हमें डॉ आंबेडकर के संदेश का सार समझना चाहिए और किसी भी तनाव या टकराव से बचना चाहिए।

जिन उपजातियों की जनसंख्या के अनुपात से भी भागीदारी कमतर है, उनको बताया गया है कि अधिक संख्या वाले तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, जबकि यह नतीजा है आरक्षित पदों के न भरे जाने का; आरक्षित वर्गों के लिए नए पद सृजित न करने का; निजी क्षेत्र में अमेरिका की तरह 'अफर्मेटिव डायवर्सिटी' (पिछड़े तबकों के लिए अवसर बढ़ाने वाली सकारात्मक विविधता) लागू नहीं किए जाने का; सरकारी शिक्षा को सीमित करने का और निजी क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दुर्लभ हो जाने का। इस संदर्भ में भारतीय विदेश सेवा से सेवानिवृत्त विवेक काटजू ने 15 दिसंबर, 2022 को संसद में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का विश्लेषण कर प्रशासनिक सेवाओं में उच्च पदों पर प्रतिनिधित्व के वस्तुपरक सुझाव दिए हैं। उसमें उन्होंने बताया है कि उच्च अधिकारियों के 322 पद हैं, जिनमें संयुक्त सचिव, सचिव और केंद्रीय अधीनस्थ स्टाफ और विभिन्न मंत्रालयों के विभागीय पद हैं। इनमें एससी और एसटी की भागीदारी क्रमशः चार और 4.9 फीसदी है। वे शीर्ष पदों पर हैं ही नहीं। यही कारण है कि संयुक्त सचिव, सचिव और निदेशकों के 45 पदों को लेटरल भर्ती को संभव नहीं होने दिया गया। इन भर्तियों में भी एससी/ एसटी/ ओबीसी आरक्षण का प्रश्न खड़ा हो गया है।

सवाल यह भी है कि एससी वर्ग की कुछ उपजातियां आरक्षण में कम क्यों दिखती हैं? यह भ्रामक स्थिति साफ होनी ही चाहिए।

काटजू का सुझाव है, 'शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व पूरा करने के लिए पदोन्नति में रोका गया आरक्षण दिया जाए। पात्रता और आयु कारक को लेकर प्रशासनिक सेवाओं में सकारात्मक सुधार करके प्रतिनिधित्व पूरा किया जा सकता है। सिविल सेवा में सामान्य भर्ती के लिए आयु-सीमा 21 से 32 साल है, जबकि एससी/एसटी के लिए यह 37 साल होता है। होता यह है कि वे अधिक आयु में ही सेवा में जा पाते हैं और शीर्ष पर पहुंचने से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उन्हें सेवा काल कम मिलता है, इसलिए सिविल सेवा में उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए।

विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए राजकीय सेवाओं को समावेशी बनाया जाना चाहिए, भागीदारी के अवसरों को न्यायसंगत करने के प्रति सकारात्मक दृष्टि अपनानी चाहिए। एससी/एसटी की आबादी बढ़ने के अनुसार सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के कारगर उपाय होने चाहिए। एससी/एसटी के हिस्से का बजट उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास की बेहतरी पर ही व्यय होना चाहिए। उच्च शिक्षा में आज उनकी स्थिति क्या है, इसका अंदाजा इसी तथ्य से लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सौ साल में मुस्लिम सहित सभी उच्च जातियों के कुलपति बने, परंतु एससी/एसटी से कभी कोई नहीं आया। ऐसा ही हाल बीएचयू, एमएमयू का रहा है।

वस्तुस्थिति से अनभिज्ञ समाज के मानस में कैसी-कैसी धारणाएं पैठ जाती हैं, यह बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लोक गीतों में सहज देखी जा सकती है। क्या एससी/एसटी से जुड़ी अत्याचार, उत्पीड़न, छुआछूत की आपराधिक घटनाएं किसी भी संवेदनशील नागरिक की आंखें खोलने को काफी नहीं हैं? सवाल यह भी है कि एससी वर्ग की कुछ उपजातियां आरक्षण में कम क्यों दिखती हैं? यह भ्रामक स्थिति साफ होनी ही चाहिए। अगर विभाजन हुआ, तो संसदीय आरक्षण का क्या होगा? वंचितों के शिक्षण-प्रशिक्षण की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दीजिए। बैकलॉग खाली है, एनएफएस जारी है। विभाजन इनमें इजाफा ही करेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

अहंकार से मन कमजोर होगा

कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अहंकार से मुक्ति कैसे पाएं? इसको समझने के लिए बस घास पर गौर कीजिए। घास की गिनती सबसे मामूली चीजों में होती है, फिर भी इसके बिना असंख्य प्राणी अपना जीवन नहीं जी पाते। इसलिए अहंकार शून्यता की स्थिति को यदि कोई चीज सही रूप में दर्शाती है, तो वह घास है। मनुष्य को घास की तरह ही अहंकार मुक्त होना चाहिए। किसी किस्म के श्रेष्ठता-बोध, हीनता की भावना से दूर रहने की कोशिश में ही मनुष्य जीवन की वास्तविक प्रगति है, क्योंकि ये एक प्रकार से मानसिक रोग हैं। ये मानव-प्रगति में सबसे ज्यादा बाधक हैं।

मेरे एक परिचित के पास बड़ा बगीचा था। बाग के बीचोबीच उन्होंने अपना निवास बना रखा था। एक रात उनकी पत्नी को लगा कि बगीचे के कोने में भूत खड़ा है। वह डरकर जोर से चीख उठीं और बेहोश होकर गिर पड़ीं। कुछ समय बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस हादसे के कुछ दिनों बाद एक रात मेरे परिचित अपने शयन कक्ष की खिड़की पर खड़े पत्नी को याद कर रहे थे। तभी उन्हें भी लगा कि उन्हें भी भूत दिख रहा है। लेकिन जब डंडा लेकर वह उस आकृति के नजदीक पहुंचे, तो पाया कि वह एक झाड़ी थी, जो चांदनी रात में बिल्कुल इंसान जैसी दिख रही थी। भय की भावना इसी तरह से विकसित होती है।

पराजयवादी भावना भी मानव मन पर गहराई से वार करती है। 'मैं यह काम कैसे कर पाऊंगा? इतनी भारी बाधाओं से कैसे लड़ पाऊंगा? अपना काम ठीक से कैसे कर सकूंगा?' जो लोग काम करने से पहले इस तरह सोचते हैं, वे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते। साहसी लोग ही अधिक सफल होते हैं। इसलिए अध्यात्म को समझना यहां उपयोगी साबित होगा। आध्यात्मिक पथ का सबसे आवश्यक पहलू यह है कि मन को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाए और अंत में उसे परमपुरुष को समर्पित कर दिया जाए। लेकिन जो लोग श्रेष्ठता की भावना से ग्रस्त हैं या अति-प्रशंसा पाकर अहंकार से ग्रस्त हैं, उनके लिए मन को उसकी वस्तुओं से हटाना असंभव है। निराशा होने पर उनका मन आसानी से अपनी एकाग्रता से दूर चला जाता है। ऐसा मन कभी भी परमपुरुष को समर्पित नहीं हो सकता।

घास की गिनती सबसे मामूली चीजों में होती है, पर इसके बिना असंख्य प्राणी अपना जीवन नहीं जी पाते। अहंकार शून्यता की स्थिति को यदि कोई चीज सही रूप में दर्शाती है, तो वह घास है।

ऐसे लोग कभी भी यह समझ नहीं पाते कि अहंकार जितना अधिक फलता-फूलता है, मन उतना ही अधिक अपनी एकाग्रता खोता है, ठीक वैसे ही, जैसे चावल जितना अधिक फूलता है, वह उतना ही हल्का होता है- अंदर केवल हवा होती है। ऐसा न हो पाए, इसके लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा नहीं देना है। यह सबसे हानिकारक है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, यानी युद्ध के दौरान नागरिकों की रक्षा करने वाले विधान की अनदेखी की जा रही है और उसे कुचला जा रहा है। यह समूची मानवता, इंसानी जवाबदेही और नेतृत्व की विफलता है।

अनुलोम-विलोम
लेटरल एंट्री

बेहतर प्रशासन के लिए सीधी भर्ती जरूरी

सीधी भर्ती, यानी लेटरल एंट्री का एकमात्र लक्ष्य होता है, प्रतिभाशाली विशेषज्ञों को सरकार का अंग बनाना। इसमें आप आरक्षण घुसा ही नहीं सकते। यदि आरक्षित वर्ग का कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली है और विशेष ज्ञान रखने वाला है, तो उसे भी इसमें बिना आरक्षण के आने का पूरा अधिकार है। लेटरल एंट्री की आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है, क्योंकि अलग-अलग विषय में स्नातक प्रशासनिक अधिकारियों के हर तीन साल में विभाग बदलते रहते हैं। उनसे यह आशा रखना कि वे प्रशासन के अलावा किसी भी विषय के विशेषज्ञ होंगे (अपवाद को छोड़कर), उनके साथ अन्याय ही है। जल संरक्षण से लेकर नदियों की सफाई तक, बाल पोषण से लेकर उपग्रहों के प्रक्षेपण तक, आपको 'इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स' चाहिए, न कि तंत्र द्वारा चुने हुए छिछले जानकार। हर राज्य सरकार में आपको ऐसे दर्जनों लोग मिलेंगे, जो ऐसे कार्य करते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री के विज्ञापन को वापस लेना वास्तव में पिछले कई निर्णयों की वापसी की शृंखला में एक और कदम है। पहले तो आप ऐसे निर्णय मत लीजिए, जिस पर तनकर बोल नहीं सकते। यदि लेते हैं, तो अपने मंत्रियों से यह मत लिखवाइए कि यह तो कांग्रेस ही करती थी, हम तो बस आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस और उसके नेता पर सत्य बोलने का दबाव नहीं है। वे हर दिन आधिकारिक रूप से मिथ्या लिख और बोल रहे हैं। वे टैक्स पर आधी बात लिखते हैं और आप अपने ही फैसले से पीछे हटते हैं। बाद में आप वही करते हैं, जो वे चाहते हैं। इसीलिए वे 99 सीटों को अपनी जीत मान रहे हैं, क्योंकि कानून तो उनके मतलब के पास हो रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के पास इतना भी साहस नहीं है कि किसी भी बिल को यह कहकर लाए कि इससे ये लाभ होंगे। कृषि कानून भी यही कहकर लाया गया था कि कांग्रेस ही इसे लाना चाहती थी।

यदि ऐसा ही चलता रहा, तो विपक्षी दल जातिगत जनगणना भी कराएंगे, 75 प्रतिशत आरक्षण भी लागू कराएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी भी दिलवाएंगे और उसके बाद यह कहकर चुनाव भी जीत लेंगे कि जब विपक्ष में रहकर हम यह सब करा रहे हैं, तो सरकार में आने पर हम काफी काम करेंगे। साफ है, सत्तारूढ़ दल को ऐसी दुर्घटनाओं से स्वयं को बचाना चाहिए। निर्णय वही लीजिए, जिस पर आप अडिग रह सकें या निर्णय के बाद विपक्ष क्या बोल सकता है, उसके हर आयाम के आकलन और समाधान के बाद ही कुछ सार्वजनिक करें।

अजीत भारती, टिप्पणीकार

दलितों-पिछड़ों की हकमारी वाला कदम

लेटरल एंट्री का मतलब है, बिना मुश्किल परीक्षा पास किए और बिना समीक्षा के सीधे प्रशासनिक अधिकारी बनने का परोक्ष रास्ता। कुछ दिनों पहले भारत के नीति-निर्माताओं ने भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में खुलेआम जाने की अनुमति दी थी और अब सीधी भर्ती के नाम पर अपने लोगों को सीधे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति का रास्ता खोल दिया गया था। उनका यह कदम राष्ट्र-विरोधी है। ऐसी किसी व्यवस्था से देश कमजोर होगा और 'ए' ग्रेड की नौकरियों के लिए जी-जान लगाकर मेहनत करने वालों का अपमान होगा। आरक्षित वर्गों की हकमारी तो यह खैर है ही।

अरमान अली, टिप्पणीकार

नीति बदले

लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन सरकार ने वापस क्यों लिया, यह तो वही जाने, लेकिन इस पर कोई चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह है क्या? इस व्यवस्था का सामान्य अर्थ है, बिना परीक्षा के उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति। अगर देश में इसका प्रचलन बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, तो यह उन लोगों के लिए अभिशाप बन जाएगा, जो अपनी नियुक्ति या पदोन्नति के लिए ईमानदारी से काम करते हैं। वैसे, सरकारी विभागों में जिस तरह भ्रष्टाचार पसरा है, उसमें कहा जा सकता है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने या न होने से किसी को शायद ही कोई फर्क पड़ता, क्योंकि यहां सब गोलमाल है। मगर इसमें आमतौर पर मेहनत और ईमानदारी से काम करने वाले पीछे रह जाएंगे और चालाक-चापलूस आगे निकल जाएंगे। देश में बेरोजगारों की संख्या जिस तरह बढ़ती जा रही है, उसे देखते हुए लेटरल एंट्री जैसी व्यवस्था उन्हें आहत ही करेगी। अगर सरकार चाहती है कि विशेषज्ञ प्रशासनिक व्यवस्था में आएं, तो यूपीएससी परीक्षा में इस तरह का बदलाव हो कि अलग-अलग विषयों में दक्ष लोग प्रशासन का हिस्सा बन सकें। रही बात बेरोजगारी की, तो उसे दूर करने के लिए कुछ छोटे-छोटे प्रयास ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। मसलन, हमारे देश में कुछ सरकारी विभाग ऐसे हैं, जिनमें अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, तो उसका किसी अन्य विभाग में समावेश कर लिया जाता है। इसके बजाय, सरकार को उन बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रावधान करना चाहिए, जो दिन-रात नौकरी पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेटरल एंट्री जैसी व्यवस्था बनाने के बजाय पुरानी व्यवस्था में ही बदलाव किया जाए, तो बेरोजगारों को काफी फायदा हो सकता है।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जागरण
धर्म का सबसे बड़ा साधन स्वस्थ शरीर है

महत्वपूर्ण विदेश यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पोलैंड यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही यूक्रेन का उनका दौरा भी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा 45 वर्षों बाद हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश की यात्रा में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि दोनों देशों के दशकों से मधुर संबंध रहे हैं। पोलैंड के लिए भारत इसलिए भी महत्व रखता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वहां की सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को कहीं शरण नहीं मिल रही थी, तब भारतीय रियासतों ने उन्हें शरण दी थी। पोलैंड भारत के इस उपकार को भूला नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ आर्थिक संबंधों को भी बल प्रदान करेगी, लेकिन सबसे अधिक निगाह उनकी यूक्रेन यात्रा पर होगी। वह वहां 23 अगस्त को ट्रेन से पहुंचेंगे। इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें होंगी, क्योंकि हाल में भारतीय प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। जबसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तबसे अनेक देशों के शासनाध्यक्षों ने यूक्रेन की यात्रा की है, लेकिन ऐसे शासनाध्यक्ष गिनती के ही हैं, जिन्होंने रूस के साथ-साथ यूक्रेन की भी यात्रा की है।

भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे शासनाध्यक्ष हैं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ विदेश नीति पर कायम हैं। उनके नेतृत्व में भारत इस युद्ध का विरोध भी करता रहा है और इसके साथ ही रूस से अपने संबंध तोड़ने से मना भी करता रहा है। पश्चिमी देशों को भारत की यह नीति पसंद तो नहीं आई, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है, जो रूस को संघर्ष विराम के लिए राजी कर सकता है। यह धारणा भारत की कूटनीतिक महत्ता और उसके बढ़ते कद को रेखांकित करती है। इसका श्रेय मोदी सरकार की विदेश नीति को जाता है, जिसे उसने अपने पिछले दस वर्षों के शासनकाल में नई धार दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ने का एक कारण उसकी अर्थव्यवस्था का तेज गति से बढ़ना भी है और वह भी ऐसे समय, जब प्रमुख देश आर्थिक सुस्ती से दो-चार थे। रूस-यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में विश्व समुदाय न तो इसकी अनदेखी कर सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने किस तरह रूसी राष्ट्रपति से दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं और न ही इसकी कि उनकी पहल से भारत जी-20 सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों की सहमति वाला प्रस्ताव पारित करने में सफल हुआ था। इस सम्मेलन में और फिर उसके बाद भारतीय नेतृत्व ने जिस तरह ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों की आवाज बुलंद की है, उससे भी विश्व समुदाय को यह संदेश गया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विषयों के समाधान में महती भूमिका निभाने में सक्षम है। रूस-यूक्रेन युद्ध रोकना आसान नहीं, लेकिन भारत को इसकी पहल तो करनी ही चाहिए।

सतर्क होने का समय

हाल ही में धनबाद पहुंची नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मलेरिया रिसर्च टीम की रिपोर्ट हमें फाइलेरिया के प्रति सचेत करती है। इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि आने वाले आठ वर्षों में झारखंड में हर छह लोगों में एक व्यक्ति फाइलेरिया का शिकार होगा। धनबाद में 90 प्रतिशत मच्छर फाइलेरिया फैलानेवाले हैं, जिसके कारण इस रोग की चपेट में आने की आशंका बहुत अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि मच्छरों के नियंत्रण की व्यवस्था बहुत पुख्ता नहीं है। नगर निगम को मच्छरों को फैलने से रोकने की दिशा में जितना काम करना है, उतना हो नहीं पा रहा है। कहा तो जा रहा है कि मच्छरों को मारने के लिए फागिंग हो रही है, इस पर हर माह लाखों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। रिसर्च टीम ने विभिन्न स्थानों पर जाकर 560 मच्छरों के सैंपल लिए। इसकी जांच की गई तो इस गंभीर तथ्य का पता चला कि धनबाद जिले में 90 प्रतिशत मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति (फाइलेरिया बीमारी पैदा करनेवाले) के हैं। ये गंदे पानी में पनपते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि साफ-सफाई के तमाम दावे हवा-हवाई ही हैं। राज्य की राजधानी रांची समेत अन्य शहरों में जांच हो तो और उन स्थानों में भी ऐसी ही स्थिति मिलेगी, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप सभी जगह है। साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवा के मामले में हालात अच्छे नहीं हैं। विभाग के आंकड़े बताते हैं कि धनबाद में फाइलेरिया के करीब 7300 मरीज हैं। झारखंड की बात की जाए तो 50 हजार से अधिक मरीजों की संख्या है। समय की मांग है कि राज्य सरकार नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मलेरिया रिसर्च टीम की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए अभियान की समीक्षा करे और रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए।

झारखंड में फाइलेरिया मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अकेले धनबाद में 7300 मरीज हैं

बांग्लादेश में भारत के विकल्प

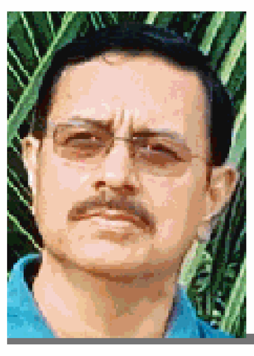

आर. विक्रम सिंह

बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और मजहबी शोषण एवं प्रताड़ना से उनकी मुक्ति भारत का लक्ष्य होना चाहिए

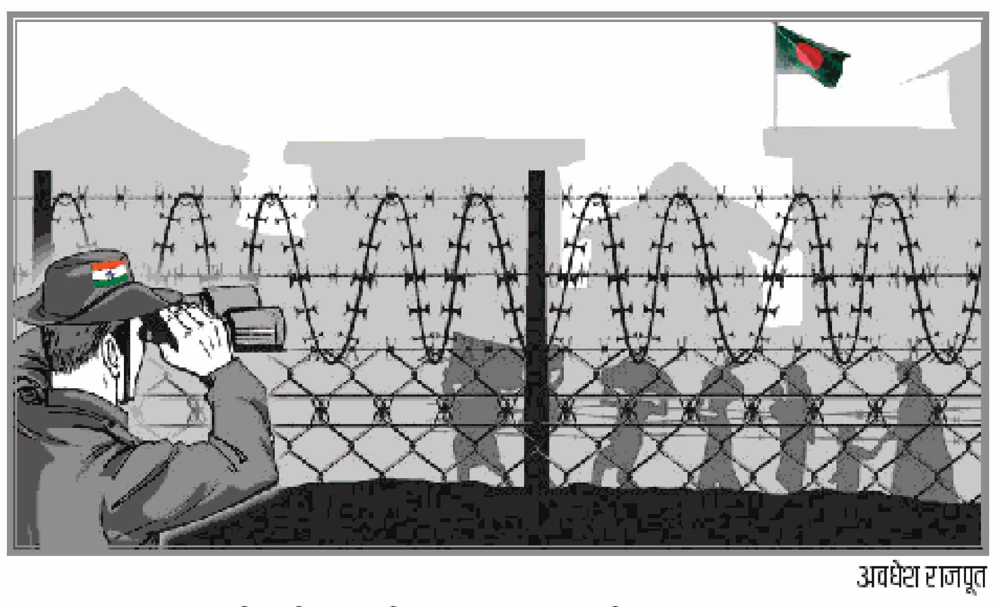

अवधेश राजपूत

पचास वर्षों की आजादी के बाद बांग्लादेश वापस पूर्वी पाकिस्तान बनने की दिशा में चल पड़ा है। इसके केंद्र में जमात-ए-इस्लामी और रजाकार हैं। इनका लक्ष्य हिंदू समाज भी है। इस अभियान में विदेशी शक्तियों की भूमिका भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप न मिलने के कारण उन्होंने हसीना सरकार को बर्खास्त करा दी। उनका एक उद्देश्य शेख हसीना को बेदखल कर वहां भारत विरोधी शक्तियों को सशक्त करना भी था। पूर्वोत्तर में ईसाई राज्य की स्थापना भी उनका एक एजेंडा है। फिलहाल इस पहले राउंड में वे सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन उनका खेल सामने आ गया है। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, जब बांग्लादेश में शेख मुजीब की परिवार सहित सेना और मजहबियों के गठजोड़ ने हत्या की थी। तब बांग्लादेश में भारत का तत्काल दखल देना बनता था। दिया भी, पर इंदिरा गांधी पर्याप्त साहस नहीं दिखा सकीं। उनके पास बांग्लादेश का भटकाव रोकने, वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने का आदर्श अवसर था। उनकी अनदेखी का नतीजा है कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति भयावह होने की तरफ बढ़ रही है। इसके कारण हिंदू बड़ी संख्या में भारत आना चाहते हैं, पर बीएसएफ द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। एक अच्छी बात यह हुई कि हत्या, आगजनी, लूटपाट, मंदिर ध्वंस के मध्य हिंदू समाज ने ढाका में प्रदर्शन करने का साहस किया। हालांकि दूसरे ही दिन इसकी प्रतिक्रिया में इस्लामिस्टों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इससे वहां की विषम स्थितियों का आभास होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत द्वारा बांग्लादेश शासन को सचेत करना चाहिए कि बांग्लादेशी हिंदू भारतीय सीमा को पार नहीं करेंगे, पर वे वापस हिंसक माहौल में नहीं भेजे जा सकते। अच्छा होगा कि भारत सरकार की व्यवस्था में बांग्लादेश की सीमा के अंदर ही शरणार्थी कैंप बनें। दोनों तरफ की सेनाएं शरणार्थियों की व्यवस्था के लिए बांग्लादेश की सीमा के इलाकों की प्रशासनिक सुविधाओं का उपयोग करें।

बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1947 (तब पूर्वी पाकिस्तान) में 28 प्रतिशत से घटकर आज 7.5 प्रतिशत रह गई है। बांग्लादेश बनते समय वहां हिंदू 15 प्रतिशत बचे थे। यह भी अजीब है कि 75 वर्षों की लगातार प्रताड़ना एवं अत्याचार के बावजूद वहां के हिंदू समाज ने कभी आजादी की मांग नहीं की, कोई प्रतिरोध मोर्चा, सशस्त्र सेना नहीं बनाई। 1.3 करोड़ के संख्याबल के बावजूद वे कश्मीरी पंडितों के समान जीवन व्यतीत करते रहे। उनमें कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं उभरा, कोई हथियारबंद संगठन नहीं बना, जबकि वे इजरायल के यहूदियों से संख्याबल में दोगुने हैं।

एक बड़ी और अवैध बांग्लादेशी आबादी भारत में निवास कर रही है और वहां बांग्लादेश के हिंदू मजहबी कट्टरता के शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के मानवाधिकार हनन की जो वीभत्स स्थितियां हैं, वे हमारे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा भी नहीं बन पातीं। सेक्युलरिज्म से बीमार हमारे नेताओं ने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया। अब भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने रास्ता क्या है? कट्टर मजहबियों की जकड़न से बांग्लादेश के हिंदू समाज की मुक्ति एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मुक्ति की राहों पर कोई फूल नहीं बिछे होते। वह संघर्ष और बलिदान से होकर आता है। बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक राजनीतिक दल का गठन समाधान के रास्ते का पहला पड़ाव है। आगे संघर्ष प्रारंभ होंगे। संघर्षों की सफलताएं हमें हमारे दूसरे कदम यानी स्वशासी स्वायत्त हिंदू परिक्षेत्रों के गठन की राह खोलेंगी। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी आबादी के सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करके अपने संख्याबल को एकत्रित करना होगा। फिर वहां से आगे की रूपरेखा बननी प्रारंभ होगी। यहां भारत की भूमिका 1971 की तरह सफलता एवं असफलता में निर्णायक सिद्ध होगी। इससे भारत की चिकेन नेक जैसी रणनीतिक समस्याओं का समाधान भी होगा। चटगांव एवं रंगपुर के क्षेत्रों को स्वायत्त हिंदू क्षेत्र बना कर वहां हिंदुओं को स्थानांतरित किया जाना संभव तभी हो सकेगा, जब भारत की इसमें भूमिका होगी।

1947-48 के युद्ध के समय पाकिस्तान ने कश्मीर में हमारी 85 हजार वर्ग किमी भूमि पर कब्जा कर लिया था। उस समय यदि नेहरू चाहते तो उसकी प्रतिक्रिया में पूर्वी पाकिस्तान के रंगपुर, सिलहट, चटगांव के इलाके अपने अधिकार में आसानी से लिए जा सकते थे। ये स्थायी रूप से भारत से जुड़े हुए क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लिए सुरक्षित परिक्षेत्र बन सकते थे, लेकिन हमारे तुष्टीकरणजीवी नेता रणनीतिक बुद्धि-चातुर्य नहीं दिखा पाए। अब समाधान संघर्ष और बलिदानों से ही संभव है। न भूलें जब इजरायल देश बना और सिर पर युद्ध आ गया तो यहूदी जबर्दस्त लड़ाके बने।

विश्व में सुरक्षित परिक्षेत्र जैसी व्यवस्थाओं के अनेक उदाहरण हैं। रूस ने एक वर्ष पहले डोनबास में दो स्वायत्त परिक्षेत्र के गठन की घोषणा की। कुछ इसी तरह बांग्लादेश के रंगपुर डिविजन के 17,000 वर्गकिमी एवं चटगांव डिविजन के 34,500 वर्ग किमी क्षेत्रों को अधिकार में लेकर वहां के समस्त 1.3 करोड़ हिंदुओं के समायोजन की व्यवस्था करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कभी जिन्ना ने कहा था कि हिंदू-मुसलमान अलग राष्ट्र हैं, वे साथ नहीं रह सकते। यही पाकिस्तान के गठन का आधारभूत सिद्धांत बना। वही तर्क इस्लामी बांग्लादेश में भी लागू करने का समय आ गया है। 1950 में हुए ढाका के भीषण दंगों में दस हजार हिंदुओं की नृशंस हत्या से सरदार पटेल इतने व्यथित हो गए थे कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा कर वहां हिंदुओं को बसाने की चेतावनी तक दे दी थी। आज इतने वर्षों बाद 1971 के बांग्लादेश युद्ध जैसी स्थितियां पुनः बन रही हैं। अंतर यह है कि जो पिछला अभियान था, वह बांग्लादेश की आजादी का था और अगला अभियान बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और मजहबी शोषण एवं प्रताड़ना से मुक्ति के लिए होना चाहिए। यह एक बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा, जो भारत की बांग्लादेश समस्या और चीन, पाकिस्तान एवं अमेरिका की कुटिल चालों की आशंका का स्थायी अंत कर देगा।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

सहकारी क्षेत्र में नई जान फूंकते पैक्स

शाजी के वी

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने से बेरोजगारी खत्म होने के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी

दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025' के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत का सहकारिता क्षेत्र मजबूत स्थिति में है और देशभर में नई, मजबूत एवं तेजी से उभरती हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स का प्रसार हो रहा है। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से लैस ये पैक्स अब ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यद्यपि भारत में सहकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुप्रबंधन, संकट के समय पर्याप्त सरकारी समर्थन की कमी और आवश्यक सुधारों की अनुपस्थिति के कारण इसका विकास बाधित रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय का गठन करने और गृहमंत्री अमित शाह को इसकी कमान सौंपने के तुरंत बाद सहकारिता क्षेत्र में बदलाव की बयार बहने लगी। सहकारिता की क्षमता को अब देश के भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के पुराने जानकार हैं। वह सहकारिता क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले कारणों से अच्छी तरह परिचित हैं। इन बाधाओं में पैक्स के विविधीकरण की कमी थी, जिसने उन्हें लगभग अव्यवहार्य बना दिया था।

अमित शाह ने पैक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, वह उनके बायलाज यानी उप-नियमों में बदलाव लाना था। पैक्स की समस्याओं से छुटकारे के लिए माडल बायलाज लाकर उन्हें बहुद्देश्यीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पैक्स को अपने व्यवसाय को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर विविधता लाने में मदद मिली है। अब वे कामन सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण भारत में 300 से अधिक ई-सेवाएं जैसे-बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और ट्रेन/बस/हवाई टिकट आदि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को ये सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जल समितियों, एलपीजी वितरकों, खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों, किसान उत्पादक संगठनों आदि के रूप में कार्य करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है। पैक्स अब गांवों में सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हुए आय का एक और स्रोत पैदा हो रहा है। ये सभी प्रयास पैक्स की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किए जा रहे हैं।

ग्रामीण भारत में आ रहा है बदलाव। फाइल

सहकारिता मंत्रालय का अगला महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतना है। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक 23 हजार से अधिक पैक्स को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग साफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा चुका है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उन्हें सीधे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से जोड़ा जा सकेगा। कामन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम से संचालन में एकरूपता आएगी। इससे पैक्स संचालन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता क्षेत्र में हुई इन अनूठी पहलों से यह क्षेत्र अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरे देश में संगठित रूप में काम कर रहा है, जो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से जिला सहकारी बैंकों में बैंक खाते खोलने का आह्वान किया है, ताकि उन्हें व्यवहार्य बनाया जा सके। उनके अनुसार, सहकारी समितियों के बीच सहयोग एक मजबूत आर्थिक सिद्धांत है, जो मजबूत सहकारी क्षेत्र के निर्माण के लिए जरूरी है। अमित शाह ने जमीनी स्तर पर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करके इस क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके पिछले कार्यकाल में नीतिगत ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और वर्तमान कार्यकाल में उनकी प्राथमिकता इन नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाने की होगी।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक सहकारी क्षेत्र में 'विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम' है। इस योजना का उद्देश्य पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण के लिए विकेंद्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि अवसंरचनाएं बनाना है। इन गोदामों का उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना है। कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण आदि का उद्देश्य देश के लिए एक विशाल भंडारण क्षमता का निर्माण करना है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे और विभिन्न कृषि जरूरतों को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा।

चूंकि पैक्स ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं, इसलिए इनके सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार से बहुत जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने से जहां मौसमी बेरोजगारी खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, वहीं इससे करीब एक लाख पैक्स से सीधे जुड़े 13 करोड़ किसानों को विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन में फायदा होगा।

(लेखक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड-के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चमत्कार

एक बार एक साधक ने प्रश्न किया, क्या दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज है? यदि है तो वह क्या है? अलौकिक नाम की कोई चीज है नहीं। सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर छिपी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं होता। समय-समय पर हर कोई अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को महसूस करता है। इसे ही बुद्धि और बोधि कहते हैं। इनका विकास होने पर मनुष्य में असाधारण शक्ति आ जाती है। यह स्वाभाविक है।

साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, जिसके कारण, वे इस शक्ति को अलौकिक समझ बैठते हैं। जब तक मन बंधनयुक्त रहता है, उसकी गति जड़ वस्तुओं की ओर रहती है, लेकिन साधना से मन का बंधन टूट जाता है। मन स्थूल विषय से भी हट जाता है। यही है मनुष्य का विकास। विकास की ओर उन्मुख होने पर ही शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति संभव है। मानसिक प्रगति के कारण मनुष्य में असाधारण बुद्धि आ जाती है और मानसिक प्रगति के कारण वह समाज में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। रिपु का अर्थ है आंतरिक दुश्मन। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है रिपुओं का वश में हो जाना। इस हालत में मनुष्य का जड़ तत्वों पर और अधिक स्वामित्व हो जाता है।

तंत्र के अनुसार जड़ या बाह्य तत्वों पर विजय पाने की चेष्टा है 'अविद्या साधना'। आत्मज्ञान के लिए जो साधना की जाती है, उसे 'विद्या साधना' कहते हैं, लेकिन जहां विद्या या अविद्या में कोई नहीं है, उसे कहते हैं उपविद्या। मनुष्य के लिए विद्या साधना ही कल्याणकारी है, बाकी दोनों से केवल समय नष्ट होता है। अलौकिक शक्ति पाने के लिए जो लोग साधना करते हैं उनका विषय जड़ तत्व रहता है। इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करने पर व्यक्ति इसका उपयोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए या द्वेष वश करते हैं। मनुष्य को साधना करनी चाहिए ब्रह्म बनने के लिए, न कि पिशाच बनने के लिए।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

जीवन के रंग सहेजतीं लोक कथाएं

डा. मोनिका शर्मा

वैश्विक समाज आज अपनी जड़ों से स्वयं को कटा हुआ महसूस कर रहा है, तब विश्व लोक कथा दिवस की महत्ता और बढ़ जाती है

हर वर्ष 22 अगस्त को दुनिया भर में लोग विश्व लोककथा दिवस मनाते हैं। इस दिन इन मौखिक कथाओं और कला रूपों की संस्कृति के महत्व को समझकर इनके संरक्षण के प्रति सजगता लाने की कोशिश करते हैं। इन मौखिक परंपराओं में लोकगीत, कहानियां और अनगिनत किंवदंतियां, हास्य से जुड़ी कहावतें और यहां तक कि गूढ़-गंभीर जीवन दर्शन भी शामिल होता है। विश्व के सभी समुदायों में जनजीवन, स्वास्थ्य, रीति-रिवाज और सामाजिक जीवनशैली से जुड़ी बहुत बातें लोककथाओं के माध्यम से ही आगे बढ़ती रही हैं। विश्व लोककथा दिवस ऐसे ही आख्यानों के महत्व को समझने का दिन है, जो इंसानी जीवन से जुड़ा बहुत कुछ संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इतना ही नहीं, हर तरह की विरासत को समेटकर संरक्षित रखने वाले इन मौखिक आख्यानों की फेहरिस्त में लोक मान्यताएं भी अपनी भागीदारी रखती हैं। भौतिक रूप से भी वास्तुकला यानी कि भवन निर्माण की शैली, लोक नृत्य यानी प्रथागत कलात्मक विद्या और हस्तनिर्मित खिलौने भी इसका हिस्सा माने जाते हैं। बहुत सी ऐतिहासिक जानकारियों को समर्पित यह दिन मानव सभ्यता की विकास यात्रा का लेखा-जोखा सा है।

मौजूदा समय में जब संसार का हर समाज ही अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस कर रहा है, तब ऐसे आख्यानों की अहमियत और बढ़ जाती है। दरअसल सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जुड़ाव की यह पहल ब्राजील में वर्ष 1965 में शुरू हुई थी। अब पूरी दुनिया के देश अपनी लोक परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए इस दिन को विशेष मानते हैं। कहानियों, किंवदंतियों और लोक कलाओं के विभिन्न माध्यमों के साथ इस दिन लोक कथाओं की परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास किए जाते हैं। लाजिमी भी है, क्योंकि लोक कथाओं के जरिये ही दुनिया भर के समुदायों की सांस्कृतिक और परंपरागत थाती अगली पीढ़ी तक पहुंचती रही है।

भारत की समृद्ध लोक परंपराओं के रंग पूरी दुनिया को आकर्षित करते रहे हैं। लोक के आलोक ने आंचलिक रीति-नीति को सहेजते हुए समाज की संवेदनाओं को आगे बढ़ाया है। स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रकृति संरक्षण की जो बातें आज जीवन सहेजने के लिए आवश्यक हैं, वे हमारे परिवारों में मौखिक आख्यानों के माध्यम से पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती आ रही हैं। आज मनोविज्ञानी भी मानते हैं कि तनाव, अवसाद और अकेलेपन की परिस्थितियों वाली मौजूदा जीवनशैली में लोक जीवन से जुड़ा हर पक्ष जीवन को उत्साह दे सकता है। समाज को सामाजिक, सांस्कृतिक और परंपरागत एकता के सूत्र में बांधने वाली इस भावों भरी धरोहर के हर पक्ष को सहेजना जरूरी है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

शातिर अमेरिकी इरादों की काट

''अमेरिकी पिछलग्गुओं से सावधान'' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में विकास सारस्वत ने तथ्यों के साथ अमेरिकी शातिर इरादों को उजागर करते हुए आम भारतीयों को जागरूक करने का कार्य किया है। यह सत्य है कि कुछ पश्चिमी शक्तियां किसी भी देश और वहां के लोगों का केवल शोषण ही करती हैं, उनका उत्थान तो सपने में भी नहीं करती हैं। अब सभी देशों को अपने-अपने जयचंदों को भी जानना-समझना चाहिए। महज कुछ पैसों के लिए वे अपने ही देश के भोले-भाले नागरिकों को, कभी आरक्षण तो कभी लोकतंत्र के नाम पर डराते और बहकाते हैं। इन पश्चिमी शक्तियों से ओतप्रोत कुछ एनजीओ और यूट्यूबरों ने आजकल भारत के युवा वर्ग को भी बरगलाना शुरू कर दिया है। ये आस्तीन के सांप की तरह बड़ा ही प्रभावी एजेंडा दिन-रात इंटरनेट मीडिया पर चला रहे हैं और इनका शिकार भारत के अल्पसंख्यक, पिछड़े और वंचित तबके के लोग हो रहे हैं, जिनका गुस्सा सरकार के किसी न किसी योजना में किसी कारणवश वंचित हो जाने को लेकर है। ये आस्तीन के सांप इन्हें ही अपना शिकार बनाकर किसी दिन कोई बड़ा बखेड़ा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। अब केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इंटरनेट मीडिया के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वह कुछ उपाय करे। इसमें कुछ देशप्रेमी यूट्यूबरों का भी सहयोग लिया जा सकता है। ये राष्ट्रविरोधी कथित बुद्धिजीवियों और यूट्यूबरों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की अपनी तर्कपूर्ण बातों से काट करेंगे तो आमजन को विभिन्न विषयों पर संतुलित दृष्टिकोण बनाने में

मेलबाक्स

मदद मिलेगी।

संपूर्णानंद वर्मा, हेतिमपुर, गोरखपुर

समाज भी सुधरे

हाल के दिनों में पूरे देश में महिलाओं पर यौन हिंसा सहित विभिन्न तरह के अत्याचार के मामले काफी हद तक बढ़ गए हैं। साल 2012 के निर्भया कांड के बाद कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में निर्भया कांड की पुनरावृत्ति के बाद देश उबाल में है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या का इंतजार नहीं कर सकता। कोर्ट द्वारा गठित 14 सदस्यीय टास्क फोर्स को दो माह माह में अंतिम रिपोर्ट देनी है। इस बीच कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल और उसके हास्टल की सुरक्षा सीआइएसएफ को दे दी गई है। एक टीस-सी मन में उठती है कि आखिर नारी कब तक भोग की वस्तु बनी रहेगी? उसका जीवन कब तक खतरों से घिरा रहेगा? दुष्कर्म, छेड़खानी, भ्रूण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी? कब तक उसके अस्तित्व एवं अस्मिता को नोचा जाता रहेगा? तमाम जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों के बावजूद देश में महिलाओं की स्थिति में यथोचित बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानूनों की कठोरता से अनुपालना एवं सरकारों में इच्छाशक्ति जरूरी है।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

सरकार पलटने की कोशिश

कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद ने बांग्लादेश में तख्तापलट की घटना के बाद यह कहने में तनिक भी देर नही लगाई कि भारत में भी ऐसा संभव है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी यहां बांग्लादेश एवं श्रीलंका जैसे हालात होने की आशंका व्यक्त की है। वस्तुतः भारत में विपक्षी दल किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा तीसरी बार सरकार बनाने को पचा नहीं पा रहे हैं। वर्तमान विपक्ष न तो रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण से खुश है, न उसको अनुच्छेद-370 का हटना भा रहा है, न वह तीन तलाक पर बंदिश को पचा पा रहा है। अमेरिका भी भारत के विकास से खुश नहीं है। भारत ने अमेरिका के मना करने पर भी रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली को खरीदा एवं रूस से तेल खरीदना जारी रखा, जिससे अमेरिका नाराज है और वह भारत में ऐसी कमजोर सरकार की कामना करता है जो उसके इशारे पर चले। ऐसे में विपक्षी नेताओं के बयान विचलित करने वाले हैं।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

धर्म का सबसे बड़ा साधन स्वस्थ शरीर है

महत्वपूर्ण विदेश यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पोलैंड यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही यूक्रेन का उनका दौरा भी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा 45 वर्षों बाद हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री की यूरोप के इस महत्वपूर्ण देश की यात्रा में इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था। इसलिए और भी नहीं, क्योंकि दोनों देशों के दशकों से मधुर संबंध रहे हैं। पोलैंड के लिए भारत इसलिए भी महत्व रखता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब वहां की सैकड़ों महिलाओं और बच्चों को कहीं शरण नहीं मिल रही थी, तब भारतीय रियासतों ने उन्हें शरण दी थी। पोलैंड भारत के इस उपकार को भूला नहीं है। यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने के साथ आर्थिक संबंधों को भी बल प्रदान करेगी, लेकिन सबसे अधिक निगाह उनकी यूक्रेन यात्रा पर होगी। वह वहां 23 अगस्त को ट्रेन से पहुंचेंगे। इस यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें होंगी, क्योंकि हाल में भारतीय प्रधानमंत्री रूस भी गए थे। जबसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, तबसे अनेक देशों के शासनाध्यक्षों ने यूक्रेन की यात्रा की है, लेकिन ऐसे शासनाध्यक्ष गिनती के ही हैं, जिन्होंने रूस के साथ-साथ यूक्रेन की भी यात्रा की है। भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसे शासनाध्यक्ष हैं, जो रूस-यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ विदेश नीति पर कायम हैं। उनके नेतृत्व में भारत इस युद्ध का विरोध भी करता रहा है और इसके साथ ही रूस से अपने संबंध तोड़ने से मना भी करता रहा है। पश्चिमी देशों को भारत की यह नीति पसंद तो नहीं आई, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है, जो रूस को संघर्ष विराम के लिए राजी कर सकता है। यह धारणा भारत की कूटनीतिक महत्ता और उसके बढ़ते कद को रेखांकित करती है। इसका श्रेय मोदी सरकार की विदेश नीति को जाता है, जिसे उसने अपने पिछले दस वर्षों के शासनकाल में नई धार दी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का कद बढ़ने का एक कारण उसकी अर्थव्यवस्था का तेज गति से बढ़ना भी है और वह भी ऐसे समय, जब प्रमुख देश आर्थिक सुस्ती से दो-चार थे। रूस-यूक्रेन युद्ध के सिलसिले में विश्व समुदाय न तो इसकी अनदेखी कर सकता है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने किस तरह रूसी राष्ट्रपति से दो टूक कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं और न ही इसकी कि उनकी पहल से भारत जी-20 सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर सभी देशों की सहमति वाला प्रस्ताव पारित करने में सफल हुआ था। इस सम्मेलन में और फिर उसके बाद भारतीय नेतृत्व ने जिस तरह ग्लोबल साउथ कहे जाने वाले देशों की आवाज बुलंद की है, उससे भी विश्व समुदाय को यह संदेश गया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विषयों के समाधान में महती भूमिका निभाने में सक्षम है। रूस-यूक्रेन युद्ध रोकना आसान नहीं, लेकिन भारत को इसकी पहल तो करनी ही चाहिए।

सराहनीय फैसला

राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर प्रदेश सरकार का फैसला सराहनीय है। लेकिन, सरकार का नया निर्णय प्रभावी ढंग से लागू हो, इसका क्रियान्वयन ठीक से हो और काम मानक के अनुसार समय पर हो, इसका ध्यान रखना होगा। तभी सरकार के इस निर्णय की सार्थकता होगी। अभी तक विश्वविद्यालय स्तर पर सीनेट की बैठक में योजनाएं तय होती थीं। सीनेट की बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाता था। उसमें प्रस्ताव पास कर राशि की मांग सरकार से की जाती थी। अब यह काम राज्य सरकार करेगी। इसके लिए राज्य मुख्यालय स्तर पर निर्माण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्यों के लिए तीन अलग-अलग कमेटियों का गठन भी किया है। कालेजों के विकास के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। अनुशंसित योजनाओं के बारे में पोर्टल पर जानकारी देने का निर्णय भी अच्छा है। इससे पारदर्शिता रहेगी। योजनाओं के बारे में आसानी से कोई भी जानकारी ले सकेगा। एक बार अनुशंसित योजना के पूरा होने के बाद ही दूसरी योजना लेने संबंधी निर्णय भी बढ़िया है। इससे काम को गति मिलेगी। अभी तक होता यह है कि एक साथ कई योजनाएं ले ली जाती हैं। कुछ का काम पूरा हो पाता है कुछ का नहीं। कई काम तो वर्षों तक चलते रहते हैं। योजना में देरी से उनकी लागत भी बढ़ती जाती है। उनकी निगरानी भी ठीक से नहीं हो पाती। इस निर्णय से उसपर भी रोक लगेगी। योजनाओं का कार्यान्वयन बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के स्तर पर होने से गड़बड़ी की कम आशंका रहेगी।

> सरकार का नया निर्णय प्रभावी ढंग से लागू हो, इसका क्रियान्वयन ठीक से हो और काम मानक के अनुसार समय पर हो, इसका ध्यान रखना होगा।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या विपक्ष के दबाव के चलते मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लिया?

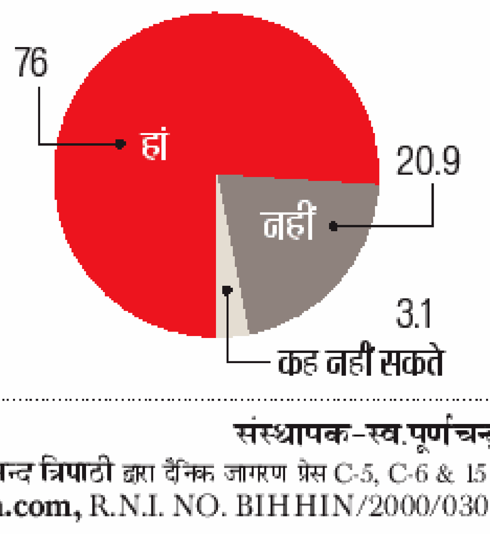

आज का सवाल
क्या प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा से रूस-अमेरिका के साथ संबंधों को संतुलित करने में मदद मिलेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

बांग्लादेश में भारत के विकल्प

आर. विक्रम सिंह

बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और मजहबी शोषण एवं प्रताड़ना से उनकी मुक्ति भारत का लक्ष्य होना चाहिए

पचास वर्षों की आजादी के बाद बांग्लादेश वापस पूर्वी पाकिस्तान बनने की दिशा में चल पड़ा है। इसके केंद्र में जमात-ए-इस्लामी और रजाकार हैं। इनका लक्ष्य हिंदू समाज भी है। इस अभियान में विदेशी शक्तियों की भूमिका भी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश का सेंट मार्टिन द्वीप न मिलने के कारण उन्होंने हसीना सरकार को बर्खास्त करा दी। उनका एक उद्देश्य शेख हसीना को बेदखल कर वहां भारत विरोधी शक्तियों को सशक्त करना भी था। पूर्वोत्तर में ईसाई राज्य की स्थापना भी उनका एक एजेंडा है। फिलहाल इस पहले राउंड में वे सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन उनका खेल सामने आ गया है। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, जब बांग्लादेश में शेख मुजीब की परिवार सहित सेना और मजहबियों के गठजोड़ ने हत्या की थी। तब बांग्लादेश में भारत का तत्काल दखल देना बनता था। दिया भी, लेकिन इंदिरा गांधी पर्याप्त साहस नहीं दिखा सकीं। उनके पास बांग्लादेश का भटकाव रोकने और वहां के अल्पसंख्यकों को सुरक्षित करने का आदर्श अवसर था। उनकी अनदेखी का नतीजा है कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति भयावह होने की तरफ बढ़ रही है। इसके कारण हिंदू बड़ी संख्या में भारत आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ द्वारा उन्हें रोका जा रहा है। एक अच्छी बात यह हुई कि हत्या, आगजनी, लूटपाट, मंदिर ध्वंस के मध्य हिंदू समाज ने ढाका की सड़कों पर प्रदर्शन करने का साहस किया। हालांकि दूसरे ही दिन इसकी प्रतिक्रिया में इस्लामिस्टों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इससे वहां की विषम स्थितियों का आभास होता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का सिलसिला थमा नहीं है। ऐसी स्थिति में भारत द्वारा बांग्लादेश शासन को सचेत करना चाहिए कि बांग्लादेशी हिंदू भारतीय सीमा को पार नहीं करेंगे, लेकिन वे वापस हिंसक माहौल में नहीं भेजे जा सकते। अच्छा होगा कि भारत सरकार की व्यवस्था में बांग्लादेश की सीमा के अंदर ही शरणार्थी कैंप बनें। दोनों तरफ की सेनाएं शरणार्थियों की व्यवस्था के लिए बांग्लादेश की सीमा के इलाकों की प्रशासनिक सुविधाओं का उपयोग करें।

बांग्लादेश में हिंदू आबादी 1947 (तब पूर्वी पाकिस्तान) में 28 प्रतिशत से घटकर आज 7.5 प्रतिशत रह गई है। बांग्लादेश बनते समय वहां हिंदू 15 प्रतिशत बचे थे। यह भी अजीब है कि 75 वर्षों की लगातार प्रताड़ना एवं अत्याचार के बावजूद वहां के हिंदू समाज ने कभी आजादी की मांग नहीं की, कोई प्रतिरोध मोर्चा, सशस्त्र सेना नहीं बनाई। 1.3 करोड़ के संख्याबल के बावजूद वे कश्मीरी पंडितों के समान जीवन व्यतीत करते रहे। उनमें कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं उभरा, कोई हथियारबंद संगठन नहीं बना, जबकि वे इजरायल के यहूदियों से संख्याबल में दोगुने हैं।

अवधेश राजपूत

एक बड़ी और अवैध बांग्लादेशी आबादी भारत में निवास कर रही है और वहां बांग्लादेश के हिंदू मजहबी कट्टरता के शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के मानवाधिकार हनन की जो बीभत्स स्थितियां हैं, वे हमारे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा भी नहीं बन पातीं। सेक्युलरिज्म से बीमार हमारे नेताओं ने कभी उनका मुद्दा नहीं उठाया। अब भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में भारत के सामने रास्ता क्या है? कट्टर मजहबियों की जकड़न से बांग्लादेश के हिंदू समाज की मुक्ति एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। मुक्ति की राहों पर कोई फूल नहीं बिछे होते। वह संघर्ष और बलिदान से होकर आता है। बांग्लादेश में एक अल्पसंख्यक राजनीतिक दल का गठन समाधान के रास्ते का पहला पड़ाव है। आगे संघर्ष प्रारंभ होंगे। संघर्षों की सफलताएं हमें हमारे दूसरे कदम यानी स्वशासी स्वायत्त हिंदू परिक्षेत्रों के गठन की राह खोलेंगी। अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी आबादी के सुरक्षित क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करके अपने संख्याबल को एकत्रित करना होगा। फिर वहां से आगे की रूपरेखा बननी प्रारंभ होगी। यहां भारत की भूमिका 1971 की तरह सफलता एवं असफलता में निर्णायक सिद्ध होगी। इससे भारत की चिकेन नेक जैसी रणनीतिक समस्याओं का समाधान भी होगा। चटगांव एवं रंगपुर के क्षेत्रों को स्वायत्त हिंदू क्षेत्र बना कर वहां हिंदुओं को स्थानांतरित किया जाना संभव तभी हो सकेगा, जब भारत की इसमें भूमिका होगी।

1947-48 के युद्ध के समय पाकिस्तान ने कश्मीर में हमारी 85 हजार वर्ग किमी भूमि पर कब्जा कर लिया था। उस समय यदि नेहरू चाहते तो उसकी प्रतिक्रिया में पूर्वी पाकिस्तान के रंगपुर, सिलहट, चटगांव के इलाके अपने अधिकार में आसानी से लिए जा सकते थे। ये स्थायी रूप से भारत से जुड़े हुए क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लिए सुरक्षित परिक्षेत्र बन सकते थे, लेकिन हमारे तुष्टीकरणजीवी नेता रणनीतिक बुद्धि-चातुर्य नहीं दिखा पाए। अब समाधान संघर्ष और बलिदानों से ही संभव है। न भूलें जब इजरायल देश बना और सिर पर युद्ध आ गया तो यहूदी जबर्दस्त लड़ाके बने।

विश्व में सुरक्षित परिक्षेत्र जैसी व्यवस्थाओं के अनेक उदाहरण हैं। रूस ने एक वर्ष पहले डोनबास में दो स्वायत्त परिक्षेत्र के गठन की घोषणा की। कुछ इसी तरह बांग्लादेश के रंगपुर डिविजन के 17,000 वर्गकिमी एवं चटगांव डिविजन के 34,500 वर्ग किमी क्षेत्रों को अधिकार में लेकर वहां के समस्त 1.3 करोड़ हिंदुओं के समायोजन की व्यवस्था करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। कभी जिन्ना ने कहा था कि हिंदू-मुसलमान अलग राष्ट्र हैं, वे साथ नहीं रह सकते। यही पाकिस्तान के गठन का आधारभूत सिद्धांत बना। वही तर्क इस्लामी बांग्लादेश में भी लागू करने का समय आ गया है। 1950 में हुए ढाका के भीषण दंगों में दस हजार हिंदुओं की नृशंस हत्या से सरदार पटेल इतने व्यथित हो गए थे कि उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की भूमि पर कब्जा कर वहां हिंदुओं को बसाने की चेतावनी तक दे दी थी। आज इतने वर्षों बाद 1971 के बांग्लादेश युद्ध जैसी स्थितियां पुनः बन रही हैं। अंतर यह है कि जो पिछला अभियान था, वह बांग्लादेश की आजादी का था और अगला अभियान बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता और मजहबी शोषण एवं प्रताड़ना से मुक्ति के लिए होना चाहिए। यह एक बड़ा राजनीतिक निर्णय होगा, जो भारत की बांग्लादेश समस्या और चीन, पाकिस्तान एवं अमेरिका की कुटिल चालों की आशंका का स्थायी अंत कर देगा।

(लेखक पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक हैं)

response@jagran.com

सहकारी क्षेत्र में नई जान फूंकते पैक्स

शाजी के वी

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने से बेरोजगारी खत्म होने के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी

दुनिया भर में 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025' के स्वागत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है, जब भारत का सहकारिता क्षेत्र मजबूत स्थिति में है और देशभर में नई, मजबूत एवं तेजी से उभरती हुई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी पैक्स का प्रसार हो रहा है। आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों से लैस ये पैक्स अब ग्रामीण और कृषि प्रधान भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यद्यपि भारत में सहकारिता का गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन कुप्रबंधन, संकट के समय पर्याप्त सरकारी समर्थन की कमी और आवश्यक सुधारों की अनुपस्थिति के कारण इसका विकास बाधित रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में सहकारिता मंत्रालय का गठन करने और गृहमंत्री अमित शाह को इसकी कमान सौंपने के तुरंत बाद सहकारिता क्षेत्र में बदलाव की बयार बहने लगी। सहकारिता की क्षमता को अब देश के भविष्य को आकार देने वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। अमित शाह सहकारिता क्षेत्र के पुराने जानकार हैं। वह सहकारिता क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले कारणों से अच्छी तरह परिचित हैं। इन बाधाओं में पैक्स के विविधीकरण की कमी थी, जिसने उन्हें लगभग अव्यवहार्य बना दिया था।

अमित शाह ने पैक्स के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, वह उनके बायलाज यानी उप-नियमों में बदलाव लाना था। पैक्स की समस्याओं से छुटकारे के लिए माडल बायलाज लाकर उन्हें बहुद्देश्यीय बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे पैक्स को अपने व्यवसाय को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर विविधता लाने में मदद मिली है। अब वे कामन सर्विस सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण भारत में 300 से अधिक ई-सेवाएं जैसे-बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड और ट्रेन/बस/हवाई टिकट आदि सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक 35,000 से अधिक पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को ये सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अब उन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जल समितियों, एलपीजी वितरकों, खुदरा पेट्रोल/डीजल दुकानों, किसान उत्पादक संगठनों आदि के रूप में कार्य करने में भी सक्षम बनाया जा रहा है। पैक्स अब गांवों में सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के वितरण के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में भी काम कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिए सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हुए आय का एक और स्रोत पैदा हो रहा है। ये सभी प्रयास पैक्स की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए किए जा रहे हैं।

ग्रामीण भारत में आ रहा है बदलाव ● फाइल

सहकारिता मंत्रालय का अगला महत्वपूर्ण कार्य इस क्षेत्र में लोगों का विश्वास जीतना है। इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 63,000 पैक्स का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब तक 23 हजार से अधिक पैक्स को एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग साफ्टवेयर के साथ एकीकृत किया जा चुका है। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से उन्हें सीधे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से जोड़ा जा सकेगा। कामन अकाउंटिंग सिस्टम और मैनेजमेंट इन्फार्मेशन सिस्टम से संचालन में एकरूपता आएगी। इससे पैक्स संचालन में जनता का विश्वास बढ़ेगा। सहकारिता क्षेत्र में हुई इन अनूठी पहलों से यह क्षेत्र अब नए आत्मविश्वास के साथ पूरे देश में संगठित रूप में काम कर रहा है, जो इसके लिए बहुत फायदेमंद है। अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से जिला सहकारी बैंकों में बैंक खाते खोलने का आह्वान किया है, ताकि उन्हें व्यवहार्य बनाया जा सके। उनके अनुसार, सहकारी समितियों के बीच सहयोग एक मजबूत आर्थिक सिद्धांत है, जो मजबूत सहकारी क्षेत्र के निर्माण के लिए जरूरी है। अमित शाह ने जमीनी स्तर पर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करके इस क्षेत्र को मजबूत करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके पिछले कार्यकाल में नीतिगत ढांचा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और वर्तमान कार्यकाल में उनकी प्राथमिकता इन नीतियों को जमीनी स्तर तक ले जाने की होगी।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण पहल में से एक सहकारी क्षेत्र में 'विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण कार्यक्रम' है। इस योजना का उद्देश्य पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण के लिए विकेंद्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि अवसंरचनाएं बनाना है। इन गोदामों का उद्देश्य कृषि और इससे जुड़े कामों के लिए इस्तेमाल करना है। कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विपणन अवसंरचना, कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण आदि का उद्देश्य देश के लिए एक विशाल भंडारण क्षमता का निर्माण करना है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी और परिवहन लागत में कमी आएगी, किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिलेंगे और विभिन्न कृषि जरूरतों को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा।

चूंकि पैक्स ग्रामीण विकास की रीढ़ हैं, इसलिए इनके सुदृढ़ीकरण और पुनरुद्धार से बहुत जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। पैक्स से जुड़ी गतिविधियों के बढ़ने से जहां मौसमी बेरोजगारी खत्म होने की उम्मीद की जा रही है, वहीं इससे करीब एक लाख पैक्स से सीधे जुड़े 13 करोड़ किसानों को विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय सृजन में फायदा होगा।

(लेखक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड-के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

चमत्कार

एक बार एक साधक ने प्रश्न किया, क्या दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज है? यदि है तो वह क्या है? अलौकिक नाम की कोई चीज है नहीं। सारी शक्तियां मनुष्य के अंदर छिपी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं होता। समय-समय पर हर कोई अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को महसूस करता है। इसे ही बुद्धि और बोधि कहते हैं। इनका विकास होने पर मनुष्य में असाधारण शक्ति आ जाती है। यह स्वाभाविक है।

साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकते, जिसके कारण, वे इस शक्ति को अलौकिक समझ बैठते हैं। जब तक मन बंधनयुक्त रहता है, उसकी गति जड़ वस्तुओं की ओर रहती है, लेकिन साधना से मन का बंधन टूट जाता है। मन स्थूल विषय से भी हट जाता है। यही है मनुष्य का विकास। विकास की ओर उन्मुख होने पर ही शारीरिक तथा आध्यात्मिक उन्नति संभव है। मानसिक प्रगति के कारण मनुष्य में असाधारण बुद्धि आ जाती है और मानसिक प्रगति के कारण वह समाज में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। रिपु का अर्थ है आंतरिक दुश्मन। आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है रिपुओं का वश में हो जाना। इस हालत में मनुष्य का जड़ तत्वों पर और अधिक स्वामित्व हो जाता है। साधारण लोग इसे एक अद्भुत शक्ति समझने लगते हैं।

तंत्र के अनुसार जड़ या बाह्य तत्वों पर विजय पाने की चेष्टा है 'अविद्या साधना'। आत्मज्ञान के लिए जो साधना की जाती है, उसे 'विद्या साधना' कहते हैं, लेकिन जहां विद्या या अविद्या में कोई नहीं है, उसे कहते हैं उपविद्या। मनुष्य के लिए विद्या साधना ही कल्याणकारी है, बाकी दोनों से केवल समय नष्ट होता है। अलौकिक शक्ति पाने के लिए जो लोग साधना करते हैं उनका विषय जड़ तत्व रहता है। इस प्रकार से शक्ति प्राप्त करने पर व्यक्ति इसका उपयोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए या द्वेष वश करते हैं। मनुष्य को साधना करनी चाहिए ब्रह्म बनने के लिए, न कि पिशाच बनने के लिए।

श्रीश्री आनंदमूर्ति

पाठकनामा

pathaknama@pat .jagran.com

शातिर अमेरिकी इरादों की काट

''अमेरिकी पिछलग्गुओं से सावधान'' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में विकास सारस्वत ने तथ्यों के साथ अमेरिकी शातिर इरादों को उजागर करते हुए आम भारतीयों को जागरूक करने का कार्य किया है। यह सत्य है कि कुछ पश्चिमी शक्तियां किसी भी देश और वहां के लोगों का केवल शोषण ही करती हैं, उनका उत्थान तो सपने में भी नहीं करती हैं। अब सभी देशों को अपने-अपने जयचंदों को भी जानना-समझना चाहिए। महज कुछ पैसों के लिए, वे अपने ही देश के भोले-भाले नागरिकों को, कभी आरक्षण तो कभी लोकतंत्र के नाम पर डराते और बहकाते हैं। इन पश्चिमी शक्तियों से ओतप्रोत कुछ एनजीओ और यूट्यूबरों ने आजकल भारत के युवा वर्ग को भी बरगलाना शुरू कर दिया है। ये आस्तीन के सांप की तरह बड़ा ही प्रभावी एजेंडा दिन-रात इंटरनेट मीडिया पर चला रहे हैं और इनका शिकार भारत के अल्पसंख्यक, पिछड़े और वंचित तबके के लोग हो रहे हैं, जिनका गुस्सा सरकार के किसी न किसी योजना में किसी कारणवश वंचित हो जाने को लेकर है। ये आस्तीन के सांप इन्हें ही अपना शिकार बनाकर किसी दिन कोई बड़ा बखेड़ा करें तो कोई आश्चर्य नहीं। अब केंद्र सरकार को भी चाहिए कि इंटरनेट मीडिया के इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए वह कुछ उपाय करे। इसमें कुछ देशप्रेमी यूट्यूबरों का भी सहयोग लिया जा सकता है। ये राष्ट्रविरोधी कथित बुद्धिजीवियों और यूट्यूबरों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम की अपनी तर्कपूर्ण बातों से काट करेंगे तो आमजन को विभिन्न विषयों पर संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद मिलेगी।

संपूर्णानंद वर्मा, हेतिमपुर, गोरखपुर

इच्छाशक्ति व नैतिकता का प्रश्न

'सरकारों के साथ समाज भी सुधरे' शीर्षक आलेख में राजीव सचान ने महिलाओं से दुष्कर्म के अपराध में कठोरतम सजा फांसी के प्रविधान के बावजूद हो रही ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए उचित लिखा है कि ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए दुष्कर्मियों को यथाशीघ्र कड़ी सजा मिले। साधारणतः अभी ऐसा होता नहीं है। यह वही देश है, जहां हम नारी को देवी के तौर पर पूजते हैं। नैतिकता के क्षरण के कारण आज महिलाओं पर यौन हिंसा सहित विभिन्न तरह के अत्याचार बढ़ गए हैं। वर्ष 2012 के निर्भया कांड के बाद कोलकाता के मेडिकल कालेज में निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है, इससे पूरे देश में उबाल है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि जमीनी बदलाव के लिए देश एक और दुष्कर्म या हत्या की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। कोर्ट द्वारा गठित 14 सदस्यीय टास्क फोर्स को दो माह में अंतिम रिपोर्ट देनी है। इस बीच कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल और हास्टल की सुरक्षा केंद्रीय बल सीआइएसएफ को देने का निर्देश दिया है। एक टीस सी मन में उठती है कि आखिर नारी कब तक भोग की वस्तु बनी रहेगी? उसका जीवन कब तक खतरों से घिरा रहेगा? बलात्कार, छेड़खानी, भ्रूण हत्या और दहेज की धधकती आग में वह कब तक भस्म होती रहेगी? तमाम जागरूकता एवं सरकारी प्रयासों के देश में महिलाओं की स्थिति में यथोचित बदलाव नहीं आया है। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कानूनों की कठोरता से अनुपालना एवं सरकारों में इच्छाशक्ति जरूरी है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार।

विशेषज्ञता में आरक्षण अनुचित

संपादकीय आलेख 'दबाव में आई सरकार' (21 अगस्त) पढ़ा। आजादी के बाद सभी सरकारों ने विशेषज्ञों को सीधी भर्ती के द्वारा सरकारी सेवा में शामिल किया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में 45 उच्च पदों पर नियुक्त करने के लिए लेटरल एंट्री का विज्ञापन निकाला। यह नियुक्ति अस्थाई होती है। इनका कार्यकाल तीन वर्षों का होता है, एवं दो वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर सभी विपक्षी दल विरोध में आ गए एवं सरकार से आरक्षण की मांग करने लगे। विरोधी दलों के साथ सरकार के सहयोगी नितीश कुमार और चिराग पासवान भी लेटरल एंट्री में आरक्षण की मांग करने लगे, इससे सरकार दबाव में आ गई एवं लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस ले लिया। सरकार के इस कदम से मजबूत इच्छाशक्ति वाली सरकार की छवि को चोट पहुंची है। गठबंधन सरकार की कई विवशताएं होती हैं। सरकार को अपने सहयोगी दलों को विश्वास में लिए बिना कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। विपक्षी दलों को सरकार की हर नीति की आलोचना करने की आदत हो चुकी है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा आरक्षण के मुद्दे को तूल देना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरक्षण हर मर्ज की दवा नहीं हो सकती है। जो लोग पिछड़े हैं और उन्हें मजबूत बनाने के लिए यदि आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो वह जायज है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

भारत बंद का असर हो अथवा न हो, ऐसे आंदोलनों से दबे-कुचले समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और एकजुटता आती है।
सूर्य प्रताप सिंह@suryapsingh_IAS

भारत बंद होना चाहिए कोलकाता के डाक्टर बिटिया के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में, लेकिन हो रहा है आरक्षण में आरक्षण के विरोध में। जब तक समाज की प्राथमिकताएं सही नहीं होंगी, देश ऐसे ही चलेगा।
अनुरंजन झा@anuranjanj

वर्ष 1979 के बाद से नरेन्द्र मोदी पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जो पोलैंड की यात्रा पर गए हैं। सोचकर ही आश्चर्य होता है।
आदित्य राज कौल@AdityaRajKaul

हारे हुए रवनीत बिट्टू, किरण चौधरी चाहिए। रविंद्र भाटी को टिकट भी नहीं देंगे, अगर वह मांगेंगे तो। कौन निर्णय ले रहा है ये सब, भाजपा को बर्बाद करने के लिए?
रवि भदौरिया@ravibhadoria

लेटरल एंट्री की अवधारणा ब्यूरोक्रेसी में वैल्यू एडिशन ही करती है। इसलिए इसका अंध विरोध करना बुद्धिमानी नहीं है। किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता बहुत मायने रखती है।
संकेत उपाध्याय@sanket

जनपथ

'लेटरल एंट्री' लीजिए अन्य पार्टी जाय,
राज्यसभा मिल जायगी बिन कुछ किए-कराय।
बिन कुछ किए-कराय न इसमें कोई धोखा,
लगे हर्र ना सोंठ स्वाद मिलता है चोखा।
दलबदलू समुदाय प्रदूषित करता कंट्री,
औरों का हक छीन स्वयं ले 'लेटरल एंट्री'!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एगजीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प.बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 131

****

कर्ज में डूबने से बेहतर है, भूखे सो जाना।
-बेंजामिन फ्रैंकलिन

प्राइम डाटाबेस के अनुसार, भारतीय शेयर बाजार में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी का सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचना आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिहाज से शुभ संकेत है। विदेशी संस्थागत निवेश की हिस्सेदारी कम होना वैश्विक अनिश्चितताओं से उपजी एक अस्थायी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन इस पर ध्यान देना होगा।

आत्मनिर्भर बाजार

कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार कई बदलावों से गुजरा है, लेकिन प्राइम डाटाबेस की ताजा रिपोर्ट का यह बताना कि 30 जून, 2024 तक बाजार में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 25.85 फीसदी के सार्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, न केवल बाजार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह देश के निवेशकों की बढ़ती जागरूकता के साथ आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। इसका श्रेय घरेलू संस्थागत निवेशकों के साथ खुदरा निवेशकों (किसी कंपनी में दो लाख रुपये तक की शेयरधारिता वाले) और उच्च निवल मूल्य वाले (एचएनआई) यानी कंपनी में दो लाख रुपये से ज्यादा शेयरधारिता वाले निवेशकों को भी जाता है, जो अब बाजार में मजबूत भूमिका निभा रहे हैं। पहले शेयर बाजार में खुदरा निवेशकों का हिस्सा सीमित था, लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की उपलब्धता, सोशल मीडिया पर वित्तीय शिक्षा के प्रसार और डीमैट खातों की संख्या में बढ़ोतरी ने स्थितियां बदली हैं। खुदरा निवेशकों की भागीदारी फायदेमंद भी है, जो बाजार में विविधता लाने के साथ इसे अधिक स्थिर व लचीला भी बनाती है। रिपोर्ट का यह कहना भी उत्साह बढ़ाने वाला है कि जून तिमाही के दौरान एनएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी बढ़कर 9.17 फीसदी के सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि पिछले कुछ वर्षों में एसआईपी के माध्यम से निवेश का चलन बढ़ा है, जो खुदरा निवेशकों को अनुशासित और दीर्घकालिक निवेश की ओर प्रेरित कर रहा है। म्यूचुअल फंड की कामयाबी इसका भी संकेत है कि देश के निवेशक अब पहले की अपेक्षया अधिक समझदार और सतर्क हुए हैं और अब वे अपने निवेश को पेशेवर प्रबंधन के हाथों में सौंपने के महत्व को समझने लगे हैं। घरेलू निवेशकों की बढ़ती भागीदारी भारतीय बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेश (एफआईआई) का बारह वर्ष के निम्नतम स्तर पर पहुंचना भी ध्यान देने योग्य है। वर्षों से विदेशी संस्थागत निवेश भारतीय बाजार में सबसे बड़ी गैर-प्रवर्तक शेयरधारक श्रेणी रही है, जिनके निवेश-निर्णयों का बाजार की समग्र दिशा पर भारी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अब अगली कुछ तिमाहियों में घरेलू संस्थागत निवेश (डीआईआई) की हिस्सेदारी एफआईआई से आगे निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। एफआईआई में गिरावट वैश्विक स्तर पर कुछ आर्थिक अनिश्चितताओं की वजह से भी हो सकती है। लिहाजा, यह एक अस्थायी प्रवृत्ति हो सकती है, जो वैश्विक परिस्थितियों में सुधार के साथ बदल भी सकती है। हालांकि इसमें संदेह नहीं कि घरेलू निवेशकों का प्रभुत्व आर्थिक आत्मनिर्भरता और बाजार व अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिहाज से एक शुभ संकेत है।

चीन खुद एक वैश्विक समस्या है

चीनी कर्ज के चलते वित्तीय संकट में फंसे जांबिया, श्रीलंका और पाकिस्तान को तो छोड़िए, यूरोप की आर्थिक महाशक्ति जर्मनी जैसे धनी देश भी व्यापार में चीन पर अत्यधिक निर्भरता के संकट को महसूस कर रहे हैं। चीनी निर्माताओं को मिल रही भारी सब्सिडी से दुनिया भर के बाजार चीन के सस्ते उत्पादों से भर गए हैं।

वेनेजुएला के भूतपूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो शावेज ने 2000 के दशक में अपने देश का आर्थिक भविष्य उभरते चीन के ऊपर दांव पर लगा दिया, इससे उसे अरबों डॉलर का निवेश मिला और तेल सौदों के लिए कर्ज भी। शुरुआत में इससे फायदा हुआ। चीन ने जमकर वेनेजुएला के तेल का उपभोग किया और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का वित्त पोषण किया। लेकिन 2010 के दशक में तेल की कीमतें गिर गईं और अर्थव्यवस्था के साथ-साथ चीन की ओर से तेल की मांग भी घट गई। नतीजतन वेनेजुएला के तेल निर्यात का राजस्व 2016 में घटकर 22 अरब डॉलर रह गया। उसकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। लोग कचरे के ढेर में भोजन तलाशने लगे, अस्पतालों में दवाओं की कमी थी और अपराध बढ़ गए थे। तब से, लगभग 80 लाख लोग देश छोड़कर चले गए हैं। चीन ने वेनेजुएला को नए ऋण देने से मना कर दिया, जिससे वहां अधूरी परियोजनाओं का ढेर लग गया।

माइकल बेकले
द न्यूयॉर्क टाइम्स

चीन पर वेनेजुएला की अत्यधिक निर्भरता एक चेतावनी थी, जिसकी दुनिया ने अनदेखी की। चीन के उदय से लाभान्वित दर्जनों अन्य देश अब वित्तीय संकट और ऋण न चुका पाने के जोखिम में फंसे हैं, क्योंकि चीनी अर्थव्यवस्था ठहर गई है। फिर भी चीन ऋण राहत देने से इन्कार कर रहा है और संरक्षणवादी गतिविधियों पर दोगुना जोर दे रहा है, जबकि उसे अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त करने और नई शुरुआत के लिए सुधार करने चाहिए। यह बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था के जादुई गुब्बारे का दूसरा पहलू है।

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद दुनिया को एक रक्षक की जरूरत थी और चीन ने वह भूमिका निभाई। इसका सकारात्मक प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया गया। वर्ष 2008 से 2021 तक चीन ने वैश्विक विकास में 40 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। विकासशील देशों ने खुद को चीन से जोड़ा, और चीन दुनिया के अधिकांश देशों का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। वेनेजुएला की तरह कई देशों ने पाया कि तेजी से बढ़ती चीनी अर्थव्यवस्था उनके वस्तु निर्यात के लिए एक

आकर्षक बाजार है, और उन्होंने उसमें भारी निवेश किया, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को सुस्ती का सामना करना पड़ा। चीन ने विभिन्न देशों को दस खरब डॉलर से ज्यादा का ऋण दिया है, जिसका बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों द्वारा बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव) के तहत बनाए जाने वाले बुनियादी ढांचे के लिए है। मगर चीन की तेजी टिकाऊ नहीं थी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उद्यमशीलता को दबाया, सुधार का विरोध किया और अमेरिकी संरक्षणवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया को उकसाया। शी जिनपिंग के सत्ता संभालने के बाद चीन के आर्थिक विकास में काफी कमी आई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुश्किल से ही बढ़ रहा है। हालांकि चीन ने लगातार बाहरी स्रोतों के अनुमान से ज्यादा विकास का दावा किया है। इसका सीधा असर उन देशों पर पड़ता है, जिन्होंने अपने आर्थिक विकास को चीन से जोड़ रखा है। कई देशों द्वारा चीन को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट आई है।

चीन अपनी आर्थिक मंदी से निपटने के लिए चीनी निर्माताओं को भारी ऋण और सब्सिडी दे रहा है, जिससे दुनिया भर के बाजार सस्ते उत्पादों से भर गए हैं, वैश्विक वस्तुओं की कीमतें गिर रही हैं और दूसरे देशों के निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। बेशक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में कमजोरी के लिए सिर्फ चीन ही जिम्मेदार नहीं है, जो महामारी, युद्ध और व्यापार तनावों से प्रभावित है। लेकिन वह नाजुक समय में हालात को और भी बदतर बना रहा है। चीन ने विदेशी ऋण में भारी कटौती की है और विकासशील देशों को अपने मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए मजबूर कर रहा है। जांबिया और श्रीलंका को गहरे वित्तीय संकट में धकेलने में चीनी ऋणों का बहुत बड़ा हाथ था। आंशिक रूप से चीनी ऋण की अपारदर्शी प्रकृति के कारण दोनों देशों के संकट और बढ़ गए।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने चेताया कि विकासशील दुनिया के दर्जनों देश, जिनमें से कई के चीन से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हैं, अब ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान एक गहरे आर्थिक संकट में फंस गया है, जिससे वह बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि उसे बुनियादी ढांचे और अन्य परियोजनाओं के लिए चीन को अरबों डॉलर का ऋण चुकाना है। यहां तक कि यूरोप की आर्थिक महाशक्ति कहे जाने वाले जर्मनी जैसे कुछ धनी राष्ट्र भी चीन के साथ व्यापार करने की अत्यधिक निर्भरता के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पिछले साल चीन को जर्मनी के निर्यात में नौ फीसदी की गिरावट आई व उसकी अर्थव्यवस्था भी सिकुड़ गई।

ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और सऊदी अरब जैसे प्रमुख कमोडिटी निर्यातक असुरक्षित हैं, क्योंकि चीन को निर्यात उनकी अर्थव्यवस्थाओं का अहम हिस्सा है। अमेरिका सीधे तौर पर कम प्रभावित हुआ है, क्योंकि चीन को विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात अमेरिका के सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम है। लेकिन चीनी उत्पादों की अधिकता अमेरिकी निर्माताओं के लिए खतरा है। दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु ऋणदाता चीन ने अक्सर गैर-पारदर्शी व्यवस्थाओं के माध्यम से कई देशों को कर्ज के बोझ तले दबाने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जो 1980 के दशक में विकासशील देशों, खासकर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के ऋण संकट के समान है।

पिछले दशक में चीन ने पेरिस क्लब (दुनिया के 22 सबसे बड़े ऋणदाता देशों का समूह) से भी ज्यादा ऋण दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि अनुमानित रूप से 3.3 अरब लोग ऐसे देशों में रहते हैं, जहां ब्याज भुगतान शिक्षा या स्वास्थ्य में निवेश से अधिक है। आर्थिक संकट में फंसे वेनेजुएला के उदाहरण ने दिखाया है कि ये परिस्थितियां आर्थिक पतन, दमन और मानवीय आपदा की ओर ले जा सकती हैं। हाल में, फ्रांस, पोलैंड, केन्या, बोलीविया, श्रीलंका और कई अन्य देशों में लोगों ने बिगड़ती आर्थिक स्थितियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। धनी अर्थव्यवस्थाओं और ऋणदाता देशों से ऋण राहत, बाजार पहुंच और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की मदद के लिए अन्य तरीकों से सहयोग करने की मांग बढ़ रही है। लेकिन ऐसे कदमों का केवल सीमित प्रभाव होगा, जब तक कि चीन को कठघरे में नहीं खड़ा किया जाता, क्योंकि वह खुद में एक वैश्विक समस्या है।

©The New York Times 2024

https://t.me/AllNewsPaperPaid

जीवन धारा

मोपासां

एक जिंदगी, कुछ दिन, और फिर कुछ नहीं। आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, आप खुश होते हैं, आप इंतजार करते हैं, फिर आप खत्म हो जाते हैं। आखिर प्रेम के क्षण ही तो हैं, जो इस निरर्थक जिंदगी को अर्थ देते हैं।

वर्तमान क्षण में रहेंगे, तभी प्रेम को समझ पाएंगे

__जीवन__ एक ढलान है। जब तक आप ऊपर जा रहे हैं, आप हमेशा शीर्ष की ओर देखते हैं और आपको खुशी महसूस होती है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं, तो अचानक आप नीचे की ओर जाने वाली सड़क और उसके अंत में मौत को देखने लगते हैं। ऊपर जाना हमेशा धीमा होता है और नीचे उतरना तेज होता है। सांस लेना, सोना, खाना-पीना, सपने देखना, हम हर दिन जो कुछ भी करते हैं, वह दरअसल मरना है। वास्तव में, जीना ही मरना है। हम सभी एक यात्री हैं, और यात्रा, सपनों की तरह, एक द्वार है, जो वास्तविक दुनिया से एक ऐसी दुनिया में खुलता है, जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। हम सब यात्री ही तो हैं, जो जीवन में मिलते हैं और इसे जीने लायक बनाते हैं। हमारी स्मृति ब्रह्मांड से भी अधिक परिपूर्ण है। यह उन लोगों को जीवन देती है, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। हम हर क्षण मर रहे हैं और ऐसे निरर्थक जीवन को एक ही चीज है, जो अर्थ देती है। वह है प्रेम, जिसका मतलब है शरीर, आत्मा, जीवन, पूरा अस्तित्व। प्रेम को वैसे ही महसूस किया जाना चाहिए, जैसे हम अपने खून की गर्मी को महसूस करते हैं। जीवन की सुंदरता और अच्छाई एक ही चीज में मौजूद है वह प्रेम में है। प्रेम के विचार की हर बुरे विचार से रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि, एक बीमार विचार शरीर को बुखार या किसी बीमारी से भी बुरी तरह से खा सकता है। बुरे विचारों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है कि वर्तमान में रहा जाए। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, इसका एक ही कारण है कि अतीत हमेशा हमें आकर्षित करता है, वर्तमान हमें भयभीत करता है, अंत में जिसे भविष्य कहते हैं, वह मृत्यु होता है।

कई वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने भी बाकी लोगों की तरह ही जिया, खाया, हंसा, प्यार किया, उम्मीदें कीं। और इसके बाद यह सब खत्म हो गया, हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक जिंदगी, कुछ दिन, और फिर कुछ नहीं। आप पैदा होते हैं, आप बड़े होते हैं, आप खुश होते हैं, आप इंतजार करते हैं, फिर आप मर जाते हैं। पुरुष हो या महिला, आप इस धरती पर लौटेंगे, क्या इसकी कोई गारंटी है। फिर भी हममें से हर कोई अपने भीतर अनंत काल की तीव्र, अवास्तविक लालसा रखता है, लेकिन सच तो यह है कि हममें से हर कोई जल्द ही नए जीवों के कूड़े के ढेर में पूरी तरह से गायब हो जाता है। पौधे, जानवर, इन्सान, तारे, दुनिया, सब कुछ तेजी से बढ़ते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें जीवन में खुद से और इस पृथ्वी से प्रेम करना चाहिए। एक उम्र के बाद हम अपनों से दूर हो जाते हैं, ताकि हम जीवन को बेहतर बना सकें, लेकिन हम कई बार अपने जीवन की सबसे अनमोल चीजों से भी दूर हो जाते हैं। हमें कई बार मालूम नहीं होता कि हम अपनी मां से अनजाने में ही प्यार करते हैं, और यह एहसास हमें तब होता है कि यह प्यार कितना गहरा है, जब हम उनसे अलग हो जाते हैं।

खुद से प्रेम करें

सूत्र

सबसे पहले खुद से प्रेम करें। बाकी सब खुद-ब-खुद हो जाएगा। जब आप दुनिया में प्रेम फैलाते हैं, तो वह फैलता है, और लोगों को छूता है तथा उन तरीकों से हम तक लौटकर आता है, जिनकी हमने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी। प्यार ही जीवन की असली पूंजी है।

दूसरा पहलू

जर्मनी के कील को 'जीरो वेस्ट सिटी' (शून्य अपशिष्ट शहर) के रूप में प्रमाणित किया गया है।

'जीरो वेस्ट सिटी' : सतत विकास की नई राह

कील शहर को जर्मनी के पहले शून्य अपशिष्ट शहर (जीरो वेस्ट सिटी) के रूप में प्रमाणित किया गया है। शहर में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देकर और जगह-जगह कचरे के पहाड़ खड़े होने से रोकने की दिशा में कील की यह उपलब्धि दुनिया के अन्य शहरों के समक्ष मिसाल है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व आर्थिक मंच जैसी वैश्विक संस्थाएं भी 'जीरो वेस्ट सिटी' की स्थापना को प्रोत्साहित कर रही हैं।

'जीरो वेस्ट सिटी' का अर्थ एक ऐसे शहर से है, जहां अपशिष्ट पदार्थों को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उत्पन्न कचरे का प्रभावी और जिम्मेदार तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाता है, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। शहरी कचरे की समस्या से निपटने के लिए कील शहर में जीरो वेस्ट सिटी योजना लागू है, जिसके तहत वहां के सभी घर, प्रतिष्ठान, स्कूल और सार्वजनिक निकाय अपशिष्ट प्रबंधन को सुनिश्चित करने में जुटे हैं। इस योजना का लक्ष्य 2035 तक प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 15 फीसदी कचरे को कम करना है। शून्य अपशिष्ट की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस शहर में प्लास्टिक से बने डिस्पोजेबल डायपर के बजाय कपड़े के डायपर के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। ये डायपर न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि पुनः प्रयोज्य भी हैं। कपड़े के डायपर की खरीद पर सरकार 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 यूरो तक की सब्सिडी प्रदान करती है।

सुधीर कुमार

योजना का लक्ष्य 2035 तक प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 15 फीसदी कचरा कम करना है। इसलिए बच्चों को प्लास्टिक के बजाय कपड़े के डायपर पहनाते हैं।

कील शहर भोजन की बर्बादी के भी खिलाफ है। वहां के लोग खाने योग्य भोजन को कूड़े के रूप में कम से कम फेंकते हैं। शहर में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति से कचरे के वजन के आधार पर शुल्क लिए जाने की व्यवस्था है।

कील शहर भोजन की बर्बादी के भी खिलाफ है। वहां के लोग खाने योग्य भोजन को कूड़े के रूप में कम से कम फेंकते हैं, जिससे संसाधनों की बर्बादी रोकने में मदद मिलती है। यही नहीं, शहर में फल और सब्जी की दुकानों में पुनः प्रयोज्य थैले मुफ्त में दिए जाते हैं। शहर में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति से कचरे के वजन के आधार पर शुल्क लिए जाने की व्यवस्था है। कील की यह व्यवस्था अनुकरणीय है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अपशिष्ट का उत्पादन और उसके समुचित निपटान का अभाव जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और प्राकृतिक विनाश के तिहरे संकट को बढ़ावा दे रहा है। दुनिया के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और ग्लोबल वार्मिंग को धीमा करने के प्रयासों में शून्य अपशिष्ट जीवन एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। कचरा उत्पन्न करने से बचकर हम अपने मूल्यवान संसाधनों की बर्बादी को कम कर सकते हैं।

आंकड़े

डीटीएच ग्राहक घटे

फाइबर केबल के बढ़ते प्रचलन की वजह से पिछले पांच वर्षों में डीटीएच उद्योग को काफी नुकसान हुआ है। 80 लाख से अधिक डीटीएच सब्सक्राइबर (ग्राहक) इन वर्षों में कम हुए हैं।

2019	6.998
2021	6.957
2023	6.525
2024	6.197

ग्राहकों के आंकड़े करोड़ में हैं। | स्रोत : TRAI

भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे, तब लक्ष्मण के शंका करने पर प्रभु श्रीराम ने कहा, भरत के समान शीलवान भाई विधाता की सृष्टि में न तो कहीं देखा और न सुना है।

भरत की भक्ति

मान्यता है कि भरत का अवतार रामभक्ति का आदर्श स्थापित करने के लिए ही हुआ था। संतों का तो यहां तक कहना है कि भगवान श्रीराम के प्रेम ने ही भरत का रूप धारण किया था। भरत ने 'तत्सुखसुखित्वम' के महान आदर्श को अपने जीवन में खूब निभाया। श्रीराम के अनुकूल आचरण करना ही भरत का एकमात्र ध्येय था। गोस्वामी तुलसीदास ने उनके बारे में लिखा है, '*भरत सरिस को राम सनेही। जगु जप राम रामु जप जेही।*' अर्थात भरत के समान राम को कौन प्यारा होगा, जिन राम का जाप सारा संसार करता है, राम उन भरत का स्मरण करते हैं यानी जपते हैं।

भरत जी जब राम को वन से लौटाने के लिए चित्रकूट की ओर जा रहे थे, तब लक्ष्मण जी ने उनकी नीयत पर शंका की थी। उस वक्त प्रभु श्रीराम ने भरत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, 'भरत के समान शीलवान भाई विधाता की सृष्टि में न तो कहीं देखा और न सुना है।' '*विधि प्रपंच महुं सुना न दीसा।*' भगवान भरत के संबंध में सम्मति देते हैं कि भरत को अयोध्या के राज्य की, तो बात ही क्या? ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पद प्राप्त होने पर भी मद नहीं हो सकता। चित्रकूट में भरत की स्थिति को देखकर ज्ञानियों में अग्रगण्य राजर्षि जनक ने तो यहां तक कहा, 'भरत की महिमा का वर्णन करना तो दूर, मेरी बुद्धि उनकी छाया को छल से भी नहीं छू सकती।'

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला पुराने पन्नों से — 27 मार्च, 1958

उड़ीसा का मंत्रिमंडल इस्तीफा देगा, कांग्रेस पार्टी में फूट

उड़ीसा का मंत्रिमंडल स्तीफा देगाः कांग्रेस पार्टी में फूट

मुख्यमंत्री डाक्टर मेहताब स्तीफा देने के पूर्व कांग्रेस हाईकमांड से इस पर मंत्रणा करेंगे

पति द्वारा पत्नी की हत्या

उड़ीसा (अब ओडिशा) के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देने का निश्चय किया है, क्योंकि कांग्रेस में जबर्दस्त फूट पड़ गई है। कल कांग्रेस पार्टी की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें सारी स्थिति पर विचार किया गया।

'जान बचाने वाले' कितने सुरक्षित

कोलकाता की घटना ने दिन-रात सेवारत चिकित्सकों की कार्य परिस्थितियों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं।

विवेक एस अग्रवाल | मुद्दा

अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही जूनियर डॉक्टर की नौ अगस्त को कोलकाता में एक क्रूर घटना में जघन्य हत्या कर दी गई। इससे पूरे राष्ट्र का जनमानस हिल गया है। इसने एक बार पुनः निर्भया हत्याकांड की याद ताजा कर दी, लेकिन यह घटना तो उससे भी कहीं ज्यादा वीभत्स है। निर्भया की हत्या राह चलती बस में यात्रा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी, लेकिन हाल में घटित घटना को अस्पताल जैसे सुरक्षित स्थान पर अंजाम दिया गया है। घटनाक्रम से प्रतीत होता है कि यह पूर्व नियोजित था।

अस्पताल के अंदर कार्यरत चिकित्सक की कार्यावधि के दौरान की गई हत्या जूनियर एवं प्रशिक्षु डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े करती है। इस घटना के बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के जरिये राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने में लगी हैं और चिकित्सक के प्रति हिंसा का विषय नेपथ्य में चला गया है। विभिन्न अवसरों पर चिकित्सकों

के विरुद्ध हिंसक वारदात के विरोध में चिकित्सक संगठन अपनी सुरक्षा को लेकर आवाज उठाते हैं, लेकिन ज्यादातर अवसरों पर ठंडे छींटे देकर आंदोलन को शांत कर दिया जाता है। चिकित्सकों से सेवा की तो पूर्ण अपेक्षा रखी जाती है, किंतु उनकी सुरक्षा के प्रति जवाबदेही के लिए बनाया जाने वाला कानून वर्ष 2022 से लंबित है। उल्लेखनीय है कि केंद्र द्वारा कानून बनाने के बावजूद स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय होने के कारण संपूर्ण दारोमदार राज्यों पर ही आ जाता है। कई राज्यों ने विभिन्न अवसरों पर आंदोलनरत चिकित्सकों को शांत करने के लिए कानून तो बना दिए, लेकिन वे धरातल पर नहीं उतरे। जैसे राजस्थान में कानून तो वर्ष 2008 में बन गया था, किंतु प्रभावी क्रियान्वयन डॉ. अर्चना शर्मा द्वारा दबाव में की गई आत्महत्या के उपरांत वर्ष 2022 में तय मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पश्चात ही हो पाया है।

कोलकाता की घटना ने चिकित्सकों विशेष तौर पर दिन-रात सेवारत सहयोगी चिकित्सकों की कार्य परिस्थितियों पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। चिंतनीय है कि जिनके हाथों में जीवन बचाने का दायित्व सौंपा जा रहा है, उनके पास ठीक से उठने-बैठने, आराम करने और निवृत्त होने की उचित व्यवस्था भी नहीं रहती। चिकित्सा के व्यावसायीकरण और विशेष तौर पर कॉरपोरेट संस्कृति में ढलने से वहां कार्यरत चिकित्साकर्मी भी एक सामान्य कर्मी बन कर रह गए हैं। मरीजों के बोझ में दबे सरकारी चिकित्सा संस्थानों का तो हाल और भी चिंताजनक है। विभिन्न राज्यों द्वारा नर्सिंग होम या अस्पताल की स्थापना के मानक तय करने को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किए गए हैं, जिनमें ड्यूटी डॉक्टर हेतु कक्ष एवं शौचालय का भी मानक रखा गया है, किंतु वह अत्यंत अल्प है, जिसमें अनेक चुनौतियां रहती हैं। हाल की घटना के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की पहल पर पुरुष व महिला प्रशिक्षु और ड्यूटी चिकित्सकों के लिए समुचित कक्ष की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन क्रियान्वयन का दायित्व तो राज्य सरकारों एवं चिकित्सा संस्थान संचालकों की नीयत पर है। एक ओर भारत सरकार हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की महत्वाकांक्षा के साथ तीव्र गति से कार्य कर रही है, वहीं चिकित्सक इस व्यवसाय के प्रति पुनर्विचार करने लगे हैं। इन सबके मूल में निरंतर असुरक्षा का भाव सबसे प्रमुख है। पूर्व में चिकित्सक का स्वप्न होता था कि अपनी अगली पीढ़ी को भी चिकित्सक बनाना, लेकिन विगत वर्षों में इस चलन में कमी आई है। इस कमी के पीछे जहां आर्थिक कारण एक पक्ष है, वहीं नित्य प्रति घटित होने वाली घटनाएं प्रमुख रूप से दोषी हैं।

भारत की शीर्ष संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि लगभग 83 प्रतिशत चिकित्सक व्यवसाय संबंधी तनाव में जीवनयापन करते हैं। लगभग 63 प्रतिशत को हिंसा का भय सताता रहता है, तो आधे चिकित्सकों के तनाव की मुख्य वजह हिंसक वारदात होती है। क्या तनावग्रस्त चिकित्सक से बेहतर इलाज की अपेक्षा की जा सकती है? यदि चिकित्सक असुरक्षित महसूस करते रहे, तो संस्थान निर्मित होने के बावजूद सूने रह जाएंगे। चिकित्साकर्मियों के कार्य एवं आवास हेतु उपयुक्त व्यवस्था के अभाव के चलते ही चिकित्सक गांवों से विमुख हुए थे और अब शहरों से भी मोह भंग हो रहा है। इस तरह के आघात चिकित्सा व्यवसाय के साथ जुड़े गौरव को भी समाप्त कर रहे हैं। लंबी अवधि तक एवं जटिल शिक्षण के पश्चात कार्यरत चिकित्सक को उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने में आमजन को भी सरोकार रखना होगा। जिस प्रकार चिकित्सक उनको स्वस्थ रखने का यत्न करते हैं, उसी प्रकार तनावमुक्त कार्यस्थल व्यवस्था हेतु स्वैच्छिक संगठनों समेत सभी को मुखर होना होगा।

edit@amarujala.com

कल्पमेधा

चालबाज और धूर्त आदमी को सबसे अधिक व्याकुलता उस समय होती है, जब उसका पाला किसी सच्चे व्यक्ति से पड़ता है।

– कोल्टन

विकृति के विरुद्ध

कोलकाता के बाद अब महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के खिलाफ जनाक्रोश उभरा है। वहां के एक स्कूल में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने पर लोगों का रोष फट पड़ा। हालांकि राज्य सरकार ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच दल गठित कर दिया, मगर प्रशासन के रवैए पर प्रश्नचिह्न बना हुआ है। घटना आठ-नौ दिन पहले की है। जब बच्चियों के परिजनों को पता चला कि स्कूल के ही एक कर्मचारी ने उनका यौन उत्पीड़न किया है, तो उन्होंने पुलिस के पास संबंधित मामले की प्राथमिकी दर्ज करानी चाही। मगर पाक्सो अधिनियम का मामला होने के बावजूद उनकी शिकायत लिखने में टालमटोल की गई। इससे लोगों में नाराजगी और बढ़ गई। यही रवैया कोलकाता मामले में भी देखा गया था। वहां भी प्राथमिकी देर से दर्ज कराई गई। पिछले करीब एक पखवाड़े से देश के विभिन्न हिस्सों से बलात्कार, यौन उत्पीड़न और नृशंस हत्या की घटनाएं रोज ही सामने आ रही हैं। बदलापुर के बाद अकोला में भी छह बच्चियों के यौन शोषण का मामला उजागर हो गया। ऐसी घटनाओं से महिला सुरक्षा को लेकर बने कानूनों और प्रशासनिक सतर्कता पर स्वाभाविक ही सवाल गहरे हुए हैं।

बलात्कार, डरा-धमका कर किए जाने वाले यौन शोषण, राह चलते छेड़खानी आदि के खिलाफ कड़े कानून हैं, मगर आपराधिक वृत्ति के लोगों में उनका खौफ इसलिए नहीं पैदा हो पा रहा कि उन कानूनों पर संजीदगी से अमल नहीं हो पाता। ऐसे मामलों में पुलिस का रवैया प्रायः टालमटोल का ही देखा जाता है। अगर यौन उत्पीड़न का मामला समाज के निचले कहे जाने वाले वर्ग की महिला से जुड़ा हो, तो पुलिस का प्रयास अक्सर समझा-बुझा कर रफा-दफा करने का होता है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित कानूनों को काफी सख्त बनाया गया था। बाल यौन उत्पीड़न से जुड़े पाक्सो कानून में तो तत्काल गिरफ्तारी और जमानत तक न मिलने का प्रावधान है। मगर इन कानूनों का ठीक से पालन न हो पाने के कारण ऐसे मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाज में बढ़ती यौन विकृति और हिंसक वृत्ति की अनेक वजहें हैं, जिनमें से इंटरनेट पर परोसी जाने वाली उत्तेजक और हिंसापूर्ण सामग्री का बड़ा योगदान है। इसलिए ऐसी सामग्री पर रोक लगाने के उपाय करने की मांग उठती रही है। मगर, प्रशासनिक शिथिलता इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जा सकती है।

हमारे देश में यौन उत्पीड़न के बहुत सारे मामलों में परिजन खुद चुप्पी साध जाते हैं। जो मामले पुलिस तक पहुंचते भी हैं, उनमें दोषियों को सजा दिलाने में तत्परता नहीं दिखाई जाती। जांच और गवाहियों में वर्षों लग जाते हैं। बहुत सारे मामलों में पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण देखा जाता है। इसलिए चर्चित मामलों में भी न्याय मिलने में लंबा वक्त लग जाता है। करीब बत्तीस वर्ष पहले हुए अजमेर के ऐसे ही यौन उत्पीड़न मामले में अब दोषियों को सजा सुनाई जा सकी है। उसमें डरा-धमका कर सौ महिलाओं का यौन शोषण किया गया था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनमें लोगों का गुस्सा फूटा, उन्हें लेकर खूब चर्चा हुई, मगर उनमें पीड़िताओं को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जब तक ऐसे मामलों में प्रशासनिक जवाबदेही तय नहीं होगी, विकृत मानसिकता के लोगों पर लगाम कसना कठिन बना रहेगा।

पानी और परेशानी

दिल्ली देश की राजधानी है, मगर बुनियादी सुविधाओं के लिहाज से कई मामलों में यहां व्यवस्थागत खामियां आज भी जस की तस हैं। बरसात के दिनों में तेज बारिश से यहां के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है। लोगों को घंटों जाम से जूझना पड़ता है। इस बार भी दिल्ली में मानसून के आगमन के साथ ही लोगों को जलभराव और यातायात बाधित होने की दिक्कतों से दो-चार होना पड़ रहा है। दरअसल, दिल्ली में बारिश से जलभराव की समस्या का मुख्य कारण जल निकासी की माकूल व्यवस्था न होना है। यहां अलग से बरसाती नालों की कमी हमेशा महसूस की जाती रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक, क्षेत्रफल के आधार पर दिल्ली में बरसाती नालों का एक बड़ा संजाल होना चाहिए, ताकि ज्यादा बारिश होने पर पानी इन नालों के जरिए शहर से बाहर निकल सके। दूसरा, शहर की जल-मल निकासी प्रणाली को बरसाती नालों से अलग करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बरसाती नाले सीवर में बहने वाले कचरे से भर जाते हैं और पानी की पर्याप्त निकासी नहीं हो पाती।

किसी भी शहर में जल-मल निकासी व्यवस्था का चुस्त-दुरस्त होना बेहद जरूरी है। मगर, दिल्ली में सीवेज प्रणाली के रखरखाव में प्रशासन की अनदेखी भी बारिश के दिनों में जलभराव का बड़ा कारण बन जाती है। यहां के कई इलाकों में सीवर की नालियां कूड़े-कचरे से भरी रहती हैं, जिस कारण बारिश का पानी बाहर निकलने के बजाय वहीं पर जमा हो जाता है। वैसे, हर साल बरसात शुरू होने से पहले नालियों की सफाई को लेकर नगर निगम विशेष अभियान चलाता है, लेकिन इस पर कितना काम होता है, इसकी हकीकत तब सामने आती है जब तेज बारिश से कई स्थान जलमग्न हो जाते हैं। इस समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव हो पाएगा, जब प्रशासनिक स्तर पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। जल निकासी के लिए अलग से बरसाती नालों की पर्याप्त व्यवस्था करने के साथ-साथ सीवरों के रखरखाव पर ध्यान देना होगा और इस कार्य में लापरवाही बरतने वालों की जिम्मेदारी तय करनी होगी।

तस्करों के चंगुल में फंसा बचपन

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि हर वर्ष तस्कर दुनिया भर में लगभग तीन लाख बच्चों को गुलामी के लिए बेच देते हैं। मानव तस्करी विरोधी एक संगठन के अध्ययन में बताया गया है कि गरीबी और अशिक्षा के चलते इस तस्करी का संजाल मजबूत हो रहा है।

जयप्रकाश त्रिपाठी

यह एक दर्दनाक सच्चाई है कि पूरे विश्व में तस्करों के गिरोह लाखों नौनिहालों का बचपन छीन रहे हैं। इस समय विश्व में बच्चों की तस्करी का अवैध कारोबार डेढ़ सौ अरब डालर वार्षिक से अधिक का हो चुका है। भारत के कई राज्यों में भूमिगत शिशु तस्कर गिराह सक्रिय हैं, जो माता-पिता की गरीबी का फायदा उठाते हैं। सरकारी अस्पतालों में ढीली सुरक्षा व्यवस्था के कारण हर वर्ष हजारों नवजात शिशु तस्करों के हवाले कर दिए जाते हैं। इसमें चिकित्सा क्षेत्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को बड़ी संख्या में शामिल पाया गया है।

आमतौर पर नशीली दवाओं के धंधे में शामिल तस्कर गिरोह बड़ी खूबसूरती से माता-पिता को यह विश्वास दिलाते हैं कि वे उनके बच्चे का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। तस्करी के शिकार बच्चों की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि उन्हें जानबूझकर उन सेवाओं और समुदायों से छिपाया और अलग-थलग रखा जाता है, जो उन्हें पहचान कर उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। तस्करों के अंतरराष्ट्रीय संजाल में छोटे से छोटे क्षेत्र भी चिह्नित होने लगे हैं, जहां उनके मुखबिर किस्म के एजंट अनाथालयों, बाल सुरक्षा गृहों, अस्पतालों आदि में सक्रिय रहते हैं।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि हर वर्ष तस्कर दुनिया भर में लगभग तीन लाख बच्चों को गुलामी के लिए बेच देते हैं। मानव तस्करी विरोधी एक संगठन के अध्ययन में बताया गया है कि गरीबी और अशिक्षा के चलते इस तस्करी का संजाल मजबूत हो रहा है। इससे निपटने के लिए अब व्यापक सुरक्षा, रोकथाम, कानून प्रवर्तन और पीड़ितों की त्वरित सहायता बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार संरक्षण, खासकर बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र में 'पलेर्मो प्रोटोकाल' सूचीबद्ध है। इसके साथ ही कई अन्य अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियां भी संयुक्त कार्रवाई के तहत इस आपराधिक संजाल की चुनौतियों से निपटने में लगी हुई हैं।

अंतरराष्ट्रीय बालश्रम संगठन की रपट के मुताबिक तस्करी के शिकार शिशुओं में से लगभग साठ फीसद को बड़े होने पर कृषि बालश्रम में लगा दिया जाता है। ऐसे बच्चों से घरों, खेतों, कारखानों, रेस्तरां आदि में काम कराया जाता है। यौन शोषण के साथ ही, उन्हें भीख मांगने, सशस्त्र बलों और नशीली दवा व्यापार में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। गरीबी दुनिया भर में बाल तस्करी का प्रमुख कारण है। एक अध्ययन में पता चला है कि ऐसे बारह करोड़ बच्चे सड़कों पर दिन गुजार रहे हैं, जिनमें से लगभग तीन करोड़ अकेले अफ्रीका में हैं।

एक अध्ययन के मुताबिक भारत में गरीबी से बाहर निकलने या कर्ज चुकाने के लिए अनेक माता-पिता अपने बच्चों को तस्करों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत में गरीबी और संस्थागत चुनौतियों के अलावा, पारंपरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं भी कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। हर वर्ष ग्रामीण भारत से लाखों लड़कियों की तस्करी शहरी क्षेत्रों में घरेलू सहायक के रूप में काम करने के लिए की जाती है। घरेलू नौकरानी के रूप में लड़कियों को

बहुत कम वेतन मिलता है। दुर्व्यवहार के अलावा कभी-कभी उनका यौन उत्पीड़न भी किया जाता है।

यूनीसेफ का अनुमान है कि वर्तमान में दुनिया भर में तीस से अधिक सशस्त्र संघर्षों में अठारह वर्ष से कम उम्र के तीन लाख से अधिक बच्चों

> **मानव तस्करी के बारे में प्रेस, पुलिस, गैरसरकारी संगठनों से बड़ी संख्या में मिली रपटों को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि भारत तेजी से बच्चों की तस्करी करने वालों के लिए एक बड़ा स्रोत, पारगमन बिंदु और गंतव्य बनता जा रहा है। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओड़ीशा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीबी से त्रस्त राज्यों में सबसे अधिक चिंताजनक हालात हैं। इन राज्यों में बाल तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है।**

का शोषण किया जा रहा है। अधिकांश बाल सैनिक 15 से 18 वर्ष आयु के हैं, कुछ की आयु सात या आठ वर्ष के बीच है। शोषित बच्चे बाल पोर्नोग्राफी, बाल वेश्यावृत्ति और बलात्कार के लिए लेन-देन के अधीन पाए गए हैं। अकेले मुंबई शहर में महिलाओं और बच्चों का व्यावसायिक यौन शोषण लगभग चालीस करोड़ अमेरिकी डालर वार्षिक का धंधा है। राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो के अनुसार, भारत में युवा लड़कियों की तस्करी चौदह गुना तक बढ़ गई है।

वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र में पहली बार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई, जिसमें बच्चों की तस्करी रोकने का 'प्रोटोकाल' शामिल किया गया। महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए हमारे देश में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम को पहली बार 1956 में संशोधित किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 स्पष्ट रूप से मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। देश में तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है, जिसने बाल तस्करी विरोधी इकाई का गठन किया है।

मानव तस्करी के बारे में प्रेस, पुलिस, गैरसरकारी संगठनों से बड़ी संख्या में मिली रपटों को आधार बनाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि भारत तेजी से बच्चों की तस्करी करने वालों के लिए एक बड़ा स्रोत, पारगमन बिंदु और गंतव्य बनता जा रहा है। असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, ओड़ीशा और पश्चिम बंगाल जैसे गरीबी से त्रस्त राज्यों में सबसे अधिक चिंताजनक हालात हैं। इन राज्यों में बाल तस्करी में लगातार वृद्धि हो रही है। यूनीसेफ के अनुसार, 1.26 करोड़ बच्चे खतरनाक व्यवसायों में लगे हुए हैं। भारत में मानव तस्करी का केवल दस फीसद अंतरराष्ट्रीय है, जबकि 90 फीसद अंतरराज्यीय पाया गया है। यौन तस्करी में शामिल बच्चों में अधिकांश लड़कियां हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रपट के अनुसार, भारत में हर साल कम से कम 40 हजार बच्चों का अपहरण हो जाता है, जिनमें से 11 हजार बच्चों का तो पता तक नहीं चल पाता। हमारे देश में कम से कम तीन लाख बाल भिखारी हैं। एक एनजीओ का अनुमान है कि हर वर्ष 12 हजार से 50 हजार तक महिलाओं और बच्चों को यौन व्यापार के तहत पड़ोसी देशों से तस्करी करके लाया जाता है। हर वर्ष कम से कम 44 हजार बच्चे तस्कर गिरोहों के चंगुल में फंस जाते हैं। सीबीआइ की एक पुरानी रपट के मुताबिक भारत में अनुमानित 12 लाख बच्चे वेश्यावृत्ति में धकेल दिए गए हैं।

भ्रष्टाचार के चलते कानूनों का कड़ाई से अनुपालन न हो पाना बच्चों की तस्करी की एक बुनियादी वजह है। चूंकि गरीब बच्चे सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं, इसलिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरोहों की निगाहें सबसे ज्यादा उन्हीं पर टिकी रहती हैं। ऐसे परिवार अपने जीवन यापन के लिए अक्सर बच्चों का भविष्य तस्करों के दांव पर लगा बैठते हैं। वयस्कों की तुलना में बच्चों की तस्करी चार गुना से अधिक है। तस्करी के शिकार, 12 से 14 वर्ष के बच्चों को जबरन श्रम, यौनकर्म में झोंकने के साथ ही उनके अंग निकालकर बेचना भी शामिल है। तस्करों द्वारा अगवा वयस्कों की तरह ही बच्चों को भी घरेलू दासता, बंधुआ मजदूरी आदि तरह-तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। व्यावसायिक यौन व्यापार ही बच्चों के शोषण का सबसे बड़ा अपराध-क्षेत्र है। जिनके माता-पिता सशस्त्र संघर्षों के शिकार हो जाते हैं, उनके ज्यादातर अनाथ बच्चे तस्करी के शिकार हो जाते हैं। उसके बाद तो आजीवन वे बच्चे निरक्षरता और बाल तस्करी की भयावहता से जूझते रहते हैं।

पराई खुशी में अपनी खुशी

नरेंद्र सिंह 'नीहार'

दुनिया मेरे आगे

मानव जीवन अनमोल है। शास्त्रों की मानें तो चौरासी लाख योनियों के बाद मानव शरीर मिलता है। हमारे माता-पिता हमारे लिए कितनी मन्नतें और दुआएं मांगते हैं और हमारे लालन-पालन में कितने कष्ट उठाते हैं। हमारी शिक्षा-दीक्षा पर अपनी हैसियत से अधिक खर्च भी करते हैं। वे हमें एक बेहतर और कामयाब इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। मानव जीवन के कुछ मायने हैं। हम बुद्धि और कौशल में अन्य प्राणियों से बेहतर हैं। फिर भी अपना समय परनिंदा, ईर्ष्या, राग-द्वेष, शिकायतों और व्यर्थ के कामों में खोते रहते हैं। इस तरह जीने को जीना नहीं माना जा सकता। इस सत्य को स्वीकार करके अपना परिष्कार करने की आवश्यकता है। अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए कि हमें क्या करना है। उससे ज्यादा हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या कुछ नहीं करना है। जब हम किशोर से युवा होने की ओर बढ़ते हैं, तब हमारे विचारों में प्रौढ़ता और परिपक्वता आने लगती है। हम किसी विषय, वस्तु, विचार या घटना आदि के प्रति अपना नजरिया बनाने लगते हैं। सच्चे अर्थों में यही दृष्टि निर्माण कहलाता है। यहां हमारे परिवार, गुरुजनों, मित्रों और हमारे द्वारा पढ़ी जा रही किताबों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है। यही वे स्रोत हैं, जो हमारे दृष्टिकोण को आधार और आकार देते हैं। हमें सावधानी से इस दिशा में चिंतन-मनन करना चाहिए।

आमतौर पर विद्वानों का समय साहित्य को पढ़ने और मनोविनोद के अन्य साधनों में व्यतीत होता है। इसके विपरीत ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, जिनका समय व्यसनों या बुरी आदतों, सोने और झगड़ा करने में व्यतीत होता है। हमें अपने बारे में गौर करना चाहिए कि हम किस पायदान पर खड़े हुए हैं। पशुओं से अलग होने के लिए कुछ लिप्साओं से अलग होना होगा, तभी हम मनुष्य कहलाने के सच्चे अधिकारी कहे जाएंगे। हम विनम्र हों, मृदुभाषी हों, दूसरों के प्रति संवेदनशील और निज कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक और सचेत हों। सहयोग और सहकार की भावना से प्रेरित हों, मानवीय गुणों को धारण करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। किसी का अहित करने का विचार मन में न लाएं। मन-वचन और कर्म से अहिंसक रहें, इसी में हमारे जीवन की सार्थकता है। ऐसा करके हम एक सुंदर, सुखद और सहयोगी समाज का निर्माण कर सकते हैं।

सोद्देश्य जीवन सरल, सहज और सुंदर होता है। उसे अपने लक्ष्य को पाने की ललक बनी रहती है। वह निराशा में भी आशा की किरण ढूंढ़ लेता है। असफलताओं से घबराता नहीं है। लगन और परिश्रम को अपना पाथेय बना लेता है और जीवन यात्रा में अविराम चलता रहता है। प्रतिकूल धाराओं यानी परिस्थितियों में विचलित हुए बिना जो योजनाबद्ध तरीके से काम करता रहता है, वही विजेता कहलाता है। भारत के एक कामयाब क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि हमें अपना ध्यान परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर केंद्रित रखना चाहिए। परिणाम अपने आप बेहतर होगा। काम करते समय हमारा ध्यान अपने सबसे अच्छे अभ्यास पर होना चाहिए। सकारात्मक सोच और विवेकपूर्ण निर्णय हमेशा हमें आगे रख सकते हैं। जब हम 'स्व' से अधिक 'पर' के लिए सोचते हैं तो हमारी नीयत पर नियति मेहरबान हो सकती है।

एक पहलू यह भी है कि हमें अपने सभी कार्य और व्यवहार अच्छे लगते हैं और यह स्वाभाविक है, पर हमारे कार्य-व्यवहार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन पर इसका कैसा प्रभाव होगा और वे हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, बस इतना ध्यान रख लेना चाहिए। हम सही दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। जिस दिन से आप खुद को समझदार और जिम्मेदार नागरिक के सांचे में ढालना शुरू कर देंगे, हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल जाएंगे। प्रगति के द्वार खुलने लगेंगे।

> **एक पहलू यह भी है कि हमें अपने सभी कार्य और व्यवहार अच्छे लगते हैं और यह स्वाभाविक है, पर हमारे कार्य-व्यवहार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कितने लोग जुड़े हुए हैं, उन पर इसका कैसा प्रभाव होगा और वे हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, बस इतना ध्यान रख लेना चाहिए।**

दिन के चौबीस घंटे सबके लिए समान हैं। किसी से वक्त काटे नहीं कटता तो कोई सोकर और कोई रो-रो कर वक्त काटता है। मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिन्हें यह समय कम पड़ जाता है। सफलता की इबारत ऐसे लोग ही लिखते हैं। कब, कहां, कितना समय देना है, यह स्पष्ट होना चाहिए। जीवन में स्पष्टता बहुत जरूरी है। वह बातों में, काम में और व्यवहार में आ जाए तो जीवन जीने योग्य हो जाए। काम करने के बाद अपने बारे में हमारी राय जब बेहतर होती है, तब हमारी मनोदशा को चेहरे पर पढ़ा जा सकता है। वहां एक संतोष से भरा मुस्कान दिख सकता है। संसाधनों को सहेजते हुए, सबको साथ लेकर, वस्तुओं का सीमित उपभोग करते हुए, परस्पर संबंधों में खुशियां ढूंढ़ते हुए समझदारी के साथ जीवन को जीना ही सबसे बड़ी कला है। आनंदमय जीवन ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। अपना संतोष जरूर प्राथमिक होना चाहिए, लेकिन इसका स्रोत यह हो कि हमारे विचार और व्यवहार से दूसरों को थोड़ी खुशी मिले, अपने व्यक्तित्व का हनन होता न लगे। हमसे मिलने वाली दूसरों की खुशी से हमें जो खुशी मिलेगी, उसका स्वाद अलग होगा, हमारे भीतर गहरे तक उतरेगा।

तकनीक का संजाल

'आभासी जरूरतों का संसार' (दुनिया मेरे आगे, 20 अगस्त) पढ़ा। डिजिटल तकनीक ने हमें फायदे और सुविधाएं दी हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में हम सब इसकी गिरफ्त में आ गए और हमें पता ही नहीं चला। आज के युग में पैसे का लेनदेन, संवाद, व्यापार और बाजार शोध जैसे कार्य आनलाइन माध्यम से हो रहे हैं, जिसे डिजिटल व्यवहार कहा जाता है। हम सब इसके इतने आदी हो चुके हैं कि इसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि हम स्वयं को अचानक असुरक्षित महसूस करने लगे और क्यों वास्तविक दुनिया में डिजिटल व्यवहार के अनुशासन की बात करने लगे? डिजिटल व्यवहार हमें सीधा विकास से जोड़ता है। मगर इसके विपरीत प्रभाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, जो भविष्य में विध्वंस का कारण बन सकता है। आज स्थिति यह है कि तकनीकी व्यवहार हमारे ऊपर शासन करने लगा है। सबसे अधिक प्रभावित बच्चे और युवा हो रहे हैं। ऐसे में हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, जो सबके हित में हों। अगर हम बच्चों से कुछ अपेक्षा कर रहे हैं, तो हमें भी उनका आदर्श बनना पड़ेगा।

– कल्पना झा, फरीदाबाद, हरियाणा

बुजुर्गों के लिए

पेंशनधारियों की आय और जमा आयकर से मुक्त होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्तमंत्री ने बैंकों से कहा है कि लोगों से जमा आकर्षित करने के लिए आकर्षक योजनाएं चलाएं, जिसका पालन भी हो रहा है। मगर कोरोना काल और महंगाई की मार, कर्ज पर ब्याज की भरपाई के साथ रोजगार और आय के स्रोत घटने से बचत करने में मुश्किलें आ रही हैं। 'बचत की बुनियाद' (संपादकीय, 12 अगस्त) में उल्लेख है कि जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज की दर भी बहुत कम है, क्योंकि रेपो रेट से आधा से एक फीसद तक ब्याज की दर ही रखी जा सकती है। अपेक्षित जमा राशि बढ़ाने के लिए पेंशनरों की आय और जमा राशि से मिलने वाले ब्याज को आयकर से पूरी तरह मुक्त रखा जाए, क्योंकि पेंशनभोगियों की संख्या, आय और जमा राशि से बचत की बुनियाद मजबूत होगी।

– बीएल शर्मा 'अकिंचन', उज्जैन

चुनौतियों का मैदान

हमारी आबादी लगभग एक सौ चालीस करोड़ है और ओलंपिक खेलों में हमारे हिस्से में आए कुल छह पदक। पांच कांस्य और एक रजत। दूसरे पक्ष से देखने पर यह भी सामने आता है कि सन 1900 के पेरिस ओलंपिक से लेकर 2004 के पेरिस ओलंपिक तक हमने कुल दस स्वर्ण पदक ही अपनी झोली में डाले हैं, जो एक ही ओलंपिक में इटली जैसे छोटे से देश को मिले ग्यारह स्वर्ण की बराबरी भी नहीं करते। ऐसा भी नहीं कि सरकार अपने खिलाड़ियों पर पैसा खर्च नहीं करती। मगर जिन खिलाड़ियों पर खर्च किया जाता है, वे भी पदक प्राप्त नहीं कर पाते। हमारी ऐसी स्थिति ओलंपिक में है, तो हमें सोचना होगा। इसका प्रमुख कारण भारत में राजनीति का खेल है। दूसरा कारण है क्रिकेट के पीछे हमारी और कंपनियों की दीवानगी। हमारे खिलाड़ियों का खेल के प्रति समर्पण का भाव कम और कमाई पर अधिक ध्यान होना भी हमें ओलंपिक में पीछे धकेलने में अपनी भूमिका निभाता है।

– नरेंद्र टोंक, मेरठ

गुणवत्ता का पाठ

जब से निजी विद्यालयों का जोर बढ़ने लगा, अभिभावकों को समाज मे अपनी शानो-शौकत दिखाने के लिए अपने बच्चों को निजी विद्यालयों मे पढ़ाना ज्यादा रास आने लगा। निजी स्कूलों के संचालकों और कर्ताधर्ताओं ने अच्छी शिक्षा का लालच देकर, मनमाने पाठ्यकर्मों को लागू कर अपने स्कूलों मे ली जाने वाली फीस में हर सत्र में मनमानी वृद्धि करनी शुरू कर दी। बच्चों की पढाई के आर्थिक बोझ से परेशान अभिभावकों को घूम-फिर कर आखिर सरकारी स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। इस सत्र में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या आशा जगाती है कि सूने पड़े सरकारी स्कूलों के दिन बदलने वाले हैं। विभिन्न राज्यों की उन सरकारों के पाठ्यक्रमों मे बदलाव लाने वाले कदमों का स्वागत किया जाना चाहिए, जिनमें स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा अपनाने पर जोर देने का सोचा जा रहा है।

– नरेश कानूनगो, देवास,मप्र

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

चिंतन

धार्मिक कट्टरता की हद पार कर रहा पड़ोसी पाकिस्तान

जब 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो इसके धर्मनिरपेक्ष संस्थापकों ने इस्लामिक राज्य की बात नहीं की थी। मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि नए देश में गैर-मुस्लिम समान नागरिक होंगे। अपने इन्हीं विचारों पर चलते हुए जिन्ना ने बहु-धर्मीय राज्य स्थापित करने की कोशिश की, और पाकिस्तान के पहले मंत्रिमंडल में एक हिंदू, कई शिया और एक अहमदी को नामित किया गया। हालांकि, आज पाकिस्तान धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न का गढ़ बन गया है। पूरे देश में, शिया मुसलमानों को सुन्नियों द्वारा बदनाम करने वाले अभियानों का सामना करना पड़ रहा है जो उन्हें गैर-मुस्लिम घोषित करने का प्रयास किया जाता है। अहमदी- जो उपमहाद्वीप पर मुस्लिम मातृभूमि बनाने की जिन्ना की खोज में उनके सबसे उत्साही समर्थकों में से थे, अब पूरी तरह से प्रतिनिधित्वहीन हैं, आधुनिक पाकिस्तान में वस्तुतः बहिष्कृत के रूप में रह रहे हैं। इसके अलावा, पाकिस्तानी सरकार की नीतियां और संस्थाएं गहराई से सांप्रदायिक हो गई हैं, और कैबिनेट-स्तर पर गैर-सुन्नी मुस्लिम प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक नियुक्तियों तक सीमित है। अगर मुस्लिम समाज के ही एक हिस्से का यह हाल है तो अन्य धर्म से जुड़े हिंदू, सिख, पारसी, जैन समाज की हालत क्या होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब एक नया मामला सामने आया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ईशनिंदा से जुड़े एक फैसले पर नाराज थे। प्रदर्शनकारी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे थे। उनकी अदालत का फैसला पलटने की भी मांग थी। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट का सुरक्षा घेरा तोड़ा। उन्हें कोर्ट में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन आलमी मजलिस ने सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले की समीक्षा के लिए 7 सितंबर तक का वक्त दिया है। बताया जा रहा है कि एफसीर-ए-सगीर, अहमदिया समुदाय से जुड़ी एक धार्मिक किताब है। इसमें अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक के बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने कुरान की व्याख्या अपने हिसाब से की है। सानी को कुरान (प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग) (संशोधन) एक्ट, 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया था। सानी ने अदालत में दलील दी कि उसे जिस एक्ट के तहत सजा दी जा रही है वह 2019 में था ही नहीं। वह तब अपने धर्म से जुड़ी किताब का प्रचार करने के लिए आजाद था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर सहमति जताई और उसे रिहा कर दिया। इस फैसले से धार्मिक संगठन नाराज हो गए। उन्होंने इसकी अलग तरह से व्याख्या करते हुए कहा कि अदालत ने यह माना है कि अहमदिया समुदाय अपनी मस्जिदों के बाहर धर्म का प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते हैं। मतलब यह है कि वे अपनी मस्जिद में अपने मजहब का पालन कर सकते हैं। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में ऐसी कट्टरता देखी गई हो। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वहां हिन्दू, सिख, पारसी महफूज नहीं है और लगातार पलायन कर रहे हैं। कट्टरता का इससे दर्दनाक उदाहरण क्या होगा कि वहां के एक हिन्दू पूर्व सांसद भागकर हरियाणा के फतेहाबाद में आ गए और मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं। उनका कहना था कि वहां उनका परिवार सुरक्षित नहीं था। वहां विश्वविद्यालय को मदरसे से कम आंका जाता है। भविष्य में भी सुधार की गुंजाइश नहीं है।

स्वरूप

डॉ. विशेष गुप्ता

ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षा के भंवर में फंसा छात्र

कोरोना काल ने जिसे सबसे अधिक प्रभावित किया वह शिक्षा व्यवस्था के साथ-साथ पठन-पाठन का स्वरूप रहा है। प्राथमिक स्कूल की शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक भी इस काल में प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। परन्तु इस कालखंड में ऑनलाइन शिक्षा का ऐसा महिमामंडन किया गया जैसे भारत की परम्परागत शिक्षा अपने नये स्वरूप में ऑनलाइन शिक्षा का ढांचा लेकर स्वदेशी शिक्षा का ही अहसास करा रही हो। आज भी देखने में आ रहा है कि शिक्षक, छात्र व अभिभावकों ने भी शिक्षा की समस्त समस्याओं का समाधान इस ऑनलाइन शिक्षा को ही मान लिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ऑफलाइन शिक्षा को छोड़कर इस ऑनलाइन शिक्षा में छात्र के साथ-साथ देश व समाज की सभी समस्याओं का हल मौजूद है। क्या ऑनलाइन शिक्षा ऑफलाइन अथवा कक्षीय शिक्षा का सही विकल्प हो सकती है ? क्या ऑनलाइन शिक्षा भारतीय परिवेश की मूल शिक्षा के समानान्तर खड़ी हो सकती है? ये कुछ ऐसे सामयिक प्रश्न हैं जिनका उत्तर समय रहते खोजना समीचीन प्रतीत होता है। दरअसल, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हमें शिक्षा के कुछ मूल व प्राथमिक उद्देश्यों को जानना व समझना होगा। यहां हम भारतीय ज्ञान परम्परा में समाहित प्रमुख रूप से शिक्षा के तीन उद्देश्यों की चर्चा करेंगे।

शिक्षा के प्रथम उद्देश्य व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर दृष्टिपात करने से ज्ञात होता है कि कक्षा शिक्षण द्वारा छात्र को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि साथ ही उसके व्यक्तित्व को निखारने और उसके चारित्रिक गुणों के विकास की प्रक्रिया भी निरन्तर चलती रहती है। शिक्षा के ऑफलाइन प्रकार में शिक्षक का आचरण और उसके संतुलित व्यवहार के प्रत्यक्ष पहलू भी छात्रों को प्रभावित करते हैं। संस्था के परिसर में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्रों का आपसी संवाद, बहस, विवेचन तथा तर्क प्रस्तुति इत्यादि छात्र के संतुलित व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। संस्था में सम्पन्न होने वाली विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियां छात्र के व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती हैं। ऑनलाइन शिक्षा में गतिविधियां लगभग शून्यता लिए हुए रहती हैं। इस परिस्थिति में छात्र गूगल अथवा इन्टरनेट के अन्य माध्यमों से सैद्धान्तिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन वहां मानवीय व एकल व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया नगण्य ही रहती है। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज का कल्याण है, जो पहले लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति में सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण जैसे सामूहिकता,भ्रातृ भाव, सहिष्णुता व आपसी सद्भाव इत्यादि ठीक से विकसित न हो पाएं तो समाज भौतिक स्तर पर भले ही सम्पन्न हो जाएं, लेकिन उसमें अनेक प्रकार की विसंगतियां रहेंगी और जो विविध प्रकार की सामाजिक समस्याओं को जन्म देंगी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। उसमें पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल होगा, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत छात्र वंचित ही रहेंगे। देखा जाये तो विज्ञान, तकनीक और चिकित्सा जैसे विषयों की पढ़ाई तो इन विषयों के व्यावहारिक ज्ञान के बिना न तो संभव होगी और न ही पूर्णता प्राप्त करेगी। छात्रों के ज्ञान के परीक्षण में भी ऑनलाइन पद्धति पूरी तरह से सफल नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा में आमतौर पर वस्तुनिष्ठ प्रारूप में परीक्षाएं होती हैं। इसमें ऑफलाईन परीक्षा की तरह विद्यार्थियों के संपूर्ण विवेचन और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का सम्यक परीक्षण नहीं हो पाता। शिक्षा के अन्य उद्देश्यों में एक अन्य उद्देश्य रोजगारपरक शिक्षा भी है। परन्तु यहां कहना न होगा कि विशुद्ध ऑनलाइन डिग्री से जुड़ी शिक्षा इसमें ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगी। मल्टीटास्किंग के वर्तमान कालखंड में विशुद्ध सैद्धान्तिक ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान और सामाजिक कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो ऑनलाइन में कमोबेश अधूरा ही रह जाता है।

आज ऑनलाइन शिक्षा को वर्तमान आधुनिक शिक्षा के लिए एक अचूक औषधि माना जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा को बिल्कुल खारिज कर दिया जाए? नहीं। निश्चित ही यह शिक्षा उन कामकाजी लोगों के लिए बहुत लाभकारी है जिनके लिए नियमित शिक्षा प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। नए तरह के रोजगार पाने अथवा प्रमोशन में ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े प्रोग्राम उनके लिए बहुत सहायक सिद्ध होंगे। कहा जा सकता है कि छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा की तुलना में ऑफलाइन शिक्षा के प्रतिमान को अधिक महत्व दिए जाने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होल्कर

जयंती विशेष

शिवप्रकाश

पुण्य श्लोक महारानी अहिल्याबाई होल्कर की संपूर्ण देश 300वीं जन्म-जयंती मना रहा है। अनेक सामाजिक संस्थाएं एवं महिला संगठन उनके जयंती वर्ष में उनके अलग-अलग गुणों को प्रकट करने वाले कार्यक्रम एवं गोष्ठियो का आयोजन कर रहे हैं। अनेक सरकारे भी महारानी अहिल्याबाई के सुशासन, नगरीय विकास, रोजगार परक उद्योगनीति जैसे विषयों पर संवाद आयोजित कर रही हैं। महारानी का जीवन एवं शासन शैली संवेदनशील, सादगी, सहजता, धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय एवं लोक कल्याणकारी थी। इन्हीं गुणों के कारण उनकी प्रजा उन्हें सदैव लोकमाता के रूप में देखती थी। उनके अप्रतिम गुणों को देखकर ब्रिटिश इतिहासकार जॉन केयस ने उन्हें 'दार्शनिक रानी' (The Philosopher Queen) की उपाधि दी।

अहिल्या बाई पिता मंकोजीराव शिंदे एवं माता सुशीला बाई के परिवार में 31 मई 1725 को जन्मी थीं। उनका जन्म स्थान चौंडी (अहमदनगर, महाराष्ट्र) जो अब अहिल्यानगर के नाम से ही परिवर्तित हो गया है। धनगर जाति में जन्म लेने के बाद भी उनकी प्रतिभा को पहचानकर पेशवा बाजीराव एवं मल्हारराव होल्कर दोनों के परस्पर परामर्श के उपरान्त अहिल्याबाई का विवाह मल्हारराव ने अपने पुत्र खंडेराव के साथ संपन्न कराया। युद्ध में वीरगति प्राप्त होने के कारण उनको पति वियोग सहना पड़ा। अपने जीवनकाल में उन्होंने श्वसुर मल्हारराव होल्कर,नवासे (पुत्री के पुत्र) एवं पुत्री सभी की असमय मृत्यु को देखा। इसी असहय वेदना को सहते- सहते वे स्वयं भी 70 वर्ष की उम्र में 1795 में संसार छोड़ कर चली गई।

पति की मृत्यु के पश्चात अपने श्वसुर के आग्रह पर उन्होंने राजकाज सम्हालना प्रारंभ किया। उनका शासन प्रजा वत्सल, न्यायप्रिय, सुशासन का प्रतीक था। अपनी धर्म के प्रति भक्ति के कारण उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से परिवर्तित कर पवित्र नदी नर्मदा के किनारे महेश्वर में स्थानांतरित की। उनका महेश्वर में राजधानी स्थानान्तरित करने का उद्देश्य था कि राज्य संचालन के साथ-साथ वह माँ नर्मदा की सेवा एवं आराधना कर सके। माँ नर्मदा के किनारे उनका महल एक सर्वस्वत्यागी सन्यासिनी का महल था। जिसमें उन्होंने अपनी आयु के 28 वर्ष व्यतीत किए थे।

देश की सरकारे वर्तमान समय में अपनी आर्थिक नीतियों के केंद्र में समाज के जिस पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं लघु उद्योग केंद्रित नीतियों का विचार करती हैं। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने इस दूरदृष्टि का परिचय देते हुए उन्होंने 1745 में एक राजज्ञा द्वारा बुनकर, सुतार, कारीगरों को महेश्वर में निवास करने का आग्रह किया।आर्थिक विकास की दिशा में उनके द्वारा की गई अनेक पहल में से एक महेश्वर में निर्मित साड़ी आज भी संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। जिसे महेश्वरी साड़ी के नाम से जाना जाता है। इस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए वह स्वयं भी वहाँ निर्मित वस्त्र पहनती थी एवं देश- विदेश से आने वाले महानुभावों को भेंट स्वरूप इन्हीं वस्त्रों को प्रदान भी करती थी। प्राकृतिक आपदा में किसानों का सहयोग, सेना आवागमन से होने वाली फसलों की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था भी उन्होंने की थी।आत्म निर्भरता के साथ-साथ शिक्षा का केंद्र महेश्वर बने इसके लिए विद्वानों, धर्माचार्यों को बुलाकर संस्कृत पाठशाला प्रारंभ करने का कार्य भी उनके द्वारा हुआ।

मल्हार राव के युद्ध अभियानों पर जाने के उपरांत महारानी अहिल्याबाई राज्य का संचालन भी कुशलता के साथ करती थी। पत्राचार के माध्यम से मल्हार राव को अपने राज्य के समाचार भेजना एवं प्रत्युत्तर में राज्य संचालन के लिए सुझाव लेना यह उनकी नियमित प्रक्रिया थी। सेवा एवं रसद सामग्री का प्रबंध,कर वसूली आदि की व्यवस्था बड़ी निपुणता के साथ उन्होंने की थी।

महारानी स्त्री होने के बाद भी न केवल राज्य संचालन में निपुण बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। बचपन में ही सैन्यशिक्षा, घुड़सवारी, शस्त्र संचालन उन्होंने सीखा था। राघोवा के आक्रमण के समय अपने राज्य की रक्षा के लिए कूटनीति का परिचय देते हुए उन्होंने पुराने संबंधों के आधार पर सिंधिया, भोंसले, गायकवाड आदि का सहयोग माँगा। राघोवा को उचित दंड देने के लिए 500 महिलाओं की सैन्य टुकड़ी को प्रशिक्षित भी किया।राघोवा को उनके द्वारा लिखा पत्र आज भी उनकी कूटनीतिक दूरदर्शिता को प्रकट करता है। जिसमें उन्होंने लिखा कि "आप मुझे अबला समझकर राज्य हड़पने के लिए यहां आए हैं लेकिन मेरी शक्ति आपको युद्ध क्षेत्र में ज्ञात होगी। मैं महिला सेना के साथ आपका मुकाबला करूंगी। यदि मैं युद्ध में पराजित हो गई तब मेरी हंसी और आपकी प्रशंसा कोई नहीं करेगा और यदि आप युद्ध में हार गए तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।" केवल राघोवा ही नहीं अपने राज्य की सीमाओं पर राजस्थान की ओर से मिलने वाली चुनौती का भी उन्होंने साहस के साथ सामना कर शत्रु को कुचल ने का कार्य किया। सेना का संचालन, सैनिकों की चिकित्सा आदि भी उन्होंने कुशलता के साथ की। नाना फड़नवीस ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि "अब तक देवी अहिल्याबाई की धार्मिकता की प्रशंसा तो हम सुनते आए हैं मगर हम नहीं जानते थे कि वह बहादुर भी हैं अपने शत्रुओं के दांत खट्टे कर सकती हैं।"

महारानी अहिल्याबाई का शासन कठोर एवं न्याय प्रिय शासन था। उन्होंने जाति-पाति, ऊँच - नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर चोरो के भय से जनता को मुक्ति प्रदान करने वाले नौजवान से अपनी पुत्री का विवाह किया। गरीब एवं कमजोर लोगों की सेवा में वह हमेशा तत्पर रहती थी। पति की मृत्यु के पश्चात पति की संपत्ति पर पूर्ण अधिकार की व्यवस्था एवं स्त्री को दत्तक लेने का अधिकार देना यह उनके महिला सशक्तिकरण के उदाहरण है। उनके राज्य में रहने वाले भीलों (जनजाति) को अपराध मुक्त करने के लिए कृषि के औजार उपलब्ध कराकर सशक्त करने का कार्य उन्होंने किया। अपराध करने पर कठोर दंड एवं समस्याओं का त्वरित समाधान यह उनके शासन की विशेषता थी। पक्षपात रहित सभी को समान न्याय उनके शासन में था। इसके लिए अपने सेनापति के पुत्र को भी अपराध करने पर उन्होंने जेल में डलवा दिया था। प्रजा को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति उन्होंने की थी।अपने राज्य कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील एवं आत्मीयता पूर्ण व्यवहार, युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिक परिवारों के कल्याण की व्यवस्था को राज्य कोष से करने का प्रबंध उन्होंने किया था। अपने प्रति कठोर जीवन जीते हुए , प्रजा का पुत्र की तरह पालन, लोक कल्याण की योजनाएं एवं न्यायप्रियता के कारण उनको लोकमाता की उपाधि मिली।

राज्य संचालन में अनेक गुण होने के बाद भी उनका शासन मूलतःधर्म अधिष्ठित शासन था। जहां उनके व्यक्तिगत जीवन में सेवा, त्याग -तपस्या एवं दान का महत्व था वहीं उन्होंने मंदिरों के जीर्णोद्धार, उनकी स्थायी आर्थिक व्यवस्था,यात्रियों के लिए विश्राम स्थल एवं अन्न क्षेत्र स्थापित कराए।अपना राज्य भगवान शिव को समर्पित कर वह उनके प्रतिनिधि के रूप में शासनचलातीं थी। हिमालय में स्थित भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ , दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिका से लेकर पूर्व में जगन्नाथ पुरी तक उनके द्वारा चलाएं सेवा कार्य आज भी प्रसिद्ध है। तीर्थ स्थानो पर गंगा जल भिजवाने की व्यवस्था देश को एकसूत्र में बांधती दिखाई देती है।काशी विश्वनाथ मंदिर केजीर्णोद्धार सहित देश के लगभग समस्त तीर्थ क्षेत्रों के विकास, हरिद्वार के गंगा घाटों सहित देशभर की नदियों के किनारे सैकड़ो स्थानो पर उन्होंने पक्के घाटों का निर्माण कराकर तीर्थ यात्रियों के उचित स्नान की व्यवस्था करायी। समस्त अगणित धार्मिक कार्य वह अपने भाग में प्राप्त संपत्ति के द्वारा कराती थी। वह दीन- दुखी, गरीबों के लिए समर्पित निष्ठावान कर्मयोगी थी।

दक्षिण के प्रसिद्ध इतिहास कार रायबहादुर चिंतामणि विनायक वैद्य ने महारानी के संदर्भ में लिखा है कि वह लोकोत्तर स्त्री अपने अनेक गुणों के कारण महाराष्ट्र के लिए ही नहीं वरन समूची मानव जाति के लिए भूषण रूप हुई है। इंदौर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रमोदीजी अपने उद्बोधन में कहा था कि "मैं देवी अहिल्याबाई को भी नमन करता हुँ उनका पुण्यस्मरण करता हुँ। देवी अहिल्याबाई ने शासन संचालन में छोटी-छोटी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, उनके जीवन का एक-एक अध्याय इतना प्रेरक होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उनसे सीख मिलती रहेगी। लोकमाता महारानी अहिल्याबाई केजीवन से प्रेरणा लेकर उनकी 300 वीं जयंती के अवसर पर हम उनके दिखाये मार्ग का अनुसरण करते हुए एकात्म, समृद्ध, समरस एवं शक्तिशाली भारत का निर्माण करें तथा अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हुए विश्वकल्याण करने का संकल्प लें। महारानी अहिल्याबाई होल्कर को उनकी 300वीं जन्म-जयंती पर यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

-भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री

मुंह के मौन से ज़्यादा ज़रूरी 'मन का मौन'

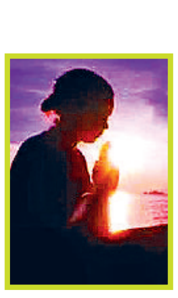

संकलित

दर्शन

हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी-कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन अवश्य मौन रहें, परंतु हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। इसलिए ही तो अधिकतर डाक्टर सभी मरीजों को कहते हैं कि 'अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ।' अर्थात 'मन का मौन' करो। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है, तो कइयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए तो हमें यह बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदहारण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुबान के फिसलने से संकटकाल का निर्माण हो गया। इसीलिए 'कम बोलें-धीरे बोलें-मीठा बोलें।' हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, न कि कांटा चुभाने वाले दुखदायी। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसलिए हमें सदैव सही समय और सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

काम करते रहना ज्यादा महत्वपूर्ण

संकलित

प्रेरणा

एक प्राचीन कथा के मुताबिक, ब्रह्मा और विष्णु ने शिवलिंग के मस्तक और पैरों की खोज शुरू की। ब्रह्मा को शिव का मस्तक ढूंढने का और विष्णु को शिव के पैर ढूंढने का कार्य सौंपा गया। सभी देवता इसके आरंभ और अंत के विषय में जानने के लिए उत्सुक थे। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा आरंभ की और वे आगे बढ़ते गए। कई लोक पीछे छूट गए और कई युग बीत गए। फिर भी ब्रह्मा शिव के मस्तक का पता नहीं लगा पाए। सृष्टि का एक अंत है। सृजन एक बिंदु पर समाप्त होता है। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा उसके बाद भी जारी रखी। उन्होंने एक केतकी का पुष्प देखा जो आकाश से नीचे आ रहा था। ब्रह्मा ने केतकी पुष्प से पूछा, 'तुम कहां से आ रहे हो? क्या तुमने शिव का मस्तक देखा है? यहां से शिव का मस्तक कितनी दूर है?' केतकी पुष्प ने कहा, 'मैं शिव के मस्तक से आ रहा हूं।' तो ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि शिव का एक मस्तक था और वे पुष्प लेकर नीचे आए। विष्णु का कार्य शिव के पैरों की खोज करना था। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु बहुत विनम्र हैं। पालनकर्ता को हमेशा बहुत विनम्र होना चाहिए। रचयिता जैसा भी हो, यदि पालनकर्ता विनम्र हो, तभी पालन कार्य संभव है। व्यवसाय आरंभ करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको व्यवसाय चलाने के लिए बहुत सतर्क, बहुत विनम्र रहना पड़ेगा, अन्यथा व्यापार डूब जाएगा। विष्णु की विनम्रता ने ही उन्हें शिव के चरणों को ढूंढने का कार्य करने योग्य बनाया। युगों तक यात्रा करने के बाद, विष्णु शिव के चरणों को ढूंढने में सक्षम नहीं हुए।

स्वर्ण आभूषण

सुनार संजय नाना वेदक ने बुधवार को मुंबई में अपनी दुकान पर भगवान गणेश की मूर्ति के लिए अपने द्वारा तैयार किए गए आभूषणों को प्रदर्शित किया। वह तीन दशकों से अधिक समय से गणेश की मूर्तियों के लिए सोने और सोने की परत चढ़े आभूषण बना रहे हैं।

आज की पाती

मनुष्य जन्म का महत्त्व समझें

श्रीरामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि 'बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन्हि गावा। साधन धाम मोच्छ कर द्वारास पाइ न जेहिं परलोक संवारा॥' अर्थात हमें मनुष्य का तन मिलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यह तन देवताओं के लिए भी दुर्लभ होता है। मनुष्य तन से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें जो अपने अच्छे कर्मों से मनुष्य का जीवन सौभाग्य से मिला है, इसका हमें उचित प्रयोग करना चाहिए, अनुचित काम करके इस मनुष्य जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान के दिए अनमोल इनसानी जीवन को आत्महत्या द्वारा समाप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को नैतिकता और हर मुसीबत का सामना करने का सबक पढ़ाएं, ताकि बच्चे जिंदगी में कभी कोई गलत राह न चुनें। *– कमलेश चतुर्वेदी, दुर्ग*

ट्रेंड

यूक्रेन का दौरा

मैं ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति के निमंत्रण पर यूक्रेन का दौरा करूंगा। यह यात्रा उनके साथ पहले हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने और भारत-यूक्रेन मित्रता को गहरा करने का अवसर होगी। हम यूक्रेन में चल रहे शांतिपूर्ण समाधान पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। **-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

जातिगत गिनती

संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की 'लेटरल एंट्री' जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम कर के दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं - 50% आरक्षण सीमा को तोड़ कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। **-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद**

खुशी की बात

मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिलना सौभाग्य और खुशी की बात थी। मलेशिया में सबसे बड़ा बायोफार्मा निवेश है। हमने आयात को प्रतिस्थापित करते हुए एशिया की सबसे बड़ी इंसुलिन सुविधाएं बनाई हैं और वैश्विक स्तर पर इंसुलिन का निर्यात भी किया है। **- किरण मजूमदार शॉ, उद्यमी**

'इमरजेंसी' का प्रचार

क्या आप कलर्स टीवी पर लाफ्टर शेफ्स देखते हैं? वहां मेरी फिल्म इमरजेंसी का प्रचार हो रहा है, गणेश चतुर्थी एपिसोड देखें। **-कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री**

करंट अफेयर

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की पश्चिम एशिया की यात्रा समाप्त

गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की पश्चिम एशिया की नौवीं यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन इस दौरान इजराइल और हमास के बीच संघर्ष-विराम समझौता नहीं हो सका। हमास और इजराइल द्वारा चुनौतियां बरकरार रहने के संकेत दिए जाने के बीच ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि समझौते को इसी 'समय करना बहुत महत्वपूर्ण है।'' ब्लिंकन ने सहयोगी मध्यस्थ देशों मिस्र और कतर में बैठकों के बाद कहा कि चूंकि, इजराइल ने हमास के साथ मतभेदों को पाटने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब 'हमास को साथ लाने' के लिए हर संभव प्रयास करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित है कि दोनों पक्ष समझौते के कार्यान्वयन संबंधी मुख्य बिंदुओं पर सहमत हों। उन्होंने कतर से जाने से पहले पहले संवाददाताओं से कहा, ''हमारा संदेश सरल, स्पष्ट और अत्यावश्यक है।' ब्लिंकन ने कहा, 'हमें संघर्ष-विराम और बंधकों की रिहाई संबंधी समझौते को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है, और हमें इसे अभी करना होगा। इसे इसी समय करना अहम है।' ईरान और लेबनान में हमास और हिजबुल्ला के दो शीर्ष कमांडर की हाल में निशाना बनाकर हत्या किए जाने से समझौते की आवश्यकता और बढ़ गई है।

ऑफ बीट

पुरुषों में होती है जैविक घड़ी क्षमता होती है प्रभावित

हम महिलाओं की जैविक घड़ी के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और कैसे उम्र गर्भधारण की संभावना को प्रभावित करती है। नए शोध से पता चलता है कि पुरुषों की प्रजनन क्षमता भी उम्र से प्रभावित होती है। जब पुरुष की उम्र 50 से अधिक हो, तो उसकी पत्नी को गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। 2011 और 2022 के बीच अमेरिका में चार करोड़ 60 लाख से अधिक जन्मों के डेटा में 30 साल के पिता की तुलना 50 साल के पिता से की गई। मां की उम्र और गर्भावस्था के परिणामों को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए, शोधकर्ताओं ने पाया कि माता-पिता की उम्र में हर दस साल की वृद्धि अधिक जटिलताओं से जुड़ी हुई थी। शोधकर्ताओं ने पाया कि उन जोड़ों की तुलना में जहां पिता की उम्र 30-39 थी, उन जोड़ों की तुलना में जहां पिता की उम्र 50 के आसपास थी, समय से पहले जन्म का जोखिम 16% बढ़ गया था जन्म के समय कम वजन का खतरा 14% बढ़ गया गर्भावधि मधुमेह में 13% की वृद्धि। अपने युवा समकक्षों की तुलना में अधिक उम्र के पिताओं द्वारा गर्भधारण के लिए आईवीएफ सहित सहायक प्रजनन तकनीक का उपयोग करने की संभावना दोगुनी थी।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

Want to get these Newspapers Daily at earliest

1. AllNewsPaperPaid
2. आकाशवाणी (AUDIO)
3. Contact I'd:- https://t.me/Sikendra_925bot

Type in Search box of Telegram
@AllNewsPaperPaid And you will find a
Channel
Name All News Paper Paid Paper join it and
receive
daily editions of these epapers at the earliest

Or you can tap on this link:

https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid https://t.me/AllNewsPaperPaid

https://t.me/AllNewsPaperPaid